[2014] 10 एस. सी. आर *1*

मद्रास बार संगठन

वी.

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

(2006 का हस्तांतरित मामला *(*सी*)* संख्या *150)*

सितंबर *25,2014*

[आर. एम. लोधा, सीजेआई। , जगदीश सिंह खेहर, जे।

चेलामेश्वर, ए. के. सिकरी और आर. एफ. नरीमन, जे. जे.*]*

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, *2005:*

एन. टी. टी. अधिनियम की घोषणा का इतिहास-चर्चा की गई। क्या उच्च न्यायालय जो न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं, एन. टी. टी. जैसे अतिरिक्त न्यायिक निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और क्या एन. टी. टी. अपने संविधान के तरीके को कमजोर करता है स्वतंत्रता और निष्पक्षता की एक प्रक्रिया, जो अनिवार्य है गैर-न्यायिक प्राधिकरण-आयोजितः यह अस्वीकार्य था विधायिका के लिए मुख्य न्यायिक अपीलीय को निरस्त/विभाजित करने के लिए पारंपरिक रूप से उच्च न्यायालय के पास निहित कार्य, और इसे एक स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के साथ प्रदान करना/निहित करना, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी के बुनियादी तत्व भी नहीं थे। न्यायालय, उच्च न्यायालय की तरह *(*जिसका अधिकार क्षेत्र स्थानांतरित करने की मांग की जाती है*)*-उच्च न्यायालयों में निहित अधिकार क्षेत्र *226* और संविधान का *227*, केवल के संबंध में नहीं है न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर वैधानिक प्रावधानों का, लेकिन पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का भी सही कार्यान्वयन और नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में कटौती की जाए।

चाहे वह नए बनाए गए क्षेत्राधिकार को हस्तांतरित करते समय हो न्यायालय/न्यायाधिकरण, मानकों को बनाए रखना आवश्यक है और न्यायालय का दर्जा बदल दिया गया-आयोजितः संसद नहीं थी एक नए नाम के तहत एक अदालत की स्थापना से वंचित, कि ऐसे न्यायालय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति / न्यायाधिकरण की नियुक्ति उसी तरीके से की जानी चाहिए और कार्यकाल की उतनी ही सुरक्षा का हकदार होगा, जितनी न्यायिक पद धारक को, उस समय जब संविधान लागू हुआ था-उच्च न्यायालय।

क्या न्यायनिर्णायक कार्यों का हस्तांतरण निहित है एन. टी. टी. के लिए उच्च न्यायालय मान्यता प्राप्त संवैधानिक उल्लंघन करता है सम्मेलन-आयोजितः वेस्टमिंस्टर मॉडल से संबंधित मान्यता प्राप्त संवैधानिक सम्मेलनों को प्रतिबंधित न करें कानून बनाने से लेकर निहित करने तक का अधिकार न्यायिक कार्य, जो पहले एक उच्च न्यायालय में निहित थे, एक वैकल्पिक न्यायालय/न्यायाधिकरण के साथ-इस तरह की शक्ति का प्रयोग संसद अपने आप में किसी भी संविधान का उल्लंघन नहीं करेगी। सम्मेलन।

एस। *5* - खंड की वैधता जो आमतौर पर एन. टी. टी. के पास होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसकी बैठकें-की भूमिका एन. टी. टी. की पीठों की बैठक निर्धारित करने में केंद्र सरकार-आयोजितः केंद्र को अनुमति देना उचित नहीं है। स्थानों के संदर्भ में सरकार कोई भी भूमिका निभाएगी जहाँ पीठों की स्थापना की जाएगी, वे क्षेत्र जिन पर पीठों का अधिकार क्षेत्र होगा, संरचना और पीठों का गठन, साथ ही, का स्थानांतरण एक पीठ से दूसरी पीठ में सदस्य-उप-धारा *(2), (3), (4)* और *(5)* एस। *5* असंवैधानिक हैं।

एस। 6 -- - खंड की वैधता कि कोई व्यक्ति योग्य होगा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए, यदि वह सदस्य है या रहा है आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या सीमा शुल्क, कम से कम 5 वर्षों के लिए उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण

आयोजित किया गयाः केवल पेशेवर योग्यता रखने वाला व्यक्ति

- कानून में, कानून के अभ्यास में पर्याप्त अनुभव के साथ, उन भारी जिम्मेदारियों को संभालने की स्थिति में होगा जो एक अध्यक्ष और एनटीटी के सदस्यों को अपने कंधों पर उठानी होंगी।

लेखाकार सदस्य और तकनीकी सदस्य यह नहीं कह सकते हैं

न्यायाधीशों का कद और योग्यता होना

उच्च न्यायालय - धारा 7 को असंवैधानिक घोषित किया गया है।

एस। 7- अध्यक्ष और अन्य की नियुक्ति की वैधता

केंद्र सरकार द्वारा सदस्य

आयोजित किया गयाः एनटीटी ने किया है

उच्च के प्रतिस्थापन के रूप में गठित

न्यायालय-मद्रास बार एसोसिएशन का तरीका v. भारत संघ 3

एन. टी. टी. में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति होगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रचलित प्रक्रिया के समान (या समान प्रक्रिया द्वारा) होना।

अदालतें - धारा 7 को संवैधानिक रूप से वैध नहीं माना जा सकता है,

चूंकि इसमें एन. टी. टी. के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में केंद्र सरकार के विभागों के सचिवों की भागीदारी शामिल है - एस. 7 असंवैधानिक घोषित किया जाता है।

एस. 8 - अध्यक्ष/सदस्य की नियुक्ति की वैधता

एन. टी. टी. को, पहली बार में, 5 साल की अवधि के लिए और पुनर्नियुक्ति, 5 वर्ष की और अवधि के लिए- आयोजितः पुनर्नियुक्ति के लिए एक प्रावधान का प्रभाव स्वयं होगा

अध्यक्ष/सदस्यों की स्वतंत्रता को कम करना। एन. टी. टी.-के लिए नियुक्त प्रत्येक अध्यक्ष/सदस्य

एनटीटी, मामलों को इस तरह से तय करने के लिए विवश होगा कि

एस के संदर्भ में उनकी पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। 8 अधिनियम-उसके निर्णय उसकी स्वतंत्र समझ पर आधारित हो भी सकते हैं और नहीं भी। 8 असंवैधानिक घोषित किया जाता है।

एस. *13 (1)* - चाहे एस। *13 (1)* जहाँ तक यह लेखाकारों को एन. टी. टी. के वैध होने से पहले अपील में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है -

आयोजित किया गयाः एस का एक अवलोकन। *13* पता चलता है, कि एक अपील के लिए एक पक्ष *(*अन्य

राजस्व से अधिक*)* या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं, या एक या अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट को अधिकृत कर सकते हैं, या कानूनी हो सकते हैं। व्यवसायियों, या उनके द्वारा विधिवत अधिकृत कोई भी व्यक्ति, प्रस्तुत करने के लिए

एनटीटी के समक्ष उनका मामला-एनटीटी के सदस्य करेंगे निश्चित रूप से उभरते कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ेगा

न्यासों और समितियों, अनुबंध कानून, संबंधित कानून से संबंधित संपत्ति का हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा से संबंधित कानून, कानूनों की व्याख्या और अन्य विविध प्रावधान

कानून, समय-समय पर-एन. टी. टी. को इन कानूनों के अलावा, न केवल तीनों के प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी। कानून, जिनमें से अपीलों की सुनवाई इसके द्वारा की जाएगी, लेकिन वैधानिक शक्तियों के लिए एक चुनौती की भी जांच करनी होगी

उक्त प्रावधानों में किए गए संशोधन, समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

4

चार्टर्ड एकाउंटेंट सबसे अच्छा विशेषज्ञ होंगे

खातों से संबंधित मुद्दों को समझना और समझाना-उन्हें एन. टी. टी. के समक्ष किसी पक्ष की ओर से उपस्थित होने की अनुमति देना।

अस्वीकार्य होगा - एस. *13* जहाँ तक यह चार्टर्ड को अनुमति देता है

लेखाकार एन. टी. टी. के समक्ष अपील करने के लिए किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा असंवैधानिक घोषित किया जाता है।

एस। *15* - क्या कंपनी सचिवों को अनुमति दी जानी चाहिए

अपील में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए एन. टी. टी. के समक्ष उपस्थित होना

समान रूप से, और लेखाकारों के साथ समानता पर-आयोजितः

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि एस के संदर्भ में। *15* , एन. टी. टी. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की अपीलों की सुनवाई करेगा और

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण *(* सी. ई. एस. टी. ए. टी.*)* केवल "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों" पर, यह मुश्किल है।

एन. टी. टी.-निर्धारण से पहले, किसी पक्ष की ओर से, किसी अपील के लिए, चार्टर्ड एकाउंटेंट या कंपनी सचिवों के माध्यम से, प्रतिनिधित्व के औचित्य की सराहना करना।

एन. टी. टी. के हाथों में तथ्यात्मक विवाद हैं-यह है

केवल "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों" का निर्णय करना-कंपनी सचिवों को किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एनटीटी के समक्ष अपील-कंपनी सचिवों का दावा,

एन. टी. टी. खारिज होने से पहले किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करना।

एसएस। *5 , 6 , 7 , 8* और *13*-एनटीटी के इन प्रावधानों के बाद से

अधिनियम को अवैध और असंवैधानिक ठहराया गया है, शेष प्रावधानों को अनुचित और असंवैधानिक बना दिया गया है।

एन. टी. टी. अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है-क्योंकि उक्त प्रावधान इस प्रकार हैं -

एन. टी. टी. अधिनियम की इमारत, और इन प्रावधानों के बिना शेष प्रावधान अप्रभावी हो जाते हैं और

असंगत, पूरे अधिनियम को घोषित किया जाता है

असंवैधानिक है।

संविधान *(*बयालीसवां संशोधन*)* अधिनियम, *1976* की संवैधानिक वैधता पर इस आधार पर हमला किया गया कि यह उच्च न्यायालय में निहित "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति को बाधित करके भारत के संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।

न्यायालय-चर्चा-आयकर अधिनियम-सीमा शुल्क अधिनियम, *1962 -* केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, *1944*।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *5*

भारत का संविधान, *1950:* बुनियादी संरचना-क्या एन. टी. टी. अधिनियम "बुनियादी" का उल्लंघन करता है*?*

संविधान की संरचना-आयोजितः एन. टी. टी. अधिनियम द्वारा हस्तांतरित क्षेत्राधिकार के तहत निर्दिष्ट विषयों के संबंध में था कर संबंधी कानून-यह अनुमत था-हालाँकि, एन. टी. टी. अधिनियम ने न्यायालयों में निहित शक्तियों का हस्तांतरण नहीं किया है।

संविधान-संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालय में निहित "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति बनी हुई है।

अक्षुण्ण-चूंकि उच्च न्यायालय का उपरोक्त अधिकार क्षेत्र नहीं है

न्यायिक कार्य, जो पहले उच्च न्यायालय में निहित थे, एक वैकल्पिक न्यायालय/न्यायाधिकरण के साथ इस तरह की शक्ति का प्रयोग संसद अपने आप में संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन नहीं करेगी।

उल्लंघन किया गया है, यदि संबंधित कानून बनाते समय

न्यायिक शक्ति का हस्तांतरण, संसद यह सुनिश्चित नहीं करती है कि

नव निर्मित न्यायालय/न्यायाधिकरण, न्यायालय की मुख्य विशेषताओं और मानकों के अनुरूप है

प्रतिस्थापित-राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, *2005*।

कला *129,131,132* से *134* ए, *136,141,145,214,215,225,*

226 , 227 , 368 – उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ-इसके दायरे पर चर्चा की गई।

Art.227-का दायरा-आयोजितः की अधीक्षण शक्ति

कला के तहत उच्च न्यायालय। *227* अदालतों और न्यायाधिकरणों को कानून की सीमा के भीतर रखना है-इसलिए, कानून की त्रुटियां जो हैं

अभिलेख के चेहरे पर स्पष्ट हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है

इस तरह की त्रुटियों को सुधारने में, उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से यह कहना होगा कि

कानून के प्रश्नों को तय करके कानून क्या है, जो भविष्य के मामलों में अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरणों को बाध्य करता है -

सिविल प्रक्रिया, *1908 - s.100*।

सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908: s.100*-का दायरा-आयोजितः केवल उच्च न्यायालयों को ही कानून के प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है-अब तक संसद ने एक

कानून के प्रश्नों पर निर्णयों के साथ अभिलेख का वरिष्ठ न्यायालय/*6*

कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न-यह स्पष्ट है कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कराधान से संबंधित हैं, उनमें भी शामिल होंगे।

दीवानी और आपराधिक कानून के कई क्षेत्र-इसलिए, यह नहीं है

यह कहना सही है कि कराधान, एक विशेष विषय होने के नाते, कर सकता है

एक न्यायाधिकरण द्वारा निपटा जाए-कानून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमारी संवैधानिक योजना के तहत तय किया जाना है

केवल उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।

भारत में आयकर कानून-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

चर्चा की।

भारत में सीमा शुल्क कानून-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -

चर्चा की। केंद्रीय उत्पाद शुल्क-भारत में विधान-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-पर चर्चा की गई।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पर जगदीश सिंह खेहर, जे।

पकड़नाः *1.* एन. टी. टी. अधिनियम की संवैधानिक वैधता

क्या एन. टी. टी. अधिनियम संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन करता है*? [167 - ए]*

"न्यायिक समीक्षा" की शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि कार्यकारी कार्यप्रणाली स्वयं को न्यायिक समीक्षा के दायरे में सीमित रखे।

विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून की रूपरेखा। तदनुसार,

विधायिका के बीच शक्तियों का सीमांकन,

कार्यपालिका और न्यायपालिका को संवैधानिक योजना का मूल तत्व माना जाता है। जब न्यायिक प्रक्रिया को कानून द्वारा यह निर्धारित करने से रोका जाता है कि क्या

अधिनियमित विधान के ढांचे के भीतर की गई कार्रवाई, थी या नहीं थी, यह राशि होगी

न्यायनिर्णायक/निर्धारक प्रक्रिया का उल्लंघन

विधायिका द्वारा। इसलिए, शक्ति का बहिष्कार

"न्यायिक समीक्षा", संविधान के "मूल ढांचे" पर प्रहार करेगी। न्यायिक समीक्षा संविधान की "मूल संरचना" का एक हिस्सा है। अपीलीय शक्तियाँ

विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय में निहित, निश्चित रूप से उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया जा सकता है

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* अन्य न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के लिए न्यायालय, संतुष्टि के अधीन।

भारत का संघ

7

इस न्यायालय द्वारा घोषित मानदंड। इसमें एन. टी. टी. अधिनियम द्वारा हस्तांतरित अधिकारिता विनिर्दिष्ट के संबंध में थी

कर संबंधी कानूनों के तहत विषय। यह होगा कि

अनुमति है। हालाँकि, एन. टी. टी. अधिनियम ने संविधान द्वारा न्यायालयों में निहित शक्ति को हस्तांतरित नहीं किया है। "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है

संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* बरकरार हैं। इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सत्ता

अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति अपरिवर्तित रही है।

उच्च न्यायालयों के न्यायालयों में निहित है कि वे अपने भीतर एन. टी. टी. की पीठों पर न्यायिक पर्यवेक्षण का प्रयोग करें।

संबंधित अधिकार क्षेत्र को सचेत रूप से संरक्षित किया गया है। चूंकि उच्च न्यायालय की उपरोक्त अधिकारिता नहीं है

हटा दिए जाने पर, एन. टी. टी. को एक संस्थागत भूमिका के बजाय एक पूरक भूमिका निभाते हुए माना जाएगा। में।

मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार, यह निवेदन कि एन. टी. टी. अधिनियम संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन करता है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। में संशोधन

संविधान के प्रावधान, टिकाऊ नहीं होंगे यदि यह संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन करता है, तो भी

यद्यपि संशोधन किया गया था, द्वारा

के "भाग *XI*" के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन करना

संविधान। यह इस दृढ़ संकल्प की ओर ले जाता है कि "मूल संरचना" अलंघनीय है। *[* पैरा *53 63 (i), 64,65] [259]*

ई, एफ*; 270-*ई-एच*; 271-*ए-बी*; 272-*एफ*]*

केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य *(1973) 4* एससीसी

225 : 1973 (0) पूरक। एस. सी. आर. *1;* श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम

श्री राज नारायण *1975* सप. एससीसी *1: 1976* एस. सी. आर. *347;* मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(1980) 2* एससीसी *591: 1981 (1)* एस. सी. आर. *206;* मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ

भारत संघ *1981 (*सप.*)* एससीसी *87: 1982* एससीआर *365;* एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ *(1987) 1* एससीसी *124: 1987 (1)* एस. सी. आर. *435;* एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ *(1995) 1* एससीसी *400 : 1994 (6)* पूरक। एस. सी. आर. *261--* पर निर्भर था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

8 बैराक्लो वी। ब्राउन *(1897)* एसी *615;* आर्गोसम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। ऑक्सबी *(1964) 1 796*-एच पर सभी ई. आर. *791;* वित्त कंपनी।

लिमिटेड वी. ऑक्सबी *(1964) 1* ऑल ई. आर.; हिंड्स बनाम। रानी निदेशक

लोक अभियोजन *v.* जमैका के अटॉर्नी जनरल जैक्सन

(इंटरवेनर*), 1976* ऑल ई. आर. वॉल्यूम। *(1) 353 ;* लियानगे वी। रेजिनाम, *(1966) 1* सभी ई. आर. *650;* के लोक अभियोजन निदेशक जमैका बनाम। मोलिसन, *(2003) 2* एसी *411;* हैरी ब्रांडी बनाम।

183 सी. एल. आर. *245;* आवासीय किरायेदारी अधिनियम, *123* डी. एल. आर. *(3* डी*) 554* - संदर्भित किया गया।

क्या न्यायनिर्णायक कार्यों का हस्तांतरण निहित है

एन. टी. टी. के लिए उच्च न्यायालय मान्यता प्राप्त संवैधानिक सम्मेलनों का उल्लंघन करता है*?*

चाहे वह नए बनाए गए क्षेत्राधिकार को हस्तांतरित करते समय हो

न्यायालय/न्यायाधिकरण, प्रतिस्थापित न्यायालय के मानकों और कद को बनाए रखना आवश्यक है*? 2.1 .* ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि कर/शुल्क देयता के प्रारंभिक मूल्यांकन के विपरीत,

चुनौती के लिए पहला मंच पारंपरिक रूप से एक कार्यकारी अपीलीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ रहा है। विधायी विवरण से पता चलता है कि कुछ समय के लिए एक शक्ति थी

"कानून के प्रश्नों" पर प्रयोग करने योग्य संदर्भ। द.

एकर न्यायनिर्णायक अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयक लग रहैत छल। दूसरा अपीलीय उपचार हमेशा से रहा है एक अर्ध-न्यायिक अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष, एक के रूप में शैलीबद्ध

अपीलीय न्यायाधिकरण। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को विधायी रूप से "न्यायिक" के रूप में वर्णित किया गया है।

कार्यवाही "। कानून के प्रश्नों को मूल रूप से अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया था। संदर्भ क्षेत्राधिकार, सभी में प्रतिस्थापित किया गया था

अधिनियम, और अपीलीय क्षेत्राधिकार में परिवर्तित।

तत्काल अपीलीय अधिकार क्षेत्र अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के पास निहित था। आयकर अधिनियम, *1961* के तहत,

धारा *260* ए ने एक से एक अपीलीय उपचार प्रदान किया

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय को पारित आदेश। इसी तरह मद्रास बार एसोसिएशन की धारा *129* ए *v.*

भारत का संघ

9

सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* और केंद्रीय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *35* जी

आबकारी अधिनियम, *1944*, से एक अपीलीय उपचार के लिए प्रदान किया गया

उच्च न्यायालय में संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण। क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय इन पर अपीलों की सुनवाई करेगा अपीलीय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध कानून के प्रश्न

न्यायाधिकरण। *[* पैरा *67] [273-*एफ़-एच*; 274-*ए-सी*]*

महाराष्ट्र राज्य बनाम। श्रम कानून व्यवसायियों *'*

एसोसिएशन *(1998) 2* एस. सी. सी. *688: 1998 (1)* एससीआर *793;* धूलाभाई बनाम। एम. पी. राज्य *(1968) 3* एस. सी. आर. *662;* प्रीमियर

ऑटोमोबाइल वी। कमलेकर शांताराम वाडके, *(1976) 1* एस. सी. सी. *496;* भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसोसिएशन *(2010) 11* एससीसी

87 ; औंडल अम्मल बनाम। सदाशिवन पिलाई *(1987) 1* एस. सी. सी. *183:*

1987 (1) एससीआर *485;* जेठा बाई एंड संस बनाम। सुंदरदास

रथेनाई *(1988) 1* एस. सी. सी. *722;* मफतलाल इंडस्ट्रीज बनाम। संघ का

भारत *(1997) 5* एससीसी *536: 1988 (2)* एस. सी. आर. *871;* एल. चंद्रा

कुमार बनाम। भारत संघ *(1997) 3* एससीसी *261: 1997 (2)*

एस. सी. आर. *1186;* भारत संघ बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन *(2002) 4* एससीसी *275: 2002 (2)* एस. सी. आर. *450;* कर्नाटक राज्य बनाम विश्वभारती हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य।

(2003) 2 एससीसी *412: 2003 (1)* एस. सी. आर. *397;* नवीनचंद्र मफतियाल, बॉम्बे बनाम। आयकर आयुक्त,

बॉम्बे सिटी ए. आई. आर *1955* एस. सी. *58: 1955* एस. सी. आर. *829;* भारत संघ बनाम। हर्भजन सिंह ढिल्लन *(1971) 2* एससीसी *779: 1972 (2)*

एस. सी. आर. *33-*संदर्भित।

2.2 . वर्तमान के लिए प्रासंगिक सभी अपीलीय न्यायाधिकरण

विवाद अनिवार्य रूप से न्यायिक थे

लेखाकार या तकनीकी सदस्यों के अलावा सदस्य। को।

न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य, यह था

यह आवश्यक है कि पदधारी ने *10* साल की अवधि के लिए भारत में न्यायिक पद संभाला था, या इसी अवधि के लिए एक अधिवक्ता के रूप में काम किया था। इस योग्यता ने अधिनियमों को कानून की कल्पना द्वारा यह प्रदान करने में सक्षम बनाया कि सभी

कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण "न्यायिक" कार्य कर रहे थे

कार्यवाही "। अपीलीय निर्धारण का अगला चरण पारंपरिक रूप से उच्च न्यायालयों के पास निहित है। आय-कर कानून, सीमा शुल्क कानून, साथ ही *10* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून समान रूप से प्रदान करता है, कि अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, क्षेत्राधिकार उच्च

न्यायालय संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न अपीलों पर निर्णय लेगा। उक्त अपीलें विधायी निर्धारण द्वारा की गई थीं, जिन पर सुनवाई की जानी थी

उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों वाली पीठों द्वारा

अदालत। कम से कम दो न्यायाधीशों वाली पीठ का निर्णय अपने आप में कानूनी निर्णय का संकेत है।

जटिलताएँ, जहाँ तक अपीलीय न्यायनिर्णायक की भूमिका है,

अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय का संबंध था। *[पैरा 68]*

क्या उत्पन्न होने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन संदर्भ के तहत प्रावधान, के भीतर रहना चाहिए

अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों का क्षेत्र? *[पैरा 69] [275-जी]*

क्या दुनिया भर में स्वीकार किए गए तरीके से संवैधानिक व्याख्या एक संवैधानिक होगी

कर मामलों पर अपीलीय अधिकारिता के लिए अधिदेश,

अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के साथ बने रहें। *[पैरा 69] [275 एच; 276-ए]*

3. प्रत्येक नए संविधान में, जो विधायिका के लिए अलग-अलग प्रावधान करता है, कार्यपालिका और

न्यायपालिका, यह माना जाता है कि "शक्तियों के पृथक्करण" का मूल सिद्धांत लागू होगा। और यह कि शासन की तीन शाखाएँ काम करेंगी।

उनके निर्दिष्ट क्षेत्र/प्रांत में। न्यायिक कार्यों के निर्वहन की शक्ति, जिसका प्रयोग किया गया था

उच्च न्यायपालिका के सदस्यों को, उस समय जब संविधान लागू हुआ था, आम तौर पर उस न्यायालय के साथ रहना चाहिए, जो उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता था।

नए संविधान की घोषणा का समय। लेकिन न्यायिक शक्ति का उपयोग एक समान/समान अदालत/न्यायाधिकरण द्वारा एक अलग नाम के साथ करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, संवैधानिक परंपरा के आधार पर, समान अदालत/न्यायाधिकरण का गठन करते समय, इसे करना होगा

यह सुनिश्चित किया जाए कि नियुक्ति और कार्यकाल की सुरक्षा

उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वही होगी जो न्यायालय मद्रास बार एसोसिएशन *v* की होगी।

भारत का संघ

11

क्या कंपनी सचिवों को अनुमति दी जानी चाहिए एन. टी. टी. के समक्ष उसी तरीके से और लेखाकारों के साथ समानता पर एक अपील के लिए एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित होना*? [* पैरा *73] [280-*बी*]*

क्या एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *13 (1)* जहां तक इसकी अनुमति है एन. टी. टी. के समक्ष अपील में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए लेखाकार वैध हैं*? [* पैरा *73] [280-*सी*]*

4. एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *13* के अवलोकन से पता चलता है*,*

कि किसी अपील के लिए एक पक्ष *(*राजस्व के अलावा*)*

या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, या एक या अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट, या कानूनी व्यवसायियों, या उनके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी व्यक्ति को अपने मामले को पेश करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

एनटीटी। एन. टी. टी. के सदस्यों को पारिवारिक कानून, हिंदू से उभरने वाले कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ेगा।

कानून, मुस्लिम कानून, कंपनी कानून, साझेदारी का कानून, प्रादेशिकता से संबंधित कानून, न्यासों और समितियों से संबंधित कानून, अनुबंध कानून, संबंधित कानून संपत्ति का हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा से संबंधित कानून, कानूनों की व्याख्या और अन्य विविध

कानून के प्रावधान, समय-समय पर। एनटीटी इसके अलावा

इन कानूनों को न केवल व्याख्या करनी होगी

तीन कानूनों के प्रावधान, जिनमें से अपीलों की सुनवाई इसके द्वारा की जाएगी, लेकिन एक चुनौती की भी जांच करनी होगी

उक्त में किए गए वैधानिक संशोधनों के अधिकार के लिए

कुछ मामलों में यह निर्धारित करें कि क्या प्रावधान निर्भर थे एक संभावित या पूर्वव्यापी प्रयोज्यता थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि की धारा *15* के संदर्भ में

एन. टी. टी. अधिनियम, एन. टी. टी. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से अपीलों की सुनवाई करेगा।

सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण *(*सी. ई. एस. टी. ए. टी*)* केवल

*"*कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न *"*, इसकी सराहना करना मुश्किल है

किसी पक्ष की ओर से किसी अपील के लिए, या तो चार्टर्ड एकाउंटेंट या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के माध्यम से प्रतिनिधित्व का औचित्य।

12

एन. टी. टी. से पहले कंपनी सचिव। दृढ़ संकल्प

एन. टी. टी. के हाथों में तथ्यात्मक विवाद हैं। इसे केवल *"*कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों*"* का निर्णय लेना है। चार्टर्ड

लेखाकार और कंपनी सचिव मुद्दों को समझने और समझाने में विशेषज्ञ होंगे।

खातों से संबंधित। ये मुद्दे विशुद्ध रूप से गिरेंगे।

तथ्यों के दायरे में। कंपनी सचिवों को अपील में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एनटीटी से पहले। यहाँ तक कि जहां तक चार्टर्ड एकाउंटेंटों का संबंध है, उन्हें उपस्थित होने की अनुमति

एन. टी. टी. से पहले पार्टी को अस्वीकार कर दिया जाता है। धारा *13 (1)*, जहाँ तक यह चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है एन. टी. टी. के समक्ष एक अपील, असंवैधानिक और

कानून में अस्थिर। *[* पारस *75,77,78] [280-*जी, एच*; 307-*ई

एच*; 308-*ए*-*ई*]*

दिल्ली प्रदेश पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बनाम।

स्वास्थ्य निदेशक, दिल्ली प्रशासन सेवा *(1997) 11*

एससीसी *687: 1997 (4)* पूरक। एस. सी. आर. *514;* राजस्थान राज्य बनाम लता अरुण *(2002) 6* एस. सी. सी. *252;* जे. बी. चोपड़ा बनाम भारत संघ

(1987) 1 एससीसी *422;* एम बी मजूमदार बनाम भारत संघ *(1990)*

4 एससीसी *501: 1990 (3)* एस. सी. आर. *946;* अमूल्या चंद्र कलीता बनाम। भारत संघ *(1991) 1* एस. सी. सी. *181;* आर. के. जैन बनाम। भारत संघ

(1993) 4 एससीसी *119: 1993 (3)* एससीआर *802;* डॉ. महाबल राम बनाम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद *(1994) 2* एस. सी. सी. *410;*

भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसोसिएशन *(2010) 11* एससीसी

1 : 2010 (6) एससीआर *857;* मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। संघ का

भारत *(2010) 11* एससीसी *67: 2010 (6)* एससीआर *957;* सुभाष शर्मा बनाम। भारत संघ *(1991)* पूरक। *1* एससीसी *574: 1990 (2)* पूरक। एस. सी. आर. *433;* उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता रिकॉर्ड पर एसोसिएशन वी। भारत संघ *(1993) 4* एस. सी. सी. *441*-निर्दिष्ट

को।

संविधान की धारा *5,6,7,8* और *13* की संवैधानिक वैधता

एन. टी. टी. अधिनियमः

5.1 . एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5* की वैधता। धारा *5 (2)*

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *13*

एन. टी. टी. अधिनियम में कहा गया है कि एन. टी. टी. की बैठकें आम तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होंगी। यह संसद के लिए अपील को प्रतिस्थापित करने के लिए खुला है

अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों में निहित अधिकारिता और

तथापि, उक्त अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए न्यायालयों/न्यायाधिकरणों का गठन करते हुए

वैकल्पिक न्यायालय/न्यायाधिकरण, यह विधायिका के लिए अनिवार्य है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवारण उसी के साथ उपलब्ध होना चाहिए

सुविधा और समीचीनता, जैसा कि पहले था

नवनिर्मित न्यायालय/न्यायाधिकरण की शुरूआत। इस प्रकार

एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5 (2)* में इस आशय का अधिदेश शामिल किया गया है कि एन. टी. टी. की बैठकें

आम तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आयोजित किया जाता है दिल्ली सरकार, उपचार को अप्रभावी बना देगी, और इस प्रकार कानून में अस्वीकार्य होगी। *[* पैरा *80] [308*-ई-एफ, एच*; 309*-बी-एफ*]*

5.2 . निर्धारण में केंद्र सरकार की भूमिका

एन. टी. टी. की पीठों की बैठक। केंद्र सरकार को इस क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है

जिसके संबंध में प्रत्येक पीठ अधिकारिता का प्रयोग करेगी,

पीठों के गठन का निर्धारण करना, और अंत में, एक के सदस्यों के स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग करना।

दूसरी बेंच पर बैठें। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है,

कि केंद्र सरकार प्रत्येक अपील/मामले में एक हितधारक होगी, जो केंद्र सरकार के समक्ष दायर की जाएगी।

एनटीटी। इसलिए इसकी अनुमति देना उचित नहीं हो सकता है।

केंद्र सरकार कोई भी भूमिका निभाएगी, के संदर्भ में वे स्थान जहाँ बेंच लगाए जाएँगे, वे क्षेत्र

जिन पर पीठ अधिकारिता का प्रयोग करेंगी,

पीठों का गठन और गठन, साथ ही, सदस्यों का एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरण।

सरकार वनों में भाग लेने के लिए एन. टी. टी. के प्रशासनिक कामकाज में बाधा आएगी।

सदस्यों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर

एनटीटी। एन. टी. टी. अधिनियम के वैध होने के लिए, अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

14

एन. टी. टी. के सदस्यों के पास वही होना चाहिए

अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में स्वतंत्रता और सुरक्षा *(*जिसे एन. टी. टी. के लिए अनिवार्य है*)*

प्रतिस्थापन*)*। एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5* की उप-धाराएँ *(2), (3), (4)* और *(5)* असंवैधानिक हैं। *[* पैरा *81] [310*-बी-एफ*; 311 -* सी*]*

5.3 . एनटीटी अधिनियम की धारा *6* की वैधता। का एक अवलोकन

धारा *6* से पता चलता है कि एक व्यक्ति योग्य होगा

सदस्य के रूप में नियुक्ति, यदि वह सदस्य है या रहा है

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या सीमा शुल्क,

कम से कम *5* के लिए उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण

वर्षों से। आयकर अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति जिसने चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में एकाउंटेंसी में काम किया है

10 वर्ष की अवधि के लिए, या *10* वर्ष की अवधि के लिए एक पंजीकृत लेखाकार के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है

लेखाकार सदस्य। सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा *(समूह ए)* का सदस्य रहा है, इस शर्त के अधीन कि ऐसा व्यक्ति सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क *(स्तर I)* के कलेक्टर का पद धारण कर चुका है,

या समकक्ष या उच्चतर पद, कम से कम *3* वर्ष के लिए, पात्र है।

तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना। जिन लोगों के साथ

उपरोक्त योग्यताएँ, जिन्हें संबंधित में लेखाकार सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था

अपीलीय न्यायाधिकरण, एन. टी. टी. के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए भी पात्र हैं, बशर्ते कि उन्होंने निर्दिष्ट वर्षों की सेवा प्रदान की हो। यह मुश्किल है

इस बात की सराहना करें कि लेखाकार सदस्य और तकनीकी सदस्य कानून के जटिल प्रश्नों को कैसे संभालेंगे कर मामलों से संबंधित, और विभिन्न विषयों *(कर से असंबद्ध)* पर कानून के प्रश्न भी,

एन. टी. टी. के अधिकार क्षेत्र में निहित है। चूँकि एन. टी. टी. के अध्यक्ष/सदस्यों को यह निर्धारित करना आवश्यक होगा

"निर्णयों से उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न

अपीलीय न्यायाधिकरणों की, यह सराहना करना मुश्किल है कि कैसे

एक व्यक्ति, जो केवल खातों में पारंगत है, मद्रास बार एसोसिएशन *v* में सक्षम होगा।

भारत का संघ

15

ऐसे कार्यों का निर्वहन करना। एनटीटी होगा

पारिवारिक कानून से उत्पन्न होने वाले विवादों का सामना करना, हिंदू कानून, मोहम्मदन कानून, कंपनी कानून,

कानून के प्रावधान। उपरोक्त के अलावा, एन. टी. टी. के सदस्यों को नियमित रूप से इन प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी - आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम। केवल पेशेवर योग्यता रखने वाला व्यक्ति

कानून के अभ्यास में पर्याप्त अनुभव के साथ, भारी जिम्मेदारियों को संभालने की स्थिति में रहें

जो एन. टी. टी. के अध्यक्ष और सदस्यों के पास होगा कंधे तक। *[* पैरा *82* से *84] [311*-डी-एच*; 312*-ए, ई-जी*; 313*

ए-सी*]*

5.4 . न्यायालय/न्यायाधिकरण के सदस्य जिनके लिए

न्यायनिर्णायक कार्य स्थानांतरित किए जाते हैं, उनका संचालन किया जाना चाहिए

न्यायाधीशों/सदस्यों द्वारा जिनका कद और योग्यताएँ उस न्यायालय के अनुरूप हैं जहाँ से न्यायिक प्रक्रिया स्थानांतरित की गई है। यह पद है

दुनिया भर में पहचाना। यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि लेखाकार सदस्यों और तकनीकी सदस्यों का कद और योग्यता न्यायाधीशों के पास है।

उच्च न्यायालय। यह विवादित नहीं था कि एनटीटी ने

उन मामलों को संभालने के लिए बनाया गया जो पहले के भीतर थे अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों की अपीलीय परिधि। द.

लेखाकार सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति

दुनिया भर में अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त संवैधानिक सम्मेलनों का स्पष्ट उल्लंघन। संदर्भों पर कानून के प्रश्न (तीन विधायी अधिनियमों के तहत)

प्रश्न में), एक विधायी जनादेश द्वारा आवश्यक थे कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया जाए

अधिकारिता वाला उच्च न्यायालय। जब संदर्भ का उपाय

(उच्च न्यायालय के समक्ष) एक अपीलीय उपचार में परिवर्तित किया गया था (जे में तीन विधायी अधिनियमों के तहत

प्रश्न), फिर से एक विधायी जनादेश द्वारा, अपील की सुनवाई अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी थी। कोई नज़र नहीं खो सकता है

तथ्य यह है कि अब तक, जो मुद्दे एनटीटी के अधिकार क्षेत्र में निहित होंगे, उनका निर्णय एक पीठ द्वारा किया जा रहा था

उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीश। न्यायनिर्णायक प्रक्रियाक कठिन आ जटिल प्रकृति स्पष्ट अछि।

"न्यायिक समीक्षा" की शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है

संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत नहीं है

एन. टी. टी. अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से हटा लिया गया। "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है

संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* को अस्वीकार कर दिया गया था। इस तथ्य के कारण कि, एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *24* एक पीड़ित पक्ष के पास निहित है, अपील का एक उपाय

सुप्रीम कोर्ट। वनाच्छादित अपील को ध्यान में रखते हुए उपाय, एन. टी. टी. द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय को पारित आदेश से, शायद ही कोई अवसर होगा,

से उत्पन्न होने वाले कर मामले पर एक चुनौती उत्पन्न करें

आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और

एक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के समक्ष उत्पाद शुल्क अधिनियम। एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *6* के अवलोकन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है।

इसमें कोई संदेह है कि उपरोक्त मापदंडों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है

जहाँ तक अध्यक्ष और अन्य की नियुक्ति का संबंध है

इस मामले में, एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *6 (2) (बी)* उत्तरदायी है असंवैधानिक घोषित किया गया। *[* पारस *85,86] [313*-डी-एच*; 314*

ए-जी*; 315*-सी, ई*]*

5.5 . धारा *7* नियुक्ति के बारे में बात करती है

केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्य। यदि उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र स्थानांतरित किया जा रहा है

एन. टी. टी. के अनुसार, न्यायाधिकरण के सदस्यों का कद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान होना चाहिए। इसी तरह इसके अध्यक्ष/सदस्यों की सेवा की शर्तें भी।

और उनकी नियुक्ति और हटाने का तरीका, जिसमें उनके कार्यकाल सहित स्थानांतरण भी शामिल हैं।

एच. मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *17*

नियुक्तियाँ। धारा *7* अन्यथा भी नहीं हो सकती है संवैधानिक रूप से मान्य माना जाता है, क्योंकि इसमें चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया शामिल है

एन. टी. टी. के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के विभागों के सचिव। केंद्र सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व एक पर किया जाएगा

पक्ष, एन. टी. टी. के समक्ष प्रत्येक मुकदमे में। यह संभव नहीं है।

मुकदमे में किसी पक्ष को स्वीकार करने के लिए, चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जिसके द्वारा अध्यक्ष और

न्यायनिर्णायक निकाय के सदस्यों का चयन किया जाता है। यह

मान्यता प्राप्त संवैधानिक का भी उल्लंघन होगा

हिंद के मामले में अभिलिखित परिपाटी, अर्थात्, कि यह

संविधान का मजाक बनाओ, अगर विधायिका

द्वारा पूर्व में प्रयोग किए जाने योग्य अधिकार क्षेत्र का हस्तांतरण कर सकता है न्यायिक कार्यालयों के धारकों को, एक नए न्यायालय के धारकों को /

न्यायाधिकरण (जिसके साथ कुछ अलग नाम संलग्न किया गया था) और नए न्यायिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए,

न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित तरीके और शर्तों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। धारा *7* को असंवैधानिक घोषित किया गया है। *[* पारस *87,88]*

[319 - एफ-एच*; 320-*ए-डी*]*

5.6 . एनटीटी अधिनियम की धारा *8* की वैधता। धारा *8*

यह बताता है कि एक अध्यक्ष/सदस्य को पहली बार में *5* साल की अवधि के लिए एन. टी. टी. में नियुक्त किया जाता है। इस तरह

अध्यक्ष/सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं,

5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि। पुनर्नियुक्ति के लिए एक प्रावधान का प्रभाव स्वयं को कम करने का होगा

एन. टी. टी. के अध्यक्ष/सदस्यों की स्वतंत्रता।

एन. टी. टी. में नियुक्त प्रत्येक अध्यक्ष/सदस्य, मामलों को इस तरह से तय करने के लिए विवश किया जाए जो एनटीटी की धारा *8* के संदर्भ में उनकी पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित करे

एक्ट करें। उसके निर्णय उसकी स्वतंत्र समझ पर आधारित हो भी सकते हैं और नहीं भी। एन. टी. टी. के बाद से नियुक्ति और कार्यकाल के विस्तार के सभी मामलों में जो अधिकारिता पहले उच्च न्यायालयों के पास थी, उसे कार्यकारी भागीदारी से बचाया जाना चाहिए।

[2014] 10 एस सी आर।

18

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *8* असंवैधानिक है। धारा *5,*

6 , 7 , 8 और एन. टी. टी. अधिनियम के *13* को निर्धारित मापदंडों के आधार पर अवैध और असंवैधानिक माना गया है।

इस न्यायालय की संवैधानिक पीठों के निर्णयों और मान्यता प्राप्त संवैधानिक सम्मेलनों के आधार पर वेस्टमिंस्टर पर बनाए गए संविधानों के लिए संदर्भित

मॉडल। उक्त प्रावधानों के अभाव में, जिन्हें असंवैधानिक माना गया है, शेष प्रावधान अनुचित और बेकार बना दिया गया है, और इस तरह,

समग्र रूप से एन. टी. टी. अधिनियम के प्रावधानों को अलग रखा गया है।

[पारस 89,90] [317-डी-एच; 318-ए-बी]

पी. ई. आर. *R.F.NARIMAN*, जे. *(परिणाम से सहमत)*

1. यह माना गया है कि अमेरिका के विपरीत।

भारत के संविधान में शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं है। इसके बावजूद संविधान

सरकार की तीन शाखाओं में से प्रत्येक के लिए समर्पित कई अलग-अलग अध्याय हैं। भाग *5* का अध्याय *4*

विशेष रूप से केंद्रीय न्यायपालिका और अध्याय *V* से संबंधित है।

विवादों में मूल अधिकार क्षेत्र वाला सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार और राज्यों के बीच उत्पन्न होना। कला. *132 134* क सिविल और सिविल में एक अपीलीय अधिकारिता निहित करता है।

उच्च न्यायालयों से आपराधिक मामले। कला. *136* निहित करता है

किसी से भी अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए एक असाधारण विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के साथ सर्वोच्च न्यायालय निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश

भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाया गया कोई कारण या मामला। कला के तहत। *137*, उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद *141* द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। और कला के आधार पर। *145 (3)*

मद्रास बार एसोसिएशन *v* की व्याख्या के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न।

भारत संघ *19*

भारत का संविधान विशेष रूप से कम से कम *5* माननीय न्यायाधीशों की पीठ में निहित है। इसी तरह, कला के तहत। *214* ऊँचा। प्रत्येक राज्य के लिए न्यायालय स्थापित किए जाते हैं और कला के तहत होते हैं। *215* उच्चतम न्यायालय की तरह, उच्च न्यायालय इन न्यायालयों के होंगे

अभिलेख रखेंगे और अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियां उनके पास होंगी। कला के तहत।

225, किसी भी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि संरक्षित है। कला. *226* वेस्ट द हाई

मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए विभिन्न रिट जारी करने की शक्ति वाला न्यायालय

व्यक्ति या प्राधिकरण। कला के तहत। *228* संबंधित प्रश्न

संविधान की व्याख्या द्वारा तय की जानी है

केवल उच्च न्यायालय जब उसके अधीनस्थ न्यायालय इस तरह के प्रश्न पर विचार करता है। इसके अलावा, इनका महत्व

प्रावधानों को कला द्वारा आगे उजागर किया गया है। *368* परंतुक जो

इन सभी अनुच्छेदों के संशोधन की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब इस तरह के संशोधन को कम से कम विधानसभाओं द्वारा भी अनुमोदित किया जाता है। राज्यों के आधे से अधिक। सिविल प्रक्रिया संहिता

इनमें ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं जो उच्च न्यायालय को कानून के कुछ प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं।

धारा *113* और, जब वे अधिकारिता संबंधी त्रुटियों से संबंधित हैं,

1915. भारत सरकार अधिनियम *1935* की धारा *224* ने कमोबेश *1915* के अधिनियम की धारा *107* को अपनाया कुछ बदलाव। कला. *227* "और न्यायाधिकरण" शब्द जोड़ता है

और इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि अधीक्षण अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को विषय होना चाहिए

अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में। *[* पैरा *6,8* से *13] [323*-एफ, एच; *324*-ए-जी; *325*-डी; *326*-जी*]*

2. यह स्वयंसिद्ध है कि की अधीक्षण शक्ति

कला के तहत उच्च न्यायालय। *227* न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को कानून की सीमा के भीतर रखना है। इसलिए, कानून की त्रुटियां जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट हैं, उत्तरदायी हैं।

ठीक करने के लिए। इस तरह की त्रुटियों को सुधारने के लिए, उच्च न्यायालय को यह तय करना आवश्यक है कि कानून क्या है।

कानून के प्रश्न, जो *[2014] 10* एस. सी. आर. के अधीनस्थ न्यायालयों को बाध्य करते हैं।

भविष्य के मामलों में न्यायाधिकरण। उच्च न्यायालयों का निर्णय कानून के प्रश्नों के अभिलेख और ऐसे निर्णयों का बाध्यकारी प्रभाव संवैधानिक योजना में निहित है।

चीज़ों से। न केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना सर्वोच्च न्यायपालिका का प्रांत है।

हाथ में मामले के लिए लेकिन भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का मार्गदर्शन करने के लिए भी। इसलिए,

और/या वैकल्पिक विचारों पर चर्चा का आह्वान करता है। यह है। स्पष्ट, इसलिए, कि एक न्यायिक रूप से प्रशिक्षित मन के साथ

कानून के प्रश्नों को तय करने का अनुभव अनिवार्य है ताकि ऐसे प्रश्नों का सही निर्णय लिया जा सके।

चाहे कोई पुरानी धारा *100*, सी. पी. सी. या धारा को देखे।

100 जैसा कि *1976* में प्रतिस्थापित किया गया था, परिणाम यह है कि केवल उच्च न्यायालयों को ही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है

कानून के प्रश्न। अब तक संसद ने एक कानून के प्रश्नों/कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णयों के साथ अभिलेख का उच्च न्यायालय। *[* पैरा *15,16,18* से *20]*

[327 - डी-ई*; 328-*ई*; 329-*बी, सी*; 331-*बी-सी*; 332-*डी-ई*]*

मफतलाल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ *(1997) 5* एससीसी *536:*

1996 (10) पूरक। एससीआर *585-*विशिष्ट।

3. कला. *323* बी संविधान का हिस्सा था *42* वां

संशोधन अधिनियम जो, जैसा कि सर्वविदित है,

संशोधन जिसे *1975* के आपातकाल के दौरान जल्दबाजी में पारित किया गया था। इसकी कई विशेषताओं को संविधान के *44* वें संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्ववत कर दिया गया था।

वर्षों बाद। जिन दिलचस्प विशेषताओं को पूर्ववत किया गया था, उनमें से एक कला में संशोधन था। *227.* एक सरसरी

प्रतिस्थापित खंड के पढ़ने से पता चलता है कि भारत सरकार अधिनियम *1915* की पुरानी धारा *107* को वापस लाया गया था: न्यायाधिकरण अब उच्च न्यायालयों के अधीक्षण और अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन नहीं थे।

केवल उच्च न्यायालयों के अधीक्षण के अधीन थे,

यदि वे भी इसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अधीन थे।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ *21*

44 संशोधन ने इसे रद्द कर दिया और उपखंड *(1)* को बहाल कर दिया।

अपनी मूल स्थिति में। हालांकि, कला। *323* बी जारी है

संविधान का हिस्सा। उक्त अनुच्छेद को शामिल करने का वास्तविक कारण वही था जो अनुच्छेद में किया गया था। *227* - उच्च न्यायालयों के पर्यवेक्षी को हटाना न्यायाधिकरणों पर अधिकारिता। *[* पैरा *24* से *26], [336*-ई, जी, एच*; 337*-ए*]*

4. राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण जो उच्च न्यायालय की जगह लेता है

देश में अदालतें केवल निर्णय लेने के लिए उनकी जगह लेती हैं

कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कराधान से संबंधित हैं। वास्तव में, एक प्रत्यक्ष कर कानून समिति ने एक रिपोर्ट दी *1978* चोकसी समिति को उसके अध्यक्ष के नाम पर बुलाया गया। इस रिपोर्ट में वास्तव में केंद्रीय कर की सिफारिश की गई थी कि

न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए। यह सिफारिश नहीं थी

संसद द्वारा स्वीकृत। यह स्पष्ट है कि कराधान से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे।

इसमें सिविल और आपराधिक कानून के कई क्षेत्र शामिल हैं। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि कराधान, एक विशेष विषय होने के कारण, एक न्यायाधिकरण द्वारा निपटा जा सकता है। सभी

हमारे संविधान के तहत कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

उच्च न्यायालयों द्वारा तय की जाने वाली योजना और

केवल उच्च न्यायालय। *[* पैरा *30,31] [342*-सी*; 347*-ई-एफ*]*

5. राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के बीच हस्तक्षेप किया जाता है

बहुत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय

इसका अच्छा कारण यह है कि अंततः यह केवल सर्वोच्च न्यायालय ही होगा जो भविष्य में कानून का पालन करने की घोषणा करेगा। के रूप में अपीलीय न्यायाधिकरण पहले से ही एक दूसरा अपीलीय न्यायालय है,

राष्ट्रीय कर का होना पूरी तरह से अनावश्यक होगा।

न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों और अपीलीय के परस्पर विरोधी निर्णयों के मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय करता है।

इन न्यायाधिकरणों का निर्णय अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा, जो अनुच्छेद के तहत निर्णय लेगा।

141 सभी कर प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी होना।

दूसरा, सभी कर मामलों में, राज्य निश्चित रूप से एक पक्ष है

और उच्च न्यायालय निर्णय लेने के लिए आदर्श रूप से स्थित है

[2014] 10 एस. सी. आर. के बीच उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न।

राज्य और निजी व्यक्ति, जो संवैधानिक रूप से कार्यकारी नियंत्रण से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यह ठीक है।

यह तय किया गया कि एक अपील क़ानून का एक प्राणी है और हो सकता है

कानून द्वारा हटा दिया गया। यहाँ सवाल यह है कि

पूरी तरह से अलग और उस प्रश्न का उत्तर हमारे न्यायशास्त्र के लिए मौलिक हैः कि एक अधिकार क्षेत्र के लिए

हमारे कानून के तहत निहित महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय लें। संविधान, केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के साथ, और किसी अन्य निकाय में निहित नहीं किया जा सकता है

इससे संवैधानिक मूल्य प्रभावित होगा। चंद्रा

कुमार और आर. गांधी ने कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन मूल चरण में न्यायाधिकरण की अनुमति दी है। द.

इस मामले में आखिरकार सीमा पार कर दी गई है।

इसलिए, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम है

असंवैधानिक, में अभिलेख के वरिष्ठ न्यायालयों के अनन्य क्षेत्र पर अंतिम अतिक्रमण होने के नाते

भारत। *[पैरा 32,37,41] [647-एच; 348-ए-सी; 352-सी; 354-जी-एच]*

भारत संघ बनाम। आर. गांधी *(2010) 11* एससीसी *1: 2010*

(6) एस. सी. आर. *857;* वरयाम सिंह बनाम अमरनाथ *1954* एससीआर *565;*

ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड बनाम कलकत्ता सीमा शुल्क कलेक्टर *(1963) 3* एस. सी. आर. *338;* सर चुनिलाल वी. मेहता बनाम। द.

सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड *(1962)* पूरक। *3* एस. सी. आर. *549;* कन्हैया लाल मुकुंदलाल सराफ का मामला *1959* एस. सी. आर.

1350 ; एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ *(1997) 3* एससीसी *261: 1997 (2)* एस. सी. आर. *1186;* भारत संघ बनाम आर. गांधी *(2010) 11*

एससीसी *1: 2010 (6)* एस. सी. आर. *857*-संदर्भित।

क्यूबेक के लिए महान्यायवादी बनाम। फराह *(1978) Vol.86*

डी. एल. आर. *[3* डी*] 161;* री. आवासीय किरायेदारी अधिनियम *123* डी. एल. आर. *(3* डी*)*

554 ; हिन्स वी। लोक अभियोजन की रानी निदेशक *v.* जमैका के जैक्सन महान्यायवादी *(मध्यस्थ) 1976 (1)* सभी ई. आर. *353;* प्रोपराइटरी आर्टिकल्स ट्रेड्स एसोसिएशन बनाम। कनाडा के लिए महान्यायवादी *1931* एसी *311*-संदर्भित।

पर जगदीश सिंह खेहर, जे।

मामला कानून संदर्भः

1998 (1) एससीआर *793*

संदर्भित किया गया है

पैरा *24* एन *2:*

5 बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ

: एससीआर *662*

संदर्भित किया गया है

पैरा *37*

11 एससीसी *87*

उस पर भरोसा करें

पैरा *41*

एससीआर *485*

संदर्भित किया गया है

पैरा *42*

एस. सी. सी. *722*

संदर्भित किया गया है

पैरा *42*

एससीआर *871*

संदर्भित किया गया है

पैरा *43*

एससीआर *1186*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

एससीआर *450*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

एससीआर *397*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

सीआर *829*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

एससीआर *33*

पूरक। एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *55*

उस पर भरोसा करें

सीआर *347*

पैरा *56*

एससीआर *206*

उस पर भरोसा करें

पैरा *57*

उस पर भरोसा करें

सीआर *365*

पैरा *58*

उस पर भरोसा करें

एससीआर *435*

पैरा *59*

एससीआर *1186*

संदर्भित किया गया है

पैरा *60*

पूरक। एस. सी. आर. *261* पर निर्भर

पैरा *60*

एस. सी. सी. *422*

संदर्भित किया गया है

पैरा *60*

एससीआर *946*

संदर्भित किया गया है

पैरा *60*

एससीसी *181*

संदर्भित किया गया है

पैरा *60*

संदर्भित किया गया है

एससीआर *802*

पैरा *60*

2 एस. सी. सी. *410*

संदर्भित किया गया है

पैरा *60*

एससीआर *857*

संदर्भित किया गया है

पैरा *61*

संदर्भित किया गया है

एससीआर *957*

पैरा *62*

पूरक। एससीआर *433*

संदर्भित किया गया है

पैरा *62*

पूरक। एससीआर *514*

संदर्भित किया गया है

पैरा *75*

संदर्भित किया गया है

6 एस. सी. सी. *252*

पैरा *75 [2014] 10* एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24

पेर आर. एफ. नरीमन, जे.

मामला कानून संदर्भः

2010 (6) एससीआर *857*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

1954 एससीआर *565*

संदर्भित किया गया है

पैरा *14*

(1963) 3 एससीआर *338*

संदर्भित किया गया है

पैरा *15*

(1962) पूरक। *3* एससीआर *549*

पैरा *17*

संदर्भित किया गया है

1996 (10) पूरक। एससीआर *585*

विशिष्ट

पैरा *21*

1959 एससीआर *1350*

संदर्भित किया गया है

पैरा *26*

1997 (2) एससीआर *1186*

संदर्भित किया गया है

पैरा *26*

2010 (6) एससीआर *857*

पैरा *28*

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः स्थानांतरण मामला *(*सिविल*)* सं।

150 2006 से।

संविधान के अनुच्छेद *139* के तहत।

के साथ

सी. ए. सं. *3850 , 3862 , 3881 , 3882 , 4501* और *2006* का *4052*।

टी. सी. *(*ग*)* संख्या। *116 , 117* और *2006* का *118*। डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* संख्या। *621* और *2007* का *697*।

रंजीत कुमार, एस. जी. , अरविंद पी. दातार, अंबुज अग्रवाल,

आकांक्षा धनंजय बैजल, निखिल नय्यर, विक्रम गुलाटी, बीनू टम्टा, अभिनव मुखर्जी, अपराजित सिंह, अरिजीत प्रसाद *(*बी. वी. के लिए*)*

बलराम दास*)*, बी. डी. मखीजा, बी. के. सतीजा के. सी. दुआ, शिबाशीष मिश्रा, रुस्तम बी. हाथीखानावाला, ई. सी. विद्या सागर

याचिकाकर्ता।

ए. जी. मुकुल रोहतगी। , रंजीत कुमार, एस. जी. , के. वी. विश्वनाथन

अरविंद पी. दातार, प्रवीण एच. पारेख, बीनू तमाटा, अभिनव मुखर्जी, अपराजित सिंह, अरिजीत प्रसाद *(*बी. वी. बलराम दास के लिए*)*

प्रमोद दयाल, निकुंज दयाल, पायल दयाल, गौतम भारद्वाज,

ए. एस. कौशिक, मेहूल एम. गुप्ता, अदीबा मोजाहिद, के. सी. दुआ, अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, अविरल शुक्ला, पंखुड़ी

भारद्वाज, अमित राय, प्रियदर्शी चैतन्यशील, विकास जैन,

निखिल नय्यर, सत्य मित्रा गार्ड, ई. आर. कुमार, रितिका सेठी,

अभिषेक विनोद देशमुख, प्रियांशी चंदाराना *(*पारेख मद्रास बार एसोसिएशन बनाम।

भारत संघ *25*

&), रुस्तम बी. हाथीकनावाला, गगन गुप्ता, परमानंद गौर और अजय पाल उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जगदीश सिंह खेहर, जे।

विवादः

1. उपरोक्त सभी मामलों का निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है। विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा

हमारे समक्ष, वर्तमान मामलों के समूह में, संबंधित है

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, *2005* की संवैधानिक वैधता

(इसके बाद एन. टी. टी. अधिनियम के रूप में संदर्भित*)*। साथ ही, संविधान की संवैधानिक वैधता *(42)*

संशोधन*)* अधिनियम, *1976* पर यह कहते हुए हमला किया गया है कि यह भारत के संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।

(इसके बाद संविधान के रूप में संदर्भित*)*, उच्च न्यायालय में निहित "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति पर प्रभाव डालते हुए। में

उपरोक्त प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करने की इस न्यायालय की घटना, वैकल्पिक रूप से एक चुनौती, को विभिन्न पक्षों के समक्ष उठाया गया है। एन. टी. टी. अधिनियम के प्रावधान, जिसके कारण इसका गठन हुआ है

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण *(*इसके बाद एन. टी. टी. के रूप में संदर्भित*)*। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, एन. टी. टी. को अर्ध-न्यायिक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह हो चुका है

से उत्पन्न होने वाली अपीलों पर निर्णय लेने की शक्ति के साथ निहित

अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेश *(*के तहत गठित*)* आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* और केंद्रीय उत्पाद शुल्क

अधिनियम, *1944)*। इससे पहले भी तत्काल अधिकार क्षेत्र निहित था

उच्च न्यायालयों के साथ। इंगित मुद्दा इस ओर से प्रचार किया गया

यह है कि न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले उच्च न्यायालयों को एक अतिरिक्त न्यायिक निकाय द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह उन्होंने कहा कि एन. टी. टी. अपने संविधान के तरीके से

स्वतंत्रता और निष्पक्षता की प्रक्रिया को कमजोर करता है, जो हैं

यह किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संबंधित नहीं है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः भारत में आयकर कानूनः

2 ((i)। आयकर से संबंधित कानून *186* साल का है जब सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

26

आय पर कर लगाने से संबंधित कानून, भारत में पहली बार पेश किया गया था। मूल अधिनियम को बदल दिया गया था

1865, 1886, 1918 में अधिनियमित बाद के विधानों द्वारा और

1922. अखिल भारतीय कर समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारतीय आयकर अधिनियम, *1922* *(*जिसे इसके बाद *1922* अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है*)* लाया गया था। *1922* का अधिनियम

प्रत्यक्ष कर के विकास में एक मील का पत्थर के रूप में वर्णित किया जा सकता है

भारत में कानून। *1922* के अधिनियम के प्रावधानों का विस्तृत संदर्भ दिए जाने की आवश्यकता है।

((ii) कर निर्धारण के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया के बाद

अपने पाठ्यक्रम को चलाने, और कर का आकलन किया गया था, एक कार्यकारी

अपीलीय उपचार का प्रावधान अपीलीय के समक्ष किया गया था

सहायक आयकर आयुक्त *(1922* अधिनियम की धारा *30* के तहत*)*। एक और अर्ध-न्यायिक अपीलीय उपाय,

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय, पहले रखे गए थे

एक अपीलीय न्यायाधिकरण *(*इसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित*)*। भारतीय आयकर विभाग द्वारा धारा *33* ए जोड़ी गई थी।

(संशोधन*)* अधिनियम, *1941*। इसके माध्यम से एक उपाय प्रदान किया गया

आयकर आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण।

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपचार *(*बशर्ते कि

1922 के अधिनियम की धारा *5* ए के तहत, भारतीय आयकर *(*संशोधन*)* अधिनियम, *1939* की धारा *85* के तहत,

एक न्यायिक सदस्य की पीठ द्वारा प्रयोग किया गया और

एक लेखाकार सदस्य। राष्ट्रपति के लिए इसकी अनुमति थी।

अपीलीय न्यायाधिकरण या उसके किसी अन्य सदस्य की अपीलों का निपटान करने के लिए, अकेले बैठकर *(*इस शर्त के अधीन कि निर्धारिती की कुल आय, जैसा कि निर्धारण द्वारा गणना की गई है*)*

अधिकारी, *Rs.15,000/-)* से अधिक नहीं था। अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए भी बड़ी पीठों का गठन करने का अधिकार था तीन सदस्यों की *(*इस शर्त के अधीन, कि बड़ी पीठ

इसमें कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक लेखाकार सदस्य शामिल होगा*)*।

((iv) 1922 के अधिनियम की धारा *5* ए में शर्तें निर्धारित की गई थीं।

न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता-एक व्यक्ति जिसने *10* साल तक सिविल न्यायिक पद पर कार्य किया था, वह पात्र था।

इसके अतिरिक्त एक अधिवक्ता जो मद्रास बार एसोसिएशन *v* के समक्ष अभ्यास कर रहा था।

भारत संघ *27*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

10 साल की अवधि के लिए उच्च न्यायालय भी पात्र था। के तहत

1922 अधिनियम, एक व्यक्ति जिसने चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में एकाउंटेंसी में अभ्यास किया था (चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम के तहत, *1949*) *10* वर्ष की अवधि के लिए, या एक पंजीकृत लेखाकार (या आंशिक रूप से एक पंजीकृत लेखाकार, और आंशिक रूप से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट) था।

लेखाकार) *10* साल की अवधि के लिए (पूर्व में लागू किसी भी कानून के तहत), लेखाकार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र था।

सदस्य। केवल एक न्यायिक सदस्य को नियुक्त किया जा सकता था

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष।

(v) 1922 के अधिनियम की धारा *67*, दीवानी अदालतों में प्रतिबंधित मुकदमे

आय कर संबंधी मुद्दों से संबंधित। इसके अलावा, किसी भी

उनके खिलाफ अभियोजन मुकदमा या अन्य कार्यवाही दायर नहीं की जा सकी।

सरकार का कोई अधिकारी, किसी कार्य या चूक के लिए,

सद्भावना से किए गए या होने का इरादा रखने वाले किसी भी कार्य को आगे बढ़ाना

1922 के अधिनियम के तहत किया गया। *(vi) 1922* के अधिनियम में अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय उपचार का प्रावधान नहीं था। एकमात्र भागीदारी

क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय, *1922* के अधिनियम की धारा *66* के तहत था।

धारा *66* के तहत, या तो निर्धारिती या आयकर आयुक्त, अपीलीय याचिका दायर कर सकते हैं।

एक मूल्यांकन आदेश) अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय को। ऐसा संदर्भ देने से इनकार करने के मामले में, व्यथित निर्धारिती या आयकर आयुक्त, इनकार पर हमला कर सकता है

अपीलीय न्यायाधिकरण, अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष। ए.

उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई (*1922* अधिनियम की धारा *66* ए- भारतीय आय द्वारा अंतःस्थापित) कर (संशोधन) अधिनियम, *1926*)। *1922* के अधिनियम की धारा *66* को भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, *1939* द्वारा संशोधित किया गया था।

जिसके द्वारा संदर्भ देने की शक्ति आयकर आयुक्त द्वारा (अपीलीय के स्थान पर) निर्धारित की जा सकती है।

न्यायाधिकरण)।

(vii) संदर्भ अधिकारिता का प्रयोग करते हुए,

विधि, जो *[2014] 10* एस. सी. आर. के समक्ष लंबित एक अपील में उत्पन्न हुई थी।

अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्धारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना था।

क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ का उत्तर दिए जाने के बाद,

अपीलीय न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानूनी स्थिति के अनुरूप लंबित अपील का निपटारा करेगा।

3 (i) 1922 के अधिनियम को आयकर अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

1961 (इसके बाद आयकर अधिनियम के रूप में संदर्भित)। जैसा कि निरस्त अधिनियम में, वैसे ही आयकर अधिनियम के तहत भी, एक आदेश

एक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित, एक के माध्यम से उपलब्ध था कार्यकारी-अपीलीय उपचार। तत्काल अपीलीय उपचार, था

उपायुक्त (अपील) के पास निहित /

आयुक्त (अपील)। के समक्ष अपील करने योग्य आदेश उपायुक्त (अपील) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था (आयकर अधिनियम की धारा 246 में)। इसी तरह, आदेश

आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की स्पष्ट रूप से गणना की गई थी (आयकर अधिनियम की धारा 246 ए में)।

((ii) कार्यपालिका द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध-अपीलीय

प्राधिकरण, एक और अपीलीय उपाय एक से पहले प्रदान किया गया था

अर्ध-न्यायिक अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद के रूप में संदर्भित,

अपीलीय न्यायाधिकरण, आयकर अधिनियम की धारा 252 के तहत)।

आयकर अधिनियम की धारा 255 (6) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, सभी शक्तियां हैं जो हैं धारा में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकरणों में निहित

131 , और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही

धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर और निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी -

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 और अपीलीय न्यायाधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 195 और अध्याय XXXV के सभी उद्देश्यों के लिए एक दीवानी अदालत माना जाएगा। "

इसलिए, कानून की एक काल्पनिक कल्पना के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण को एक दीवानी अदालत माना जाता था, जो "न्यायिक" से संबंधित था। कार्यवाही "।

तत्काल निर्णय में सभी उद्धरणों में जोर दिया गया है।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *29*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

(iii) आई. टी. ए. टी. के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, पदधारी को किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए।

न्यायाधीश के रूप में कम से कम *7* साल की सेवा के साथ न्यायालय।

वैकल्पिक रूप से, केंद्र सरकार किसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष या अपीलीय न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष को अपना अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि अपील

न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष शामिल होना था।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य।

(iv) आय के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठें

कर अधिनियम *(1922* अधिनियम के तहत एक के समान था*),* कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक

लेखाकार सदस्य। अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठों के गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास था। द.

आयकर अधिनियम के तहत पीठों की संरचना थी

1922 के अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित के समान। जब केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था, तो यह अपील के लिए खुला था

न्यायाधिकरण, एकल रूप से बैठने वाली अपीलों का निपटारा करने के लिए *(*इस शर्त के अधीन, कि अपील एक विवाद से संबंधित है, जिसमें -

संबंधित निर्धारिती की कुल आय *5* लाख रुपये से अधिक नहीं आंकी गई थी*)*। अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पास विशेष पीठों का गठन करने का अधिकार था, जिसमें शामिल थे -

तीन या अधिक सदस्य *(*जिनमें से एक न्यायिक होना चाहिए*)*

सदस्य, और एक, लेखाकार सदस्य*)*। के मामले में

मतभेद के कारण, यह माना गया कि इस मामले का निर्णय बहुमत द्वारा व्यक्त की गई राय के संदर्भ में किया गया था।

(v) एक निर्धारिती या आयुक्त, एक प्रस्ताव पेश कर सकता है

धारा *256* के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन

आयकर अधिनियम, जिसे उच्च का संदर्भ देने की आवश्यकता होती है

कानून के प्रश्न पर न्यायालय *(*पूर्व में लंबित एक अपील में उत्पन्न होने वाली*)*

अपीलीय न्यायाधिकरण)। यदि प्रार्थना में किया गया है

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, आदेश (प्रार्थना को अस्वीकार करना) उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध था।

(vi) आयकर अधिनियम की धारा 257 के लिए प्रावधान किया गया है

सीधे सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ। तत्काल संदर्भ अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है, यदि उसकी राय थी, [2014] 10 एस. सी. आर.

कि कानून का सवाल जो इससे पहले उठा था,

दो या दो से अधिक क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई।

(vii) धारा 260 ए को आयकर अधिनियम में शामिल किया गया था -

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998,1.10.1998 से प्रभावी। धारा 260 ए के तहत एक अपीलीय उपचार का प्रावधान किया गया था,

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देना।

तत्काल अपीलीय उपचार, अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष होगा। धारा 260 बी में निहित अधिदेश के संदर्भ में

आयकर अधिनियम के तहत, उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील की सुनवाई कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी थी। राय.

बहुमत से, उच्च न्यायालय का निर्णय होगा।

जहां कोई बहुमत नहीं था, अंतर के बिंदु पर,

उच्च न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों की राय ली जानी थी। इसके बाद, न्यायाधीशों की बहुमत की राय (जिसमें शामिल हैं)

जिन न्यायाधीशों ने मूल रूप से मामले की सुनवाई की थी) वे उच्च न्यायालय के निर्णय का गठन करेंगे।

(viii) इसके विरुद्ध एक और अपीलीय उपाय उपलब्ध था।

अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। तत्काल अपीलीय उपचार उच्चतम न्यायालय के पास निहित था

आयकर अधिनियम की धारा *261*।

भारत में सीमा शुल्क कानूनः

4 ((i)। सीमा शुल्क अधिनियम, *1962 (*इसके बाद के रूप में संदर्भित*)*

सीमा शुल्क अधिनियम*)* सीमा शुल्क से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। सीमा शुल्क अधिनियम ने शक्ति निहित की

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *128* के तहत सीमा शुल्क कलेक्टर *(*जहां विवादित आदेश था*)* के समक्ष उपचार प्रदान किया गया था। एक अधिकारी द्वारा पारित किया गया, सीमा शुल्क कलेक्टर के पद से नीचे*)*, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड के समक्ष और

सीमा शुल्क *(*केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत गठित,

1963) , जहाँ आक्षेपित आदेश एक द्वारा पारित किया गया था

सीमा शुल्क कलेक्टर। बोर्ड को भी सम्मानित किया गया था कार्यकारी पुनरीक्षण शक्तियाँ *(*सीमा शुल्क मद्रास बार एसोसिएशन की धारा *130* के तहत *v.*

भारत संघ *31*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

अधिनियम*)*, स्वतः या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर, सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी निर्णय या आदेश से संबंधित किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच करता है। बोर्ड में स्पष्ट रूप से निहित शक्तियों के अलावा *(*के तहत*)*

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *130)* भी निहित थी केंद्र सरकार *(*सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *131* के तहत*)*।

((ii) वित्त *(*सं. *2)* अधिनियम, *1980* की धारा *128* से *131* तक

मूल अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया। मनोरंजन करने की शक्ति

पहला कार्यपालक-अपीलीय उपचार, अब धारा *128* और *128* ए के तहत कलेक्टर *(*अपील*)* के पास निहित था।

सीमा शुल्क अधिनियम। उपरोक्त उपाय के समाप्त होने पर, निम्नलिखित के लिए एक और अर्ध-न्यायिक अपीलीय उपाय प्रदान किया गया थाः सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण *(*नियंत्रण*)* अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष धारा *129* और *129* ए *(*इसके बाद के रूप में संदर्भित*)*

सी. ई. जी. ए. टी*/*अपीलीय न्यायाधिकरण*)*। सी. ई. जी. ए. टी. भी अपीलीय था प्राधिकरण, बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध। परिचय के साथ

वित्त अधिनियम, *1994* के अध्याय *5* के तहत सेवा कर,

सी. ई. जी. ए. टी. को सेवा कर विवादों से संबंधित मामलों में भी अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण को अब सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर के रूप में जाना जाता है

अपीलीय न्यायाधिकरण-सी. ई. एस. टी. ए. टी. *2003* के अधिनियम *22* द्वारा, *"*सोना *(*नियंत्रण*)"* अभिव्यक्ति को *"*सेवा कर*"* के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।

(iii) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *129* ने सी. ई. जी. ए. टी. के गठन को चित्रित किया। इसमें कई शामिल थे केंद्र सरकार के रूप में न्यायिक और तकनीकी सदस्य

उचित सोचा। तत्काल प्रावधान ने शर्तों को भी निर्धारित किया

न्यायिक*/*तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता। ए. न्यायिक सदस्य को उन व्यक्तियों में से चुना जा सकता था, जिन्होंने

कम से कम *10* वर्षों के लिए एक सिविल न्यायिक पद, या उन व्यक्तियों में से जो कम से कम *10* वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे,

केंद्रीय कानूनी सेवा के सदस्यों में से भी *(*नहीं*)*

ग्रेड*-I* से नीचे*),* जिसने कम से कम *3* साल तक इस पद पर कार्य किया हो। एक तकनीकी सदस्य उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जा सकता था, जिनके पास था

भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क *[2014] 10* एस. सी. आर. के सदस्य रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32

सेवा *(*समूह ए*),* इस शर्त के अधीन, कि ऐसे व्यक्ति सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर का पद धारण किया था

(स्तर *1),* या समकक्ष या उच्चतर पद, कम से कम *3* वर्षों के लिए। वित्त *(*सं. *2)* अधिनियम, *1996* ने अधिनियम की धारा *129 (3)* में संशोधन किया।

सीमा शुल्क अधिनियम, जिसके द्वारा यह केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करने में सक्षम बनाता है। केंद्र सरकार इस तरह की नियुक्ति कर सकती है।

इस शर्त पर कि संबंधित व्यक्ति न्यायाधीश था

उच्च न्यायालय का, या अपीलीय के सदस्यों में से एक था

न्यायाधिकरण। इसी तरह, यह केंद्र सरकार के लिए खुला था

अपीलीय न्यायाधिकरण के एक या अधिक सदस्यों को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त करना।

((iv) अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियाँ और कार्य थे -

(सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129 सी के संदर्भ में) अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के बीच से इसके अध्यक्ष द्वारा गठित पीठों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक बेंच की आवश्यकता थी

कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक

तकनीकी सदस्य। यह राष्ट्रपति के लिए खुला था कि वह कम से कम तीन सदस्यों की एक विशेष पीठ का गठन करे (जिसमें निम्न शामिल हों) -

कम से कम एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य)। द. पीठ की संरचना, एक संशोधन द्वारा संशोधित की गई थी

जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अपीलीय न्यायाधिकरण की एक विशेष पीठ

इसमें कम से कम दो सदस्य (तीन के बजाय) शामिल होने थे। यह राष्ट्रपति और/या सदस्यों के लिए भी खुला था।

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत)

अपीलों का निपटान, अकेले बैठकर, इस शर्त के अधीन कि जब्त किए गए माल का मूल्य, या शुल्क में अंतर

शामिल, या शामिल कर्तव्य, या जुर्माना या दंड की राशि

इसमें शामिल, जो Rs.10,000/- से अधिक नहीं था, सीमा को पहले संशोधित कर Rs.50,000/- कर दिया गया था, फिर 1 लाख रुपये कर दिया गया, बाद में Rs.10 लाख कर दिया गया, और वर्तमान में यह Rs.50 लाख है। एक विवाद से जुड़ा मामला जिसमें किसी भी प्रश्न का निर्धारण

सीमा शुल्क की दर या माल के मूल्य के संबंध में

मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए एकमात्र या मुद्दे में से एक मुद्दा है, हालांकि एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य [धारा 129 सी (4) (बी)] की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए।

मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत संघ 33

[जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

किसी भी बिंदु (ओं) पर मतभेद, की राय

बहुमत अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय का गठन करने के लिए था। यदि सदस्य समान रूप से विभाजित थे, तो अपील को राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे बिंदुओं पर सुनवाई के लिए, अपीलीय न्यायाधिकरण के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा भेजा जाना था। इसके बाद,

बहुमत की राय को निर्णय के रूप में माना जाना था अपीलीय न्यायाधिकरण। धारा 129 सी की उप-धाराएँ (7) और (8) निम्नानुसार प्रदान की गई हैं:

"(7) अपीलीय न्यायाधिकरण, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए होगाः

अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, उनके पास वही शक्तियाँ हैं जो हैं

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक अदालत में निहित

(5 1908 का), जब निम्नलिखित के संबंध में मुकदमा चलाया जाता है

विषय, अर्थात्ः

(अ)

खोज और निरीक्षण;

(ख)

किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना और

शपथ पर उसकी जाँच करना;

लेखा पुस्तकों के उत्पादन को बाध्य करना और

((ग)

अन्य दस्तावेज़; और

कमीशन जारी करना।

((घ)

(8) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कोई भी कार्यवाही

के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है

धारा 193 और 228 और धारा 196 के प्रयोजन के लिए

1860 की भारतीय दंड संहिता 945) और अपीलीय

न्यायाधिकरण को संहिता की धारा 195 और अध्याय XXVI के सभी उद्देश्यों के लिए एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा। दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) "।

उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि कानून की कल्पना से, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को इस प्रकार माना जाता है -

न्यायिक कार्यवाही।

(v) सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क राजस्व अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1986 23.12.1986 से लागू हुआ।

26 तत्काल अधिनियमन में, सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर रखा गया है। इसकी धारा *28* के रूप में उपबंध किया गया है

इसके अंतर्गतः

"28. अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही

न्यायिक कार्यवाही-न्यायिक कार्यवाही से पहले की सभी कार्यवाही

अपीलीय न्यायाधिकरण को न्यायिक माना जाएगा

धारा *193,219* के अर्थ के भीतर कार्यवाही और

228 भारतीय दंड संहिता *(1860* का *45) "*।

उपरोक्त संशोधन के अवलोकन से पता चलता है कि

कानून, अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्वहन माना गया था "न्यायिक कार्यवाही "। इसलिए, पूर्व में प्रचलित स्थिति

जहां तक तात्कालिक पहलू का संबंध है, संशोधन को बनाए रखा गया था।

(vi) जैसे *1922* के अधिनियम के मामले में, जिसमें अपीलीय उपचार का प्रावधान नहीं था, लेकिन एक संदर्भ की अनुमति दी गई थी

इसी तरह, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *130* में कानून के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय को निर्देश देने का प्रावधान किया गया है, जिसे धारा *66* के तहत अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। एक संदर्भ बनाया जा सकता है, सीमा शुल्क कलेक्टर या जिस व्यक्ति पर सीमा शुल्क लगाया गया है, उसके आवेदन पर अपीलीय न्यायाधिकरण को।

न्यायाधिकरण, अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष। जहाँ एक संदर्भ कानून के एक प्रश्न पर विचार किया गया था, इसे एक द्वारा सुना जाना था

उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ। किसी भी बिंदु *(ओं)* पर मतभेद के मामले में, द्वारा व्यक्त की गई राय

बहुमत को उच्च न्यायालय के निर्णय के रूप में माना जाना था। जहाँ राय समान रूप से विभाजित थी, के बिंदु *(ओं)* पर

इसके विपरीत, मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जानी थी। इसके बाद, बहुमत की राय

उच्च न्यायालय, तब अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लागू किया जाएगा, अपील के निपटारे के लिए जहाँ से संदर्भ था

उभरा।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *35*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

(vii) अपीलीय न्यायाधिकरण को भी ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया था

(सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *130* ए के तहत *)* सीधे उच्चतम न्यायालय को एक संदर्भ। यह किया जा सकता है, यदि अपीलीय न्यायाधिकरण का विचार था कि निर्णय के लिए उसके समक्ष लंबित कानून के प्रश्न के संबंध में उच्च न्यायालयों के निर्णयों में टकराव था। उच्चतम न्यायालय का निर्णय तब होगा

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उस अपील के निपटारे के लिए आवेदन किया जाए, जिसमें से संदर्भ उत्पन्न हुआ था।

उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय में अपील के एक उपाय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सीमा शुल्क अधिनियम की संशोधित धारा *130* बशर्ते कि प्रत्येक से उच्च न्यायालय में एक अपील होगी

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा *(* आई. डी. *1* पर या उसके बाद *)* पारित आदेश, इस शर्त के अधीन कि उच्च न्यायालय संतुष्ट था, कि इस मामले में कानून का एक बड़ा सवाल शामिल था। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करेगा। यह उच्च न्यायालय के लिए खुला था

इसका तत्काल अपीलीय अधिकार क्षेत्र, किसी भी मुद्दे को निर्धारित करने के लिए भी

जो अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा तय नहीं किया गया था, या था

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गलत निर्णय लिया गया। याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत, कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जा सकता था।

न्यायालय, धारा *130* के तहत दायर एक अपील पर, या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा धारा *130* के तहत *(1.7.2003* से पहले *)* या धारा *130A* के तहत किए गए संदर्भ पर किया गया संदर्भ।

(x) एन. टी. टी. अधिनियम ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *130,130* ए, *130* बी, *130* सी और *130* डी को हटा दिया। तत्काल अधिनियम प्रदान किया गया

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश से अपील के लिए

एन. टी. टी. को, इस शर्त के अधीन, कि एन. टी. टी. इस संतोष पर पहुँचा कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

एक अपील को स्वीकार करने पर, एन. टी. टी. *[2014] 10* एस. सी. आर. तैयार करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36 अपील की सुनवाई के लिए कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न। एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *23* में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से सभी मामले और कार्यवाही

उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अपीलों और संदर्भों सहित, एन. टी. टी. को हस्तांतरित किया जाएगा। एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *24* में अपील का प्रावधान है। एन. टी. टी. द्वारा पारित आदेश से, सीधे सुप्रीम कोर्ट को

अदालत। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधानः

5 ((i)। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, *1944 (*इसके बाद*)*

भारत में निर्मित और उत्पादित, और नमक के लिए। उक्त के तहत अधिनियम, कर्तव्य का आकलन करने की शक्ति, के साथ निहित था

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर और केंद्रीय कलेक्टर

एक्साइज। आयुक्त *(*अपील*)* के समक्ष धारा *35* के तहत एक कार्यकारी-अपीलीय उपचार प्रदान किया गया था।

((ii) बोर्ड को पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र दिया गया था।

एक निर्णय/आदेश/बनाए गए/पारित नियम से, के तहत संशोधन उत्पाद शुल्क अधिनियम, इस शर्त के अधीन कि कोई संशोधन तत्काल प्रावधान के तहत नहीं होगा, एक अपीलीय आदेश के खिलाफ

आयुक्त *(*अपील*)* द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा *35* के तहत पारित किया गया। केंद्र सरकार निहित थी

धारा *35* के तहत आयुक्त *(*अपील*)* द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के साथ। *1978* में, पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता जो अब तक बोर्ड के पास थी,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर के पास निहित था।

*((*ग*)* प्रथम कार्यपालक के समाप्त हो जाने पर-अपीलीय

समाधान, एक और अर्ध-न्यायिक अपीलीय उपचार, उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा *35* बी के तहत, एक अपीलीय के लिए प्रदान किया गया था।

न्यायाधिकरण। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का उपाय, मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *37*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

(क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर द्वारा एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के रूप में पारित निर्णय या आदेश के विरुद्ध, (ख)

कलेक्टर (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध

उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 ए (वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित), (सी) धारा 35 के तहत बोर्ड या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपीलीय कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ।

(जैसा कि यह 21.8.1980 से पहले था), और (डी) पारित आदेश के खिलाफ

बोर्ड या केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर द्वारा धारा 35 ए के तहत (जैसा कि यह 21.8.1980 से पहले था)।

((iv) अपीलीय न्यायाधिकरण में इतनी संख्या में न्यायिक/तकनीकी सदस्य शामिल होने थे कि केंद्रीय सरकार उचित समझेगी। न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति केवल उन व्यक्तियों में से की जा सकती थी जिन्होंने

कम से कम 10 वर्षों से भारत में न्यायिक कार्यालय, या जो कम से कम 10 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, या जिन्होंने

भारतीय कानूनी सेवा का सदस्य रहा हो (उक्त सेवा के ग्रेड 1 में पद धारण किया हो, या कोई समकक्ष या उच्चतर पद हो)

कम से कम 3 साल के लिए। केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता था

तकनीकी सदस्य जो भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, समूह ए के सदस्य रहे हों और सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क (या कोई अन्य) के कलेक्टर के पद पर रहे हों।

कम से कम 3 साल के लिए समकक्ष या उच्चतर पद)। द सेंट्रल

सरकार के पास किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति थी, जो या

किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों, या जो उनमें से एक थे अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य, अध्यक्ष के रूप में

अपीलीय न्यायाधिकरण। अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यों का निर्वहन उसके अध्यक्ष द्वारा गठित पीठों के माध्यम से किया जाना था। केंद्र सरकार के पास भी एक को नियुक्त करने का अधिकार था।

उप के रूप में अपीलीय न्यायाधिकरण के या अधिक सदस्य

सदस्य और एक तकनीकी सदस्य। किसी भी मुद्दे पर मतभेद की स्थिति में, बहुमत की राय होगी अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय गठित करता है। यदि सदस्य

पीठ समान रूप से विभाजित थी, राष्ट्रपति को विवादित राय को सुनवाई के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता थी, इन बिंदुओं पर

अपीलीय [2014] 10 एस. सी. आर. के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा अंतर।

न्यायाधिकरण। इस तरह के संदर्भ के बाद बहुमत की राय होगी,

अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय। यह राष्ट्रपति और सदस्यों (द्वारा अधिकृत) के लिए भी अनुज्ञेय था।

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष), अपीलों की सुनवाई और निपटान करने के लिए, अकेले बैठने के लिए (शर्त के अधीन, कि

शुल्क या इसमें शामिल शुल्क में अंतर, या जुर्माने की राशि या

जुर्माना शामिल था, जो Rs.10,000/- से अधिक नहीं था-सीमा थी

पहले इसे संशोधित कर Rs.50,000/- कर दिया गया, फिर इसे 1 लाख रुपये कर दिया गया, बाद में इसे Rs.10 लाख कर दिया गया और वर्तमान में यह Rs.50 लाख है)। इसी तरह

प्रावधान (अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के संबंध में)

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत) द्वारा सुने जाने वाले मामलों के संबंध में डिवीजन बेंच, उत्पाद शुल्क की धारा 35 डी (3) (ए) में आदेशित है

एक्ट करें।

(v) सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क राजस्व अपीलीय न्यायाधिकरण

अधिनियम, 1986,23.12.1986 पर लागू हुआ। तत्काल अधिनियम की धारा 26 ने उच्चतम न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर दिया। धारा 14, अधिकारिता, शक्तियों के लिए प्रदान की गई

और अपीलीय न्यायाधिकरण का अधिकार। धारा 28 निम्नानुसार प्रदान की गई है:

"28. अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही

न्यायिक कार्यवाही-न्यायिक कार्यवाही से पहले की सभी कार्यवाही

अपीलीय न्यायाधिकरण को न्यायिक माना जाएगा

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193,219 और 228 के अर्थ के भीतर कार्यवाही।

उपरोक्त संशोधन के अवलोकन से पता चलता है कि

कानून की कल्पना, अपीलीय न्यायाधिकरण को माना गया था

(vi) धारा 35 जी में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कानून के किसी भी प्रश्न पर उच्च न्यायालय को निर्देश देने का प्रावधान है। द. एक आवेदन दाखिल करके उपरोक्त उपचार का लाभ उठाया जा सकता है।

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष। इस तरह का आवेदन केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर या उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जिस पर

उत्पाद शुल्क लगाया गया था। कानून के एक प्रश्न पर एक संदर्भ,

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय को किया गया,

एक संदर्भ बनाने के लिए*),* उच्च न्यायालय के समक्ष। क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय, एक संदर्भ की स्वीकृति पर, अपने निर्णय, कानून के सवाल पर। मतभेद के मामले में, बहुमत द्वारा व्यक्त की गई राय का गठन होगा

उच्च न्यायालय का निर्णय। यदि पीठ की राय समान रूप से विभाजित थी, तो मतभेद के बिंदु *(*ओं*)* को सुना जाना था

उच्च न्यायालय का निर्णय। अपीलीय न्यायाधिकरण करेगा तत्पश्चात, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप, लंबित अपील पर निर्णय लें।

(vii) उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा *35* एच के लिए प्रावधान किया गया है

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सीधे उच्चतम न्यायालय को निर्देश। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा तत्काल संदर्भ, हो सकता है

अपीलीय न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि एक अपील में निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले कानून का प्रश्न

इसके समक्ष लंबित, दो या दो से अधिक द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई थी

अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का निर्णय,

इसके बाद लंबित अपील पर निर्णय लेने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन किया जाएगा। धारा *35* एल में अपील के लिए प्रावधान किया गया है

न्यायालय *(*अपीलीय द्वारा उच्च न्यायालय को दिए गए संदर्भ पर*)* न्यायाधिकरण*)*। तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उसके समक्ष लंबित अपील के निपटारे में आवेदन किया गया।

(viii) वित्त *(*सं*. 32)* अधिनियम, *2003* प्रतिस्थापित धारा

35 उत्पाद शुल्क अधिनियम का जी और संदर्भ के उपचार के स्थान पर,

संशोधित प्रावधान क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय में सीधी अपील के लिए प्रदान किया गया है *(*कट-ऑफ तिथि के बाद, यानी, *1.7.2003)*। क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय को एक अपील पर विचार करना था

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश, इसके होने पर

संतुष्ट, कि अपील ने कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया।

40 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय तैयार करेगा -

कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न *(*ओं*)*। यह उच्च न्यायालय के लिए खुला था अपनी तत्काल अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग, किसी ऐसे मुद्दे को निर्धारित करने के लिए भी जिसका निर्णय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा नहीं किया गया था, या जिसका निर्णय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गलत तरीके से किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई अपील की सुनवाई एक

कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ। आबकारी अधिनियम की धारा *35* एल में भी संशोधन किया गया। संशोधित प्रावधान के लिए प्रावधान किया गया है

उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय से अपील *(*के अभ्यास में*)* उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा *35* जी के तहत इसकी अपीलीय अधिकारिता,

या अपीलीय द्वारा धारा *35* जी के तहत किए गए संदर्भ पर *1.7.2003* के समक्ष न्यायाधिकरण, या धारा *35H* के तहत किए गए संदर्भ पर, सर्वोच्च न्यायालय को।

(ix) एन. टी. टी. अधिनियम ने उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा *35* जी, *35* एच, *351* और *35* जे को हटा दिया। तत्काल अधिनियम एक अपील के लिए प्रदान किया गया

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा एन. टी. टी. को पारित प्रत्येक आदेश से,

इस शर्त के अधीन, कि एनटीटी संतुष्ट था, कि इस मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था। अपील को स्वीकार करने पर, एन. टी. टी. अपील की सुनवाई के लिए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करेगा। एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *23* में प्रावधान किया गया है,

कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को और उससे, अपील सहित सभी मामले और कार्यवाही

और प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों से संबंधित संदर्भ, लंबित

क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों के समक्ष, एन. टी. टी. को हस्तांतरित किया जाएगा। एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *24* में अपील का प्रावधान किया गया है।

एन. टी. टी. द्वारा पारित एक आदेश से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक।

एन. टी. टी. अधिनियम की घोषणा करने वाले तथ्यः

6. स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग था

1955 में श्री एम. सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में तीन साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया, जो पहले भी थे।

भारत के लिए महान्यायवादी। "राष्ट्रीय कर न्यायालय" के गठन का विचार पहले विधि आयोग द्वारा अपनी *12* वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मौजूदा अपील को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था।

न्यायाधिकरण, आयकर अधिनियम के ढांचे के तहत।

यह मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ *41*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

अपीलीय आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में सीधी अपील की सिफारिश की गई। यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।

7. एक प्रत्यक्ष कर जांच समिति का गठन किया गया था

1970 में भारत सरकार के अध्यक्ष के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री के. एन. वांचू थे। जाँच समिति को निम्नलिखित उद्देश्य सौंपे गए थेः

(1) विभिन्न कानूनी खामियों के माध्यम से कर से बचने की जांच करने के तरीकों की सिफारिश करना*; (2)* अनुमत छूटों की जांच करना।

कर प्रशासन में। वांचू समिति ने सिफारिश की एक "राष्ट्रीय न्यायालय" का निर्माण, जिसमें शामिल होंगे -

कर कानूनों के विशेष ज्ञान वाले न्यायाधीश। द.

वांचू समिति द्वारा की गई सिफारिश, अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों में स्थायी "कर पीठों" के निर्माण और ऐसी पीठों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए थी। *224* संविधान का ए। इस सुझाव का उद्देश्य कर मामलों के बैकलॉग को दूर करना था। वांचू समिति ने नहीं किया

किसी भी अलग कर न्यायालय की स्थापना का सुझाव देते हुए,

समिति के अनुसार, अन्य वैधानिक और प्रावधानों के अलावा संविधान के प्रावधानों में संशोधन शामिल होगा।

प्रक्रियात्मक परिवर्तन।

8. एक अन्य प्रत्यक्ष कर कानून समिति का गठन किया गया था

1977 , श्री एन. के. पालखीवाला की अध्यक्षता में

प्रख्यात न्यायविद। बाद में इस समिति की अध्यक्षता श्री जी. सी. ने की।

चोकसी। जाँच करने के लिए समिति का गठन किया गया था और

सरलीकरण के लिए कानूनी और प्रशासनिक उपायों का सुझाव दें

और प्रत्यक्ष कर कानूनों को तर्कसंगत बनाना। चोकसी समिति

अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार के साथ एक "केंद्रीय कर न्यायालय" की स्थापना की सिफारिश की। यह सुझाव दिया गया था कि इस तरह के न्यायालय का गठन एक अलग क़ानून के तहत किया जाए। जैसे कि

चोकसी समिति की सिफारिशें भी आवश्यक थीं संविधान के प्रावधानों में संशोधन।

अंतरिम *42* के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

उपरोक्त सिफारिश के लिए उपाय, चोकसी समिति ने सुझाव दिया, "विशेष कर" के गठन की वांछनीयता

उच्च न्यायालयों में पीठें, बड़ी संख्या में लंबित कर मामलों से निपटने के लिए, पूरे वर्ष लगातार बैठती रहती हैं। यह.

यह भी सुझाव दिया गया था कि "विशेष कर" पर बैठने वाले न्यायाधीश

प्रत्यक्ष कर कानूनों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष ज्ञान रखने वालों में से पीठों का चयन किया जाना चाहिए। द.

चोकसी समिति ने सिफारिश की कि न्यायाधीशों का चयन किया जाए

"विशेष कर पीठों" को "केंद्रीय" को हस्तांतरित किया जाएगा।

कर न्यायालय ", जब और जब इसका गठन किया गया था। यह है,

इसलिए यह स्पष्ट है कि चोकसी समिति की सिफारिशों के अनुसार, "केंद्रीय कर न्यायालय" को शामिल करना था

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों या नियुक्त किए जाने के लिए योग्य व्यक्तियों की

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में। चोकसी की सिफारिशें समिति ने खुलासा किया कि सुझाए गए "केंद्रीय कर न्यायालय"

प्रत्यक्ष कर कानूनों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक विशेष प्रकार का उच्च न्यायालय होना। चोकसी समिति की रिपोर्ट के अनुच्छेद *6.22* में इसे स्पष्ट करने की मांग की गई थी। *-9*. ऊपर उल्लिखित किसी भी सिफारिश को तब तक लागू नहीं किया गया जब तक कि इसी तरह की सिफारिश फिर से नहीं की गई।

1990 के दशक की शुरुआत में प्रस्तावित। कुछ वर्षों तक इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के बाद, भारत संघ ने राष्ट्रीय कर की घोषणा की।

न्यायाधिकरण अध्यादेश, *2003*। अध्यादेश में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया था,

अपीलीय अधिकार क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए *(*प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत*)*

उच्च न्यायालयों में निहित, एन. टी. टी. को। अध्यादेश के समाप्त होने के बाद, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण विधेयक, *2004* पेश किया गया। ने कहा कि

विधेयक को संसद की प्रवर समिति के पास भेजा गया था। प्रवर समिति ने विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत सुनवाई की। मद्रास बार के प्रतिनिधियों सहित हितधारक

संघ *(*अर्थात, इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता हस्तांतरित मामले *(*ग*)* सं। *150 2006)*। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

2.8.2005 पर। अपनी रिपोर्ट में, इसने एन. टी. टी. की स्थापना पर गंभीर आपत्तियों का सुझाव दिया। उपरोक्त विधेयक *2005* में लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विधेयक में चार मुख्य कारण बताए गए हैं।

एन. टी. टी. की स्थापना के लिएः *(1)* देश भर के उच्च न्यायालयों में लंबित भारी बकायों को कम करने के लिए, *(2)* विशाल मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *43*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

विभिन्न संस्थाओं के समक्ष कर मुकदमे में कर वसूली को कथित रूप से रोक दिया गया था।

उच्च न्यायालय, जो भारत सरकार की राष्ट्रीय परियोजनाओं/कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को सीधे प्रभावित करते हैं, *(3)* कर कानूनों की व्याख्या में एकरूपता रखें। इस संबंध में

यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न राय व्यक्त की गई थी

समान कर मुद्दों पर विभिन्न उच्च न्यायालय, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी प्रक्रिया को उच्च न्यायालयों में बांधा जा रहा है, और *(4)* कर मामलों से निपटने वाले मौजूदा न्यायाधीश दीवानी अदालतों से थे,

मुद्दे। याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन मुद्दों पर प्रचार किया गयाः

10. याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई प्रस्तुतियाँ, सुविधा के उद्देश्यों के लिए, एक से जांच की जानी चाहिए

विशिष्ट और अलग दृष्टिकोण की श्रृंखला। प्रत्येक दृष्टिकोण

वास्तव में एक स्वतंत्र प्रस्तुति है। इसलिए, पहली बार में, यह स्पष्ट रूप से वर्णन करना आवश्यक है कि

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के हाथों प्रस्तुतियाँ। उसी के अनुसार चित्रित किया जा रहा है

इसके नीचेः

पहला विवादः कि एन. टी. टी. की स्थापना के कारण,

गलत और अस्तित्वहीन थे। बुनियादी आधार के बाद से

वैध और उचित के रूप में। और इसलिए, वही होने के लिए उत्तरदायी है गिरा दिया।

दूसरा तर्कः यह अस्वीकार्य है कि

मुख्य न्यायिक अपील को निरस्त/विभाजित करने के लिए विधायिका

कार्य, विशेष रूप से पारंपरिक रूप से उच्च न्यायालय में निहित कार्य। इसके अलावा, ऐसे कार्यों का हस्तांतरण

अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, आवश्यक अवयवों से रहित उच्च न्यायालय, जिसे प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी, संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य था, और इसे दरकिनार किया जा सकता था। इसके अलावा

अपीलीय अधिकारिता, उच्च न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. भी हैं।

44

एन. टी. टी. अधिनियम द्वारा अस्वीकृत किया गया। और इसलिए, वही निर्धारित किया जाए

एक तरफ।

तीसरा विवादः शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन,

और न्यायिक समीक्षा, दूसरों के बीच, संविधान की मूल संरचना का गठन करती है। संविधान *(*बयालीसवां संशोधन*)* अधिनियम, *1976* द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद *323* बी, इस हद तक कि यह संविधान के उपरोक्त घटकों का उल्लंघन करता है।

संविधान की मूल संरचना, अति घोषित होने के लिए उत्तरदायी है संविधान का अधिकार।

चौथा विवादः सहित कई प्रावधान

एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5,6,7,8* और *13,*

एन. टी. टी. में निहित न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता, और इस तरह, अपने वर्तमान प्रारूप में अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

11. अब हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रत्येक तर्क का वर्णन करेंगे।

जिस तरह से प्रस्तुतियाँ हमारे सामने आगे बढ़ा दी गई थीं। पहला विवादः

12. जहां तक उच्च न्यायालयों के समक्ष कर संबंधी मामलों के बकाया का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था कि आंकड़े इंगित करते हैं

विभाग द्वारा गलत थे। इस संबंध में यह दावा किया गया था,

कि राजस्व के कहने पर अपनाया गया रुख, कि वहाँ

विभिन्न अदालतों में लगभग *80,000* मामले लंबित थे,

असत्य है। यह विद्वान वकील का जोरदार तर्क था

याचिकाकर्ताओं के लिए, कि अक्टूबर, *2003* तक (जब राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी किया गया था), बकाया थे

मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर, यह दावा किया गया था कि मद्रास उच्च न्यायालय में आयकर अधिनियम की धारा *260* ए के तहत लंबित अपीलें *2,000* से कम थीं। यह भी दावा किया गया था कि इसी तरह की अपीलों की विचाराधीनता

अधिकांश दक्षिणी राज्य और भी कम थे।

यह इंगित किया गया था कि मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ

45

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

कर्नाटक के उच्च न्यायालय और केरल के उच्च न्यायालय में ऐसी अपीलों की लंबितता *2,000* से भी कम थी।

13. राजस्व के दावे के संबंध में, कि भारी कर

उच्च न्यायालयों के समक्ष कर मुकदमे में वसूली को रोक दिया गया था

प्रस्तुत किया कि विभाग के कहने पर पेश किए गए आंकड़े गलत थे। यह बताया गया था कि

राजस्व को, उच्च न्यायालयों में लंबित मामले शामिल हैं

और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। यह बताया गया कि कर कानूनों के तहत ब्याज प्रति वर्ष *40* प्रतिशत तक हो सकता है। दंडात्मक ब्याज के अलावा। तदनुसार यह चाहा गया था कि

प्रचार किया कि यदि मुख्य अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है, तो शायद ही कोई बकाया देय होगा

बिल्कुल भी सरकार। इसके अतिरिक्त, यह दावा करने की मांग की गई थी,

जैसे कि रोक दिया गया है, लेकिन इसे वापस करना पड़ सकता है। यह आगे कहा गया कि ज्यादातर मामलों में, राजस्व सक्षम था जब तक मामला उच्च न्यायालय में पहुँचा (पूर्व-जमा के कारण), तब तक निर्धारिती से पर्याप्त राशि की वसूली की जाए।

इसलिए यह प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि ये आंकड़े कर की राशि के संदर्भ में राजस्व द्वारा इंगित

उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों में रखा जाना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था

और धोखेबाज।

14. यह विद्वान वकील का भी तर्क था

याचिकाकर्ताओं, कि केवल स्थापना और निर्माण

एन. टी. टी. के परिणामस्वरूप कर कानूनों से संबंधित निर्णयों में एकरूपता नहीं आएगी। इस संबंध में यह दावा करने की मांग की गई थी कि जैसे-जैसे

जिस तरह से दो उच्च न्यायालय एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, इसलिए

एन. टी. टी. की दो कर पीठ भी हो सकती हैं। तथ्यात्मक मोर्चे पर, यह

यह इंगित किया गया था कि उच्च न्यायालयों में राय का विचलन बहुत दुर्लभ था। अनुमान के रूप में, यह सुझाव दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

46

अधिकांश मामलों में *(*लगभग *99* प्रतिशत*)*, एक उच्च न्यायालय

एक अन्य उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पालन करें। विद्वान वकील ने हालांकि बताया कि उच्च न्यायालयों में एक सदियों पुराना तंत्र,

विचारों के टकराव को हल करने के लिए या तो ऐसे मामलों को बड़ी पीठों के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाता था। आई. टी. ए. टी. और सी. ई. एस. टी. ए. टी. की ओर इशारा करते हुए, यह था

दावा किया, कि विचलन के कई मामले हुए थे राय, जिसे बड़ी पीठों द्वारा हल किया गया था। यह था,

इसलिए प्रचार करने की मांग की गई, कि तत्काल आधार

संबंधित मुद्दों पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि एन. टी. टी. के निर्माण के लिए आधार के रूप में उपरोक्त का उल्लेख अत्यंत था। दुर्भाग्यपूर्ण है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस देश की स्वतंत्रता से बहुत पहले और उसके बाद भी, उच्च न्यायालयों को

कर संबंधी विवादों की व्याख्या और उनका न्यायसंगत अर्थ निकालना,

विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, संबंधित मुद्दे, राजस्व के साथ-साथ निर्धारिती दोनों द्वारा उच्च न्यायालयों में व्यक्त किए गए विश्वास से स्पष्ट थे। इसके अलावा, सच्चाई और सत्यनिष्ठा, तत्काल दावे की, विद्वानों के अनुसार

वकील, इस तथ्य से अनुमान लगाया जा सकता है, कि द्वारा हस्तक्षेप उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में

कर संबंधी मामले न्यूनतम रहे हैं।

16. सुनवाई के दौरान हमारा ध्यान भी था

इस तथ्य के लिए आमंत्रित किया, कि तत्काल प्रकृति के कानून

इसका एक तरफा प्रभाव पड़ेगा। इस ओर से यह इंगित करने की मांग की गई थी कि उच्च न्यायालयों में निहित अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जा रहा है, लेकिन भार को स्थानांतरित किया जा रहा है

भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इस दावे की मांग की गई थी

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा, उन विधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके, जिनकी शक्ति

न्यायिक समीक्षा पारंपरिक रूप से उच्च न्यायालयों में निहित है, जिसे मद्रास बार एसोसिएशन *v* कहा गया है।

भारत संघ *47*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

अव्यवस्थित, और अपील का एक उपाय प्रदान किया गया हैसीधे उच्चतम न्यायालय में गठित बूनल। इसमें

आधा, संदर्भ स्पष्ट रूप से निम्नलिखित के लिए किया जा सकता हैः

अंडाशयः

((i)

विद्युत अधिनियम, *2003*

125. उच्चतम न्यायालय में अपील-कोई भी व्यक्ति

अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

संसूचना की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय या आदेश

निर्दिष्ट किसी एक या अधिक आधार पर

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *100* में,

उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने के लिए पर्याप्त कारण, इसे आगे की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दें साठ दिनों से अधिक।

*((*ख*)*

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010*

धारा *22*। उच्चतम न्यायालय में अपील-किसी भी निर्णय, निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति

न्यायाधिकरण, संचार की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

उसे न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय, निर्णय या आदेश का,

में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक आधार पर

सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908* की धारा *100*

(5 1908 का*)* बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय, किसी भी

नब्बे दिनों की समाप्ति के बाद अपील, यदि यह संतुष्ट है कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारण से रोका गया था

अपील को प्राथमिकता देने से।

(iii) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, *1997* जे. पी. आर. ई. एम. कोर्ट रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

धारा *18.* उच्चतम न्यायालय में अपील *(1)* की संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

सिविल प्रक्रिया, *1908 (1908* का *5)* या किसी अन्य मामले में

उस संहिता की धारा *100* में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर उच्चतम न्यायालय में अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी, जो एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है।

(2) किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

पक्षकारों की सहमति से अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किया गया।

(3) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील

निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर वरीयता दी गईः

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय इस पर विचार कर सके कि

नब्बे दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील, यदि यह संतुष्ट है कि अपीलार्थी था

समय पर अपील को प्राथमिकता देने से पर्याप्त कारण से रोका गया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, *1992*

धारा *15Z.* सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। - किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण एक अपील दायर कर सकता है

तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय

उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने के लिए पर्याप्त कारण, इसे आगे की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दें साठ दिनों से अधिक।

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कम्पनी अधिनियम, *1956*

(v)

धारा *10* जी. एफ. सुप्रीम कोर्ट में अपील करें।

■■ किसी भी

किसी निर्णय या आदेश से व्यथित व्यक्ति

अपीलीय न्यायाधिकरण अपील दायर कर सकता है

की तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय

के निर्णय या आदेश का संचार

कानून के किसी भी प्रश्न पर उसे अपीलीय न्यायाधिकरण

इस तरह के निर्णय या आदेश से उत्पन्न होनाः

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय, यदि वह

संतुष्ट है कि अपीलार्थी को रोक दिया गया था

उक्त अवधि के भीतर इसे दाखिल करने की अनुमति दें। अवधि साठ दिनों से अधिक नहीं।

17. यह भी बताया गया कि एन. टी. टी. का अधिनियमन

एक्ट पर से में प्रामाणिकता का अभाव है। इस संबंध में तर्क

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि एक संसदीय परंपरा है कि यदि कोई प्रवर समिति एक

विधेयक, यह आम तौर पर संसद द्वारा पारित नहीं किया जाता है। बहुत हद तक

कम से कम, प्रवर समिति द्वारा व्यक्त आपत्तियों को ध्यान में रखा जाता है, और विचाराधीन विधेयक उचित रूप से है

संशोधित किया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि संदर्भ के तहत विधेयक था

29.11.2005 पर लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और वही

एक भी संशोधन किए बिना पारित किया गया।

18. इसलिए, यह जोरदार विवाद था कि

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील, कि मूलभूत तथ्य

गलत होने के कारण, और जिस तरीके से विधेयक पारित किया गया था, वह प्रामाणिकता से रहित होने के कारण, स्वयं विधान यानी एनटीटी अधिनियम, अलग रखे जाने के योग्य था।

दूसरा तर्कः

19. यह विद्वान वकील का जोरदार तर्क था

याचिकाकर्ताओं के लिए, कि विधायिका के लिए मुख्य न्यायिक अपीलीय कार्यों को निरस्त/विभाजित करना अनुज्ञेय नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

50

पारंपरिक रूप से उच्च न्यायालय के पास निहित है, और इसे एक स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के साथ प्रदान/निहित करने के लिए, जिसमें एक उच्च न्यायालय के बुनियादी तत्व भी नहीं थे, जैसे उच्च न्यायालय (जिसके अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित करने की मांग की जाती है)। तत्काल विवाद के संयोजन में, यह भी था

विद्वान वकील की प्रस्तुति, कि अधिकार क्षेत्र निहित है के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालयों में

संविधान, केवल सही कार्यान्वियन के संबंध में नहीं है

न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र में भी कटौती नहीं की जा सकती है।

परिस्थितियाँ।

20. तत्काल विवाद के पूरक के लिए, सीखा

वकील ने संविधान के अनुच्छेद *225* पर भी भरोसा जताया

जिसे नीचे निकाला जा रहा हैः

के आधार पर बनाई गई उपयुक्त विधानमंडल की विधि इस संविधान द्वारा उस विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियाँ,

किसी भी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि और न्यायाधीशों की संबंधित शक्तियाँ

न्यायालय में न्याय प्रशासन के संबंध में, जिसमें न्यायालय के नियम बनाने की कोई शक्ति शामिल है और

न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों को विनियमित करना।

अकेले या डिवीजन न्यायालयों में बैठना, समान होगा प्रारम्भ होने से ठीक पहले

संविधानः

बशर्ते कि कोई प्रतिबंध जिसके लिए

राजस्व से संबंधित किसी मामले के संबंध में या उसके संग्रह में आदेशित या किए गए किसी कार्य के संबंध में किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारिता इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले के अधीन थी।

अब ऐसी अधिकारिता के प्रयोग पर लागू नहीं होगा।

संविधान के अनुच्छेद *225* के प्रावधान की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना। संविधान में यह प्रस्तुत किया गया था कि मद्रास बार एसोसिएशन की मूल अधिकारिता *v.*

भारत का संघ *51*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

राजस्व या संग्रह से संबंधित मामलों पर उच्च न्यायालय

इसके बारे में, भले ही वर्जित माना जाए, उक्त प्रतिबंध को अनुच्छेद *225* के परंतुक द्वारा स्पष्ट रूप से समाप्त करने का आदेश दिया गया था

संविधान से। वर्तमान संदर्भ में, विद्वान सलाहकार के लिए

याचिकाकर्ताओं ने भारत सरकार अधिनियम, *1935* की धारा *226 (1)* की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उक्त खंड को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 226 (1) जब तक उपयुक्त के अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता है

विधानमंडल, किसी भी उच्च न्यायालय के पास कोई मूल नहीं होगा राजस्व से संबंधित किसी मामले में, या संग्रह में आदेशित या किए गए किसी कार्य से संबंधित किसी भी मामले में अधिकारिता

देश के उपयोग और व्यवहार के अनुसार

या उस समय लागू कानून।

यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधान के तहत, ए

उच्च न्यायालय कर निर्धारण के संबंध में अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए राजस्व प्राधिकरण को बुलाने के लिए अनिवार्य रूप से एक रिट जारी नहीं कर सकता था। इसी तरह, यह उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था, की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए

मूल्यांकन के किसी आदेश को अलग करने या संशोधित करने के लिए प्रमाणित या प्रमाणित अधिदेश, का उल्लंघन करते हुए या में पारित किया गया किसी भी वैधानिक प्रावधान *(*ओं*)* का उल्लंघन। यह प्रस्तुत किया गया था कि

संविधान के अनुच्छेद *225* के परंतुक को, जैसा कि यहाँ ऊपर निकाला गया है, संविधान द्वारा हटा दिया गया था *(*चालीस

दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *1976 (1.2.1977* से प्रभावी*)*। हालाँकि, यह बताया गया था कि संसद ने महसूस किया है

जैसा कि मूल रूप से संविधान द्वारा अधिनियमित किया गया था *(44* वाँ संशोधन*)* अधिनियम, *1978 (*से प्रभावी*)*

20.6.1979) . इस प्रकार देखा गया, विद्वान वकील के अनुसार

याचिकाकर्ता, संविधान के प्रावधानों के तहत,

वर्तमान समय में उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता *(*अर्थात उच्च न्यायालय के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत अधिकारिता*)*

संविधान*)*, साथ ही, संविधान के अधिनियमन के समय उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासित कानून,

प्रतिबंधित। तदनुसार, यह दावा किया गया कि मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

52

राजस्व या उसके संग्रह से संबंधित, उच्च न्यायालयों के न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को कम नहीं किया जा सकता था।

21. संविधान के अनुच्छेद *226* और *227*, जिन पर

विद्वान सलाहकार द्वारा जोरदार निर्भरता रखी गई है, जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

"226. उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति -

(1) अनुच्छेद *32* में किसी भी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में सभी क्षेत्रों में शक्ति होगी -

जिसे वह किसी व्यक्ति को जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है या

उपयुक्त मामलों सहित कोई भी सरकार,

उन क्षेत्रों के निर्देशों, आदेशों या रिटों के भीतर, जिनमें शामिल हैं

बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में रिट, मैंडमस,

निषेध, यथा वारंट और प्रमाणपत्र, या उनमें से किसी के लिए

भाग *III* द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रवर्तन

अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा। उन क्षेत्रों के संबंध में जिनके भीतर कार्रवाई का कारण है,

ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है,

इसके बावजूद कि ऐसी सरकार का स्थान या

ऐसे व्यक्ति का अधिकार या निवास उनके भीतर नहीं है।

क्षेत्र।

(3) जहाँ कोई भी पक्ष जिसके खिलाफ अंतरिम आदेश हो,

चाहे निषेधाज्ञा या रोक के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से,

याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में किया जाता है

खंड *(1)* के तहत, इसके बिना -

(क*)* ऐसी याचिका की प्रतियां ऐसे पक्ष को प्रस्तुत करना।

और ऐसे अनुरोध के समर्थन में सभी दस्तावेज

अंतरिम आदेश*;* और

(ख*)* ऐसे पक्ष को सुनवाई का अवसर देना, ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v* के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करता है।

भारत संघ *53*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

ऐसे आदेश की समाप्ति और इस तरह की एक प्रति प्रस्तुत करता है

उस पक्ष को आवेदन जिसके पक्ष में ऐसा आदेश है

उच्च न्यायालय आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर या ऐसी प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उसका निपटारा करेगा।

आवेदन इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, जो भी बाद में हो, या

जहाँ उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन, अगले दिन की समाप्ति से पहले बंद रहता है।

जिसके बाद उच्च न्यायालय खुला है*;* और यदि

आवेदन का इस प्रकार निपटान नहीं किया गया है, अंतरिम आदेश, उस अवधि की समाप्ति पर, या, जैसा भी मामला हो, अगले दिन सहायता की समाप्ति पर, खड़ा होगा।

खाली कर दिया।

(4) इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति। करेंगे।

प्रदत्त शक्ति का अवमूल्यन न करें उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद *32* के खंड *(2)* द्वारा।

227. उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति

अदालत *(1)* प्रत्येक उच्च न्यायालय का सभी पर अधीक्षण होगा।

के संबंध में सभी क्षेत्रों में न्यायालय और न्यायाधिकरण

जो यह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। *(2)* पूर्वगामी की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

उपबंध, उच्च न्यायालय कर सकता है -

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी की मांग करना;

(ख) सामान्य नियम बनाएँ और जारी करें और निर्धारित करें।

अभ्यास और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए प्रपत्र

ऐसे न्यायालयों का; और *(ग)* प्रपत्र निर्धारित करें जिनमें पुस्तकें, प्रविष्टियाँ और

ऐसे किसी भी अधिकारी के खाते रखे जाएँगे। अदालतें।

[2014] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

54

(3) उच्च न्यायालय भी शुल्क की तालिकाओं का निपटारा कर सकता है

शेरिफ और ऐसे न्यायालयों के सभी क्लर्कों और अधिकारियों और वकीलों, अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं को अनुमति दी गई

उसमेंः

बशर्ते कि बनाए गए कोई नियम, निर्धारित प्रपत्र या

खंड *(2)* या खंड *(3)* के तहत तय की गई तालिकाएं कुछ समय के लिए किसी भी कानून के प्रावधान के साथ असंगत नहीं होंगी।

लागू है और इसके लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी

राज्यपाल।

(4) इस अनुच्छेद में कुछ भी प्रदान करने के लिए नहीं माना जाएगा

किसी भी न्यायालय पर अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ या

संबंधित किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित न्यायाधिकरण

सशस्त्र बल "।

यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त मूल अधिकार क्षेत्र में निहित है

उच्च न्यायालय को विशेषाधिकार रिट जारी करने के लिए दिखाया गया है

लेवी से संबंधित मामलों के लिए सचेत रूप से संरक्षित किया गया है

और कर का संग्रह। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एन. टी. टी. अधिनियम के अधिनियमन का स्पष्ट और स्पष्ट प्रभाव उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का है। यह समझाने की कोशिश की गई थी

यह इंगित करते हुए कि अपीलों पर निर्णय लेने की अधिकारिता,

पारंपरिक रूप से क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित, से आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम (सभी कर कानून) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों में

उच्च न्यायालयों के दायरे से बाहर कर दिया गया है, और

एन. टी. टी. अधिनियम द्वारा एन. टी. टी. के साथ निहित। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अनुच्छेदों के तहत उच्च न्यायालयों में निहित अधिकार क्षेत्र भी

226 और संविधान के 227 को व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में स्पष्टीकरण यह था कि एन. टी. टी. द्वारा सीधे उच्चतम न्यायालय को पारित एक आदेश के खिलाफ अपीलीय उपचार, जो उच्च न्यायालयों का उपरोक्त मूल अधिकार क्षेत्र था, व्यावहारिक रूप से निराश और प्रभावी था।

तटस्थ। यह इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में कटौती

संविधान को समर्पण, विशिष्ट और मद्रास बार संगठन के रूप में देखा जाना चाहिए।

के प्रतिस्थापन से उभरने वाले से अलग, धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता

आयकर अधिनियम, 1961, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 130 और आबकारी अधिनियम की धारा 35 जी। जबकि पूर्व विवाद एक स्पष्ट संवैधानिक अधिकार पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण के आधार पर

कर लगाने वाले कानूनों के प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 225 के प्रावधान में व्यक्त स्पष्ट इरादे के साथ एक अच्छी तरह से स्वीकृत संवैधानिक परंपरा से उभरते हैं।

22. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दूसरे तर्क का समर्थन करने के लिए, निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया थाः

(i) रिलायंस को सबसे पहले, के निर्णय पर रखा गया था

अभियोजन *v.* जमैका के अटॉर्नी जनरल जैक्सन *(* इंटरवेनर*), 1976* ऑल ई. आर. वॉल्यूम। *(1) 353.* तथ्यात्मक/कानूनी स्थिति

जो जमैका की संसद द्वारा अधिनियमित बंदूक न्यायालय अधिनियम, *1974* से संबंधित उद्धृत मामले में निर्धारण के लिए उत्पन्न हुआ।

उपरोक्त अधिनियम का पालन किए बिना बनाया गया था संविधान की धारा *49* द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया

जमैका*)*। गन कोर्ट एक्ट, *1974* ने तीन अलग-अलग प्रकारों में बैठने के लिए एक नया कोर्ट-"गन कोर्ट" बनाने का प्रभाव डाला। विभाजनः एक निवासी मजिस्ट्रेट का प्रभाग, एक पूर्ण न्यायालय

डिवीजन और एक सर्किट कोर्ट डिवीजन। इनमें से एक या दूसरा प्रभाग, कोशिश करने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ प्रदान किया गया था, अलग

आपराधिक अपराधों के अपराधियों की श्रेणियाँ। गुजरने से पहले

अधिनियम के, और के लागू होने की तारीख पर

संविधान, ये अपराध केवल एक से पहले संज्ञेय थे रेजिडेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट, या जमैका के सुप्रीम कोर्ट के सर्किट कोर्ट के समक्ष। गन कोर्ट एक्ट, *1974* भी लागू किया गया था।

पालन की जाने वाली प्रक्रिया *(*प्रत्येक प्रभाग में*)*।

अनधिकृत अपराधों से संबंधित कुछ निर्दिष्ट अपराधों के लिए

आग्नेयास्त्रों का कब्जा, अधिग्रहण या निपटान और

गोला-बारूद, "गन कोर्ट" को अनिवार्य रूप से कठिन श्रम पर निरोध की सजा देने की आवश्यकता थी। गवर्नर जनरल के निर्देश पर ही एक ड्यूटेन्यू का निर्वहन किया जा सकता था।

'

14

!

[2014] 10 एस सी आर।

56

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समीक्षा बोर्ड की सलाह के अनुसार कार्य करना। द.

समीक्षा बोर्ड बंदूक अदालत अधिनियम, *1974* के तहत एक गैर-न्यायिक निकाय था।

लार्ड डिप्लॉक ने हिंड्स मामले *(ऊपर)* में बहुमत के दृष्टिकोण को दर्ज करते हुए कहाः

...... जमैका के संविधान की व्याख्या को लागू करने की मांग में जो विशेष रूप से कहा गया है

अन्य संविधानों के बारे में मामले, ध्यान रखा जाना चाहिए न्यायिक तर्क के बीच अंतर जो निर्भर करता है

विशेष संविधान में उपयोग किए गए स्पष्ट शब्द

विचार और तर्क जो किस पर निर्भर करता है,

हालांकि व्यक्त नहीं किया गया है, फिर भी एक आवश्यक है

विषय से निहितार्थ-पदार्थ और इसकी संरचना संविधान और वे परिस्थितियाँ जिनमें यह था

बनाया गया। इस तरह की सावधानी विशेष रूप से मामलों में आवश्यक है। एक संघीय संविधान से निपटना जिसमें प्रश्न

तुरंत जारी किया गया हो सकता है कि कुछ हद तक इस पर निर्भर हो

घटक राज्य और आंशिक रूप से न्यायिक विभाजन पर संघ और एक घटक राज्य के बीच शक्ति।

फिर भी इन सभी संविधानों में दो बातें हैं

समान रूप से जिनका उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है व्याख्या। वे अपनी प्रकृति में मौलिक रूप से भिन्न हैं।

संसद द्वारा पारित सामान्य कानून

संप्रभु राज्य। वे मूर्त रूप धारण करते हैं जो सार में है और प्रतिनिधियों के बीच समझौता

सरकार के अंगों की संरचना के बारे में राज्य में राजनीतिक राय के विभिन्न रंग जिनके माध्यम से राज्य की संप्रभु शक्ति की प्रचुरता होनी है

भविष्य में प्रयोग करें। उन सभी पर बातचीत के साथ-साथ उस शाखा की परंपरा में पोषित व्यक्तियों द्वारा मसौदा तैयार किया गया था। इंग्लैंड के सामान्य कानून का जो जनता से संबंधित है

कानून और विशेष रूप से ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन की मूल अवधारणा से परिचित।

विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण

इसे के अलिखित संविधान में विकसित किया गया था

यूनाइटेड किंगडम। जहाँ तक उनके विषय-वस्तु की बात है, लोग

जिनके लिए नए संविधान प्रदान किए जा रहे थे

पहले से ही सार्वजनिक कानून की एक प्रणाली के तहत रह रहे हैं जिसमें

स्थानीय संस्थान जिनके माध्यम से सरकार चलती थी, विधायिका, कार्यपालिका और अदालतों ने प्रतिबिंबित किया

एक ही मूल अवधारणा। नए संविधान, विशेष रूप से

एकात्मक राज्यों के मामले में, विकासवादी नहीं थे

क्रांतिकारी। उन्होंने सरकार की निरंतरता का प्रावधान किया

उत्तराधिकारी संस्थानों, विधायी, कार्यपालिका और

न्यायिक, जिसमें से सदस्यों का चयन किया जाना था

अलग-अलग तरीके से, लेकिन प्रत्येक संस्थान को शक्तियों का प्रयोग करना था, जो यद्यपि विस्तारित थे, लेकिन समान चरित्र के बने रहे।

उन लोगों के लिए जो संबंधित द्वारा प्रयोग किए गए थे

संस्था जिसे इसने बदल दिया था।

इस वजह से बहुत कुछ हो सकता है, और मसौदा तैयार करने में

अभ्यास अक्सर आवश्यक निहितार्थ के लिए छोड़ दिया जाता है एक सरकार के नए संविधान में अपनाना

संरचना जो एक विधानमंडल के लिए प्रावधान करती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह माना जाता है कि

शक्तियों के पृथक्करण का मूल सिद्धांत लागू होगा

सरकार के इन तीन अंगों द्वारा अपने-अपने कार्यों का अभ्यास करना। इस प्रकार संविधान सामान्य रूप से ऐसा नहीं करता है के अभ्यास पर कोई स्पष्ट निषेध शामिल है

कार्यपालिका या न्यायिक शक्तियों द्वारा विधायी शक्तियाँ

या तो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा। इस संबंध में

न्यायपालिका, विशेष रूप से यदि यह इरादा है कि पहले

मौजूदा अदालतें काम करना जारी रखेंगी, संविधान

स्वयं भी प्रदान करने वाले किसी भी स्पष्ट प्रावधान को छोड़ सकता है

न्यायपालिका पर न्यायिक शक्ति। फिर भी यह अच्छा है

लागू होने वाले निर्माण के नियम के रूप में स्थापित

संवैधानिक साधन जिनके तहत यह सरकार

संरचना को अपनाया जाता है कि व्यक्त शब्दों की अनुपस्थिति

वह प्रभाव विधायी, कार्यपालिका को नहीं रोकता है

और नए राज्य की न्यायिक शक्तियां प्रयोग करने योग्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. हैं।

विशेष रूप से विधायिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा और न्यायपालिका द्वारा। संवैधानिक रूप से लागू करने की कोशिश करना

सिविल कानून, उनके लॉर्डशिप के विचार में, भ्रामक होगा - विशेष रूप से वे जो कर लगाने वाले कानूनों पर लागू होते हैं जिनके बारे में यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है जो शब्दों को व्यक्त करता है

विषय पर आरोप लगाने की आवश्यकता थी।

परिणाम में उन सभी में देखा जा सकता है

संविधान जिनका उद्गम किसी अधिनियम में है

वेस्टमिंस्टर में शाही संसद या किसी आदेश में

परिषद, ड्राफ्टमैनशिप का एक सामान्य पैटर्न और शैली

जिसे आसानी से वेस्टमिंस्टर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

मॉडल '। जमैका के संविधान के उन स्पष्ट प्रावधानों की ओर मुड़ने से पहले जिन पर अपीलार्थी भरोसा करते हैं

इन अपीलों, उनके प्रभुता कुछ सामान्य बना देंगे

वेस्टमिंस्टर मॉडल का पालन करने वाले संविधानों की व्याख्या के बारे में अवलोकन।

वेस्टमिंस्टर मॉडल पर सभी संविधान विधायिका के साथ अलग-अलग अध्याय शीर्षकों के तहत सौदा करते हैं,

कार्यपालिका और न्यायपालिका। से संबंधित अध्याय

न्यायपालिका में निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रावधान होते हैं -

नियुक्ति की विधि और कार्यकाल की सुरक्षा न्यायपालिका के सदस्य जो आश्वस्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं

उन्हें अन्य दो से स्वतंत्रता की एक डिग्री

सरकार की शाखाएँ। जैसा कि सीलोन के संविधान के मामले में है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। विभिन्न न्यायालयों के बीच न्यायिक शक्ति की प्रचुरता के वितरण के बारे में संविधान खुद जिस हद तक चुप है, यह निहित है कि यह दोनों के बीच वितरित किया जाता रहेगा।

और उन न्यायालयों द्वारा प्रयोग किया जाता है जो पहले से ही अस्तित्व में थे जब नया संविधान लागू हुआ था; लेकिन

विधायिका, कानून बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए

राज्य की 'शांति, व्यवस्था और अच्छी सरकार', आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *59*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

नए न्यायालयों की स्थापना और उन्हें अधिकार क्षेत्र के पूरे या हिस्से के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करना।

एक मौजूदा अदालत द्वारा पहले से प्रयोग किया जा सकता है। हालाँकि, संविधान की संरचना में क्या निहित है

वेस्टमिंस्टर मॉडल वह न्यायिक शक्ति है, हालांकि यह

विभिन्न न्यायालयों के बीच समय-समय पर वितरित किया जाता है

में निर्धारित तरीके और शर्तों पर कार्यालय न्यायपालिका से संबंधित अध्याय, भले ही यह नहीं है

संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है *(* लियानगे बनाम। आर. *[1966] 1* सभी ई. आर. *650 658* पर, *[1967]* ए. सी. *259 287,288* पर*)*। वेस्टमिंस्टर मॉडल पर हाल के संविधानों में, उनके पहले के प्रोटोटाइप के विपरीत, एक अध्याय शामिल है।

मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं से निपटना। द.

इस अध्याय के प्रावधान मूल कानून का हिस्सा हैं।

राज्य का और जब तक कुछ भी विशेष द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है

इस उद्देश्य के लिए संविधान में प्रक्रिया निर्धारित की गई है,

विधायिका द्वारा अभ्यास पर एक बंधन लागू करना,

कार्यपालिका और उनकी न्यायपालिका की पूर्णता

संबंधित शक्तियाँ। के शेष अध्याय

सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से विधायी, कार्यकारी या न्यायिक शक्तियों की प्रचुरता का प्रयोग करने के लिए-उनकी योग्यताएँ विधायी, कार्यपालक या न्यायिक कार्यालय के लिए, के तरीके

उनका चयन, उनका कार्यकाल, जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना है जिसमें व्यक्तियों के एक वर्ग को शक्तियां प्रदान की जाती हैं

सामूहिक रूप से कार्य करना और इसके लिए आवश्यक बहुमत

उन शक्तियों का प्रयोग करें। इस प्रकार, जहाँ एक संविधान पर

वेस्टमिंस्टर मॉडल एक विशेष 'अदालत' की बात करता है जो पहले से ही अस्तित्व में है जब संविधान आता है

यह इस अभिव्यक्ति का उपयोग उन सभी व्यक्तिगत न्यायाधीशों के सामूहिक विवरण के रूप में करता है जो, चाहे अकेले बैठे हों या

अन्य न्यायाधीशों के साथ या एक जूरी के साथ, संविधान सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के समक्ष उस न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के हकदार हैं।

लागू हुआ। संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान

उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या कार्यकाल की सुरक्षा के लिए बाद में सभी व्यक्तिगत न्यायाधीशों पर लागू होगा।

समान अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त, उस 'न्यायालय' को जो भी अन्य नाम दिया जा सकता है जिसमें वे बैठते हैं *(*अटॉर्नी-जनरल फॉर ओंटारियो *v.* अटॉर्नी-कनाडा के लिए जनरल*) [19251* ए. सी. *750*।

जहाँ, वेस्टमिंस्टर पर एक संविधान के तहत

मॉडल, संसद द्वारा एक कानून बनाया जाता है जिसका उद्देश्य है

एक नए नाम से वर्णित न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करें,

सवाल यह है कि क्या कानून न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित संविधान के प्रावधानों के साथ टकराव करता है।

शक्ति लेबल पर निर्भर नहीं करती है *(*तत्काल मामले में*)*

*'*गन कोर्ट *')* जिसे संसद न्यायाधीशों को उनके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय संलग्न करती है।

उस कानून द्वारा जिसकी संवैधानिकता विवादित है। यह वह है

कानून का सार जिसे माना जाना चाहिए, न कि रूप। द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति क्या है जिन न्यायाधीशों को उस न्यायालय की रचना करनी है जिससे नया लेबल जुड़ा हुआ है*?* उनकी नियुक्ति का तरीका क्या है*?*

और उनके कार्यकाल की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप है।

उन न्यायाधीशों पर लागू होने वाले संविधान का, जो उस समय

संविधान लागू हुआ, उस प्रकृति के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया*? (* अटॉर्नी-ऑस्ट्रेलिया के लिए जनरल बनाम। आर. और

बॉयलरमेकर्स सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, *[1957]* ए. सी. *288,309*

310) .

XXX

XXX

XXX

...... तो यह तय करने में कि क्या किसी कानून के कोई प्रावधान हैं

जमैका की संसद द्वारा एक साधारण कानून के रूप में पारित किया गया जमैका के संविधान के साथ असंगत है, न तो जमैका की अदालतें और न ही उनके लॉर्डशिप बोर्ड हैं।

विवादित कानून की औचित्य या समीचीनता से संबंधित। वे केवल इस बात से चिंतित हैं कि क्या वे

प्रावधान, हालांकि उचित और समीचीन हैं, ऐसा चरित्र कि वे एक मजबूत आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन के साथ संघर्ष करते हैं।

भारत संघ *61*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

संविधान का प्रावधान और इसलिए वैध रूप से पारित किया जा सकता है

प्रावधान "। प्रिवी काउंसिल द्वारा जांच किए गए प्रश्न में

ऊपर व्यक्त तथ्यात्मक/कानूनी स्थिति का आधार था

निम्नलिखित शब्दों में निर्दिष्ट किया गयाः

"पूर्ण न्यायालय प्रभाग की संवैधानिकता पर हमला गन कोर्ट दो आधारों पर आधारित हो सकता है। सबसे पहले

यह है कि गन कोर्ट एक्ट *1974* एक अदालत को प्रदान करने का इरादा रखता है

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य और नियुक्त व्यक्ति अदालत। दूसरा आधार बहुत कम मौलिक है। यह.

केवल संक्षेप में उल्लेख करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह केवल तभी उत्पन्न होता है जब पहला

जमीन विफल हो जाती है। यह है कि भले ही अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया हो तीन निवासियों से युक्त एक पूर्ण न्यायालय प्रभाग पर

मजिस्ट्रेट वैध हैं, संविधान की धारा *112*

यह आवश्यक है कि निवासी मजिस्ट्रेट का कोई भी कार्य

आयोग और *1974* के अधिनियम के रूप में मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं प्रदान करता है "।

ई प्रश्न के साथ निम्नलिखित रूप में राय दी गई थीः

"संविधान का अध्याय *VII*, 'न्यायपालिका' था

उनके लॉर्डशिप के दृष्टिकोण से निपटने का इरादा है सभी व्यक्तियों की नियुक्ति और कार्यकाल की सुरक्षा

कोई भी वेतनभोगी पद जिसके वे हकदार हैं

जमैका में नागरिक या आपराधिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। इसके लिए

उद्देश्य उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः *((i)* उच्चतर

न्यायपालिका, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अपील न्यायालय के न्यायाधीश, और *(ii)* निचली न्यायपालिका,

जिसमें धारा *112 (2)* में वर्णित लोग शामिल हैं। *:*

रेजिडेंट मजिस्ट्रेट, यातायात न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, न्यायालय के पंजीयक

अपील और जमैका के न्यायालयों से जुड़े ऐसे अन्य कार्यालय, जो इस संविधान के प्रावधानों के अधीन हों, संसद द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

अपील न्यायालय के न्यायाधीश और पंजीयक के कार्यालयों के अलावा, जो नए थे, ये दो श्रेणियां हैं।

न्यायपालिका के सभी वेतनभोगी सदस्यों को गले लगाया जिन्होंने

तारीख में जमैका में नागरिक या आपराधिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया

जब संविधान लागू हुआ। एक लघु अधिकार क्षेत्र,

विशेष रूप से किशोरों के संबंध में, द्वारा प्रयोग किया गया था

शांति के न्यायाधीश लेकिन, इंग्लैंड की तरह, वे केवल अंशकालिक रूप से बैठे थे, अवैतनिक थे और उनके पास कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं थी।

पेशेवर योग्यता।

दोनों श्रेणियों के लिए सामान्य, के अपवाद के साथ

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति

अपील न्यायालय की, इसके तहत आवश्यकता है संविधान कि उन्हें न्यायिक की सिफारिश पर गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए

सेवा आयोग-धारा के तहत स्थापित एक निकाय *111* जिनकी संरचना लोक सेवा आयोग से अलग है और इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनके होने की संभावना है -

उच्च न्यायपालिका और निचली न्यायपालिका के बीच अंतर यह है कि उच्च न्यायपालिका को अधिक डिग्री दी जाती है कार्यकाल की सुरक्षा बाद वाले की तुलना में। संविधान में निचली न्यायपालिका की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं है।

संसद द्वारा साधारण कानून पारित करना *(क)* उनके पद को समाप्त करना

(ख) कार्यालय में रहते हुए उनके वेतन को कम करना या *(ग)*

यह प्रावधान करते हुए कि न्यायिक पद पर उनकी नियुक्तियां केवल वर्षों की एक छोटी निश्चित अवधि के लिए होंगी। उनकी स्वतंत्रता

राजनीतिक दल की अच्छी इच्छा जो एक नंगे आदेश देती है

इस प्रकार संसद में बहुमत पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। एकमात्र

धारा *112* द्वारा उन्हें जो सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है, वह यह है कि आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *63*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

उन्हें हटाया या अनुशासित नहीं किया जा सकता है सिवाय इसके कि

न्यायिक सेवा आयोग की सिफारिश

प्रिवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार। यह अंतिम एक स्थानीय है संविधान की धारा *82* के तहत स्थापित निकाय

जिनके सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है-जनरल

प्रधानमंत्री के साथ परामर्श करने और पद धारण करने के बाद तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं।

इसके विपरीत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और

अपील न्यायालय को अधिक मजबूती से निहित किया गया है

कार्यकाल की सुरक्षा। वे घेराबंदी द्वारा संरक्षित हैं संसद द्वारा पारित किए जाने के विरुद्ध संविधान के प्रावधान

साधारण कानून *(ए)* उनके पद को समाप्त करना *(बी)* उनके पद को कम करना पद पर रहते हुए वेतन या *(ग)* यह प्रावधान करते हुए कि उनका कार्यकाल *65* वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले समाप्त हो जाएगा। कार्यालय में रहते हुए वे किसी भी अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन नहीं होते हैं।

उन्हें केवल उनकी सलाह पर ही पद से हटाया जा सकता है।

में महामहिम की प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति

यूनाइटेड किंगडम पर किए गए एक संदर्भ पर दिया गया

जांच के एक न्यायाधिकरण की सिफारिश जिसमें

ऐसे व्यक्ति जो कुछ क्षेत्रों में उच्च न्यायिक पद धारण करते हैं या रखते हैं

राष्ट्रमंडल का हिस्सा।

इन प्रावधानों का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि सभी

जो जमैका में कोई वेतनभोगी न्यायिक पद रखते हैं, वे

न्यायपालिका की सिफारिश पर नियुक्त किया जाए सेवा आयोग और उनसे उनकी स्वतंत्रता

संसद या कार्यपालिका द्वारा राजनीतिक दबाव

उनके न्यायिक कार्यों के प्रयोग का आश्वासन दिया जाएगा उन्हें उनके कार्यकाल में इस तरह की सुरक्षा प्रदान करना

कार्यालय जैसा कि अधिकार क्षेत्र के महत्व द्वारा उचित है

कि वे व्यायाम करते हैं। उच्च न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों के लिए उपयुक्त कार्यकाल की सुरक्षा और निम्न न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों के लिए उपयुक्त सुरक्षा के बीच एक स्पष्ट अंतर किया जाता है।

न्यायपालिका।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

उनके अधिपति यह स्वीकार करते हैं कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसद को एक द्वारा स्थापित करने से रोक सके सामान्य कानून एक नए नाम के तहत एक अदालत, जैसे

"राजस्व न्यायालय, "उस अधिकार क्षेत्र के हिस्से का प्रयोग करने के लिए जिसका प्रयोग उच्च न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा या द्वारा किया जा रहा था

उस समय निचली न्यायपालिका के सदस्य जब संविधान लागू हुआ। ऐसा करना केवल परिवर्तन करना है।

लेबल को उस क्षमता से जोड़ा जाना है जिसमें

नए न्यायालय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति

धारकों द्वारा पहले प्रयोग किए गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें अध्याय *VII* में नामित न्यायिक कार्यालयों में से एक या दूसरे का

संविधान से। हालाँकि, उनके लॉर्डशिप्स के विचार में, यह संविधान का स्पष्ट इरादा है कि कोई भी व्यक्ति

ऐसे न्यायालय का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए

उसी तरीके से नियुक्त और उसी के हकदार

संविधान के अध्याय *VII* में नामित न्यायिक पद के धारक के रूप में कार्यकाल की प्रतिभूति जो उसे संविधान के लागू होने के समय संबंधित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देती है।

उनके अधिपति महान्यायवादी को किसी भी नए न्यायालय के वेतनभोगी न्यायाधीशों को स्वीकार करने के लिए समझते हैं कि

संसद को एक साधारण कानून द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए

रीति से नियुक्त और प्रतिभूति के हकदार निम्न न्यायपालिका के सदस्यों के लिए प्रदान किया गया कार्यकाल

संविधान की धारा *112*। उनके प्रभुओं के दृष्टिकोण में यह

रियायत देना सही था। परिचित शब्दों को अपनाना

अटॉर्नी-जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाम में विस्काउंट सिमंड्स द्वारा उपयोग किया गया। आर. और बॉयलरमेकर्स सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया *[1957]* ए. सी. *288* , *309-310* , अगर संसद पहले अधिकार क्षेत्र का हस्तांतरण कर सकती है तो यह संविधान का मजाक बन जाएगा।

में नामित न्यायिक कार्यालयों के धारकों द्वारा प्रयोग करने योग्य

जिन कार्यालयों से कुछ अलग नाम जुड़ा हुआ था और यह प्रावधान करें कि नए न्यायिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को

तरीके और शर्तों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा

सदस्यों की नियुक्ति के लिए अध्याय *VII* में विहित *65*

आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ

[जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

न्यायपालिका से। अगर ऐसा होता तो

संसद को पूरे हस्तांतरण से रोकने के लिए कुछ भी नहीं

जमैका की न्यायिक शक्ति *(*दो मामूली अपवादों के साथ*)*

न्यायपालिका के सदस्य नहीं होने के कारण, 'नहीं होगा अध्याय *VII* के संरक्षण के हकदार हैं।

महान्यायवादी जो स्वीकार नहीं करते हैं वह यह है कि

संसद को अध्याय *VII* द्वारा स्थानांतरण से प्रतिबंधित किया गया है।

विधिवत नियुक्त सदस्यों से बना न्यायालय

निम्न न्यायपालिका क्षेत्राधिकार जो, उस समय

संविधान लागू हुआ, केवल एक द्वारा प्रयोग किया गया था

उच्च न्यायालय के विधिवत नियुक्त सदस्यों से बना न्यायालय

न्यायपालिका।

उनके लॉर्डशिप्स के दृष्टिकोण में धारा *110*

संविधान यह स्पष्ट करता है कि धारा में उपबंध करते हुए *103 (1)* वहः *'*जमैका के लिए एक अपील न्यायालय होगा

*'*ड्राफ्ट्समैन ने शब्दों के इस रूप को ले जाने वाला माना

इसके साथ आवश्यक निहितार्थ से कि न्यायालय के न्यायाधीश

धारा *103* के तहत स्थापित किया जाना आवश्यक है

सभी महत्वपूर्ण सिविल में एक अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें

मामलों और सभी गंभीर आपराधिक मामलों में; और यह कि शब्द

जिसका पालन होता है, अर्थात *'*। जिसकी ऐसी अधिकारिता होगी और

इस संविधान द्वारा उसे जो शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं

या कोई अन्य कानून, 'संसद को एक साधारण द्वारा हकदार नहीं बनाता है

अपील न्यायालय को एक महत्वपूर्ण भाग से वंचित करने के लिए कानून ऐसी अपीलीय अधिकारिता या इसे उन न्यायाधीशों को प्रदान करना जो ऐसा करते हैं

कार्यकाल की सुरक्षा का आनंद नहीं लेते हैं जो संविधान

अपील न्यायालय के न्यायाधीशों को गारंटी। धारा *110*

(1) संविधान जो वादियों को व्यापक अधिकार प्रदान करता है परिषद में महामहिम से अपील की लेकिन केवल

*'*अपील न्यायालय के निर्णय, 'स्पष्ट रूप से इस पर आगे बढ़ते हैं धारा *103*, धारा *110* के प्रभाव के बारे में धारणा

यदि इसका व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार है तो इसे निरर्थक बना दिया जाएगा।

एक साधारण द्वारा अपील न्यायालय से हटाया जा सकता है

संविधान के संशोधन के बिना कानून।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

उनके प्रभुत्त्वों को ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि ऐसा ही क्यों है

धारा *97* के संबंधित शब्दों से निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। जमैका का अपील न्यायालय था

1880 से। उस न्यायालय के न्यायाधीशों में वह सारा अधिकार क्षेत्र जमैका में निहित किया गया था जो उनके लॉर्डशिप्स का दृष्टिकोण एक अदालत की विशेषता थी जिसके लिए *1962* में 'एक सर्वोच्च न्यायालय' का वर्णन उपयुक्त था।

न्यायालयों के एक पदानुक्रम में जो एक अलग को शामिल करना था

'अपील का न्यायालय '। तीन प्रकार की अधिकारिता जो उच्चतम न्यायालय की विशेषता है जहाँ अपीलीय अधिकारिता एक अलग अदालत में निहित हैः *(1)* असीमित

सभी महत्वपूर्ण दीवानी मामलों में मूल अधिकारिता; *(2)* सभी गंभीर आपराधिक अपराधों में असीमित मूल अधिकार क्षेत्र; *(3)* कार्यवाही पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र।

निचली अदालतों (अर्थात। उस प्रकार का जो अपनी उत्पत्ति का श्रेय सर्टिओरारी, मैंडमस और के विशेषाधिकार रिटों को देता है

निषेध)।

संविधान की उस धारा *97 (1)* का उद्देश्य जमैका में एक सर्वोच्च न्यायालय को संरक्षित करना था जो इसका प्रयोग करता है।

परिषद *1962* में जमैका (संविधान) आदेश, कि 'सुप्रीम कोर्ट तुरंत पहले अस्तित्व में है

इस आदेश का प्रारंभ संविधान के प्रयोजनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होगा। यह बनाया गया है

(1) परिषद में आदेश का, और पुष्टि करता है कि शब्दों में संदर्भित न्यायालय का प्रकार 'एक सर्वोच्च होगा 'कोर्ट फॉर जमैका' एक ऐसा न्यायालय था जो जमैका में सर्वोच्च न्यायालय की विशेषता वाले तीन प्रकार के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा जो ऊपर बताए गए हैं।

आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *67*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

यदि, जैसा कि महान्यायवादी द्वारा प्रतिवाद किया गया है, धारा *97 (1)* में ऊपर दिए गए शब्दों को संसद द्वारा एक

इसके अलावा दीवानी और आपराधिक मामलों में स्पष्ट रूप से धारा *25* और धारा *44* द्वारा उसे जो कुछ दिया गया है, वह ऐसी सीमित अधिकारिता वाला न्यायालय होगा कि -

यदि इसके सभी अधिकार क्षेत्र *(*उन दो अपवादों के साथ*)* थे अन्य न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से प्रयोग किया जा सकता है

निचली न्यायपालिका के सदस्य। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण, इसके लिए

इस मामले का सार है, व्यक्तिगत नागरिक कर सकता है सुरक्षा से वंचित किया जाए, जिसके निर्माता

संविधान को आवश्यक माना जाता है, जो महत्वपूर्ण है

उसकी नागरिक या आपराधिक जिम्मेदारियों को प्रभावित करने वाले प्रश्न एक अदालत द्वारा निर्धारित, हालांकि नामित, से बना

ऐसे न्यायाधीश जिनके द्वारा सभी स्थानीय दबावों से स्वतंत्रता

संसद या कार्यपालिका द्वारा गारंटी दी गई थी

निचले न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से अधिक पूर्ण कार्यकाल की सुरक्षा।

इसलिए उनके अधिपति यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि

धारा *97 (1)* के शब्द, जिन पर अधिवक्ता

जनरल एक साधारण कानून द्वारा संसद को निहित करने के लिए निर्भर करता है, हकदार बनाता है

निचली न्यायपालिका के सदस्यों से बनी एक नई अदालत में

एक अधिकार क्षेत्र जो असीमित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है

सिविल, आपराधिक या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार जो विशिष्ट है

एक *'*सर्वोच्च न्यायालय*'* का और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया था

उस समय जमैका का न्यायालय जब संविधान आया था

बल में, किसी भी दर पर जहां इस तरह के निहित सहायक प्रावधानों के साथ है, जैसे कि धारा में निहित

6 (1) गन कोर्ट एक्ट *1974*, जिसका परिणाम यह होगा कि सभी मामले इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं

नए न्यायालय को व्यवहार में सुना और निर्धारित किया जाएगा

इसके बजाय न्यायाधीशों से बने न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट।

XXXX

XXXX

XXXX सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

उनके लॉर्डशिप्स के दृष्टिकोण में *1974* के प्रावधान

अधिनियम, जहाँ तक वे एक पूर्ण की स्थापना के लिए प्रदान करते हैं

गन कोर्ट का कोर्ट डिवीजन जिसमें तीन निवासी शामिल हैं मजिस्ट्रेट, संविधान के अध्याय *VII* के साथ संघर्ष करते हैं और तदनुसार धारा *2* के आधार पर अमान्य हैं।

XXXX

XXXX

XXXX

इस प्रकार संसद, अपने विधान के अभ्यास में

शक्ति, उस पर सीमाएँ अधिरोपित करने वाला कानून बना सकता है न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीशों का विवेकाधिकार

जिन पर उस कानून के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चलाया जाता है ताकि किसी व्यक्तिगत अपराधी को हिरासत की सजा दी जा सके।

उसकी विशेष परिस्थिति में अपराधी के आचरण की गंभीरता के बारे में न्यायाधीश के अपने मूल्यांकन को दर्शाता है।

मामला। संसद क्या नहीं कर सकती, लगातार

शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका से किसी भी कार्यकारी निकाय में हस्तांतरण करना है जिसके सदस्य नियुक्त नहीं किए जाते हैं।

संविधान के अध्याय *VII* के तहत, दी जाने वाली सजा की गंभीरता को निर्धारित करने का विवेकाधिकार

अपराधियों के एक वर्ग के एक व्यक्तिगत सदस्य पर। जबकि

कोई भी यह सुझाव नहीं देगा कि गन कोर्ट एक्ट *1974* की धारा *22* में दिए गए प्रावधानों के अनुसार गठित एक समीक्षा बोर्ड

अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी और निष्पक्षता से पालन न करने पर, तथ्य यह है कि इसके अधिकांश सदस्य व्यक्ति नहीं हैं

न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संविधान द्वारा योग्य।

संवैधानिक प्रतिबंध के उल्लंघन को विधायी शक्ति के अच्छे इरादों से माफ नहीं किया जाता है।

विशेष कानून द्वारा पार किया गया। यदि, लगातार

संविधान, संसद के लिए यह अनुमति है कि वह समीक्षा बोर्ड के रूप में गठित निकाय पर आपराधिक अपराधों के लिए अभिरक्षा दंड की अवधि निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्रदान करे, यह समान रूप से अनुमति होगी -

कम सुविचारित संसद किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को समान विवेकाधिकार प्रदान करती है जो न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए योग्य नहीं है, और इस तरह से।

संविधान के किसी भी संशोधन के बिना, मद्रास बार एसोसिएशन को खोलने के लिए *v.*

भारत संघ *69*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

कार्यपालिका द्वारा मनमाना शक्ति के प्रयोग के लिए द्वार

आपराधिक कानून का पूरा क्षेत्र।

XXXX

XXXX

XXXX

उनके प्रभुत्त्वों का मानना होगा कि के प्रावधान

गवर्नर के दौरान हिरासत-जनरल की खुशी और समीक्षा बोर्ड से संबंधित धारा *22* के प्रावधान हैंः

संविधान के लागू होने के बाद बनाया गया कानून

जो संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत है

शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित। वे तदनुसार हैं

संविधान की धारा *2* के आधार पर शून्य। *'*

(ii) इसी क्रम में, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील

उद्धृत निर्णय। प्रिवी काउंसिल के समक्ष मामले में सभी *11* अपीलार्थियों पर एक अपराध से उत्पन्न होने वाले अपराधों का आरोप लगाया गया था। *27.1.1962* पर असफल तख्तापलट। उक्त तख्तापलट का तथ्य, सीलोन सरकार द्वारा *13.2.1962* पर जारी एक श्वेत पत्र में निर्धारित किया गया था। श्वेत पत्र ने नाम दिए

13 अपीलार्थियों सहित कथित षड्यंत्रकारी। द व्हाइट

पत्र ने यह टिप्पणी करते हुए निष्कर्ष निकाला कि एक निवारक दंड उन सभी पर एक गंभीर चरित्र थोपा जाना चाहिए जो दोषी थे। आई. डी. *1* पर आपराधिक कानून *(* विशेष प्रावधान *)* अधिनियम, *1962* का संख्या *1* पारित किया गया था। इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था

1.1.1962 . यह उन लोगों तक सीमित था जो थे

27.1.1962 पर या उसके आसपास राज्य के खिलाफ अपराधों का अभियुक्त।

उपरोक्त अधिनियम ने अपीलार्थियों के कारावास को वैध बना दिया, जबकि

वे मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसने दंड संहिता की एक धारा को संशोधित किया,

ताकि असफल तख्तापलट की परिस्थिति से निपटने के लिए एक नया अपराध, पूर्व कार्योत्तर रूप से लागू किया जा सके। इसने पूर्व पोस्ट फैक्टो को बदल दिया,

अभियुक्त द्वारा किए गए समझौतों के संबंध में साक्ष्य का कानून,

हिरासत में रहते हुए। इसने एक न्यूनतम सजा लागू की,

संपत्ति की जब्ती के साथ, उन अपराधों के लिए जिनके लिए अपीलार्थियों पर मुकदमा चलाया गया था। आपराधिक की धारा *440* ए के तहत

प्रक्रिया संहिता, राजद्रोह के मामले में मुकदमा, *[2014] 10* एस. सी. आर. को निर्देशित किया जा सकता है।

जूरी के बिना तीन न्यायाधीशों के सामने रहें। तत्काल प्रावधान को उपरोक्त अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, ताकि इसे उन अपराधों तक बढ़ाया जा सके जिनके लिए अपीलकर्ताओं पर आरोप लगाया गया था। उपरोक्त अधिनियम की धारा *9* के तहत, न्याय मंत्री को अधिकार दिया गया था -

तीन न्यायाधीशों को नामित करें। धारा *9* के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय मंत्री ने तीन न्यायाधीशों को नामित किया था।

अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई आपत्ति, कि धारा *9* अल्ट्रा थी सीलोन के संविधान का अधिकार है, और यह कि, नामांकन था

अमान्य है। इसके बाद, आपराधिक विधि अधिनियम, *1962* का सं. *31* पारित किया गया। इसने पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा *9* को निरस्त कर दिया। इसमें संशोधन किया गया नामांकन की शक्ति, उस में, शक्ति को प्रदान किया गया था

मुख्य न्यायाधीश। अपीलार्थियों की अपील पर, के विरुद्ध

अधिनियम के तहत नामित तीन न्यायाधीशों के न्यायालय के समक्ष उनके मुकदमे से दोषसिद्धि और सजा, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आपराधिक

विधि *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1962* का सं. *1*, साथ ही

आपराधिक विधि अधिनियम, *1962* का सं. *31,* दो कारणों से अमान्य था। सबसे पहले, सीलोन के संविधान के तहत, एक था

शक्तियों का पृथक्करण। न्यायपालिका की शक्ति, जबकि संविधान खड़ा था, द्वारा हड़पा या उल्लंघन नहीं किया जा सकता था कार्यपालिका या विधायिका। दूसरा, दांडिक विधि *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1962* का सं. *1,* साथ ही दांडिक

होमिनेम, और पूर्व पोस्ट फैक्टो, ने आवश्यक रूप से न्यायिक का उल्लंघन किया शक्ति, फिर भी वर्तमान मामले में इस तरह का उल्लंघन था, द्वारा

उपरोक्त दो अधिनियम। उपरोक्त निष्कर्षों के अलावा, यह भी माना गया कि परिषद *1946* में सीलोन संविधान आदेश और सीलोन स्वतंत्रता अधिनियम, *1947* का संयुक्त प्रभाव था

सीलोन संसद को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य की पूर्ण विधायी शक्तियां देने का इरादा था और इसके परिणामस्वरूप।

नतीजतन, सीलोन संसद की विधायी शक्ति,

कानून पारित करने में असमर्थता से सीमित नहीं था, जो आहत करता था

न्याय के मूल सिद्धांत। प्रिवी काउंसिल ने उपरोक्त विवाद की जांच करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः

रायः

*"*हालाँकि, सीलोन में स्थिति अलग थी। संप्रभुता के परिवर्तन ने अपने आप में कोई परिणाम नहीं दिया

न्यायपालिका के घटकों या कार्यप्रणाली में स्पष्ट परिवर्तन। जहाँ तक न्यायालयों का संबंध है, उनके नए संविधान से अप्रभावित काम जारी रहा, और

जिन अध्यादेशों के तहत वे कार्य करते थे, वे लागू रहे। सीलोन में न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई थी

1833 में न्याय का चार्टर। चार्टर का खंड *4* पढ़ता हैः

*"*और न्याय के प्रशासन के लिए प्रावधान करना इसके बाद हमारे उक्त द्वीप में हमारी इच्छा और खुशी है, और हम इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि

न्याय, दीवानी और आपराधिक प्रशासन, विशेष रूप से स्थापित न्यायालयों में निहित किया जाएगा और

यह हमारे चार्टर द्वारा गठित है। और यह हमारा है।

हमारे उक्त राज्यपाल के लिए सक्षम नहीं होगा उसके द्वारा बनाई गई किसी विधि या अध्यादेश द्वारा, उसकी विधान परिषद की सलाह से, या

अन्यथा चाहे जो भी हो, किसी भी मामले में न्याय प्रशासन के लिए किसी भी न्यायालय का गठन या स्थापना करना। सिविल या आपराधिक, इसके बाद के रूप में स्पष्ट रूप से सहेजा और प्रदान किया गया है।

खंड *5* ने उच्चतम न्यायालय की स्थापना की और खंड *6* ए मुख्य न्यायाधीश और दो कनिष्ठ न्यायाधीश। खंड *7* ने दिया कि

राज्यपाल को अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्तियाँ। वहाँ

प्रशासनिक संबंध में कई खंडों का पालन करें,

प्रक्रियात्मक और क्षेत्राधिकार संबंधी मामले। लगभग आधी सदी बाद के अध्यादेश *(*विशेष रूप से न्यायालय अध्यादेश*)*

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया को जारी रखा।

इसके तहत अदालतों ने लगातार काम किया है

आज का दिन।

XXX

XXX

XXX

संविधान महत्वपूर्ण रूप से भागों में विभाजित है -

" भाग *2* गवर्नर-जनरल, *"*भाग *3* विधानमंडल*"*, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

" भाग *4* चुनावी जिलों का परिसीमन, भाग *5*

कार्यकारी, *"*भाग *6* न्यायपालिका*"*, *"*भाग *7* लोक सेवा*"*, भाग *8* वित्त। और हालांकि कोई एक्सप्रेस नहीं

न्यायपालिका में वह न्यायिक शक्ति निहित करने का उल्लेख किया गया है जो उसके पास पहले से थी और जो वह अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग कर रही थी।

न्यायालय अध्यादेश के तहत प्रक्रिया, न्यायिक द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भाग *6* के तहत प्रावधान है।

सेवा आयोग जिसमें कोई सदस्य नहीं होगा

कोई भी सदन, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से बना होगा

और एक न्यायाधीश और एक अन्य व्यक्ति जो न्यायाधीश है या रहा होगा। किसी भी निर्णय को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास कमीशन को आपराधिक अपराध बना दिया जाता है। वहाँ भी है

प्रावधान है कि दोनों सदनों के अभिभाषण पर गवर्नर-जनरल के अलावा न्यायाधीश हटाने योग्य नहीं होंगे।

ये प्रावधान न्यायपालिका को राजनीतिक, विधायी और सामाजिक स्वतंत्रता से सुरक्षित करने के इरादे को प्रकट करते हैं।

कार्यकारी नियंत्रण। वे पूरी तरह से उपयुक्त हैं

संविधान जिसका आशय है कि न्यायिक शक्ति केवल न्यायपालिका में निहित होगी। वे अनुचित होंगे।

एक संविधान में जिसके द्वारा यह अभिप्रेत था कि न्यायिक

कार्यपालिका या विधायिका द्वारा शक्ति साझा की जानी चाहिए। न्यायपालिका के निहित होने के बारे में संविधान की खामोशी

शक्ति अपने शेष के अनुरूप है, जहाँ वह पड़ी थी।

एक सदी से अधिक समय तक, न्यायपालिका के हाथों में। यह किसी भी इरादे के अनुरूप नहीं है कि अब से इसे करना चाहिए।

कार्यपालिका या विधायिका को पारित करना या उसके द्वारा साझा किया जाना।

अपीलार्थियों के वकील विचाराधीन अधिनियमों पर अपने हमले को संक्षेप में संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। पहला अधिनियम पूरी तरह से गलत था क्योंकि यह न्यायपालिका के लिए एक विशेष निर्देश था कि उन विशेष कैदियों के मुकदमे के बारे में जिनकी पहचान की जा सकती थी *(श्वेत पत्र को देखते हुए)* और जिन पर विशेष रूप से आरोप लगाए गए थे।

किसी विशेष अवसर पर अपराध। दोनों अधिनियमों का सार और सार एक विधायी योजना थी जो पूर्व कार्योत्तर सुरक्षित करने के लिए थी।

उन विशेष व्यक्तियों को दोषी ठहराना और उनकी सजा बढ़ाना। इसने उनके कारावास को वैध बना दिया जबकि मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

वे मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह उनके स्वीकार्य बना दिया

उस अवधि के दौरान अस्वीकार्य रूप से प्राप्त बयान। यह.

साक्ष्य के मौलिक कानून को बदल दिया ताकि उनकी दोषसिद्धि को सुविधाजनक बनाया जा सके, और अंत में इसने पूर्व पोस्ट फैक्टो को बदल दिया

उन पर दंड लगाया जाए।

उनके लॉर्डशिप्स के विचार में कि ठोस सारांश निष्पक्ष रूप से

अधिनियमों के प्रभाव का वर्णन करें। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, कानून जो इस प्रकार निर्देशित किया गया है विशेष कार्यवाहियों का क्रम हमेशा नहीं हो सकता है

न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप के बराबर है।

लेकिन वर्तमान मामले में उनके प्रभुओं को कोई संदेह नहीं है कि ऐसा हस्तक्षेप था; कि यह केवल संभावना नहीं थी

लेकिन विवादित अधिनियमों का इच्छित प्रभाव; और यह कि यह उनकी वैधता के लिए घातक है। इन अधिनियमों की वास्तविक प्रकृति और उद्देश्य उनके संयुक्त प्रभाव से प्रकट होता है। विशिष्ट कार्यवाहियों पर जिनके संबंध में उन्हें अभिकल्पित किया गया था, और वे अपना रंग, विशेष रूप से,

उन परिवर्तनों को जो वे अपने अंतिम रूप में करना चाहते थे उद्देश्य, दोषी ठहराए गए लोगों की सजा। ये

परिवर्तनों ने न्यायिक क्षेत्र में एक गंभीर और जानबूझकर घुसपैठ का गठन किया। काफी स्पष्ट रूप से, उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्यायाधीश इन विशेष व्यक्तियों के साथ व्यवहार करें

इन विशेष शुल्कों को उनके सामान्य शुल्क से वंचित कर दिया गया था

उचित वाक्यों के संबंध में विवेकाधिकार। वे थे।

न करने के लिए दोषसिद्धि पर प्रत्येक अपराधी को सजा देने के लिए मजबूर

दस साल से कम कारावास, और आदेश देने के लिए मजबूर किया गया

उसकी संपत्ति को जब्त करना, भले ही साजिश में उसका हिस्सा मामूली रहा हो।

निचली अदालत ने अपनी लंबी और सावधानी से निष्कर्ष निकाला

इन शब्दों के साथ निर्णय *((1965),* पी पर *67* सी. एन. एल. आर.। *424) :*

"लेकिन हमें इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि *1962* के अधिनियम ने कार्योत्तर रूप से उस सजा को मौलिक रूप से बदल दिया जिसके लिए

अभियुक्तों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। अधिनियम ने हटा दिया

सजा की अवधि के बारे में अदालत का विवेकाधिकार

अधिरोपित किया जाए, और न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. की अवधि अधिरोपित करने के लिए मजबूर किया जाए।

10 वर्षों का कारावास, हालाँकि हम चाहते थे

सजा के मामले में साजिश रचने वालों और साजिश रचने वालों के बीच अंतर करना।

इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यह एक अनिवार्य ज़ब्ती भी लागू करता है। संपत्ति। ये संशोधन केवल नहीं थे

पूर्वगामीः वे भी तदर्थ थे, केवल लागू होते हैं

षड्यंत्र जो उन आरोपों का विषय था जिन्हें हमने आजमाया है। हम इस भेदभाव को समझने में असमर्थ हैं। को। अदालतें, जो राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए, राजद्रोही

अपराध समान रूप से जघन्य होते हैं, चाहे उनका रंग कुछ भी हो। सत्ता में सरकार या जो कोई भी अपराधी हो।

उनके प्रभुओं को उस विरोध के साथ सहानुभूति है और

इससे पूरी तरह सहमत हैं।

इन अधिनियमों पर इन शब्दों को उचित रूप से लागू किया जा सकता है -

चेज़ जे., संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में

काल्डर वी। बैलः "ये अधिनियम विधायी निर्णय और न्यायिक शक्ति का प्रयोग थे।

ब्लैकस्टोन अपनी टिप्पणियों में, वॉल्यूम। *1 (4 संस्करण),*

"अतः विधानमंडल का एक विशेष अधिनियम टिटियस के सामान को जब्त करना, या उसे उच्च राजद्रोह का दोषी ठहराना एक विचार में प्रवेश नहीं करता है

नगरपालिका कानूनः इस अधिनियम के संचालन के लिए खर्च किया जाता है

केवल टिटियस पर और इसका कोई संबंध नहीं है

सामान्य रूप से समुदायः बल्कि यह एक वाक्य है

एक कानून "।

यदि इस प्रकार के अधिनियम वैध थे तो न्यायिक शक्ति

विधायिका द्वारा पूरी तरह से अवशोषित किया जा सकता है और न्यायाधीशों के हाथों से निकाला जा सकता है। यह सराहना की जाती है कि

एक गंभीर स्थिति और इसने इससे निपटने के लिए गंभीर उपाय किए, यह सोचकर कि किसी को यह अनुमान लगाना चाहिए कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है और सही तरीके से काम कर रहा था; लेकिन यह विचार अप्रासंगिक है, मद्रास बार एसोसिएशन *V.* यूनियन ऑफ इंडिया *75*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

और संविधान का उल्लंघन करने वाले कार्यों को कोई वैधता नहीं देता है।

एक बार जो किया जाता है, यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो उसे फिर से किया जा सकता है और कम संकट और कम गंभीर परिस्थितियों में किया जा सकता है और इस प्रकार न्यायिक शक्ति का क्षरण हो सकता है। इस तरह का क्षरण है

संविधान के स्पष्ट इरादे के विपरीत। उनके लॉर्डशिप्स के विचार में अधिनियम अधिकार से परे और अमान्य थे।

XXX

XXX

XXX पक्षों के बीच यह सहमति हुई कि यदि अधिनियम

यदि वे अधिकार से बाहर थे और अमान्य थे, तो दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।

इसलिए उनके प्रभुओं ने उन्हें विनम्रता से सलाह दी है

महामहिम कि इस अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और यह कि

दोषसिद्धि को निरस्त किया जाना चाहिए। *(iii)* तब लोक निदेशक को निर्देश दिया गया था।

जमैका का अभियोजन बनाम। मोलिसन, *(2003) 2* एसी *411*। द.

तथ्यात्मक विवाद जिसके कारण उपरोक्त निर्णय लिया गया

प्रिवी काउंसिल देखी जा सकती है। *16.3.1994* पर, जब कर्ट मोलिसन केवल *16* साल के थे, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए एक हत्या की।

एक चोरी। उसके अपराध को "राजधानी हत्या" के रूप में वर्णित किया गया था।

जमैका के कानून के तहत। मुकदमे के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया था।

21.4.1997 , जब वे *19* वर्ष के थे। *25.4.997* पर, उन्हें किशोर अधिनियम, *1951* की धारा *29 (1)* के तहत सजा सुनाई गई थी।

गवर्नर की इच्छा के दौरान हिरासत में लिया जाए। उस पर

16.2.2000 , हालाँकि अपील न्यायालय ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति, यह उसकी जांच करने के लिए सहमत हो गया

विवाद, क्या उस पर लगाई गई सजा थी

अपील न्यायालय ने उनकी दलील को स्वीकार कर लिया। की सजा गवर्नर-जनरल की इच्छा के दौरान हिरासत को अलग कर दिया गया था। इसके स्थान पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

सिफारिश की गई कि जब तक वह *20* साल के कारावास की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक उसे पैरोल के लिए नहीं माना जाए। में

प्रिवी काउंसिल के समक्ष विचार के लिए आए विवाद में दो मुख्य मुद्दे थे। सबसे पहले, क्या

राज्यपाल के दौरान निरोध की सजा-धारा *29 (1)* द्वारा प्राधिकृत जनरल की खुशी, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. में उनके द्वारा प्रयोग की गई शक्ति थी।

76

उनकी कार्यकारी क्षमता। और दूसरी बात, क्या शक्ति

एक को दी जाने वाली सजा के लिए उपाय निर्धारित करें

अपराधी, संविधान के अनुरूप है। प्रिवी काउंसिल ने विवाद की जांच करते हुए निम्नलिखित राय दीः

" किशोर अधिनियम *1951* की धारा *29*

[3] व्यक्ति के विरुद्ध अपराध अधिनियम *1864* की धारा *3,*

जैसा कि संशोधित किया गया है, प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है राजधानी हत्या को मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन खास

यह अपराध करने वालों के लिए प्रावधान किया गया है।

जब उसकी आयु *18* वर्ष से कम हो। कई संशोधनों के बाद

जमैका *(*संविधान*)* की धारा *4* के अनुसार बनाया गया

परिषद में आदेश *1962 (*एस. आई. *1962/1500),* धारा *29* किशोर अधिनियम *1951* अब इस अपील में मुख्य मुद्दे के लिए सामग्री के रूप में निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

" (1) मृत्यु की सजा नहीं सुनाई जाएगी।

या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया जाता है यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि उस समय

जब अपराध किया गया था तो वह *18* वर्ष से कम आयु का था, लेकिन उसके स्थान पर अदालत

उसे महामहिम के दौरान हिरासत में रखने की सजा दें खुशी, और, यदि इस तरह से सजा सुनाई जाती है, तो वह,

के अन्य प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद

यह कानून, ऐसे स्थान पर हिरासत में लिए जाने के लिए उत्तरदायी होगा (जिसमें, एक बच्चे के मामले में, एक वयस्क को छोड़कर)

सुधारात्मक केंद्र) और ऐसी शर्तों के तहत जैसे

मंत्री निर्देश दे सकता है, और जब तक इस तरह से हिरासत में है

कानूनी हिरासत में माना जाए। (4) गवर्नर-जनरल उप-धारा (1) या (3) के तहत हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस पर रिहा कर सकता है।

इस खंड में। ऐसा लाइसेंस ऐसे रूप में होगा और

इसमें ऐसी शर्तें शामिल हैं जो गवर्नर-जनरल निर्देशित कर सकता है, और किसी भी समय निरस्त या निरस्त किया जा सकता है।

गवर्नर-जनरल द्वारा परिवर्तित। जहाँ ऐसी

लाइसेंस उस व्यक्ति को रद्द कर दिया जाता है जिससे यह मद्रास बार एसोसिएशन *v* से संबंधित है।

भारत का संघ

77

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

जनरल निर्देश दे सकता है, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो हो सकता है बिना वारंट के किसी भी सिपाही द्वारा गिरफ्तार किया गया और लिया गया

ऐसी जगह पर।

[4] मूल रूप से अधिनियमित धारा *29* में *1964* में संशोधन किया गया था। उप-धारा *(1)* में *"*राज्यपाल*"* के स्थान पर *"*मंत्री*"* रखना और

" गवर्नर जनरल *"*चारों में से प्रत्येक में*"* गवर्नर *"*के लिए

मूल रूप से उप-धारा में राज्यपाल को दिए गए संदर्भ

(4) . 1975 में उप-धारा *(1)* में और संशोधन किया गया ताकि

सादा, बेकर बनाम द क्वीन के प्रभाव को उलटते हुए, *[1975]* एसी

774 , [1975] 3 सभी ई. आर. *55,* कि पर वैधानिक निषेध

उन पर लागू मौत की सजा की घोषणा

18 वर्ष से कम आयु का प्रतीत होता है जब उनके पास था अपराध किया, सजा के समय नहीं। *1985* में,

"एक वयस्क सुधार केंद्र" का संदर्भ था

"एक जेल" के पिछले संदर्भ के लिए प्रतिस्थापित। द. "महामहिम की खुशी" के लिए अधिनियमित संदर्भ में नहीं है,

तथापि, इसमें कोई संदेह नहीं कि धारा *68 (2)* के कारण संशोधन किया गया है।

जमैका के संविधान में प्रावधान है कि कार्यपालिका

जमैका के अधिकार का प्रयोग उसकी ओर से किया जा सकता है गवर्नर-जनरल द्वारा महामहिम। इस बात को मान्यता देते हुए

संवैधानिक वास्तविकता, यह अभ्यास प्रतीत होता है जहाँ

धारा *29 (1)* लागू होती है, जैसा कि इस मामले में किया गया था, गवर्नर के दौरान हिरासत की सजा-जनरल

आनंद, और इस राय में कि उपयोग अपनाया जाएगा।

XXXXXX

XXX

XXX

संविधान

XXX

XXX

XXX

पहला प्रश्नः धारा *29* के साथ संगत है

जमैका का संविधान*? [11]* निदेशक और महान्यायवादी दोनों, जो

उनके साथ उपस्थित हुए, सुनवाई में स्वीकार किया कि, विषय

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. की धारा *26 (8)* के आधार पर उनके तर्क के लिए।

संविधान, किशोर अधिनियम *1951* की धारा *29* का उल्लंघन करता है।

संविधान की धारा *15 (1) (*बी*)* और *20 (1)* द्वारा गारंटीकृत अधिकार और इसलिए असंगत हैं। इसे देखते हुए

स्वतंत्रता किसी न्यायालय की सजा या आदेश के निष्पादन में नहीं बल्कि कार्यपालिका के विवेक पर है। ऐसा व्यक्ति नहीं है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष द्वारा एक निष्पक्ष सुनवाई प्रदान की गई

सजा प्रभावी रूप से कार्यपालिका द्वारा पारित की जाती है न कि द्वारा कार्यपालिका से स्वतंत्र न्यायालय।

XXX

XXX

XXX

[13] ...... यह वास्तव में प्रतीत होता है कि सजा

के अध्याय *III* में धाराओं द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का संविधान लेकिन एक के साथ उनकी असंगति के कारण

जिस सिद्धांत पर स्वयं संविधान की स्थापना की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कोई कारण नहीं है *(*के अधीन*)*

नीचे विचार किए गए अन्य तर्क*)* हिंदस्केस में तर्क वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। यह होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बोर्ड इस तर्क को अस्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन यह एक निर्णय से हटने के लिए अनिच्छुक होगा जो

25 वर्षों तक बिना चुनौती के खड़ा रहा है*,* क्योंकि निर्णय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हितकारी को प्रभाव देता है

सिद्धांत। जो भी ओवरलैप हो सकता है वेस्टमिंस्टर मॉडल पर कार्यकारी और विधायी शक्तियों के प्रयोग के बीच संविधान*,*

न्यायिक शक्तियों के प्रयोग के बीच अलगाव

एक ओर विधायी और दूसरी ओर कार्यकारी शक्तियाँ

कुल या प्रभावी रूप से ऐसा है। कानून के शासन पर आधारित इस तरह के अलगाव को हाल ही में लॉर्ड स्टेन ने *"*ए*"* के रूप में वर्णित किया था। लोकतंत्र की विशेषताएँ*:*

आर *(*एंडरसन*)* बनाम मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ *79*

[जगदीश सिंह खेहर*,* जे।*]*

गृह विभाग के लिए राज्य सचिव*, [2002] 4* सभी ईआर *1089, [2002] 3* डब्ल्यूएलआर *1800,* पीपी पर। *1821-1822 ,* बाद की रिपोर्ट का पैरा *5*। बोर्ड की राय में*,* श्री फिट्जगेराल्ड

धारा *29* के प्रति अपनी चुनौती को इस संवैधानिक सिद्धांत के साथ इसकी असंगतता के आधार पर पूरा किया है कि न्यायिक कार्यों *(*जैसे सजा सुनाना*)* का प्रयोग न्यायपालिका द्वारा किया जाना चाहिए न कि कार्यपालिका द्वारा।

XXX XXX

XXX

वाक्य की प्रकृति और उद्देश्य

गवर्नर के दौरान हिरासत-जनरल की खुशी है

बंदी को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए, यह तय करें। पीड़ा होती है। चूँकि धारा *29* का दोष यह सौंपना है

न्यायपालिका के बजाय कार्यपालिका को निर्णय, अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन

संविधान है *(*जैसा कि ब्राउन बनाम द क्वीन में है, *[2000] 1* एसी *45)* उप-धारा *(1)* में *"*महामहिम*"* के लिए *"*न्यायालय*"* और *"*के प्रत्येक संदर्भ के लिए*"* न्यायालय *"*को प्रतिस्थापित करना।

गवर्नर-*"*उप-धारा *(4)* में*"*।

(iv) हमारा ध्यान हैरी ब्रांडी *v* पर भी आमंत्रित किया गया था। मानवाधिकार और समान अवसर आयोग, *(1995) 183* सी. एल. आर.

245. तत्काल निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था

ऑस्ट्रेलिया। जिस तथ्यात्मक विवाद के कारण उपरोक्त निर्णय हुआ, उसका वर्णन पहले किया जा रहा है। वादी हैरी ब्रांडी

आदिवासी और टोरेस जलडमरूमध्य के एक अधिकारी के रूप में कार्यरत था

द्वीपवासी आयोग। तीसरा प्रतिवादी जॉन बेल भी था

आयोग का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। *13.3.1990* पर, जॉन बेल मानवाधिकार और समान अवसर आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने मौखिक दुर्व्यवहार और

हैरी ब्रांडी की ओर से धमकी देने वाला व्यवहार, जबकि दोनों

आयोग के कार्य में थे। इसके बाद, जॉन बेल ने नस्लीय *[2014] 10* एस. सी. आर. की धारा *24* के तहत एक नोटिस जारी किया।

भेदभाव अधिनियम, *1975*। और तदनुसार, आयुक्त ने शिकायत आयोग को भेज दी। की शक्ति

हैरी ब्रांडी के खिलाफ नस्लीय भेदभाव अधिनियम, *1975* के तहत जांच करने के लिए आयोग का प्रयोग दूसरे प्रतिवादी द्वारा किया गया था। दूसरे प्रतिवादी को नस्लीय भेदभाव अधिनियम, *1975* की धारा *24* के तहत नियुक्त किया गया था।

आयुक्त के कार्यों का निर्वहन करना। दूसरा। प्रतिवादी ने नस्लीय की धारा *25Z* के तहत अपने निष्कर्ष वापस कर दिए

22.12.1993 पर भेदभाव अधिनियम, *1975*। अभियुक्त का

विवाद, दूसरे प्रतिवादी को हैरी ब्रांडी की आवश्यकता थी, वादी को निम्नलिखित कार्य/आचरण करना चाहिएः

"(1) कि वादी तीसरे प्रतिवादी से माफी मांगे,

क्षमा याचना का रूप निर्धारण के साथ जोड़ा जा रहा है;

(2) कि वादी दर्द, अपमान के लिए हर्जाने के रूप में तीसरे प्रतिवादी को *$2,500* की राशि का भुगतान करता है, दुःख और व्यक्तिगत गरिमा की हानि जो तीसरे को झेलनी पड़ी

प्रतिवादी;

(3) कि ए. टी. एस. आई. सी. इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है

वादी, उस आचरण के संबंध में जो उसने किया था

तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ;

(4) कि ए. टी. एस. आई. सी. तीसरे प्रतिवादी से माफी मांगता है

उसकी शिकायत से निपटने के संबंध में, का रूप क्षमा याचना को निर्धारण के साथ जोड़ा जा रहा है;

(5) कि ए. टी. एस. आई. सी. दर्द, अपमान के लिए हर्जाने के रूप में तीसरे प्रतिवादी को *10,000* डॉलर की राशि का भुगतान करता है, दुःख और व्यक्तिगत गरिमा की हानि जो तीसरे को झेलनी पड़ी

प्रतिवादी "। द्वारा दिए गए दृढ़ संकल्प को चुनौती देने के लिए

दूसरे प्रतिवादी, हैरी ब्रांडी ने एक चुनौती दी

जातीय भेदभाव अधिनियम, *1975* के प्रावधान।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *81*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

उनके द्वारा उठाई गई चुनौती में तैयार किया गया था

निम्नलिखित शब्दः

" लिंग में सन्निहित संशोधनों के परिणामस्वरूप

भेदभाव और अन्य विधान संशोधन अधिनियम, *1992*

और/या विधि और न्याय विधान संशोधन अधिनियम

1993 क्योंकि वे नस्लीय भेदभाव अधिनियम *1975* को प्रभावित करते हैं

किसी भी, और यदि ऐसा है, जो, नस्लीय के भाग *III* के प्रावधानों में से

भेदभाव अधिनियम अमान्य है*?"*

इस मामले पर निर्णय लेते हुए, उच्च न्यायालय ने

ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

"अधिनियम के प्रति वादी की चुनौती

15. के विशेष प्रावधानों के लिए वादी की चुनौती

अधिनियम इस प्रस्ताव पर आधारित है कि वे एक

अनुरूपता के अलावा न्यायिक शक्ति का प्रयोग उस शक्ति में राष्ट्रमंडल संविधान का *Ch.lll*

आयोग द्वारा प्रयोग किया जाता है जो अदालत नहीं है

एस के अनुसार स्थापित। *71* और उसके अनुसार गठित किया गया

एस के साथ। *72* संविधान से। वादी आगे तर्क देता है कि इस प्रस्ताव की शुद्धता प्रभावित नहीं होती है

संघीय न्यायालय द्वारा समीक्षा के लिए प्रावधान।

XXX

XXX

XXX

21. हालाँकि निर्णय लेने के कई कार्य हो सकते हैं न्यायिक, कार्यपालिका या कार्यपालिका के अभ्यास के रूप में उनका चरित्र

उनकी विधायी व्यवस्था से विधायी शक्ति, चरित्र निर्णय निर्माता और निर्णय की प्रकृति

प्रक्रिया बनाना, निर्णय लेने के कुछ कार्य हैं -

न्यायिक शक्ति का अनन्य और अविभाज्य प्रयोग *(34*

और मैकटियरन जे*)*। जैसा कि डिक्सन सी. जे. और मैकटियरन जे. ने देखा रेग में। वी. डेविसन *(35* आईबीआईडी. *369* पर*):*

"सच्चाई यह है कि मौजूदा अधिकारों का निर्धारण तथ्य या कानून के मुद्दों का न्यायिक निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

विशेष रूप से न्यायिक शक्ति के भीतर ताकि संसद

किसी भी व्यक्ति या शरीर को कार्य पर विश्वास नहीं कर सकता है लेकिन एक एस. एस. के अधीन गठित न्यायालय। *71* और संविधान का *72* "।

उस कथन में, "न्यायिक निर्धारण" अभिव्यक्ति का अर्थ है न्यायिक पद्धति के माध्यम से एक आधिकारिक निर्धारण, यानी एक लागू करने योग्य निर्णय।

कानून के प्रासंगिक सिद्धांतों को तथ्यों पर लागू करके

पाया गया।

XXX

XXX

XXX

25. अदालत के समक्ष मामले की ओर रुख करते हुए, जो भी हो सकता है

एक घोषणा की प्रवर्तनीयता हो जो वादी करता है

क्षमा याचना ", एक घोषणा कि वादी तीसरे प्रतिवादी को" *$2,500* की राशि का भुगतान करता है ", एक बार पंजीकृत होने के बाद, आकर्षित करता है।

एस का संचालन। *53* ऑस्ट्रेलिया के संघीय न्यायालय अधिनियम *1976 (*सी. टी. एच.*)*। उस धारा द्वारा, एक व्यक्ति जिसके पक्ष में

निर्णय दिया जाता है उसी उपचार के लिए हकदार है

प्रवर्तन, निष्पादन द्वारा या अन्यथा, जैसा कि लागू राज्य या क्षेत्र के कानूनों द्वारा अनुमति दी गई है। वर्तमान में

इसका मतलब है न्यू साउथ वेल्स। धारा *53* में ऐसा नहीं है किसी के द्वारा या उसके अधीन किए गए किसी प्रावधान के संचालन को प्रभावित करना

निष्पादन के लिए अन्य अधिनियम या न्यायालय के नियम और न्यायालय के निर्णयों का प्रवर्तन *(40* एस। *53 (2)).*

26. लेकिन एस। *25* जेड. ए. बी. प्रदान करने से परे है

एक निर्धारण के प्रवर्तन के लिए तंत्र। यह एक पंजीकृत निर्धारण प्रभाव देने का इरादा रखता है जैसे कि यह

संघीय न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया था। न्यायिक आदेश

संघीय न्यायालय द्वारा किया गया कार्य राष्ट्रमंडल न्यायिक शक्ति के प्रयोग के रूप में प्रभावी होता है, लेकिन द्वारा एक निर्धारण न्यायिक शक्ति के प्रयोग में आयोग न तो बनाया जाता है और न ही पंजीकृत किया जाता है। द्वारा कार्यकारी शक्ति का प्रयोग

संघीय न्यायालय के पंजीयक द्वारा आयोग और एक प्रशासनिक कार्य का निष्पादन बस नहीं कर सकता है

एक आदेश बनाएँ जो न्यायिक शक्ति के प्रयोग के रूप में प्रभावी होता है; इसके विपरीत, एक आदेश जो मद्रास बार एसोसिएशन *v* के रूप में प्रभावी होता है।

भारत संघ *83*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

न्यायिक निर्धारण के बाद के अलावा न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, *s.25ZAB*

यह निर्धारित करने का उद्देश्य है कि संविधान क्या नहीं करता है

अनुमति दें "।

(v) तब हमारा ध्यान संदर्भ आवासीय किरायेदारी अधिनियम, *123* डी. एल. आर. *(3* डी*) 554* की ओर आकर्षित किया गया। तथ्यात्मक मैट्रिक्स, में

जिसे आगे बढ़ाते हुए कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय दिया गया था, वह इस प्रकार है। के प्रावधान

आवासीय किरायेदारी अधिनियम, *1979 (*ओंटारियो*)*, जिसके द्वारा

आवासीय किरायेदारी आयोग को आदेश देने का अधिकार दिया गया था

किरायेदारों को बेदखल करने के लिए मकान मालिकों और किरायेदारों की भी आवश्यकता हो सकती है

उक्त अधिनियम के तहत लगाए गए दायित्वों का पालन करने के लिए, इसमें निहित सीमा के खिलाफ अपमानजनक के रूप में हमला किया गया था

ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, *1867* की धारा *96* और

इसलिए, अल्ट्रा वायर्स। एक समान पर अपने निष्कर्षों को दर्ज करने में

जैसा कि ऊपर देखे गए निर्णयों में कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय

कनाडा का अवलोकन निम्नानुसार किया गया हैः

"एस के तहत। *92 (14)* ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम,

1867 , प्रांत में न्याय के प्रशासन के संबंध में प्रांतीय विधानमंडलों के पास विधायी शक्ति है। यह एक व्यापक शक्ति है लेकिन एसएस के घटाव के अधीन है। *96*

संघीय प्राधिकरण के पक्ष में *100*। एस के तहत। *96* द.

गवर्नर जनरल के पास न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की एकमात्र शक्ति है।

सर्वोच्च का। प्रत्येक में जिला और काउंटी न्यायालय

प्रांत। एस के तहत। *97* न्यायाधीश जिन्हें नियुक्त किया जाना है

सुपीरियर, जिला और काउंटी न्यायालयों को होना है

प्रत्येक प्रांत के संबंधित सलाखों में से चुना गया। के तहत

एस. *100* कनाडा की संसद तय करने के लिए बाध्य है और

उनके वेतन की व्यवस्था करें। धारा *92 (14)* और एस एस। *96 100* तक पिताओं के महत्वपूर्ण समझौतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है

एस. *96* , अगर कोई प्रांत गुजर सकता है तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा एक न्यायाधिकरण का निर्माण करने के लिए कानून बनाना, उसमें सदस्यों की नियुक्ति करना और फिर न्यायाधिकरण को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. का अधिकार क्षेत्र प्रदान करना।

उच्च न्यायालय। एक मजबूत के रूप में क्या कल्पना की गई थी

एकात्मक न्यायिक प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के लिए संवैधानिक आधार को गंभीर रूप से कमजोर किया जाएगा। धारा *96*

इस प्रकार एक न्यायाधिकरण में नियुक्तियां करने के लिए प्रांतीय क्षमता को सीमित करने के रूप में माना जाता है एस. *96* न्यायिक शक्तियाँ और इसलिए एक प्रांतीय न्यायाधिकरण को प्रदान करने के लिए प्रांतीय क्षमता को निहित रूप से सीमित करते हुए

ऐसी शक्तियाँ।

IV

यह विश्वास कि कोई भी कार्य जो *1867* में किया गया था

एस में निहित। *96* न्यायालय को हमेशा के लिए इस स्थिति में रहना चाहिए कि न्यायालय लॉर्ड एटकिन के फैसले में अपने चरम पर पहुँच गया था।

टोरंटो निगम बनाम। यॉर्क टी. पी. आदि। अल. , *(1938) 1* डीएलआर *593, (1938)* एसी *415, (1938) 1* डब्ल्यूडब्ल्यूआर *452*। एस का वर्णन करते हुए। *96* न्याय के मंदिर में तीन प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में, लॉर्ड एटकिन ने माना कि

ओंटारियो नगरपालिका बोर्ड वैध रूप से *"*न्यायिक*"* प्राप्त नहीं कर सका

प्राधिकरण "। साथ ही, उनका मानना था कि नगर निगम बोर्ड एक प्रशासनिक निकाय है।

और विवादित *'*न्यायिक कार्यों*'* को इसके तहत बोर्ड को दी गई प्रशासनिक शक्तियों से अलग किया जा सकता था

कानून बनाने में सक्षम बनाना। अंतर का कोई विश्लेषण नहीं था न्यायिक और प्रशासनिक के बीच संबंध

विधायी योजना की विशेषताएँ; धारणा यह थी कि एस प्रदान करने का कोई भी प्रयास। *96* प्रांतीय रूप से कार्य करना

नियुक्त न्यायाधिकरण विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

एस के तहत प्राधिकरण। *92* , संदर्भ पुनः दत्तक ग्रहण में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा लगभग तुरंत सीमित कर दिया गया था अधिनियम और अन्य अधिनियम, आदि *(1938) 3* डी. एल. आर. *497,71* सी. सी. सी. *110, (1938)* एस. सी. आर. *398*। मुख्य न्यायाधीश डफ ने कहा कि

निम्न न्यायालयों की अधिकारिता हमेशा के लिए तय नहीं की गई थी क्योंकि

परिसंघ की तारीख पर खड़ा था "। उनकी राय में, यह था

सुपीरियर कोर्ट मद्रास बार एसोसिएशन *v* से अधिकारिता को हटाना काफी संभव है।

और इसे संक्षिप्त क्षेत्राधिकार के न्यायालय में निहित करें। सवाल यह है

जो पूछा जाना चाहिए वह यह था कि क्या "अधिकार क्षेत्र

इन कानूनों के तहत मजिस्ट्रेटों को व्यापक रूप से प्रदान किया गया

आम तौर पर प्रयोग करने योग्य क्षेत्राधिकार के एक प्रकार के अनुरूप

अधिकारिता के बजाय संक्षिप्त अधिकारिता वाले न्यायालय

एस के दायरे में आने वाले न्यायालयों का। *96* " *(* पी। *514)*। में।

गोद लेने का संदर्भ, डफ सी. जे. ने ऐतिहासिक को देखा

इंग्लैंड में अभ्यास किया और निष्कर्ष निकाला कि अधिकार क्षेत्र इससे पहले कानून के तहत मजिस्ट्रेटों को प्रदान किया गया

अंग्रेजी गरीब कानूनों के तहत, एक अधिकार क्षेत्र जो था के बजाय संक्षिप्त प्रकृति के न्यायालयों से संबंधित थे

उच्च न्यायालय। इसके आधार पर इस कानून को बरकरार रखा गया।

गोद लेने के संदर्भ ने उदारीकरण का प्रतिनिधित्व किया एस का दृश्य। *96* टोरंटो में प्रिवी काउंसिल द्वारा अपनाया गया

वी. यॉर्क, कम से कम अधिकार क्षेत्र के हस्तांतरण के संदर्भ में

उच्च न्यायालय से निम्न न्यायालय तक।

उदारीकरण की वही प्रक्रिया, इस बार में

उच्च न्यायालय से अधिकार क्षेत्र के हस्तांतरण का संदर्भ

एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए, प्रिवी द्वारा शुरू किया गया था

सस्केचेवान के श्रम संबंध बोर्ड में परिषद

वी. जॉन ईस्ट आयरन वर्क्स लिमिटेड, *(1948) 4* डीएलआर *673,*

(1949) एसी *134, (1948) 2* डब्ल्यूडब्ल्यूआर *1055*। लॉर्ड साइमंड्स दो गुना परीक्षण का प्रस्ताव रखा। परीक्षण का पहला अंग पूछना है।

चाहे बोर्ड या न्यायाधिकरण "न्यायिक शक्ति" का प्रयोग करता हो।

लॉर्ड साइमंड्स ने 'अंतिम' उत्तर का प्रस्ताव नहीं दिया

"न्यायिक शक्ति" की परिभाषा, लेकिन उन्होंने पी में सुझाव दिया। *680*

डी. एल. आर., पी. *149* एसी, किः

...... न्यायिक कार्य की अवधारणा है

एक सूट के विचार के साथ अविभाज्य रूप से बंधे हुए

पार्टियों के बीच, चाहे क्राउन और के बीच

विषय या विषय और विषय के बीच, और यह कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उन पक्षों के बीच के मुद्दे का निर्णय करे, जिनके साथ वह केवल शुरू करना या शुरू करना है।

कार्यवाही का बचाव या समझौता करें। " सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

86

यदि न्यायिक के रूप में प्रारंभिक प्रश्न का उत्तर

शक्ति "नकारात्मक में है, फिर वह मामले को समाप्त करता है

प्रांतीय बोर्ड के पक्ष में। लेकिन अगर शक्ति है वास्तव में एक न्यायिक शक्ति, तो यह पूछना आवश्यक हो जाता है

दूसरा प्रश्नः उस शक्ति के प्रयोग में, है

एक सुपीरियर, जिला या काउंटी न्यायालय के अनुरूप न्यायाधिकरण?

XXX

XXX

XXX

दूसरे चरण में इसके भीतर कार्य पर विचार करना शामिल है।

यह निर्धारित करने के लिए कि कार्य स्वयं है या नहीं, संस्थागत व्यवस्था

उस सेटिंग में देखने पर यह अलग होता है। विशेष रूप से, कर सकते हैं

इस कार्य को अभी भी एक 'न्यायिक' कार्य माना जाता है?

इस मुद्दे को संबोधित करते समय, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि

डुपॉन्ट बनाम में रैंड जे. द्वारा आगे का बयान। इंगलिस (पृ. 424

डी. एल. आर., पी. 543 एस. सी. आर.) कि ". यह विषय है-बल्कि विषय है।

निर्णय के उपकरण की तुलना में जो निर्धारक है।

इस प्रकार सवाल यह है कि क्या कोई विशेष कार्य है

न्यायिक 'का निर्धारण केवल इस आधार पर नहीं किया जाना है कि

प्रक्रियात्मक ट्रैपिंग। मुख्य मुद्दा प्रकृति का है

वह प्रश्न जिसका निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरण को बुलाया जाता है।

जहाँ न्यायाधिकरण के बीच एक निजी विवाद होता है

नियमों के एक मान्यता प्राप्त निकाय का एक तरह से अनुप्रयोग निष्पक्षता और निष्पक्षता के अनुरूप, तो, आम तौर पर, यह

न्यायिक 'क्षमता' में कार्य कर रहा है। शब्दावली उधार लेने के लिए

प्रोफेसर रोनाल्ड ड्वोर्किन के न्यायिक कार्य में शामिल हैं

'सिद्धांत' के संकेत, अर्थात,

व्यक्तियों या समूहों के प्रतिस्पर्धी अधिकार। यह हो सकता है

प्रतिस्पर्धा से जुड़े 'नीति' के प्रश्नों के विपरीत समग्र रूप से समुदाय की सामूहिक भलाई के विचार।

(पीपी पर ड्वोर्किन, टेकिंग राइट्स सीरियसली (1977) देखें। 82 90 (डकवर्थ) "।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का अवलोकन

कनाडा का पता चलता है, कि अदालत ने तीन चरणों का परीक्षण विकसित किया एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करना जो एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण में निहित न्यायनिर्णायक कार्य करता है।

पहला कदम मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *87*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

मौजूदा ऐतिहासिक परिस्थितियों के आलोक में निर्धारित किया गया था

1867 में, यानी ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, *1867* के अधिनियमित होने से पहले। पहले कदम के लिए यह निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि क्या परिसंघ के समय, अब एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण में निहित शक्ति या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न्यायिक न्यायाधिकरण के माध्यम से किया गया था।

अदालती प्रक्रिया। यदि पहले कदम का जवाब नकारात्मक था, तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन वैध होगा। यदि ऐतिहासिक साक्ष्य इंगित करते हैं, कि शक्ति, अब निहित है

एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एक के समान या अनुरूप था

परिसंघ में धारा *96* न्यायालयों के तहत प्रयोग की गई शक्ति,

तब मामले की आगे जांच करने की आवश्यकता थी। दूसरा।

कदम यह निर्धारित करने के लिए था कि क्या प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति को न्यायिक माना जाना चाहिए।

कार्य. जहाँ तक मामले का तात्कालिक पहलू है

संबंधित, यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला गया था कि जहां प्रशासनिक न्यायाधिकरण में निहित शक्ति के संबंध में था

पक्षकारों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन, जिसकी आवश्यकता थी

नकारात्मक रूप से, मामले को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं था, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण को शक्ति सौंपना वैध माना जाना चाहिए। यदि सत्ता या अधिकारिता का प्रयोग न्यायिक तरीके से किया जाता है, तो यह है

तीसरे और अंतिम चरण पर आगे बढ़ना अनिवार्य है। तीसरा चरण प्रशासनिक के विश्लेषण और समीक्षा पर विचार करता है।

समग्र रूप से न्यायाधिकरण के कार्य, और इसके कार्यों में इसकी जांच करना।

पूरा संस्थागत संदर्भ। यह एक परीक्षा पर विचार किया

प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बीच अंतर-संबंध न्यायिक शक्तियाँ, और अन्य शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

विधायी अधिनियम द्वारा। यदि न्यायिक सुनवाई अनिवार्य है,

जिसके बाद कोई निर्णय देना आवश्यक था, प्रशासनिक न्यायाधिकरण को प्रयोग करने वाला माना जाएगा।

अधिकारिता जो आम तौर पर किसी न्यायालय में निहित हो। इसके बाद

तीनों चरणों पर सकारात्मक में एक निष्कर्ष दर्ज करना, कि

यह निष्कर्ष निकालना संभव होगा कि क्या न्यायिक कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. हैं।

88

संबंधित प्रशासनिक द्वारा प्रयोग किया जाना आवश्यक था

न्यायाधिकरण। संदर्भ पुनः आवासीय किरायेदारी अधिनियम *(*ऊपर*)* में विवाद की जांच करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने

कनाडा इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आवासीय किरायेदारी आयोग को आदेश देने के लिए अधिकृत किया जा सकता था किसी मकान मालिक को अधिकार देना या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आदेश देना।

एक किरायेदारी का प्रदर्शन।

23. अंत में, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने पेश किया

पीटर डब्ल्यू. हॉग द्वारा *"*कनाडा के संवैधानिक कानून*"* पर निर्भरता *(*तीसरा संस्करण, *1992*, कार्सवेल, थॉमसन प्रोफेशनल द्वारा*)*

प्रकाशन*)* यह दावा करने के लिए कि संविधान के तहत भी

जहाँ शक्ति पृथक्करण नियम का स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय के प्रत्यायोजन में सीमाएँ होंगी।

न्यायाधिकरणों के लिए कार्य। विषय पर प्रासंगिक पाठ, से

उपरोक्त ग्रंथ को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

" 7.3 संविधान की न्यायिक धाराओं के प्रभाव

((a) शक्तियों का पृथक्करण

में कोई सामान्य *"*शक्तियों का पृथक्करण*"* नहीं है

संविधान अधिनियम, *1867*। यह अधिनियम विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग नहीं करता है और इस बात पर जोर देता है कि

सरकार की प्रत्येक शाखा केवल "अपना" कार्य करती है। विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच, किसी भी

जिम्मेदार सरकार की प्रणाली में शक्तियों को अलग करने का कोई मतलब नहीं होगा और यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि

अधिनियम इस तरह के किसी भी अलगाव का आह्वान नहीं करता है। न्यायिक और दो राजनीतिक शाखाओं के बीच की तरह, इसी तरह शक्तियों का कोई सामान्य विभाजन नहीं है। संसद या

विधानमंडल उचित विधान द्वारा न्यायालयों को गैर-न्यायिक कार्य प्रदान कर सकते हैं और *(*एक महत्वपूर्ण अपवाद के साथ, जिस पर चर्चा की जानी है*)* न्यायिक कार्य प्रदान कर सकते हैं।

ऐसे निकायों पर जो अदालतें नहीं हैं।

प्रत्येक कनाडाई क्षेत्राधिकार ने गैर -

अपने न्यायालयों पर न्यायिक कार्य, एक क़ानून को अधिनियमित करके, जिसे मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *89*

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

सरकार को कानून के प्रश्न को संदर्भित करने में सक्षम बनाता है

एक सलाहकार राय के लिए अदालतें। सलाह का प्रतिपादन

सरकार के प्रति राय पारंपरिक रूप से एक "कार्यकारी" है।

सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला कार्य। इस कारण से, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय

और ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने देने से इनकार कर दिया है सलाहकार राय, तर्क है कि शक्तियों का पृथक्करण

उनके संविधानों में सिद्धांत अदालतों को सीमित करता है वास्तविक पर निर्णय लेने का पारंपरिक न्यायिक कार्य

विवाद। लेकिन संदर्भ अपील *(1912)* में, ए-जी ओन्ट। *V.A.-G.* कर सकते हैं। *(* संदर्भ अपील*) (1912)* अधिनियम *571,*

प्रिवी काउंसिल ने ऐसी किसी भी सीमा को पढ़ने से इनकार कर दिया

कनाडा का संविधान। उनके प्रभुत्व ने संघीय व्यवस्था को बरकरार रखा

संदर्भ कानून, जाहिरा तौर पर संबंध में एक कानून के रूप में

कानूनों के संबंध में कानूनों के रूप में भी मान्य हैं प्रांत में न्याय का प्रशासन *(* एस. *92 (14))*।

उन निकायों को न्यायिक कार्य प्रदान करना जो हैं -

अदालतें भी इसी तरह किसी सामान्य निषेध के अधीन नहीं हैं। हालाँकि, यहाँ एक महत्वपूर्ण योग्यता है

बनाया गया। अदालतों ने माना है कि प्रांतीय विधानमंडलों

एक वरिष्ठ, जिला या काउंटी अदालत द्वारा निष्पादित। यह छोटा सा शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत विकसित किया गया है

एस. एस. की शर्तों की चोरी को रोकें। *96 100* तक संविधान अधिनियम, *1867*।

यदि एसएस। *96* संविधान अधिनियम, *1867* के *100* को शाब्दिक रूप से पढ़ा गया था, उन्हें आसानी से एक प्रांत द्वारा टाला जा सकता था।

जो अपने न्यायिक नियंत्रण को ग्रहण करना चाहता था

नियुक्तियाँ। प्रांत अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकता है

इसके निचले न्यायालयों का ताकि उन्होंने अधिकांश ग्रहण किया

उच्च न्यायालयों की अधिकारिता; या प्रांत सबसे अच्छा कर सकता है

एक नव स्थापित न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय की अधिकारिता, और

उस न्यायाधिकरण को निम्न अदालत या प्रशासनिक *[2014] 10* एस. सी. आर. कहें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अदालतों ने एस में एक चमक जोड़ी है। *96* और संबंधित संवैधानिक प्रावधान। उन्होंने जो कहा है वह इस प्रकार है: यदि कोई प्रांत किसी ऐसे न्यायाधिकरण का निवेश करता है जिसकी संपत्ति किसी वरिष्ठ, जिला या काउंटी अदालत से संबंधित होनी चाहिए, तो वह न्यायाधिकरण, उसका आधिकारिक नाम जो भी हो, उसके लिए है।

संवैधानिक उद्देश्य एक वरिष्ठ, जिला या काउंटी न्यायालय और एस की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। *96* और संविधान अधिनियम, *1867* के संबद्ध प्रावधान। यह

इसका अर्थ है कि ऐसा न्यायाधिकरण अमान्य रूप से गठित किया जाएगा, जब तक कि इसके सदस्य *(1)* संघीय द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं।

एस के अनुरूप सरकार। *96* , *(2)* से खींचा जाता है एस. एस. के अनुरूप प्रांत का बार। *97* और *98.*

और *(3)* द्वारा निर्धारित और प्रदान किए गए वेतन प्राप्त करें

एस के अनुरूप संघीय संसद। *100 .*

अब तक कानून और उसमें अंतर्निहित नीति स्पष्ट है।

समझने योग्य है। लेकिन कठिनाई उन कार्यों की परिभाषा में निहित है जो उचित रूप से एक से संबंधित होने चाहिए वरिष्ठ, जिला या काउंटी अदालत। अदालतों ने

एक न्यायिक रूप से लागू करने योग्य नियम बनाने का प्रयास किया जो अलग होगा। *96* अन्य न्यायनिर्णायक के कार्य कार्य। प्रयास सफल नहीं हुआ है, और यह है

विश्वास के साथ भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि अदालतें विशेष न्यायिक कार्यों को कैसे चिह्नित करेंगी। द.

एस का पुनरुत्थान। *96* मुकदमेबाजीः एस के आधार पर निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों की शक्तियों को पांच चुनौती। *96* है। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में सफल हुए, ए. जी. क्यू।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ *91*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

वी. फराह *[1978] 2* एस. सी. आर. *638;* पुनः आवासीय किरायेदारी अधिनियम *[1981] 1* एस. सी. आर. *714;* क्रेवियर वी. ए. जी. क्यू *[1981] 2* एस. सी. आर *220;* बी. सी. पारिवारिक संबंध अधिनियम *[1982] 1.*एस. सी. आर *62;* मैकएवॉय वी। *A.G.N.B. [1983] 1* एस. सी. आर. *704.* प्रिवी काउंसिल की अपीलों के उन्मूलन के बाद से, दो अन्य चुनौतियों

ए. जी. ओंट भी सफल रहे हैं। वी. विक्टोरिया

चिकित्सा भवन *[1960]* एस. सी. आर. *32;* चिकौटिमी का सेमिनरी बनाम। ए. जी. क्यू *[1973]* एस. सी. आर. *681* और इन निर्णयों ने

इसने कई और चुनौतियों को जन्म दिया। ये विकास जिनका वर्णन निम्नलिखित पाठ में किया गया है।

24. यह याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति भी थी, कि कानून के प्रस्ताव ने प्रकाश डाला

विभिन्न देश *(*जमैका, सीलोन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा*)* प्रिवी काउंसिल या संबंधित देशों के सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा तय किया गया निर्णय भारत में भी पूरी तरह से लागू होता है। क्रम में

इसे प्रदर्शित करने के लिए, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य बनाम पर निर्भरता रखी। लेबर लॉ प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन *(1998) 2* एससीसी *688*। उद्धृत मामले में विवाद प्रतिवादी संघ द्वारा सहायक आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका दायर करने के साथ उत्पन्न हुआ

श्रम *(*अर्थात, कार्यकारी कार्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारी*)*

श्रम विभाग*)*। उपरोक्त नियुक्तियाँ, के प्रावधानों में संशोधन के परिणामस्वरूप की गई थीं

बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम और औद्योगिक विवाद

(महाराष्ट्र संशोधन*)* अधिनियम। प्रत्यर्थी संघ के हाथों प्रस्तुत किया गया निवेदन था कि श्रम

महाराष्ट्र राज्य में न्यायालयों का गठन किया गया था।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम,

साथ ही, महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम। श्रम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएँ

औद्योगिक विवाद अधिनियम, धारा *7* में निर्धारित किया गया था, जो निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" (क*)* कि वह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे या रहे थे*;* या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

92

(ख*)* जो उसके पास तीन साल से कम की अवधि के लिए नहीं था

जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो*;* या

(ग*)* कि उन्होंने अध्यक्ष या किसी अन्य पद पर कार्य किया था।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी भी न्यायाधिकरण के सदस्य

दो वर्ष से कम की अवधि के लिए*;* या

*((*घ*)* कि उन्होंने भारत में कम से कम किसी न्यायिक पद पर कार्य किया था।

सात वर्ष से अधिक*;* या

(ई*)* कि वह एक श्रम के पीठासीन अधिकारी थे

कम से कम किसी भी प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित न्यायालय

पाँच साल। *"*

औद्योगिक विवाद *(*महाराष्ट्र संशोधन*)* अधिनियम द्वारा,

1974 , धारा *7* में संशोधन किया गया और इसके तीन और स्रोत हैं -

श्रम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए भर्ती जोड़ी गई। ये थेः

" (डी*-1)* उसने एक वकील या वकील के रूप में वकालत नहीं की है

उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय या किसी औद्योगिक न्यायालय या न्यायाधिकरण में सात वर्ष से कम या

(घ-2) उसके पास भारत के किसी भी हिस्से में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री है और उसके पास एक डिग्री है या उसके पास है। उप-पंजीयक से कम पद पर नहीं

कम से कम पाँच के लिए ऐसा कोई औद्योगिक न्यायालय या न्यायाधिकरण

वर्ष; या *(घ-3)* उसके पास भारत के किसी भी हिस्से में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री है और उसके पास एक डिग्री है या उसके पास है।

सहायक के पद से कम पद पर नहीं राज्य सरकार के अधीन श्रम आयुक्त के लिए

पाँच साल से कम नहीं।

बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम के तहत, जैसा कि यह मूल रूप से मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *93*

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

धारा *9* में प्रावधान किया गया था कि केवल ऐसे व्यक्ति श्रम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जिनके पास श्रम न्यायालय के अनुच्छेद *234* के तहत निर्धारित योग्यताएं हों।

संविधान, महाराष्ट्र राज्य में न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के योग्य होने के लिए। *1977* के महाराष्ट्र अधिनियम *47* द्वारा बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा *9* में संशोधन किया गया था। एक नई उप-धारा *(2)* को प्रतिस्थापित करके, जिसने

धारा *9* की मूल उप-धारा *(2)*। संशोधित उप-धारा *(2)* इस प्रकार थीः

(2) कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा।

"9 .

श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में, जब तक किः

*(*क*)* उसने भारत में किसी भी न्यायिक पद पर कार्य किया है।

*((*ख*)* उसने उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। उसके अधीनस्थ न्यायालय, या किसी भी कानून के तहत गठित किसी औद्योगिक न्यायालय, न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय में

तत्काल प्रभाव से; या

*(*ग*)* उसके पास किसी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री है। भारत के किसी भी भाग में कानून द्वारा स्थापित और ऐसे किसी औद्योगिक न्यायालय के उप-पंजीयक से कम रैंक का पद धारण कर रहा है या धारण कर चुका है या

न्यायाधिकरण, या सहायक श्रम आयुक्त का राज्य सरकार के अधीन, दोनों मामलों में नहीं

पाँच साल से कम।

पहली बार में, इस न्यायालय ने पहली बार घोषणा की कि

दीवानी न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्यों के मुख्य घटक,

निम्नानुसारः

"*6.* भारत बैंक लिमिटेड के मामले में *v.* कर्मचारी, आकाशवाणी

1950 एस. सी. *188,* इस न्यायालय ने विचार किया कि क्या एक औद्योगिक

न्यायाधिकरण एक अदालत थी। यह कहा गया है कि कोई भी केवल नहीं जा सकता है

नामकरण।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के कार्यों की जांच करनी होती है।

न्यायाधिकरण और यह उन कार्यों का निर्वहन कैसे करता है। इसने अभिनिर्धारित किया कि एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास एक के सभी गुण थे न्यायालय और निष्पादित कार्य जो नहीं हो सकते हैं

न्यायिक माना जाता है। न्यायालय ने नियमों को संदर्भित किया

न्यायाधिकरण के समक्ष किन कार्यवाहियों को विनियमित किया गया था। न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इसमें निहित शक्तियां हैं -

सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी अदालतों द्वारा किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय प्रयोग किए जाने वाले मामलों के समान। इसकी शक्ति थी

खोज, निरीक्षण आदि का आदेश देना और मजबूर करना

गवाहों की उपस्थिति, सम्मोहक प्रस्तुति

दस्तावेज़ आदि। इसने साक्ष्य के आधार पर और कानून के अनुसार अपना निर्णय दिया। दिए गए परीक्षण को लागू करना

कूपर वी के मामले में नीचे। विल्सन, *(1937) 2* के. बी. *309*

पी पर। *340* , इस न्यायालय ने कहा कि "एक सच्चा न्यायिक निर्णय दो या दो से अधिक के बीच विवाद के अस्तित्व का अनुमान लगाता है।

पक्षकार और फिर चार आवश्यकताएँ शामिल हैं-*(1)*

पक्षकारों द्वारा अपने मामले की प्रस्तुति; *(2)* पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से तथ्यों का पता लगाना।

अक्सर तर्क की सहायता से; *(3)* यदि विवाद कानून के प्रश्न से संबंधित है, तो कानूनी तर्क प्रस्तुत करना। पक्षों द्वारा; और *(4)* निर्णय द्वारा जो निपटाता है

तथ्य पर निष्कर्षों द्वारा पूरा मामला और इस तरह पाए गए तथ्यों पर कानून का अनुप्रयोग। समान परीक्षणों द्वारा निर्णय लिया गया, एक श्रम न्यायालय

निस्संदेह सही मायने में यह एक अदालत होगी।

हालाँकि, सवाल यह है कि क्या ऐसी अदालत और

ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एक पद धारण करने वाला कहा जा सकता है। अनुच्छेद *236* में परिभाषित राज्य की न्यायिक सेवा में

संविधान से। "

उपरोक्त में दर्ज अन्य प्रासंगिक टिप्पणियाँ

जेंट को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"*13.* रिलायंस को इस फैसले पर रखा गया है

यह दर्शाता है कि न्यायिक सेवा की व्याख्या संकीर्ण रूप से की जाती है

केवल सिविल न्यायालयों के पदानुक्रम को शामिल करता है जिसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश। हालाँकि, यह न्यायालय इस पर विचार नहीं कर रहा था

ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v* के संदर्भ में अन्य दीवानी न्यायालयों की स्थिति।

भारत संघ *95*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

"जिला न्यायाधीश" शब्द की व्यापक परिभाषा दी गई है। यह

न्यायालय की स्वतंत्रता को संरक्षित करने से संबंधित था

कार्यपालिका से न्यायपालिका और यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति गैर-न्यायिक सेवाओं से, जैसे कि पुलिस, उत्पाद शुल्क या

राजस्व को नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाता था जिला न्यायाधीशों के रूप में। यही कारण है कि तथ्य पर जोर दिया जाता है

कि न्यायिक सेवा में विशेष रूप से न्यायिक शामिल होना चाहिए

अधिकारी। इस फैसले की व्याख्या संकीर्ण रूप से नहीं की जानी चाहिए

न्यायिक सेवा से नागरिक सेवाओं के नए पदानुक्रम को बाहर करना

अदालतें स्थापित की जा रही हैं जिनकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश कर सकता है

ध्यान में रखते हुए जिला न्यायाधीश के रूप में माना जाए

अनुच्छेद *236* में उस शब्द की व्यापक परिभाषा।

14. इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही व्याख्या की है

चंद्र मोहन बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ

यू. पी., ए. आई. आर. *1966* एस. सी. *1987*, सर्वोच्च महत्व देने के रूप में

संवैधानिक योजना को लागू करने के लिए

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। अदालत की चिंता यह देखना था कि इस स्वतंत्रता को नष्ट नहीं किया गया था

एक अप्रत्यक्ष विधि।

XXX XXX

XXX

18. श्री कुमार पद्म प्रसाद बनाम के मामले में। संघ का

भारत और ओआरएस। , *(1992) 2* एस. सी. सी. *428*, इस न्यायालय को

नियुक्ति के उद्देश्य के लिए योग्यताओं पर विचार करें के अनुच्छेद *217* के तहत उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश

संविधान। *"*न्यायिक*"* अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए

अनुच्छेद *217 (2) (*ए*)* के तहत, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभिव्यक्ति *"*न्यायिक कार्यालय*"* की व्याख्या की जानी चाहिए

भाग के पाँचवें और छठे अध्याय की योजना के अनुरूप

संविधान का *VI.* इसलिए इसका अर्थ है एक न्यायिक

कार्यालय जो परिभाषित न्यायिक सेवा से संबंधित है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, एक व्यक्ति को चाहिए एक न्यायिक पद धारण करें जो न्यायिक का एक हिस्सा होना चाहिए

राज्य की सेवा। चंद्रा के मामलों को संदर्भित करने के बाद

मोहन *(*ऊपर*)* और स्टेट्समैन *(*प्राइवेट*)* लिमिटेड बनाम। एच. आर. देब

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

ए. आई. आर. *1968* एस. सी. *1495*, इस न्यायालय ने कहा कि *"*न्यायिक*"* शब्द

अपने सामान्य अर्थों में कार्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यालय शामिल हो सकते हैं जो किसी न किसी तरह से न्याय के प्रशासन से जुड़े होते हैं। विभिन्न पदों पर आसीन अधिकारी

कार्यपालिका के तहत पदों को अक्सर किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट शक्ति के साथ निहित किया जाता है। अदालत ने कहा,

"क्या संविधान निर्माताओं के पास इस प्रकार की व्यवस्था थी? 'कार्यालयों' को ध्यान में रखते हुए जब उन्होंने एक स्रोत प्रदान किया

उच्च पद पर, उच्च के न्यायाधीश की नियुक्ति

'न्यायिक पद' के धारकों में से न्यायालय?

जवाब, नकारात्मक होना चाहिए। हम हैं।

विचार है कि अनुच्छेद के तहत न्यायिक पद का धारक *217 (2) (क)* का अर्थ है वह व्यक्ति जो केवल व्यायाम करता है।

न्यायिक कार्य, अंतर-पक्षीय कारणों को निर्धारित करते हैं

और न्यायिक क्षमता में निर्णय देता है। वह.

न्यायिक सेवा से संबंधित होना चाहिए जो एक वर्ग के रूप में

कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त है और अनुशासित है राज्य की गरिमा, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखें

न्यायपालिका "।

इन परीक्षणों के अनुसार क्या गठित होता है

संविधान के अनुच्छेद *236* के तहत न्यायिक सेवा

श्रम न्यायालय के न्यायाधीश और औद्योगिक न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक सेवा से संबंधित माना जा सकता है। पदानुक्रम

श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में विचार किया गया है श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों और औद्योगिक न्यायालय का पदानुक्रम

औद्योगिक न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ वरिष्ठ अधिकारी

जिला न्यायाधीशों की स्थिति। श्रम न्यायालयों ने भी इसे अनुच्छेद *227* के तहत उच्च न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति के अधीन माना गया है।

XXXXXX

20. उच्च न्यायालयों से संबंधित भाग *VI* के अध्याय *V* और भाग *VI* के अध्याय *VI* के तहत संवैधानिक योजना अधीनस्थ न्यायालयों के साथ व्यवहार करना मद्रास बार एसोसिएशन *v* को संरक्षित करने के लिए संविधान निर्माताओं की ओर से एक स्पष्ट चिंता को दर्शाता है।

भारत संघ *97*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना कार्यकारी। इस प्रकार अनुच्छेद *233,* जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, यह अपेक्षा करता है कि ऐसी नियुक्तियां

उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा किया गया। अनुच्छेद *233 (2)* की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि "संघ की सेवा में कोई व्यक्ति या

राज्य केवल संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में किसी व्यक्ति को संदर्भित कर सकता है। अनुच्छेद *234* जो इससे संबंधित है -

जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती

न्यायिक सेवा के लिए आवश्यक है कि उनकी नियुक्तियां हो सकती हैं

केवल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बनाया गया राज्य के राज्यपाल ने राज्य के साथ परामर्श के बाद

लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के साथ।

अनुच्छेद *235* में प्रावधान है कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होगा।

न्यायालय*;* और अनुच्छेद *236* "जिला न्यायाधीश" अभिव्यक्ति को व्यापक रूप से शहर के सिविल न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल करने के रूप में परिभाषित करता है। आदि जैसा कि पहले निर्धारित किया गया था, और "न्यायिक सेवा" शब्द का अर्थ है विशेष रूप से व्यक्तियों से युक्त सेवा।

जिला न्यायाधीश और अन्य सिविल के पद को भरने का इरादा

जिला न्यायाधीश के पद से निम्न न्यायिक पद।

इसलिए, शक्तियों के पृथक्करण और न्यायपालिका, न्यायिक सेवा की स्वतंत्रता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए

विशेष रूप से न्यायिक पदों की सेवा पर विचार करता है

जिसकी अध्यक्षता एक जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

उच्च न्यायालय ठीक ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि औद्योगिक और श्रम न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति करेंगे इस प्रकार परिभाषित न्यायिक सेवा का गठन करता है। इसलिए,

श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों की भर्ती की आवश्यकता है संविधान के अनुच्छेद *234* के अनुसार "।

25. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार,

ऊपर उद्धृत निर्णय और पाठ भारत में न्यायालयों के माध्यम से न्याय के प्रशासन के विषय पर पूरी तरह से लागू होते हैं। जहाँ तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, सीखा गया

वकील ने संविधान के अनुच्छेद *50* पर भरोसा रखा, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"*50.* न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना-राज्य

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएँ

राज्य की सार्वजनिक सेवाएँ "।

उपरोक्त अनुच्छेद *50* के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का यह तर्क था कि संविधान

स्वयं न्यायालयों के एक अलग न्यायिक पदानुक्रम को अनिवार्य करता है

कार्यपालिका से।

26. उपरोक्त अधिदेश के साथ, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का यह तर्क था कि

इससे पहले आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम

इस देश की स्वतंत्रता के लिए, और उसके बाद भी, निहित

"प्रश्नों" को निपटाने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय

कानून "कर विवादों से उभर रहा है। यह आगे तर्क दिया गया कि संविधान के प्रवर्तन के बाद भी, प्रभावी रूप से

26.11.1949 से, पर्याप्त निर्णय लेने की न्यायिक शक्ति

कानून के प्रश्न, उच्च न्यायालयों में निहित होते रहे, क्योंकि अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों ने जारी रखा

अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करें। पद बना हुआ है। आज तक अपरिवर्तित। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि ऐतिहासिक, संवैधानिक और

कानूनी रूप से, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार,

उच्च न्यायालयों के पास रहा है, और यह अनुमेय नहीं है

या तो स्वयं संविधान में संशोधन के माध्यम से, या उक्त अपीलीय अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित करने के लिए एक कानून बनाकर

उच्च न्यायालयों द्वारा एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण में प्रयोग किया गया। तीसरा विवादः

27. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा तीसरे तर्क पर प्रस्तुत की गई दलीलों के दौरान, जिसमें यह प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, कि "शक्तियों का पृथक्करण", "कानून का शासन" और "न्यायिक समीक्षा" का गठन करता है।

अन्य बातों के अलावा, संविधान की "मूल संरचना", यह प्रस्तुत की गई थी कि संविधान *(*बयालीसवां संशोधन*)* अधिनियम, *1976* द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद *323* बी उपरोक्त आई. ए. डी. आर. ए. एस. बी. ए. आर. एसोसिएशन *v.* का उल्लंघन था।

भारत का संघ

99

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

संविधान की मूल संरचना के उल्लिखित घटक।

सी. एल. ई. *323* बी. को नीचे निकाला जा रहा हैः

"323 बी. अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण *(1)* उपयुक्त

किसी भी विवाद, शिकायत या अपराध के न्यायाधिकरणों द्वारा खंड *(2)* में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के संबंध में

जिसके संबंध में ऐसे विधानमंडल को बनाने की शक्ति है कानून।

(2)

खंड *(1)* में निर्दिष्ट मामले हैं -

निम्नलिखित, अर्थात्ः

(क*)* अधिरोपण, निर्धारण, संग्रह और प्रवर्तन कोई भी कर*;*

(ख*)* विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात

सीमा शुल्क सीमाएँ*;*

(ग*)* औद्योगिक और श्रम विवाद*;*

(घ*)* राज्य द्वारा अधिग्रहण के माध्यम से भूमि सुधार

अनुच्छेद *31* क में परिभाषित किसी संपत्ति का या किसी

उसमें अधिकार या बुझाने या संशोधन

ऐसे किसी भी अधिकार का या कृषि पर अधिकतम सीमा के रूप में भूमि या किसी अन्य तरीके से*;*

(ई) शहरी संपत्ति पर अधिकतम सीमा;

(च) संसद के किसी भी सदन के लिए चुनाव या

किसी राज्य के विधानमंडल का सदन या कोई भी सदन,

और अनुच्छेद 329 क; (छ) उत्पादन, खरीद, आपूर्ति और वितरण

खाद्य पदार्थों (खाद्य तिलहन और तेलों सहित) और

राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक रूप से ऐसी अन्य वस्तुएँ

अधिसूचना, के लिए आवश्यक सामान होने की घोषणा

इस वस्तु का उद्देश्य और ऐसी वस्तुओं की कीमतों का नियंत्रण

माल; [2014] 10 एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

(ज) किराया, इसका विनियमन और नियंत्रण और मकान मालिकों के अधिकार, स्वामित्व और हित सहित किरायेदारी के मुद्दे और

किरायेदार;

(i) उपखंड (ए) से (एच) और शुल्क में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराध

उन मामलों में से किसी के संबंध में;

(जे) किसी भी मामले के लिए कोई आकस्मिक मामला

उपखंड (ए) से (आई) में निर्दिष्ट।

खंड (1) के अधीन बनाई गई विधि -

(क) के पदानुक्रम की स्थापना के लिए प्रावधान

न्यायाधिकरण;

(ख) अधिकारिता, शक्तियाँ (अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित) और प्राधिकरण को निर्दिष्ट करें जो

उक्त न्यायाधिकरणों में से प्रत्येक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है;

(ग) प्रक्रिया (सीमा और साक्ष्य के नियमों के प्रावधानों सहित) के लिए प्रावधान करना

उक्त न्यायाधिकरणों द्वारा अनुसरण किया गया;

(घ) को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर कर देता है -

अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता।

सभी या इसके अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के संबंध में उक्त न्यायाधिकरणों की अधिकारिता;

की स्थापना से तुरंत पहले किसी भी अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित कोई भी मामला ऐसा न्यायाधिकरण जो इसके भीतर होता

ऐसे न्यायाधिकरण की अधिकारिता यदि कार्रवाई के कारण जिन पर ऐसे मुकदमे या कार्यवाहियां आधारित हैं

ऐसी स्थापना के बाद उत्पन्न हुआ;

(च) इस तरह के पूरक, आनुषंगिक एआर शामिल हैं

परिणामी प्रावधान (मद्रास बार एसोसिएशन के प्रावधानों सहित)

भारत संघ 101

[जगदीश सिंह खेहर, जे।] शुल्क) के रूप में उपयुक्त विधानमंडल के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक समझ सकते हैं, और के लिए

ऐसे न्यायाधिकरणों द्वारा मामलों का त्वरित निपटान और उनके आदेशों का प्रवर्तन।

(4) इस अनुच्छेद के प्रावधान प्रभावी होंगे।

इसके किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी होने के बावजूद

संविधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून में।

स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद में, "उपयुक्त विधानमंडल",

किसी मामले के संबंध में, संसद या, जैसा भी मामला हो, कानून बनाने के लिए सक्षम राज्य विधानमंडल से अभिप्रेत है -

प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामले के संबंध में

भाग XI "।

जहाँ तक उपरोक्त प्रावधान का संबंध है, यह था प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 323 बी के खंड (3) ने स्पष्ट रूप से सभी का उल्लंघन किया है

"मूल संरचना" सिद्धांत के उपरोक्त अवयव।

इस संबंध में यह दावा किया गया कि न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम की स्थापना से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकला कि मौजूदा न्यायिक प्रक्रिया, जहां निर्णय अदालत के समक्ष होता है। कानून को पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया जाना था। इस प्रकार, वर्तमान अपीलीय प्रक्रिया भी जो उच्च न्यायालयों में निहित थी

न्यायाधिकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की मांग की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि

एक समानांतर न्यायिक प्रणाली का निर्माण, प्रावधानों के लिए विदेशी था

संविधान, जिसने न्यायपालिका को एक स्वतंत्र घटक के रूप में मान्यता दी, कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग विधायिका। तदनुसार यह जोरदार रूप से कहा गया था कि न्याय की प्रक्रिया को न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था

न्याय, जो संविधान के तहत स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था। अनुच्छेद *323* बी *(3)* का उपखंड *(*डी*)*, विद्वान के अनुसार

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील, सभी में निहित अधिकार क्षेत्र को विभाजित किया

अनुच्छेद *323* ख *(2)* में निर्दिष्ट विषयों पर मामलों के निर्णय के लिए दीवानी अदालतें, जिसमें न केवल अपील शामिल है।

उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, लेकिन "न्यायिक" की शक्ति भी

संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालयों में निहित समीक्षा। यह विद्वानों का भी तर्क था

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील, कि *[2014] 10* एस. सी. आर. द्वारा दिए गए निर्णयों के बावजूद।

102 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट इस न्यायालय, विधायिका ने दोहराया है और दोहराया है कि क्या था

कानून में अस्थिर पाया गया।

28. उपरोक्त विवाद का प्रचार करते हुए सीखा गया

याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि उपरोक्त

उल्लिखित अनुच्छेद *323* बी को संविधान द्वारा पेश किया गया था।

(बयालीसवां संशोधन*)* अधिनियम, *1976*, जो एक समग्र योजना, न्यायिक शक्ति में भारी कटौती करने के लिए

अन्य सभी आपत्तिजनक प्रावधानों और शक्तियों को हटा दिया गया था। पहले उच्च न्यायालयों में निहित को बहाल किया गया था। हालांकि, भाग

संविधान का *XIV A*, जिसमें अनुच्छेद *323A* और *323B* शामिल किया गया था

नियंत्रण करें। अपने वन विवाद का समर्थन करने के लिए, सीखा वकील ने "न्यायनिर्णयन या विचारण", "विवाद, शिकायत या अपराध" अभिव्यक्तियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

"मुकदमों या कार्यवाहियों आदि का हस्तांतरण जो गठित किए जा सकते हैं।

वर्तमान में जो प्रचलित था, उससे अलग तरीके से। यह इंगित किया गया था कि अनुच्छेद में निहित वन अधिदेश *323* संविधान का बी, मूल के साथ असंगत था

संविधान की संरचना, जो "के पृथक्करण" को अनिवार्य करती है

शक्तियाँ "।

29. उपरोक्त प्रस्तुतियों को देखते हुए, यह था

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का जोरदार तर्क,

कि अनुच्छेद *323* बी *(4)* को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि याचिकाकर्ताओं के तत्काल अनुरोध को इस न्यायालय का समर्थन नहीं मिलता है, तो याचिकाकर्ताओं का वैकल्पिक अनुरोध था, कि

अनुच्छेद *323* बी की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि न्यायालय के अनुरूप समानता प्रदान की जा सके।

अदालतें। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, लागू सेवा की शर्तों का विस्तार करके ऐसा किया जा सकता है। न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रतिस्थापित करने की मांग की गई।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत का यू. एन. आई. सी. एन. *103*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने उनके विवादास्पद तर्क का समर्थन करते हुए इसके द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया न्यायालय, उन सीमाओं और मापदंडों को निर्धारित करता है जिनके भीतर ऐसे न्यायाधिकरण बनाए जा सकते हैं। कानून की घोषणा के बावजूद

इस न्यायालय में यह प्रस्तुत किया गया था कि एन. टी. टी. अधिनियम अधिनियमित किया गया है, जो उन्हीं बुराइयों से ग्रस्त है, जो पहले से ही थे।

असंवैधानिक पाया गया। संक्षिप्तता के कारणों से, यह है

उन सभी निर्णयों को संदर्भित करने के लिए जिन्हें अनुचित माना जाता है तत्काल मुद्दे पर प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा। कहने के लिए पर्याप्त है,

कि उसी की जाँच की जाएगी, केवल रिकॉर्डिंग करते समय

निष्कर्ष निकालते हैं। चौथा विवादः

30. चौथे विवाद को आगे बढ़ाते हुए, विद्वान वकील

याचिकाकर्ताओं के लिए एन. टी. टी. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया, जो एन. टी. टी. की स्वतंत्रता से समझौता करने का प्रभाव डालेंगे। हम संक्षेप में उक्त प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं। अधिनियम, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उजागर किया गया, के दौरान

सुनवाई का क्रम, निम्नानुसारः

(i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5* का पालन किया गया। उसी को यहाँ नीचे निकाला जा रहा हैः

"5. न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता-*(1)* राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है।

उनके द्वारा गठित की जाने वाली पीठों द्वारा

अध्यक्ष।

(2) राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की पीठें आम तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी स्थान पर बैठें या

केंद्र सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, ऐसे अन्य स्थानों को अधिसूचित कर सकती हैः

बशर्ते कि अध्यक्ष पर्याप्त

कारण एक पीठ को पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए अपनी अस्थायी बैठक आयोजित करने की अनुमति देते हैं। सामान्य बैठने की जगह।

!

(3) केंद्र सरकार उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी जिनके संबंध में राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की प्रत्येक पीठ

अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें।

(4) केंद्र सरकार संख्या निर्धारित करेगी।

न्यायपीठों और प्रत्येक न्यायपीठ में दो सदस्य होंगे।

(5) केंद्र सरकार किसी सदस्य का स्थानांतरण कर सकती है

एक राज्य में एक पीठ का मुख्यालय

किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य पीठ का मुख्यालय किसी राज्य के भीतर किसी अन्य पीठ का मुख्यालयः

बशर्ते कि किसी भी सदस्य को इसके बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा

अध्यक्ष की सहमति "।

धारा *5* की उप-धारा *(2)* का उल्लेख करते हुए यह चाहा गया था कि -

जोर देकर कहा कि एन. टी. टी. की पीठों को आम तौर पर काम करना होता है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, यह मुकदमेबाजी से वंचित कर देगा निर्धारिती, उस राज्य के उच्च न्यायालय में जाने की सुविधा जिससे वह संबंधित है। इस संबंध में यह मांग की गई थी कि

इस बात पर जोर दिया जाए कि प्रत्येक कर संबंधी विवाद में एक तरफ एक अभिदाता होता है और दूसरी तरफ राजस्व। तदनुसार, यदि एन. टी. टी. को सामान्य रूप से बैठने के लिए अनिवार्य किया जाता है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दूरदराज के निर्धारिती

निवारण के लिए राज्यों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा उनकी शिकायत, विशेष रूप से अपीलीय स्तर पर। इसके अलावा

कठिनाइयाँ, यह बताया गया था, कि प्रत्येक प्राप्तकर्ता

अथाह वित्तीय व्यय के अधीन होना। एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5* की उप-धारा *(5)* का उल्लेख करते हुए, यह था याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति, कि केंद्र सरकार को एक हस्तांतरण करने की शक्ति निहित थी

एक राज्य में एक पीठ के मुख्यालय से सदस्य,

दूसरे राज्य में एक अन्य पीठ का मुख्यालय। केंद्र सरकार के लिए यह भी खुला था कि वह किसी सदस्य को उसी राज्य में एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकती है। यह प्रस्तुत किया गया था,

कि उच्च न्यायालयों के मामले में, ऐसी शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है

मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रशासन के सर्वोत्तम हित में मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

न्याय की। यह प्रस्तुत किया गया था कि केंद्र सरकार, जो

एक हितधारक है, जो हस्तांतरण की उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है

एन. टी. टी. के वर्तमान सदस्यों के उत्पीड़न और शोषण के लिए।

दूसरे शब्दों में, एक असुविधाजनक सदस्य को दूर ले जाया जा सकता है, और एक ऐसे सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो वांछित रेखा को खींच लेगा।

(ii) इसी तरह, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का उल्लेख किया गया है।

एन. टी. टी. अधिनियम की धारा 6 को यह प्रदर्शित करने के लिए कि इसका निर्णय प्रक्रिया पर भी कमजोर प्रभाव पड़ेगा। एन. टी. टी. अधिनियम की धारा 6 यहाँ पुनः प्रस्तुत की गई हैः

"6. अध्यक्ष और अन्य की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ

सदस्य -

(1) राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष होंगे -

एक व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।

(2) एक व्यक्ति नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा

सदस्य जब तक कि वह

(क) का न्यायाधीश है, या रहा है, या होने का पात्र है

उच्च न्यायालय; या

(ख) आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग का सदस्य है या रहा है।

कम से कम पाँच के लिए सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण

बरसों "।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बताया कि उप-धारा

(2) , उपरोक्त, एन. टी. टी. के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। के खंड (ए) का उल्लेख करते हुए एन. टी. टी. अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) प्रस्तुत की गई थी,

कि एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र है, एन. टी. टी. के सदस्य के रूप में योग्य माना जाना। हमें आमंत्रित कर रहे हैं

संविधान के अनुच्छेद 217 पर ध्यान दिया गया था, कि

एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कम से कम 10 वर्षों से,

एक या दूसरे उच्च न्यायालय, [2014] 10 एस. सी. आर. के समक्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य किया।

सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य माना गया है

एनटीटी से। एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *8* का उल्लेख करते हुए यह बताया गया था

कि एन. टी. टी. के सदस्य को एन. टी. टी. के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से पांच साल का कार्यकाल प्रदान किया जाता है। यह इंगित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद *217* के संदर्भ में, एक व्यक्ति आसानी से एक व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएगा।

35-40 वर्ष की आयु में या उसके आसपास न्यायाधीश, और इस तरह, यदि वह

केवल पाँच साल के कार्यकाल का आश्वासन दिया जाता है, यह संभव नहीं होगा

बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए,

क्योंकि, पाँच वर्ष की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, अपने भविष्य के बारे में उनके मन में हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती थी।

विस्तार नहीं दिए जाने की स्थिति में। इस पर भरोसा करें

एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *6 (2)* के खंड *(बी)* में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का यह भी निवेदन था कि

के अधीन गठित अपीलीय न्यायाधिकरणों के सदस्य

आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम भी एन. टी. टी. के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं। इसमें

पक्ष की ओर से यह दावा करने की मांग की गई थी कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के लेखाकार सदस्य भी हैं, जो

एन. टी. टी. के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनें। यह था।

प्रस्तुत किया गया, कि कानून की बारीकियों पर न्यायिक अनुभव,

विशेष रूप से विभिन्न पहलुओं पर, जिन पर कर मामलों का निर्णय लेते समय विचार करने की आवश्यकता है, उनके लिए अलग होगा।

क्योंकि वे केवल इस विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं

लेखांकन। यह इंगित किया गया था कि अधिकार क्षेत्र में निहित है

एन. टी. टी., उच्च न्यायालय के लिए एक वैकल्पिक अधिकार क्षेत्र है, और इस तरह, यह समझना मुश्किल है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के एक लेखाकार सदस्य से कैसे उम्मीद की जा सकती है।

महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करना

(iii) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तब एनटीटी अधिनियम की धारा *7* की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उक्त खंड है यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 7. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति-*(1)*

& मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *107*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

उप-धारा *(2)* के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा। *(2)* अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे -

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त

एक चयन समिति की सिफारिशें जिसमें

(क*)* भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश

उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय*; (* ख*)* विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव

((c) वित्त मंत्रालय में सचिव *(* राजस्व विभाग*)*।

(3) अध्यक्ष या किसी अन्य की कोई नियुक्ति नहीं

सदस्य को केवल किसी कारण से अमान्य कर दिया जाएगा

चयन के गठन में कोई रिक्ति या कोई दोष

समिति "।

धारा *7* की उप-धारा *(2)* के अवलोकन से पता चलता है कि

इंगित किया कि तीन सदस्यीय चयन समिति में से कार्यपालिका के दो प्रतिनिधि थे, और केवल चयन समिति में एक सदस्य न्यायपालिका से था।

तदनुसार यह दावा किया गया कि दोनों प्रतिनिधि

कार्यपालिका से संबंधित प्रत्येक के परिणाम को नियंत्रित करेगा

चयन प्रक्रिया। चूंकि एन. टी. टी. एक विकल्प था

पहले उच्च न्यायालय के पास निहित अधिकार क्षेत्र, यह प्रस्तुत किया गया था,

कि एन. टी. टी. के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन की वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रचलित थी। यह सब

यह अनिवार्य और आवश्यक है कि चयन प्रक्रिया को समान हो, जैसा कि जगह में है, क्योंकि अदालत होना चाहती है

प्रतिस्थापित। यह विद्वान वकील का भी तर्क था याचिकाकर्ताओं के लिए, कि *108* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. की धारा *7 (2)* के समान प्रावधान।

एन. टी. टी. अधिनियम, इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य बनाम में निरस्त कर दिया गया था। लेबर लॉ प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन *(ऊपर)*।

(iv) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तब हमें आमंत्रित किया

एनटीटी अधिनियम की धारा *8* पर ध्यान दें। धारा *8* को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

" 8. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के कार्यकाल -

अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य पद धारण करेंगे। उस तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिस दिन वह

अपने पद पर प्रवेश करता है लेकिन फिर से पात्र होगा नियुक्तिः

बशर्ते कि कोई भी अध्यक्ष या अन्य सदस्य

पद प्राप्त करने के बाद इस तरह से पद धारण करें,

(क) अध्यक्ष के मामले में, साठ-आठ वर्ष की आयु वर्ष*;* और

(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में, आयु साठ-पाँच साल। *"*

विद्वान वकील के अनुसार, धारा *8* के अवलोकन से पता चलता है कि एन. टी. टी. का एक अध्यक्ष और एक सदस्य पद धारण करेंगे। एन. टी. टी. में उनकी नियुक्ति की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए। हालाँकि, यह इंगित करने की कोशिश की गई थी कि एक व्यक्ति

इस तरह से नियुक्त, स्पष्ट रूप से पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है। यह था।

यह दावा करने की मांग की गई कि पुनर्नियुक्ति के लिए एक प्रावधान, स्वयं की स्वतंत्रता को कम करने का प्रभाव डालेगा

एनटीटी के सदस्य। यह दावा करने की कोशिश की गई थी कि प्रत्येक

एन. टी. टी. में नियुक्त लोगों में से एक को राजस्व को खुश करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *8* के तहत पुनर्नियुक्ति का अनुरोध किया जा सके। इस संबंध में

प्रस्तुत किया गया था कि एक न्यायाधिकरण में नियुक्ति का कार्यकाल, जो एक उच्च न्यायालय का स्थान लेगा, एक न्यायाधीश के समान होना चाहिए

उच्च न्यायालय से।

(v) तब हमारा ध्यान एन. टी. टी. की धारा *13* की ओर आकर्षित किया गया।

अधिनियम, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

व्यक्ति या एक या अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट को अधिकृत करना या कानूनी व्यवसायियों को अपने मामले को पेश करने के लिए

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण।

(2) सरकार एक या अधिक कानूनी रूप से अधिकृत कर सकती है।

व्यवसायियों या इसके किसी भी अधिकारी को अपना मामला पहले प्रस्तुत करना

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(क*)* "चार्टर्ड एकाउंटेंट" का अर्थ है एक चार्टर्ड एकाउंटेंट। उप-धारा के खंड *(*ख*)* में परिभाषित लेखाकार

(1) सनदी लेखाकार अधिनियम, *1949 (1949* का *38)* की धारा *2* और जिसने एक

की उप-धारा *(1)* के तहत अभ्यास का प्रमाण पत्र उस अधिनियम की धारा *6;*

(ख*)* "विधि व्यवसायी" से एक अधिवक्ता, वकील या किसी उच्च न्यायालय का कोई वकील अभिप्रेत है, और इसमें एक -

व्यवहार में प्लीडर "।

यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्धारिती को अनुमति देने के अलावा

एन. टी. टी. के समक्ष स्वयं का प्रतिनिधित्व करना, धारा *13* उसे एक या अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देती है या कानूनी व्यवसायियों। अब तक, विद्वान वकील के अनुसार

याचिकाकर्ताओं को लगता है कि एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *13 (1)* में कोई कठिनाई नहीं है। हालांकि, "किसी भी व्यक्ति को विधिवत अधिकृत" करने की अनुमति देना।

निर्धारिती द्वारा एन. टी. टी. के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए स्पष्ट रूप से

समझ में नहीं आता। यह प्रस्तुत किया गया था कि एन. टी. टी. का मुख्य कार्य कर मुद्दों पर कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निपटारा करना होगा, और इस तरह, धारा *13 (1)* के तहत, यह इसके लिए खुला होगा -

एक निर्धारिती जो किसी व्यक्ति को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करता है, यहाँ तक कि

हालाँकि वह उन क्षेत्रों में पूरी तरह से अयोग्य है जिन पर निर्णय प्रक्रिया आयोजित की जानी है। इसी तरह, यह याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क है, इसके अलावा

[2014] 10 एस सी आर।

अपने किसी भी अधिकारी के माध्यम से। यह दावा करने की कोशिश की गई थी कि एक

प्रावधान के पाठ को समझना एक बात है, जबकि इसकी विवेचित संदर्भ में व्याख्या करना बिल्कुल अलग है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया था कि राजस्व के अधिकारी, जिनकी कमी है व्याख्यात्मक कौशल में, प्रतिनिधित्व के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त होगा

एन. टी. टी. से पहले राजस्व।

उत्तरदाताओं द्वारा विपक्ष में प्रस्तुतियाँ /

हस्तक्षेप करने वालेः

पहला विवादः

31. पहले विवाद के जवाब में, अर्थात्, कि

एन. टी. टी. की स्थापना के कारण गलत और गैर-मौजूद थे, और इस तरह, संदर्भ के तहत विधायी अधिनियम

आयकर अधिनियम के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों से कानून के "महत्वपूर्ण प्रश्नों" पर, सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम को दरकिनार किया जाना चाहिए; यह उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क था,

कि याचिकाकर्ताओं के हाथों प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ीं,

तथ्यात्मक की अनुचित समझ पर आधारित थे

पृष्ठभूमि. इस संबंध में यह दावा किया जाना चाहिए कि -

कर प्राप्तियाँ भारत में राजस्व का प्राथमिक स्रोत हैं। भारत सरकार अपनी बजटीय आवश्यकताओं को पूरा करती है

राजस्व प्राप्तियाँ। यह समझाने की कोशिश की जाती है कि कर

एक स्थापित प्रशासनिक और कानूनी संरचना द्वारा एकत्र किया गया।

एक ओर तो कर देनदारी को बढ़ाने से भी कमी आएगी

निर्धारिती का लाभ, इससे राजस्व में वृद्धि होगी

सरकार की रसीदें। दूसरी ओर, कर देयता से छूट से निर्धारिती का लाभ बढ़ेगा, लेकिन

सरकार की राजस्व प्राप्तियों को कम करना। इसे ध्यान में रखते हुए

लाभ और हानि परिदृश्य से ऊपर, कर हानि का प्रशासन, है विवादों और मुकदमेबाजी के परिणामस्वरूप एक अंतर्निहित प्रवृत्ति। मुकदमेबाजी की प्रक्रिया मुख्य रूप से नवाचार को अपनाने पर आधारित है।

राजस्व और राजस्व दोनों द्वारा कानून की व्याख्या के साधन

कर दाता। नतीजतन, महत्वपूर्ण समय खर्च किया जाता है, पर लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी, जिसमें करदाता और सरकारी मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत का संघ *111*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

एक दूसरे के खिलाफ सींग बंद करें। स्वाभाविक रूप से इससे राजस्व प्रभावित होता है। हजारों करोड़ रुपये के कर के रूप में आय, इस तरह के मुकदमे में उलझी हुई है। होना चाहा गया था

उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटाबेस के अनुसार, भारतीय कंपनियों के पास विवादित करों में एक बड़ी राशि है। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष *2011-2012* के दौरान *30* कंपनियाँ जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार बंद था

विवादित करों का अनुमान *Rs.42,388* करोड़। विद्वान वकील के अनुसार उपरोक्त विवादित कर देयता

उत्तरदाताओं, की राशि से *27* प्रतिशत की वृद्धि थी पिछला वर्ष, जो कि *Rs.33,339* करोड़ अनुमानित था।

32. प्रत्यक्ष करों पर विवादों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था,

30,213 प्रत्यक्ष कर के मामले उच्च न्यायालयों में लंबित थे। यह प्रस्तुत किया गया कि लोकसभा को अतिरिक्त रूप से सूचित किया गया था कि विभिन्न स्तरों पर कर की विवादित राशि का अनुमान लगाया गया था

रुपये. *4,36,741* करोड़, *31.12.2011* पर। इसकी और मांग की गई थी।

इस बात पर जोर दिया जाए कि पिछले वर्ष, विभिन्न स्तरों पर विवादित राशि के संबंध में अनुमान

रु. *2,43,603* करोड़ की राशि। तदनुसार यह चाहा गया था कि

इंगित किया, कि प्रत्येक सफल वर्ष के साथ, न केवल कर

संबंधित मुकदमेबाजी को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा था, इस तरह के मामलों में अवरुद्ध वित्त में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी

विषय हैं। *33.* इसी तरह यह भी बताया गया कि अप्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण से जुड़े मामलों की संख्या इसी तरह के दुर्भाग्यपूर्ण होने का अनुमान लगाती है

प्रतिबिंब। इस संबंध में यह इंगित करने की मांग की गई थी कि

31.12.2012 पर, लंबित सीमा शुल्क विवादों की संख्या लगभग *17,800* थी, जिसमें

इसमें लगभग *7,400* करोड़ रुपये शामिल थे। जहाँ तक *31.10.2012* पर लंबित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मामलों की संख्या का संबंध है, यह आंकड़ा लगभग *19,800* था और *112* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

इसमें शामिल राशि लगभग *Rs.21,450* करोड़ थी। के द्वारा

ऊपर दर्शाए गए आंकड़ों को जोड़ते हुए, अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों के संबंध में, यह सुझाव दिया गया था कि

लगभग *Rs.28,850* करोड़। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया था कि *17,800* सीमा शुल्क मामलों में से, लगभग *6,300* न्यायनिर्णयक लेल मामला किछु समयसँ लंबित छल।

एक से तीन साल तक, और लगभग *2,800* सीमा शुल्क मामले तीन से अधिक वर्षों से निर्णय के लिए लंबित थे।

वर्षों से। इसी तरह, *19,800* केंद्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में से *1,600* मामले

एक से लेकर एक के बीच की अवधि के लिए निर्णय के लिए मामले लंबित थे।

तीन साल*;* और *240* मामले तीन साल से अधिक समय से निर्णय के लिए लंबित थे।

34. यह उत्तरदाताओं के कहने पर इंगित किया गया था,

कि कई कारणों ने लंबे समय तक जारी रखने में योगदान दिया

कर विवाद। लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि

कर मुकदमेबाजी में कानून में स्पष्टता की कमी। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप कई व्याख्याएँ हुईं। जोड़ा गया

कि, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के अनुसार, कई अपीलीय स्तरों का अस्तित्व, और स्वतंत्र

क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय, जिसके परिणामस्वरूप परस्पर विरोधी न्यायालयों का अस्तित्व था

अथाह देरी और बहुलता में योगदान कार्यवाही।

35. ऊपर वर्णित कारकों के आधार पर, यह उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति थी, कि

अधिक मात्रा में विवादों के बोझ का प्रभाव न्यायनिर्णायक के साथ-साथ न्यायिक प्रणाली पर भी पड़ा था। यह बताया गया था कि न्यायिक प्रणाली पर पहले से ही भारी बोझ था

अनसुलझे मामलों की महत्वपूर्ण संख्या का भार। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्येक वर्ष मामलों को जोड़ने से न केवल करदाता की असुविधा बढ़ती है, बल्कि राजस्व में भी वृद्धि होती है

सरकार द्वारा अर्जित। यह इंगित किया गया था कि क्षण स्थिति ने एक अनिश्चित और अस्थिर व्यवसाय पैदा कर दिया

पर्यावरण, करदाताओं के बजट बनाने में सक्षम नहीं होने के कारण, कर मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *113*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

लागतें। विद्वान वकील के अनुसार, महत्वपूर्ण रूप से ऐसी अनिश्चितता दो कारकों से उभरी है। सबसे पहले, कानून अपने आप में जटिल था, और इसलिए, अनिश्चित था। और दूसरा, एक के लिए

निश्चितता की एक डिग्री प्राप्त करने के लिए कानून की व्याख्या

उच्चतम न्यायालय स्तर पर मुकदमेबाजी के कई दौर की आवश्यकता थी। यह.

प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान परिदृश्य में विवाद समाधान तंत्र में सुधार का आह्वान किया गया था, और

सचेत प्रथाओं और प्रक्रियाओं का परिचय, जिसका उद्देश्य है आरंभ को सीमित करने के साथ-साथ कर विवादों को लंबा करना। इसलिए, यह विद्वान वकील का समर्पण है।

उत्तरदाताओं के लिए, कि हाथों में किए गए दावे

याचिकाकर्ता, पहला तर्क पेश करते हुए, पूरी तरह से थे

गलत धारणा, और इस तरह, अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

दूसरा तर्कः

36. दूसरे तर्क के जवाब में, अर्थात्, कि विधायिका के लिए मुख्य न्यायिक को निरस्त करना अस्वीकार्य है

अपीलीय कार्य, जो पारंपरिक रूप से उच्च न्यायालय के पास निहित हैं, या यह कि इसे न्यायाधिकरणों के एक स्वतंत्र, समानांतर अर्ध-न्यायिक पदानुक्रम के साथ निहित करने की अनुमति नहीं है, प्रस्तुत किया गया था, कि याचिकाकर्ता मामले को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझने में सक्षम नहीं थे। यह बताया गया कि एन. टी. टी. अधिनियम

एक कानून है जो एक पदानुक्रम में एक अपीलीय मंच बनाता है

सामने आने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए एक उपाय के रूप में

कर लगाने वाले कानूनों का। विशेष के उद्देश्य की पूरी तरह से सराहना करना कानून द्वारा बनाया गया उपाय, अधिकार की प्रकृति और/या

कराधान कानूनों और प्रवर्तन द्वारा बनाई गई देयता

जिनके लिए ये उपचार प्रदान किए गए हैं, उनकी आवश्यकता है

सही परिप्रेक्ष्य में समझें। तदनुसार,

सही कारण पर बहस करते हुए, विद्वान सलाहकार ने प्रस्ताव की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिस तरह से, जैसा कि समझ में आया था

उत्तरदाताओं। इस संबंध में प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं -

संक्षेप में आगे बताया जा रहा है।

37. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील का यह तर्क था कि आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और

आबकारी अधिनियम के साथ-साथ अन्य कर विधियां भी एक वैधानिक *114* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. बनाती हैं।

दायित्व। उक्त वैधानिक दायित्व का कोई अस्तित्व नहीं है।

कानून स्वयं। उक्त वैधानिक दायित्व का कोई अस्तित्व नहीं है।

सामान्य कानून में। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि यह लंबे समय से अच्छी तरह से तय किया गया था, कि जहां दायित्व का अनुरोध करने का अधिकार सामान्य कानून में मौजूद नहीं था, लेकिन एक क़ानून का निर्माण था, जो

एक साथ एक विशेष और विशेष उपचार के लिए प्रदान किया गया

इसे लागू करने के लिए, क़ानून द्वारा प्रदान किए गए उपाय का पालन करना बाध्य था। इस तरह के वैधानिक दायित्व के संबंध में, यह नहीं था सामान्य कानून में कार्रवाई द्वारा पक्ष के लिए आगे बढ़ने के लिए सक्षम।

इस न्यायालय द्वारा धूलाभाई बनाम में अभिलिखित। एम. पी. राज्य *(1968) 3* एस. सी. आर. *662* जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

"9. इन अपीलों में जो सवाल उठता है, वह यह है कि

अन्य कानूनों के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष और किया गया है

संविधान पीठ को संदर्भित किया जाता है और इस तरह वे हैं हमारे सामने। शुरुआत में ही हम देख सकते हैं कि

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता सभी को शामिल करती है सिवाय इसके कि जिस हद तक इसे कानून के एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा बाहर रखा गया है या

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *9* का तात्पर्य। कैसे*?* धारा *9* का संचालन शायद संदर्भ द्वारा सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है।

विल्स, जे. द्वारा उल्लिखित मामलों की श्रेणियों के लिए। में

को. वी.

वॉल्वरहैम्प्टन

नया।

वाटरवर्क्स

हॉक्सफोर्ड, *[1859] 6* सी. बी. *(*एनएस*) 336*-वे हैंः

"एक वह है जहाँ एक देयता मौजूद थी

सामान्य कानून, और उस दायित्व की पुष्टि एक

कानून जो एक विशेष और विशिष्ट रूप देता है

उस उपचार से अलग उपचार जो मौजूद था

सामान्य कानूनः वहाँ, जब तक कि क़ानून में शामिल नहीं है

ऐसे शब्द जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से

पक्ष द्वारा मुकदमा किए जाने वाले सामान्य कानून उपचार को बाहर करें

उसका चुनाव या तो उस या वैधानिक आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v* को आगे बढ़ाने के लिए है।

भारत का संघ *115*

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

उपचार। मामलों का दूसरा वर्ग है, जहाँ मूर्ति केवल मुकदमा करने का अधिकार देती है, लेकिन प्रदान करती है,

उपचार का कोई विशेष रूप नहीं हैः वहाँ, पार्टी कर सकते हैं केवल सामान्य कानून में कार्रवाई द्वारा आगे बढ़ें। लेकिन वहाँ

एक तीसरी श्रेणी है, अर्थात। , जहाँ कोई दायित्व मौजूद नहीं है

सामान्य कानून एक क़ानून द्वारा बनाया जाता है जो

उसी समय एक विशेष और विशेष उपचार देता है

इसे लागू करने के लिए। द्वारा प्रदान किया गया उपचार

कानून का पालन किया जाना चाहिए और यह सक्षम नहीं है

मामलों पर लागू पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पक्षकार

दूसरे दर्जे का "।

जे. विल्स के इस विचार को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा स्वीकार किया गया था।

नेविल वी। लंदन *'*एक्सप्रेस*'* अखबार लिमिटेड, *[1919]* ए. सी. *368*

XXX

XXX

XXX

35. इल्लूरी सुबैया की फर्म के दो मामलों में से कोई भी या

कमला मिल्स को श्रृंखला के विपरीत चलने के लिए कहा जा सकता है

पहले देखे गए मामले। इस जांच का परिणाम इस न्यायालय में व्यक्त किए गए विविध विचारों को इस प्रकार कहा जा सकता हैः

निम्नलिखित हैः

(1) जहाँ कानून आदेशों को अंतिम रूप देता है। विशेष न्यायाधिकरणों का सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

सूट पहनें। हालाँकि, इस तरह का प्रावधान नहीं है उन मामलों को बाहर करें जहाँ के प्रावधान

विशेष अधिनियम का पालन नहीं किया गया है या

सांविधिक न्यायाधिकरण ने इसके अनुरूप कार्य नहीं किया है

न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांत।

(2) जहाँ अधिकारिता का एक एक्सप्रेस बार है

न्यायालय की, योजना की परीक्षा

पर्याप्तता या पर्याप्तता का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम

प्रदान किए गए उपचारों में से कुछ प्रासंगिक हो सकते हैं लेकिन जेपीआरईएमई कोर्ट रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. नहीं हैं।

दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने के लिए निर्णायक।

जहाँ कोई स्पष्ट बहिष्करण नहीं है

इरादे का पता लगाने के लिए उपचारों और विशेष अधिनियम की योजना की जांच आवश्यक हो जाती है और जांच का परिणाम हो सकता है - निर्णायक। बाद के मामले में यह देखना आवश्यक है कि क्या

कानून एक विशेष अधिकार या दायित्व बनाता है और

अधिकार या दायित्व के निर्धारण के लिए प्रावधान करता है

और आगे यह निर्धारित करता है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्नों का निर्धारण इस प्रकार गठित न्यायाधिकरण, और क्या उपाय हैं

आम तौर पर दीवानी न्यायालयों में कार्रवाई से जुड़े होते हैं

उक्त प्रतिमा द्वारा निर्धारित या नहीं।

(3) विशेष अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती

उस अधिनियम के तहत गठित। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी न्यायाधिकरणों के निर्णय के संशोधन या संदर्भ पर उस प्रश्न में नहीं जा सकते।

(4) जब कोई प्रावधान पहले ही घोषित किया जा चुका हो

किसी की असंवैधानिक या संवैधानिकता

प्रावधान को चुनौती दी जानी है, एक मुकदमा खुला है। एक लिखावट

प्रमाणपत्र में धनवापसी के लिए एक निर्देश शामिल हो सकता है यदि दावा स्पष्ट रूप से सीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित समय के भीतर है लेकिन यह एक अनिवार्य उपाय नहीं है

(5) जहां विशेष अधिनियम में संवैधानिक सीमाओं से अधिक एकत्र किए गए कर की वापसी के लिए कोई तंत्र नहीं है या अवैध रूप से एकत्र किया गया है, एक मुकदमा निहित है। *(6)* मूल्यांकन की संवैधानिकता के अलावा इसकी शुद्धता के प्रश्न निर्णय के लिए हैं।

यदि अधिकारियों के आदेशों को अंतिम घोषित किया जाता है या विशेष अधिनियम में एक स्पष्ट निषेध है तो अधिकारियों और एक दीवानी मुकदमा नहीं होता है।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *117*

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

दोनों ही मामलों में विशेष अधिनियम की योजना की जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह एक प्रासंगिक जांच है।

(7) सिविल न्यायालय की अधिकारिता का बहिष्करण

शर्तों के बिना आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है

ऊपर दिए गए नियम लागू होते हैं "।

38. उपरोक्त प्रस्तुतियों के अलावा, यह मांगा गया था कि

यह दावा किया जा सकता है कि आयकर अधिनियम ने स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया है

दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता। इस संबंध में उल्लेख किया गया था

आयकर अधिनियम की धारा *293,* जिसे निकाला जा रहा है

इसके नीचेः

"293. दीवानी अदालतों में मुकदमों का बार। - कोई सूट नहीं लाया जाएगा।

किसी भी दीवानी अदालत में किसी भी कार्यवाही को अलग करने या संशोधित करने के लिए

इस अधिनियम के तहत लिया गया या आदेश दिया गया, और कोई अभियोजन नहीं

या इस अधिनियम के तहत सद्भावना से किए गए या किए जाने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य के लिए सरकार का कोई अधिकारी। *39.* यह आगे इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है

बैराक्लो वी. में कथन। ब्राउन *(1897)* ए. सी. *615,* कि यदि एक क़ानून एक अधिकार प्रदान करता है और उसी श्वास में इस तरह के अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रावधान करता है कि इस तरह के क़ानून द्वारा प्रदान किया गया उपाय है

अनन्य। प्रीमियर ऑटोमोबाइल में इस सिद्धांत को लागू करना वी. कमलेकर शांताराम वाडके, *(1976) 1* एस. सी. सी. *496 513* पर,

इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"23. संक्षेप में, किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लागू सिद्धांत

इस प्रकार कहा जाएः

(1) यदि विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है और न ही है

अधिनियम के तहत किसी अन्य अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित

समाधान केवल दीवानी न्यायालय में निहित है।

(2) यदि विवाद एक औद्योगिक विवाद है जो सामान्य या सामान्य कानून के तहत अधिकार या दायित्व से उत्पन्न होता है न कि *118* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

अधिनियम के तहत, दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वैकल्पिक है,

इसे चुनने के लिए संबंधित दावेदार के चुनाव पर छोड़ दें

राहत के लिए उसका उपाय जो प्रदान करने के लिए सक्षम है

एक विशेष उपचार में।

(3) यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत बनाए गए अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित है, तो केवल

दावेदार के लिए उपलब्ध उपाय निर्णय प्राप्त करना है। अधिनियम के तहत।

(4) यदि वह अधिकार जिसे लागू करने की मांग की जाती है वह एक अधिकार है।

अधिनियम के तहत बनाया गया जैसे कि अध्याय वीए तब

इसके प्रवर्तन के लिए उपाय या तो धारा *33* सी या

औद्योगिक विवाद को उठाना, जैसा भी मामला हो।

प्रीमियर ऑटोमोबाइल मामले *(*ऊपर*)* के पैराग्राफ *12* में, इस अदालत ने बैराक्लो बनाम में लॉर्ड वॉटसन के शब्दों को उद्धृत किया।

निम्नलिखित प्रभाव के लिए ब्राउन *(*ऊपर*):*

*"*अधिकार और उपाय एक साथ दिए जाते हैं और एक

दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है *"*

40. यह इस कारण से है, विद्वान वकील के अनुसार

प्रत्यर्थियों, कि दीवानी अदालतों, यहां तक कि उच्च न्यायालय भी है

मूल अधिकारिता, अधिकारों का सृजन करने और उपचार प्रदान करने वाले ऐसे विशेष कानूनों के दायरे में आने वाले मामलों पर मुकदमों को स्वीकार नहीं करेगी।

*[*आर्गोसम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम देखें। ऑक्सबी *(1964) 1* ऑल ई. आर. *791 796*-एच पर*]*।

*"*उन परिच्छेदों में अंतर्निहित सिद्धांत मुझे वर्तमान मामले की धारा *341* पर लागू होता प्रतीत होता है।

आयकर अधिनियम, *1952*, नुकसान के संदर्भ में समायोजन कर देयता का अधिकार प्रदान करता है। खंड से स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है*;* सांस में अनुभाग एक विशिष्ट उपचार देता है और एक निर्धारित करता है

इसके प्रवर्तन के लिए विशिष्ट न्यायाधिकरण, अर्थात् जनरल

आयोग या विशेष आयुक्त। इनमें

मेरी राय में परिस्थितियों में, करदाता को मद्रास बार एसोसिएशन *v* का सहारा लेना चाहिए।

भारत संघ *119*

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

वह उपाय और वह न्यायाधिकरण। नियत समय में यदि संबंधित आयुक्तों के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह मामले में उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन घोषणा द्वारा उच्च न्यायालय के किसी भी मूल अधिकार क्षेत्र में या

अन्यथा, मेरे निर्णय में, बाहर रखा गया है।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें, जो आयकर अधिनियम की धारा 260 ए को प्रतिस्थापित करती हैं और आयकर अधिनियम के उच्च न्यायालय को अलग करती हैं।

अपीलीय उपचार और इसे एन. टी. टी. में निहित करना असंवैधानिक है। क्योंकि यह कानून के शासन के सिद्धांतों में एक प्रवेश का गठन करता है

और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विद्वान वकील के अनुसार,

गलत होते हैं।

41. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के अनुसार,

याचिकाकर्ताओं के तर्क में भ्रम यह है कि वे हैं इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि जहां तक एन. टी. टी. अधिनियम का संबंध है, कोई सामान्य कानूनी उपाय नहीं है जिसे अब अलग कर दिया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 260 ए और धारा 35 (जी), (एच), (आई)

आबकारी अधिनियम की सभी सांविधिक रूप से निहित अपीलें उच्च न्यायालय में थीं, और इस तरह, जैसा कि उपरोक्त मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, पूरी तरह से विच्छेदित किया जा सकता है। विद्वानों के अनुसार

वकील, एन. टी. टी. अधिनियम, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की तुलना में एक निश्चित और मजबूत आधार पर था, जो सामने आया

भारत संघ बनाम में विचार। मद्रास बार एसोसिएशन,

(2010) 11 एस. सी. सी 87. तदनुसार, चूंकि वर्तमान अधिनियम के तहत कोई सामान्य कानूनी उपाय प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया थाः कि याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे की गई दलीलें थीं

खड़े होने के लिए पैर नहीं हैं। यहां तक कि जब कंपनी अधिनियम स्थापित किया गया था,

कंपनी विधि न्यायाधिकरण और कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को प्रतिस्थापित करते हुए, भारत संघ बनाम में यह न्यायालय। मद्रास बार एसोसिएशन (ऊपर), आयोजित

कि उक्त प्रावधान वैध थे और असंवैधानिक नहीं थे। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"87. संविधान में न्यायिक शक्ति पर विचार किया गया है न्यायालयों और न्यायाधिकरणों दोनों द्वारा प्रयोग किया जाता है। शक्तियों को छोड़कर

और उच्च न्यायालयों में निहित क्षेत्राधिकार

न्यायालयों के संविधान, शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र हैं, 120

[2014] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधायी अधिनियमों द्वारा नियंत्रित और विनियमित। उच्च न्यायालयों को अपीलों, संशोधनों और संदर्भों पर विचार करने और उनकी सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। कई विशिष्ट विधायी में निहित प्रावधानों का

अधिनियम। यदि उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र हो सकता है

उच्च न्यायालयों द्वारा सुनवाई के लिए अपीलों, संशोधनों और संदर्भों का प्रावधान करके बनाया गया, अधिकार क्षेत्र भी हो सकता है

अपील के प्रावधानों को हटाकर,

संशोधन या संदर्भ। यह भी कहा गया है कि विधायिका विशिष्ट के संदर्भ में न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति है

अधिनियम बनाते हैं और उन्हें इस तरह के विशेष मामलों से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में विवादों को तय करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं

अधिनियम। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायिका के पास पारंपरिक रूप से न्यायिक कार्यों को स्थानांतरित करने की कोई शक्ति नहीं है न्यायालयों द्वारा न्यायाधिकरणों को निष्पादित किया गया।

88. यह तर्क कि "पूर्ण-बिक्री हस्तांतरण" नहीं हो सकता है

शक्तियों की "गलत धारणा है। यह किसी का मामला नहीं है कि देश में अदालतों का पूरा कामकाज स्थानांतरित कर दिया जाता है।

न्यायाधिकरण। कानून बनाने के लिए संसद की क्षमता

या के अधीन उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने के लिए न्यायाधिकरणों का निर्माण करना

किसी विशेष क़ानून या क़ानून से संबंधित नहीं हो सकता है

विवादित। जब एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है

कंपनी अधिनियम, उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने के लिए सशक्त

उक्त अधिनियम और कानून के तहत शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है

" "उच्च न्यायालय" के स्थान पर "न्यायाधिकरण" अनिवार्य रूप से होगा कंपनी कानून मामलों का "पूर्ण-बिक्री हस्तांतरण" होना

न्यायाधिकरण। यह एक निर्माण का एक अपरिहार्य परिणाम है न्यायाधिकरण, ऐसे विवादों के लिए, और किसी भी तरह से वैधता को प्रभावित नहीं करेगा

न्यायाधिकरण का निर्माण करने वाले कानून का "।

42. इसी तरह, जिला न्यायाधीश को अंतिम खंडों के साथ संशोधन का प्रावधान करने वाले वैधानिक प्रावधानों को भी लागू किया गया है।

उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों को बाहर करने के लिए व्याख्या की गई

सीपीसी की धारा *115* के तहत। इस संबंध में औंडल अम्मल बनाम का उल्लेख किया गया था। सदाशिवन पिलाई, *(1987) 1* एस. सी. सी. *183,*

जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः

एड्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *121*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

" 15. अधिनियम की योजना के तहत ऐसा प्रतीत होता है कि एक मकान मालिक जो अपने किरायेदार को बेदखल करना चाहता है, उसे बेदखल करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है

और मामले का निपटारा किराया नियंत्रण द्वारा किया जाना है अदालत। यह धारा *11* की उप-धारा *(2)* द्वारा प्रदान किया गया है।

अधिनियम। किराया नियंत्रण न्यायालय से, निम्नलिखित शर्तों के तहत अपीलीय प्राधिकरण को एक अपील की जाती है।

उप-अधिनियम की धारा *18* की धारा *(1) (*बी*)*। अपीलीय प्राधिकरण से कुछ परिस्थितियों में एक संशोधन निहित है

ऐसे मामले में जहां अपीलीय प्राधिकारी अधीनस्थ है जिला न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य मामलों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

अदालत। इस मामले में जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, अपील किराया नियंत्रण न्यायालय से अपीलीय प्राधिकरण को होती है जो

अधीनस्थ न्यायाधीश था और इसलिए संशोधन किया गया था जिला न्यायाधीश को। वास्तव में यह निर्विवाद है कि

प्रतिवादी ने इस मामले में इन सभी का सहारा लिया है।

प्रावधान। अधीनस्थ के अपीलीय निर्णय से जिला न्यायाधीश द्वारा संशोधन को खारिज करने के बाद

न्यायाधीश जिन्होंने किराया नियंत्रक के आदेश की पुष्टि की,

प्रतिवादी-मकान मालिक ने उच्च न्यायालय के समक्ष फिर से जाने का फैसला किया सी. पी. सी. की धारा *115* के तहत न्यायालय। सवाल यह है कि

उसका उच्च न्यायालय में दूसरा संशोधन है? श्री पोती

प्रस्तुत किया कि वह नहीं कर सकता। हमारा मानना है कि वह

सही है। यह स्थिति स्पष्ट है यदि उप-धारा *(5)*

अधिनियम की धारा *18* को इसके साथ पढ़ा जाता है -

अधिनियम की धारा *20*। धारा *18* की उप-धारा *(5)*, जैसा कि हम

यहाँ पहले उल्लेख किया है, स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय और इस तरह के निर्णय के अधीन,

किराया नियंत्रक का आदेश 'अंतिम होगा' और 'किसी भी न्यायालय में प्रश्न में बुलाए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा',

धारा *20* में दिए गए प्रावधान को छोड़कर। धारा *20* द्वारा, एक संशोधन

जहां अपीलीय प्राधिकारी अधीनस्थ है, वहां प्रदान किया जाता है

तय किया गया और फिर से बताए जाने की आवश्यकता नहीं है। दो संशोधनों की कल्पना करना असंभव है। अधिनियम की योजना नहीं है इस तरह के निष्कर्ष की गारंटी देते हैं। हमारी राय में, अभिव्यक्ति *[2014] 10* एस. सी. आर.

2

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'अधिनियम में 'अंतिम' होगा जिसका अर्थ है कि यह क्या कहता है।

20. विद्वान न्यायाधीश ने मौंग बा थाव और अन्न के मामले में न्यायिक समिति के निर्णय का उल्लेख किया। - दिवाला *v.* मा पिन, एयर *1934* पीसी *81*। विद्वान।

न्यायाधीश ने दक्षिण एशिया इंडस्ट्रीज *(*पी*)* लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख किया। एस. बी. सरूप सिंह और अन्य।

(ऊपर*)*। विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक वहाँ है

कानून में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था

उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाती है, संशोधित होने योग्य था। सी. पी. सी. की धारा *115* के तहत उच्च न्यायालय द्वारा। उस में

मामले को देखते हुए, पूर्ण पीठ ने कुरियन बनाम मामले में केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विचार को खारिज कर दिया।

चाको *[1960]* के. एल. टी *1248*। सम्मान के साथ, हम असमर्थ हैं

मामले के इस पहलू पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के विचार को बनाए रखें। हमारी राय में, पूर्ण पीठ की उप-धारा *(5)* के प्रावधानों का गलत अर्थ लगाया गया

अधिनियम की धारा *18*। धारा *18* की उप-धारा *(5)* में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा निर्णय

अधिनियम की धारा *18* में उल्लिखित, अधिनियम की धारा *20* के तहत तरीके के अलावा पूछताछ के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस प्रकार एक निहित निषेध था या

उच्च न्यायालय में सी. पी. सी. की धारा *115* के तहत दूसरे संशोधन का अपवर्जन जब विचाराधीन अधिनियम की धारा *20* के तहत संशोधन का प्रावधान किया गया है। कब

अधिनियम की धारा *18 (5)* में विशेष रूप से कहा गया है कि "किसी भी न्यायालय में प्रश्न में बुलाए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा" धारा *20* के तहत प्रदान किए गए तरीके को छोड़कर, यह नहीं कर सकता है

कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय जो कानून का एक न्यायालय है और

जो सी. पी. सी. की धारा *115* के तहत एक दीवानी अदालत है।

सी. पी. सी. अधिनियम की धारा *20* के तहत संशोधन के बाद एक बार फिर से एक आदेश को संशोधित कर सकता है।

इसका अर्थ होगा मद्रास बार एसोसिएशन *v*। भारत संघ *123*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

चार न्यायालयों द्वारा एक मुकदमा चलाया जाएगा, जो विभिन्न धाराओं में प्रकट योजना के लिए प्रतिकूल होगा।

विचाराधीन अधिनियम। लोक नीति या जनहित कानून की देरी और न्याय की मांगों को कम करने की मांग करता है।

मामले के त्वरित निपटारे के भीतर अंतिमता। धारा *20* के साथ पठित धारा *18 (5)* के प्रावधानों की भाषा निषेध करती है।

आगे का संशोधन। अदालतों को ऐसा ही समझना चाहिए। *'*

इसी तरह हमारा ध्यान जेठा बाई एंड संस की ओर आकर्षित किया गया।

सुंदरदास रथेनाई *(1988) 1* एस. सी. सी. *722*, और रिलायंस थी

निम्नलिखित पर सी. डी.*:*

"15. बिना किसी चर्चा के भी इसे देखा जा सकता है

ऊपर दी गई कथा है कि वास्तव में कोई संघर्ष नहीं है

दोनों निर्णयों के बीच क्योंकि में प्रावधान

दोनों अधिनियम भौतिक रूप से अलग हैं। हालाँकि, मामलों को और स्पष्ट करने के लिए हम दोनों के बीच के अंतर को इंगित कर सकते हैं।

अधिक विस्तार और स्पष्टता में कार्य करता है। केरल अधिनियम के तहत, किराया नियंत्रण अदालत की अध्यक्षता में पारित एक आदेश के खिलाफ

जिला मुन्सिफ द्वारा पीड़ित पक्ष को सम्मानित किया जाता है

धारा *18* के तहत अपील का अधिकार। अपीलीय प्राधिकरण न्यायिक अधिकारी होना चाहिए जो किसी पद से कम न हो।

अधीनस्थ न्यायाधीश। अपीलीय प्राधिकरण को किराए के साथ-साथ व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

कोर्ट को नियंत्रित करें लेकिन ओवर-राइडिंग प्रभाव है। इनके होने से

कारकों को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल ने घोषणा की है कि अब तक

किराया नियंत्रण न्यायालय के आदेश के संबंध में यह होगा - केवल किसी संशोधन या संशोधन के लिए अंतिम विषय होना

अपीलीय प्राधिकरण; और जहाँ तक अपीलीय प्राधिकरण का संबंध है

संबंधित है, इसका निर्णय अंतिम होगा और धारा *20* में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। धारा *20* के संबंध में, ए

उसके अधीन प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण की शक्तियों का विभाजन

उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के बीच किया गया है। उन सभी मामलों में जहां एक अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ एक संशोधन को प्राथमिकता दी जाती है

धारा *18* के तहत एक अधीनस्थ न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

यह केवल सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. में है।

एक से उच्च पद के न्यायिक अधिकारी का है अधीनस्थ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का गठन किया गया है

पुनरीक्षण प्राधिकरण। धारा *20* के तहत प्रदत्त पुनरीक्षण शक्तियां, चाहे वह जिला न्यायाधीश पर हों या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *115* के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण की शक्तियों की तुलना में अधिक विस्तार का है।

धारा *20* पुनरीक्षण प्राधिकरण को संतुष्ट करने का अधिकार है

स्वयं वैधानिकता नियमितता, या आदेशों की औचित्य के बारे में

संशोधित करने की मांग की। इतना ही नहीं, अपीलीय प्राधिकरण और संशोधन प्राधिकरण को अधिनियम की धारा *20* ए के तहत स्पष्ट रूप से रिमांड की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

इसलिए, एक पार्टी को सामने रखने का अवसर दिया जाता है

उसका मामला किराया नियंत्रण न्यायालय के समक्ष और फिर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष और उसके बाद यदि आवश्यक हो तो

पुनरीक्षण न्यायालय अर्थात। जिला न्यायालय यदि अपीलीय

प्राधिकरण अधीनस्थ न्यायाधीश के पद का होता है। द.

विधायिका ने अपने विवेक में सोचा है कि

एक पक्ष को अपना मामला रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया

तीन न्यायालयों के समक्ष, अर्थात। विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय

और पुनरीक्षण न्यायालय, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी

जिला न्यायालय का पुनरीक्षण आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे पुनरीक्षण के माध्यम से आगे की जांच के अधीन है। या तो अधिनियम के तहत या सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत।

औंडल अम्मल के मामले में इसका उल्लेख किया गया है *(ऊपर)*

कि केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ विफल रही थी

धारा *18 (5)* के साथ पठित धारा *20* की शर्तों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में समझें और इस विफलता ने इसके

पूर्ण पीठ के अनुसार, एक पुनरीक्षण आदेश

किसी जिले के न्यायालय ने धारा *20* के तहत दो कारकों के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *115* के तहत उच्च न्यायालय को आगे चुनौती देने के लिए खुद को खुला रखा। *(1)* अधिनियम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि आदेश अंतिम होगा और *(2)* अधिनियम में धारा *20* के तहत पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं था। पूर्ण बेंच

कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देने में विफल रहे।

सबसे पहले, आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.* यूनियन ऑफ इंडिया *125*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

धारा *20* एक समग्र खंड है और इसका उल्लेख करता है -

उस धारा के तहत प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण की शक्तियाँ

जिला न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा। ऐसा मामला होने पर यदि यह लिया जाना है कि एक द्वारा पारित आदेश

धारा *20* के तहत जिला न्यायालय की अंतिमता नहीं होगी।

क्योंकि अनुभाग विशेष रूप से ऐसा नहीं कहता है, तो यह

इसके बाद धारा *20 (1)* के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश की भी अंतिमता नहीं होगी।

किसी के द्वारा यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि द्वारा पारित आदेश एक उच्च न्यायालय के तहत संशोधन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

धारा *20 (1)* को आगे संशोधित किया जा सकता है।

क्योंकि धारा *20 (1)* ने स्पष्ट रूप से अंतिमता प्रदान नहीं की है उस धारा के तहत पारित आदेश के लिए। दूसरा, धारा *20 (1)* की शर्तों को इसके साथ पढ़ा जाना चाहिएः

धारा *18 (5)*। धारा *18 (5)* जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, घोषित करती है

कि किराया नियंत्रण न्यायालय का आदेश अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय और के आदेश के अधीन अंतिम होगा

एक अपीलीय प्राधिकरण अंतिम होगा और कानून के किसी भी न्यायालय में प्रश्न में बुलाए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा सिवाय इसके कि

धारा *20* में प्रावधान किया गया है। जब विधानमंडल ने घोषित किया कि यहां तक कि किराया नियंत्रण न्यायालय का एक आदेश और

अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा

संबंधित चरण जब तक कि आदेश को अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है।

हो सकता है, विधायिका को घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है

एक बार फिर कि जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा धारा *20 (1)* के तहत पुनरीक्षण में पारित आदेश

मामले में अंतिमता की मुहर भी हो सकती है। तीसरा। पहलू यह है कि विधानमंडल ने न केवल एक अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय को अंतिम रूप दिया है, बल्कि

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया है कि निर्णय धारा *20* में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी भी अदालत में प्रश्नगत नहीं होगा। ये अतिरिक्त शब्द स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं। उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *115* के तहत दूसरे संशोधन का निषेध या बहिष्कार

अधिनियम की धारा *20* के तहत जिला न्यायालय द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ।

इस स्थिति को संक्षेप में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. निर्धारित किया गया है।

26

औंडल अम्मल के मामले में फैसले के पैरा *20* में *(* ऊपर*)*। जैसा कि विशेष कुमार के मामले में देखा गया था,

अधिकार क्षेत्र के विभाजन के पीछे का इरादा उच्च न्यायालय में दायर पुनरीक्षण याचिकाओं की संख्या को कम करना है और विधायी इरादे को निर्धारित करने के लिए, न्यायालय को जहां तक चाहिए

यथासंभव किसी कानून का इस तरह से अर्थ लगाया जाए कि

विधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाना और दमन करना

शरारत को इससे ठीक करने की कोशिश की गई "।

43. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ

इस न्यायालय का निर्णय, मफतलाल इंडस्ट्रीज बनाम। भारत संघ

997) 5 एस. सी. सी. *536*, धारा की वैधता पर विचार करते हुए

1 उत्पाद शुल्क अधिनियम की बी *(3)* निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित की गईः

" 77. इससे पहले, हमने प्रावधानों का उल्लेख किया है।

समय-समय पर प्राप्त धनवापसी से संबंधित

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम। चाहे वह नियम *11* हो *(*जैसा कि यह समय-समय पर बना रहा है*)* या धारा *11*-बी *(*जैसा कि उसने प्राप्त किया है*)*।

1991 से पहले या उसके बाद*)*, वे निश्चित रूप से

कथित तौर पर धनवापसी के सवाल पर संपूर्ण होना। *6* अगस्त, *1977* से पहले लागू नियम *11* में कहा गया था कि "नहीं।

शुल्क और शुल्क जिनका भुगतान किया गया है या किया गया है जब तक दावेदार अपने हस्ताक्षर और लॉज के तहत इस तरह के रिफंड के लिए आवेदन नहीं करता है, तब तक इसे वापस कर दिया जाएगा।

तारीख से तीन महीने के भीतर उचित अधिकारियों को

ऐसा भुगतान या समायोजन, जैसा भी मामला हो "। नियम

11 , जैसा कि *6.8.1977* और *17.11.1980* के बीच लागू है

उप-नियम *(4)* जिसमें स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थीः " *(4)* सहेजें

जैसा कि इस नियम द्वारा या उसके तहत अन्यथा प्रदान किया गया है, कोई दावा नहीं

किसी भी शुल्क की वापसी पर विचार किया जाएगा। धारा *11*-बी, जो अप्रैल, *1991* से पहले लागू थी, में उप-धारा *(4)* समान शब्दों में थी। इसमें कहा गया हैः " *(4)* इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, उत्पाद शुल्क के किसी भी वापसी के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उप-धारा *(5)* अधिक थी

विशिष्ट और जोरदार। इसमें कहा गया हैः

"किसी अन्य में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद

कानून, इस धारा के प्रावधान ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन वी. भी लागू होंगे।

भारत संघ *127*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्र की गई किसी भी राशि की वापसी के लिए इस आधार पर किया गया दावा कि जिस माल के संबंध में ऐसी राशि एकत्र की गई थी

शुल्क से छूट के हकदार नहीं थे और किसी भी अदालत को इस संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

इस तरह के दावे का "।

यह एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू हुआ*;* यह हर प्रकार का था।

धनवापसी और धनवापसी के लिए प्रत्येक दावा और यह स्पष्ट रूप से वर्जित है

ऐसे दावे के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता। उप.

धारा *11*-बी की धारा *(3)*, जैसा कि अब है, एक ही प्रभाव-वास्तव में, अधिक व्यापक और सभी

घेर लेते हैं। इसमें कहा गया हैः

अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय का निर्देश या इस अधिनियम या बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रावधान में

उसके अधीन या उस समय लागू किसी कानून में। उप में दिए गए प्रावधान के अलावा कोई धनवापसी नहीं की जाएगी।

खंड "।

भाषा अधिक विशिष्ट नहीं हो सकती थी और

जोरदार। धनवापसी से संबंधित प्रावधान की विशिष्टता न केवल स्पष्ट और स्पष्ट है, बल्कि इसके अतिरिक्त है -

इस तथ्य से उत्पन्न होने वाली सामान्य बाधा कि अधिनियम बनाता है

नए अधिकार और देनदारियाँ और मंच भी प्रदान करता है और

उन अधिकारों का निर्धारण और निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ

और देनदारियाँ और अन्य सभी आनुषंगिक और सहायक मामले, जैसा कि वर्तमान में बताया जाएगा। यह एक बार पर एक बार है-एक पहलू जिस पर पैरा *23 (ऊपर)* में जोर दिया गया है, और होना चाहिए

जब तक वह खड़ा है तब तक उसका सम्मान करें। इनकी वैधता

प्रावधानों पर कभी गंभीरता से संदेह नहीं किया गया है। भले ही अब हमारे समक्ष कुछ रिट याचिकाओं में, संशोधित धारा *11*-बी सहित *1991 (*संशोधन*)* अधिनियम की वैधता है

सवाल किया गया, कोई विशिष्ट कारण नहीं बताए गए हैं कि क्यों

धारा *11* की उप-धारा *(3)* की प्रकृति का प्रावधान

बी *(*संशोधित*)* असंवैधानिक है।

प्रस्तावों को लागू करना *3* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

कमला मिल्स मामला, ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *1942* में इस न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि धारा *11*-बी *(*संशोधन से पहले और बाद में दोनों*)*

वैध और संवैधानिक। कमला मिल्स मामले में, इस अदालत ने बरकरार रखा बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम की धारा *20* की संवैधानिक वैधता *(*यहाँ पहले निर्धारित*)* इस आधार पर कि बॉम्बे अधिनियम में धनवापसी, अपील, संशोधन, गलती के सुधार के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं और

अपील/पुनरीक्षण दाखिल करने में देरी की क्षमा। अदालत ने

इंगित किया कि बॉम्बे अधिनियम ने इन प्रावधानों को प्रदान नहीं किया था

उपचार और फिर भी दीवानी अदालत का सहारा लेने पर रोक, धारा *20* की संवैधानिकता गंभीर हो सकती है

संदेह है, लेकिन चूंकि यह ऐसे उपचार प्रदान करता है, इसकी वैधता

दोहराने के लिए चुनौती से परे था-और यह आवश्यक है

ऐसा करना-जब तक धारा *11*-बी संवैधानिक रूप से मान्य है, तब तक इसका पालन करना होगा और इसे प्रभावी बनाना होगा। हम नहीं देख सकते हैं

जिस कारण से उक्त प्रावधान की संवैधानिकता

- या इसी तरह के प्रावधान पर संदेह किया जा सकता है। यह भी होना चाहिए

याद रखें कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम एक विशेष अधिनियम है

नए और विशेष दायित्वों और अधिकारों का निर्माण करने वाला अधिनियम, जो एक ही समय में लेवी के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है,

मूल्यांकन, संग्रह, धनवापसी और अन्य सभी आनुषंगिक और सहायक प्रावधान। जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्य और कारण जो बन गए

अधिनियम, नियमों के साथ अधिनियम का उद्देश्य *"*गठन*"* करना था

एक पूर्ण केंद्रीय उत्पाद शुल्क संहिता "। विचार यह था कि एक एकल अधिनियम में संबंधित सभी कानूनों को समेकित करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क "। यह अधिनियम एक स्व-निहित है अधिनियमन। इसमें कर एकत्र करने के प्रावधान हैं।

जो कानून के अनुसार देय हैं लेकिन एकत्र नहीं किए गए हैं और उन करों को वापस करने के लिए भी जो कानून के विपरीत एकत्र किए गए हैं। , धारा *11*-ए और *11*-बी और उससे संबद्ध

प्रावधान। दोनों प्रावधानों में एक समान नियम है - सीमा, अर्थात। , छह महीने, प्रत्येक मामले में एक अपवाद के साथ। धारा *11*-ए और *11*-बी एक दूसरे के पूरक हैं।

ऐसी स्थिति के लिए, प्रस्ताव संख्या *3* में उल्लिखित किया गया है -

कमला मिल्स लागू हो जाती है।

, जहाँ एक क़ानून मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *129*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

एक विशेष अधिकार या दायित्व बनाता है और यह भी प्रदान करता है

उस ओर से गठित न्यायाधिकरणों द्वारा अधिकार या दायित्व के निर्धारण के लिए प्रक्रिया और आगे के प्रावधान कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न होंगे

इस प्रकार गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित, दीवानी अदालत का सहारा उपलब्ध नहीं है-कमला मिल्स में बताए गए सीमित सीमा को छोड़कर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम विशेष रूप से धनवापसी का प्रावधान करता है। यह स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि कोई रिफंड नहीं

उसके अनुसार के अलावा किया जाएगा। द.

दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्जित है-उप

धारा *11*-बी की धारा *(5)*, *1991* में इसके संशोधन से पहले, और धारा *11*-बी की उप-धारा *(3)*, जैसा कि संशोधित किया गया था।

1991 में। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

के तहत दिए गए आदेशों के खिलाफ एक से अधिक अपील

धारा *11*-बी/नियम *11*। *1981* से, न्यायाधिकरण के आदेशों से इस न्यायालय में भी एक अपील प्रदान की जाती है। जबकि न्यायाधिकरण एक विभागीय अंग नहीं है, यह न्यायालय एक दीवानी न्यायालय है। मामले के इस दृष्टिकोण में और एक्सप्रेस और

नियम *11* में निहित अतिरिक्त प्रतिबंध और विशिष्टता

धारा *11*-बी, हर समय, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि सिद्धांतों के उल्लंघन सहित कोई भी और हर आधार

प्राकृतिक न्याय और मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन

इन अपीलों में न्यायिक प्रक्रिया का आग्रह किया जा सकता है।

मामलों में वाद या रिट याचिका की आवश्यकता को दूर करना

धन वापसी से संबंधित। एक बार की संवैधानिकता

धनवापसी से संबंधित प्रावधानों सहित अधिनियम के प्रावधान प्रश्न से परे हैं, वे इसके भीतर "कानून" का गठन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद *265* का अर्थ। यह इस प्रकार है कि

उक्त प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई प्राधिकरण के तहत की गई कार्रवाई होगी। विधि का ", अनुच्छेद *265* के अर्थ के भीतर। व्यक्त प्रावधान के सामने जो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि कोई दावा नहीं है

किसी भी शुल्क के पुनर्भुगतान पर विचार किया जाएगा सिवाय इसके कि

उक्त प्रावधानों के अनुसार, इसकी अनुमति नहीं है।

अनुबंध अधिनियम की धारा *72* का सहारा लेना ताकि वह ठीक से किया जा सके जो उक्त प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

दूसरे शब्दों में, *[2014] 10* एस. सी. आर. द्वारा धनवापसी का दावा करने की अनुमति नहीं है।

130 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा *72* को एक अलग और स्वतंत्र के रूप में लागू करना उपचार जब इस तरह के पाठ्यक्रम को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाता है

अधिनियम में प्रावधान, अर्थात। , नियम *11.* और धारा *11*-बी। इस कारण से, धनवापसी का मुकदमा भी नहीं होगा। किसी को भी लेना

अन्य दृष्टिकोण नियम के प्रावधानों को रद्द करने के बराबर होगा।

11 / धारा *11*-बी, जिस पर कोई जोर देने की आवश्यकता नहीं है,

किया। इसलिए, यह इस प्रकार है कि किसी भी और प्रत्येक दावे के लिए

उत्पाद शुल्क की वापसी केवल नियम *11* या धारा *11*-बी के तहत और उसके अनुसार की जा सकती है।

अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए मंचों में हो। अनुबंध अधिनियम की धारा *72* को लागू करते हुए शुल्क की वापसी के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है।

जहाँ तक उच्च न्यायालय की अधिकारिता के तहत अनुच्छेद *226*-या उस मामले के लिए, इस न्यायालय की अधिकारिता

अनुच्छेद *32* के तहत, यह स्पष्ट है कि

अधिनियम के प्रावधान इन्हें रोक और कम नहीं कर सकते हैं।

उपचार। हालाँकि, यह समान रूप से स्पष्ट है कि अनुच्छेद *226/*अनुच्छेद *32* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय

निश्चित रूप से प्रकट विधायी इरादे पर ध्यान देगा

अधिनियम के प्रावधानों में और उनका प्रयोग करेंगे

अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अधिकार क्षेत्र।

यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त पैराग्राफ के अवलोकन से पता चलता है,

कि इस न्यायालय ने ध्यान दिया कि न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील का प्रावधान किया गया था। न्यायालय ने घोषणा की कि न्यायाधिकरण एक विभागीय अंग नहीं था और सर्वोच्च न्यायालय एक दीवानी न्यायालय था क्योंकि यह एक सांविधिक अपील की सुनवाई कर रहा था।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उल्लंघन सहित हर आधार और इनमें न्यायिक प्रक्रिया के उल्लंघन का आग्रह किया जा सकता है।

अपील, धनवापसी से संबंधित मामलों में वाद या रिट याचिका की आवश्यकता को समाप्त करना। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने का ध्यान रखा कि जहाँ तक अनुच्छेद *226* या इसके तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता है

अनुच्छेद *32* के तहत अदालत का संबंध है, उन्हें कम नहीं किया जा सकता है। इसने आगे कहा कि यह समान रूप से स्पष्ट था कि अनुच्छेद *226/32* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय निश्चित रूप से निर्णय लेगा।

के प्रावधानों में प्रकट विधायी इरादे का नोट

अधिनियम बनाएगा और इसके अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा

अधिनियम के प्रावधान। तदनुसार यह प्रस्तुत किया गया था कि मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *131*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

उपरोक्त निर्णय में लिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, सभी

याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह की गई दलीलों को खारिज करने की आवश्यकता थी।

तीसरा विवादः

44. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान परामर्श, जोरदार रूप से

के हाथों अग्रिम प्रस्तुतियों का विरोध किया

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एन. टी. टी. अधिनियम संविधान के प्रावधानों से परे है। जहाँ तक मामले का तात्कालिक पहलू है

संबंधित, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील, पहले स्थान पर

संविधान के अनुच्छेद *246* पर निर्भरता। अनुच्छेद *246* बनाया जा रहा है यहाँ नीचे निकाला गया हैः

"246. विषय-संसद और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय

राज्यों के विधानमंडल-*(1)*

खंड *(2)* और *(3)* में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को इनमें से किसी के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है -

(इस संविधान में *"*संघ सूची*"* के रूप में संदर्भित*)*। *(2)* खंड *(3)* में किसी बात के होते हुए भी, संसद और,

खंड *(1)* के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

किसी भी मामले के संबंध में उसका कोई भी भाग सातवीं अनुसूची में सूची *II* में सूचीबद्ध *(*इस में*)*

संविधान *'*राज्य सूची*'* के रूप में संदर्भित*)*।

(4) संसद के पास भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो *(*किसी राज्य में*)* शामिल नहीं है, इसके बावजूद कि ऐसा मामला एक मामला है।

राज्य सूची में सूचीबद्ध "।

उपरोक्त प्रावधान के आधार पर, यह चाहा गया था कि

इस बात पर जोर दिया कि संसद के पास अयोग्य और पूर्ण *132* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. हैं।

के संबंध में कानून बनाने की अधिकारिता, शक्ति और अधिकार

संविधान की सूची *I* और *III* में उल्लिखित मामले। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद *246 (4)* पर निर्भरता रखते हुए, यह दावा किया गया था, कि संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किए गए विषयों पर भी,

संसद के पास अभी भी कानून बनाने का पूर्ण और निरंकुश अधिकार था कानून। जहाँ तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने भरोसा व्यक्त किया

सूची *I* की प्रविष्टियों *77* से *79,82* से *84,95* और *97* पर। उपरोक्त

प्रविष्टियाँ यहाँ नीचे निकाली जा रही हैं:

सूची *1*-संघ सूची

" 77. का संविधान, संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ

उच्चतम न्यायालय (ऐसे न्यायालय की अवमानना सहित), और उसमें ली गई फीस; उच्चतम न्यायालय के समक्ष वकालत करने के हकदार व्यक्ति।

78. संविधान और संगठन (छुट्टियों सहित)

अधिकारियों के बारे में प्रावधानों को छोड़कर उच्च न्यायालय और

उच्च न्यायालयों के सेवक; व्यक्ति जो इससे पहले वकालत करने के हकदार हैं

उच्च न्यायालय।

79. उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार, और किसी भी संघ से उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन

क्षेत्र।

82. कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर।

84. तम्बाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क भारत में निर्मित या उत्पादित सिवाय -

मादक पदार्थ, लेकिन मद्रास बार एसोसिएशन वाली औषधीय और शौचालय की तैयारी को शामिल करते हुए।

भारत संघ *133*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

शराब या इस प्रविष्टि के उप-अनुच्छेद (बी) में शामिल कोई भी पदार्थ।

95. उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ, इनमें से किसी भी मामले के संबंध में

97. कोई अन्य मामला जो सूची *II* या सूची *III* में सूचीबद्ध नहीं है, जिसमें कोई भी कर शामिल है जिसका उन सूचियों में से किसी में भी उल्लेख नहीं है। ऊपर पुनरुत्पादित प्रविष्टियों के आधार पर, विशेष रूप से

प्रविष्टि *77* से *79* तक, यह प्रस्तुत किया गया था कि संसद ने

उच्चतम न्यायालय के संबंध में भी कानून बनाने की अधिकारिता

न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसके अलावा, यह शक्ति थी कि विधान बनाना, और इस प्रकार, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करना या उसे बाहर करना। *82* से *84* तक की प्रविष्टियों पर निर्भर करते हुए, यह प्रस्तुति थी

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का, कि के मामलों पर आय-कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, कानून बनाने की शक्ति स्पष्ट रूप से संसद के पास निहित थी। रिलायंस था

प्रविष्टि *95* पर यह तर्क देने के लिए रखा गया है कि मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों की अधिकारिता की सीमा सूची *I* में व्यक्त किया गया है जिसे संसद द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है।

82 से *84* तक की प्रविष्टियों का फिर से उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि कर मामलों पर अधिकार क्षेत्र का विस्तार या बहिष्कार भी संसद के अधिकार क्षेत्र में था। ताकि यह दावा किया जा सके कि यदि इस न्यायालय का विचार था, तो कानून का विषय

एन. टी. टी. अधिनियम में निहित, संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में से किसी में भी,

उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि संसद

अभी भी प्रविष्टि के तहत उस पर कानून बनाने का अधिकार होगा

97 यह सातवीं अनुसूची की सूची *I* में निहित है।

45. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील भी रखे गए

सातवीं अनुसूची की सूची *III* में निहित प्रविष्टियों *11* ए और *46* पर निर्भरता। उपरोक्त प्रविष्टियों को नीचे निकाला जा रहा हैः

सूची *III* पी समवर्ती सूची *" 11* ए. न्याय प्रशासन*;* संविधान और *[2014] 10* एस. सी. आर.

134 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का संगठन और

उच्च न्यायालय।

XXX

XXX

XXX

46. सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ, सिवाय इसके

उच्चतम न्यायालय, इसमें से किसी भी मामले के संबंध में

सूची "।

उपरोक्त प्रविष्टियों का उल्लेख करते हुए, यह विवाद था उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील कि संसद के पास था

उच्च न्यायालय सहित न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों की सीमा के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। यह.

हालाँकि, यह बताया गया था कि यह शक्ति केवल ऐसे मामलों और विषयों तक फैली हुई थी, जिनका उल्लेख सातवीं की सूची *III* में पाया गया है।

संसद के पास अनुच्छेद *246 (2)* के तहत निहित शक्ति संविधान।

एक्स

46. इसके अतिरिक्त, विद्वानों द्वारा निर्भरता रखी गई थी

संविधान के अनुच्छेद *247* पर उत्तरदाताओं के लिए वकील,

जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"247. स्थापना के लिए प्रावधान करने की संसद की शक्ति कुछ अतिरिक्त न्यायालयों का। - कुछ भी होने के बावजूद

इस अध्याय में संसद विधि द्वारा निम्नलिखित प्रावधान कर सकती है -

बेहतरी के लिए किसी भी अतिरिक्त अदालत की स्थापना

संसद या किसी अन्य द्वारा बनाए गए कानूनों का प्रशासन

में उल्लिखित किसी मामले के संबंध में विद्यमान कानून

संघ सूची "।

उपरोक्त प्रावधान का उल्लेख करते हुए, यह दावा किया गया था कि

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील, कि शक्ति स्पष्ट रूप से थी

संसद के पास अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए,

कानूनों का बेहतर प्रशासन। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह मद्रास बार एसोसिएशन *v* था।

भारत संघ *135*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

ठीक वही जो संसद ने एन. टी. टी. अधिनियम को लागू करते समय करने के लिए चुना था। वस्तुओं और कारणों का उल्लेख करते हुए, संकेत देते हुए

एन. टी. टी. अधिनियम के अधिनियमन का आधार, यह वर्गीकरण था

विद्वान वकील के हाथों दावा, कि विवादित अधिनियम को स्पष्ट रूप से लागू किया गया था

यह समझते हुए कि एन. टी. टी. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर कानूनों से उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों का बेहतर निर्णय प्रदान करेगा।

47. संविधान के अनुच्छेद *246* और *247* के अलावा,

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि लेख

323 ए और *323* बी को संविधान में शामिल किया गया था,

संविधान *(42* वां संशोधन*)* अधिनियम, *1976*। उपरोक्त प्रावधानों को नए अधिनियमित भाग *XIV A* में शामिल किया गया था

संविधान। इस बात पर जोर दिया गया कि संविधान का तत्काल संशोधन दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था।

सबसे पहले, उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बाहर करना।

और सुप्रीम कोर्ट, पूरी तरह से। इस प्रकार न्यायिक समीक्षा को बाहर रखा गया है।

पूरी तरह से। और दूसरा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ स्वतंत्र विशेष न्यायाधिकरणों का निर्माण करना, जो न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का बोझ। हालाँकि, प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों में से पहले की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा एल. चंद्र कुमार बनाम में की गई थी। संघ का

भारत *(1997) 3* एस. सी. सी. *261*, जिसने संविधान के खंड *(2) (*डी*)* को निरस्त कर दिया।

अनुच्छेद *323* बी के अनुच्छेद *323* ए और खंड *(3) (*डी*)*, इस हद तक कि

संविधान के बयालीसवें संशोधन द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया

अनुच्छेद *226/227* के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और

32/136 क्रमशः। जहाँ तक दूसरा उद्देश्य है संबंधित, एल. चंद्र कुमार मामले *(*ऊपर*)* में निर्भरता रखते हुए,

प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील का यह तर्क था कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला था कि जब तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के पास बनी रहती है। उच्चतम न्यायालय, ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के तहत, संदर्भ के तहत अधिनियम संवैधानिक रूप से मान्य होगा। इसलिए, प्रस्तुतियों के जवाब में

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के हाथ *(*जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

136

यहाँ ऊपर देखा गया*)*, यह विद्वानों का तर्क था

प्रत्यर्थियों के लिए वकील, कि एन. टी. टी. अधिनियम को लागू करने की शक्ति स्पष्ट रूप से अनुच्छेद के तहत भी संसद के पास निहित थी

323 संविधान का बी। इसके अलावा, क्योंकि विवादित अधिनियम उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता था

संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत, और साथ ही, अनुच्छेदों के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं किया गया था *32* और संविधान के *136*, के लिए चुनौती

एन. टी. टी. अधिनियम की संवैधानिक वैधता पूरी तरह से अनुचित थी।

48. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील दर्द में थे

इस बात पर जोर दें कि न्यायालयों का क्षेत्राधिकार मार्ग, अंतिम रूप में

कानून के दुभाषिया को स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया था। सबसे पहले, क्योंकि एनटीटी अधिनियम के तहत एक वैधानिक अपील का प्रावधान किया गया था

सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा, क्योंकि न्यायिक समीक्षा निहित है।

के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालयों में संविधान, और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद *32* के तहत और

136 संविधान को अक्षुण्ण रखा गया था। इसलिए, यह उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति है, कि

अपीलीय न्यायाधिकरणों *(*के तहत गठित*)* द्वारा पारित आदेशों से अपीलीय क्षेत्राधिकार के निहित होने में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम*)* एनटीटी के साथ।

49. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, कि अधिकार क्षेत्र

आयकर अधिनियम *(*धारा *260* ए के तहत*)* के तहत अपीलीय न्यायाधिकरणों से अपीलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालयों में निहित,

धारा *35* जी*)*, को अधिकार क्षेत्र उच्च से स्थानांतरित कर दिया गया है। न्यायालय ने एन. टी. टी. को यह प्रस्तुत किया कि अपीलीय अधिकार क्षेत्र

एक कानून के तहत एक उच्च न्यायालय में निहित, कानून के संशोधन द्वारा दूर किया जा सकता है। सरलता से कहा जाए तो, प्रत्यर्थियों के कहने पर प्रस्तुत किया गया था, जो कुछ भी एक वैधानिक अधिनियम द्वारा निहित

है, उसी तरह उसी तरीके से विभाजित किया जा सकता है। इसलिए यह दावा करने की मांग की गई कि एन. टी. टी. अधिनियम को चुनौती देने के आधार, के इशारे पर उठाए गए थे

याचिकाकर्ताओं को गलत समझा गया और वे अस्वीकार्य थे।

50. ऊपर उल्लिखित प्रस्तुतियों के अलावा, यह मद्रास बार एसोसिएशन *v* था।

भारत संघ *137*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

प्रत्यर्थियों की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया दावा, कि अपीलीय क्षेत्राधिकार पर

"कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न "एन. टी. टी. के पास निहित नहीं किए जा सकते थे, गलत थे। इस संबंध में यह दोहराया जाना चाहिए कि दीवानी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र *(*उच्च न्यायालय के मूल पक्ष सहित*)*

न्यायालय*)* को कर संबंधी मुद्दों के संबंध में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसकी तलाश की गई।

यह समझाया जाना चाहिए कि एक मामले में प्रारंभिक चरण से ही तथ्य के साथ-साथ कानून के प्रश्न भी शामिल हो सकते हैं।

एन. टी. टी. के हाथों निर्णय। इस तरह, निर्भरता रखना मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में निर्णय पर। भारत संघ

(1997) 5 एस. सी. सी. *536*, यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्क में खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं थे। इसके अलावा, यह इंगित करने की कोशिश की गई थी कि वाक्यांश "सारवान" है।

इस न्यायालय द्वारा कानून के प्रश्नों की व्याख्या इस अर्थ में की गई है,

न केवल सामान्य सार्वजनिक महत्व के प्रश्न, बल्कि

ऐसे प्रश्न जो प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक अधिकारों को प्रभावित करेंगे

मुकदमे के पक्षकारों से। यह भी कहा गया था कि कानून के एक प्रश्न में एक कानूनी मुद्दा भी शामिल होगा, जो पहले तय नहीं किया गया था, इस शर्त के अधीन, कि इसका एक भौतिक असर था।

पक्षों के बीच सुलझाए जाने वाले विवाद के निर्धारण पर। तदनुसार यह तर्क दिया जाता है कि कोई सीमा नहीं

व्याख्या को "सारवान" शब्द पर रखा जा सकता है।

कानून के प्रश्न "। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया था कि

एन. टी. टी. के संविधान को इस आधार पर चुनौती दी कि

एन. टी. टी. को "पर्याप्त" का निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया था।

कानून के सवाल अस्थिर थे।

51. उसके उपरोक्त समर्पण का समर्थन करने के लिए, सीखा

प्रत्यर्थियों के वकील ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों पर जोर देकर भरोसा व्यक्त किया। वही देखा जा रहा है

इसके नीचेः

(i) रिलायंस को एल. चंद्र किन वी पर भी रखा गया था।

भारत संघ, *(1997) 3* एस. सी. सी. *261*। सीखी हुई परिषद कभी नहीं

उत्तरदाताओं ने, तत्काल निर्णय पर भरोसा करते हुए, एक

उसमें अभिलिखित विभिन्न टिप्पणियों का संदर्भ।

हम *[2014] 10* एस. सी. आर. थे।

3 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टइसके तहत उन सभी अनुच्छेदों को निगमित करें जिन पर वे निर्भर हैं।

विद्वान परिषद द्वारा रखे गएः

विधान न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालयों के अपवर्जन के लिए विधायी कार्रवाई और

सर्वोच्च न्यायालय, कोई संवैधानिक निषेध नहीं है

उनके पूरक प्रदर्शन के खिलाफ-इसके विपरीत

इस संबंध में एक संस्थागत भूमिका। ऐसी स्थिति संवैधानिक योजना के भीतर विचार किया जाता है

यह तब स्पष्ट होता है जब कोई संविधान के अनुच्छेद *32* के खंड *(3)* का विश्लेषण करता है जो निम्नानुसार हैः

"32. इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय

भाग।

(1) ......

:

(2) ......

(3) प्रदत्त शक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

खण्ड *(1)* और *(2)* द्वारा उच्चतम न्यायालय। संसद कर सकती है

कानून द्वारा किसी भी अन्य न्यायालय को इसके भीतर प्रयोग करने का अधिकार है

इसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएँ सभी या कोई भी शक्तियाँ खंड *(2)* के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। "

81. यदि संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत शक्ति, जो

के "हृदय" और "आत्मा" के रूप में वर्णित किया गया है संविधान, अतिरिक्त रूप से किसी अन्य को प्रदान किया जा सकता है

अदालत ", ऐसा कोई कारण नहीं है कि वही स्थिति क्यों नहीं हो सकती है

प्रदत्त अधिकारिता के संबंध में निर्वाह करता है

संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालय। जब तक अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता

227 और अनुच्छेद *32* के तहत इस न्यायालय को बरकरार रखा जाता है,

इसकी वैधता का परीक्षण करने की शक्ति का कोई कारण नहीं है

बनाए गए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को प्रदान नहीं किया जा सकता है अधिनियम के तहत या अनुच्छेद *323* के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों पर आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *139*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

संविधान का बी। यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद *323*-ए से आने वाले प्राधिकरण के अलावा और

323 - B, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों

में परिवर्तनों को प्रभावित करने के लिए विधायी क्षमता रखता है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता अदालतें। यह शक्ति प्रविष्टियों के तहत संसद को उपलब्ध है।

77 , *78* , *79* और सूची *I* और राज्य विधानमंडलों के लिए *95*

सूची *II* की प्रविष्टि *65* के तहतः सूची *III* की प्रविष्टि *46* भी हो सकती है

इस उद्देश्य के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों द्वारा लाभ उठाया गया।

82. कुछ ठोस कारण हैं जिनसे हम चिंतित हैं इन लोगों को इस तरह की शक्ति प्रदान करना सुरक्षित रखें।

न्यायाधिकरण। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय पर विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि

सहायता के लिए अन्य संवैधानिक सुरक्षा उपाय बनाए गए थे।

वे इस भारी बोझ का प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हैं। द.

उम्मीद थी कि इस शक्ति का उपयोग केवल कभी-कभार ही किया जाना चाहिए। लेकिन इन पाँच दशकों में

आजादी के बाद से मुकदमेबाजी की मात्रा इससे पहले कि उच्च न्यायालयों में अभूतपूर्व विस्फोट हुआ हो

तरीके से। संपत कुमार के मामले में निर्णय, आकाशवाणी

1987 एस. सी. *386*, को ऐसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया था। हम.

इस तथ्य से अवगत हैं कि जब एक संविधान पीठ संपत कुमार के मामले *(ऊपर)* में इस न्यायालय ने अपना लिया

वैकल्पिक संस्थागत तंत्र का सिद्धांत, यह एक खतरनाक व्यावहारिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास कर रहा था और इसके द्वारा चुना गया दृष्टिकोण सबसे अधिक प्रतीत होता है

समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त। लगभग ए

दशक बाद, हम अब समीक्षा करने की स्थिति में हैं

सैद्धांतिक और व्यावहारिक परिणाम जो उत्पन्न हुए हैं

इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाने का परिणाम। *83.* हमें इस स्तर पर तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

जिसने विकल्प के सिद्धांत को अपनाने का अवसर दिया

संपत कुमार के मामले में संस्थागत तंत्र *(ऊपर)*। आर. मिश्रा, जे. ने अपने प्रमुख निर्णय में *[2014] 10* एस. सी. आर. का उल्लेख किया है।

) सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकदमेबाजी में वृद्धि ने उच्च न्यायालयों में विचाराधीनता का बोझ बहुत बढ़ा दिया था। संदर्भ दिया गया था उच्च न्यायालयों को उनके बढ़े हुए बोझ से राहत देने की दिशा में किए गए अध्ययन। इस संबंध में, स्वतंत्र गठन के लिए शाह समिति की सिफारिशें

न्यायाधिकरणों के साथ-साथ प्रशासनिक का सुझाव भी सुधार आयोग कि सिविल सेवा न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाए

ऊपर, नोट किए गए थे। निर्णय का भी उल्लेख किया गया था

के. के. दत्ता बनाम भारत संघ, *(1980) 4* एस. सी. सी. *38*, जहाँ इस न्यायालय ने शीघ्रता की आवश्यकता पर जोर देते हुए

सेवा विवादों का समाधान, प्रतिष्ठान का प्रस्ताव

सेवा न्यायाधिकरणों का।

84. उच्च न्यायालयों के बैकलॉग को हटाने की समस्या, जो हमारे समय में भारी अनुपात में पहुंच गई है,

फिर भी, एक जो निकट के लिए अध्ययन का केंद्र रहा है

आधी सदी तक। समय के साथ, कई विशेषज्ञ समितियों और आयोगों ने इसमें शामिल जटिलताओं का विश्लेषण किया है

और सुझाव दिए हैं, जिनमें से सभी नहीं हैं

निरंतरता। कई अध्ययनों में से जो इस संबंध में आयोजित, बारह के रूप में कई किया गया है

भारत के विधि आयोग द्वारा *(*इसके बाद*)*

एल. सी. आई.*)* या इसी तरह की उच्च स्तरीय समितियों के रूप में संदर्भित

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, और विशेष रूप से हैं

उल्लेखनीय है। *(* उच्च न्यायालय बकाया समिति की रिपोर्ट, *1949 ;* न्यायिक सुधार पर एल. सी. आई. की *14* वीं रिपोर्ट

प्रशासन *(1958);* एल. सी. आई., सिविल संहिता पर *27* वीं रिपोर्ट

प्रक्रिया, *1908 (1964);* एल. सी. आई., दंड प्रक्रिया संहिता पर *41* वीं रिपोर्ट, *1898 (1969);* एल. सी. आई., सिविल प्रक्रिया संहिता की *54* वीं रिपोर्ट, *1908 (1973);* एल. सी. आई., उच्च न्यायपालिका की संरचना और क्षेत्राधिकार पर *57* वीं रिपोर्ट।

(1974) ; उच्च न्यायालय बकाया समिति की रिपोर्ट, *1972;* एल. सी. आई., उच्च न्यायालयों में देरी और बकाया पर *79* वीं रिपोर्ट और

अन्य अपीलीय न्यायालय *(1979);* एल. सी. आई., मौखिक पर *99* वीं रिपोर्ट

उच्च न्यायालयों में तर्क और लिखित तर्क

(1984) ; सतीश चंद्र की समिति की रिपोर्ट *1986;* एल. सी. आई.,

एड्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

124 उच्च न्यायालय के बकाया पर रिपोर्ट-एक नया रूप

(1988) ; बकाया समिति की रिपोर्ट *(1989-90)*। *85.* कठिन कार्य का मूल्यांकन जो सामना करता है

मूल्यांकन का उल्लेख करके उच्च न्यायालय बनाए जा सकते हैं।

एल. सी. आई. ने अपनी *124* वीं रिपोर्ट में कहा था कि

संपत में फैसले के कुछ समय बाद रिहा किया गया

कुमार का मामला *(*ऊपर*)*। यह रिपोर्ट *1988* में दी गई थी।

नौ साल पहले, और तब से कुछ बदलाव हुए हैं,

लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य जो उभरता है वह अभी भी है बड़ा, सचः

...... उच्च न्यायालय सिविल के साथ-साथ आपराधिक भी होते हैं।

सामान्य और साथ ही असाधारण, और सामान्य के रूप में

विशेष अधिकार क्षेत्र के रूप में। इसका स्रोत अधिकारिता संविधान और विभिन्न है

के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदान किया गया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, *1951*

कंपनी अधिनियम, *1956* और कई अन्य विशेष

अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के रूप में। द हाई न्यायालयों को इसके तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र प्राप्त है -

संविधान के अनुच्छेद *226* और *227*

यह विशेषाधिकार रिट जारी करने के लिए है, जैसे कि,

बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति, आदेश, निषेध,

प्रतिभूति और प्रतिभूति। इसके अलावा,

बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली के उच्च न्यायालय,

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और

मद्रास भी साधारण मूल नागरिक का प्रयोग करता है।

अधिकार क्षेत्र। उच्च न्यायालयों को भी सलाह का लाभ मिलता है

अधिकारिता, जैसा कि धारा *256* द्वारा प्रमाणित है

भारतीय कंपनी अधिनियम, *1956,2* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. की धारा *27*।

धन कर अधिनियम, *1957*, उपहार कर अधिनियम, *1958* की धारा *26* और कंपनियों *(*लाभ*)* की धारा *18*

सलाहकार अधिकारिता प्रदान करने वाले प्रावधान उच्च न्यायालय, जैसे कि सीमा शुल्क की धारा *130*

अधिनियम, *1962* और केंद्रीय राजकोष की धारा *354*

और नमक अधिनियम, *1944*। उच्च न्यायालयों को भारतीय तलाक अधिनियम के तहत भी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।

1869 , और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम,

1936. विभिन्न प्रकार के मुकदमे सामने आते हैं

अपने व्यापक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के अलग-अलग नाम हैं। अधिकारिता का विशाल क्षेत्र कर सकता है उन नामों के संदर्भ में सराहना की जाए, अर्थात। , *(* ए*)* पहली अपील*; (*बी*)* पत्रों के तहत अपील

पेटेंट*; (*ग*)* दूसरी अपील*; (*घ*)* पुनरीक्षण याचिकाएँ*;*

(ई*)* आपराधिक अपील*; (*च*)* आपराधिक संशोधन*; (*छ*)* दीवानी और आपराधिक संदर्भ*; (*छ*)* रिट याचिकाएँ*; (1)* रिट अपील*; ()* प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के तहत संदर्भ

कानून*; (*के*)* बिक्री कर अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामले*;*

अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और अन्य विशेष अधिनियम और *(*एन*)* जहाँ भी उच्च न्यायालय के पास मूल है

अधिकारिता, मुकदमे और अभ्यास में अन्य कार्यवाही

उस अधिकार क्षेत्र से। इस विविध अधिकार क्षेत्र को

कुछ हद तक बहुत भारी के लिए जिम्मेदार था

उच्च न्यायालयों में मामलों की संस्था।

86. उच्च न्यायालयों में मौजूदा स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद, एल. सी. आई. ने विशेषज्ञ न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए विशिष्ट सिफारिशें कीं, जिससे ऋण दिया जा सके।

संपत कुमार के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण पर बल

(ऊपर*)*। एल. सी. आई. ने पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रवृत्ति का उल्लेख किया जो सामान्य अदालतों द्वारा विशेषज्ञ न्यायाधिकरणों को अपना स्थान देने की ओर इशारा करती थी। विचाराधीनता का वर्णन करते हुए

उच्च न्यायालयों को "विनाशकारी, संकटग्रस्त, लगभग असहनीय, लागू करने वाला. आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन पर एक अथाह बोझ।

भारत संघ *143*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

एल. सी. आई. ने कहा कि भारतीय न्यायशास्त्र में प्रचलित दृष्टिकोण कि उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त अधिकार क्षेत्र एक पवित्र गाय है, की समीक्षा की आवश्यकता है। इसलिए,

विशेषज्ञ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों की स्थापना करके उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को कम करने की सिफारिश की गई है, जबकि

साथ ही उच्च के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करना

अदालतें।

87. यह समझना महत्वपूर्ण है कि हालांकि सिद्धांत

वैकल्पिक संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव किया गया था

के संबंध में संपत कुमार का मामला *(*ऊपर*)*

प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अवधारणा स्वयं की

विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों का निर्माण करना जो

उच्च न्यायालयों को उनके बोझ से राहत मिलेगी, जबकि

साथ ही विशेष न्याय प्रदान करना कोई नई बात नहीं है।

वास्तव में, एक विशेष कर अदालत होने के मुद्दे पर कई दशकों से चर्चा की जा रही है; हालाँकि

उच्च न्यायालय की बकाया समिति *(1972)* ने इसे "गलत कल्पना" के रूप में खारिज कर दिया, एल. सी. आई. ने अपनी *115* वीं रिपोर्ट *(1986)* में

अलग केंद्रीय कर स्थापित करने की सिफारिश

अदालतें। इसी तरह, एल. सी. आई. की अन्य रिपोर्टों ने 'ग्राम न्यायालय' *[*एल. सी. आई., *114* वीं रिपोर्ट*]* की स्थापना का सुझाव दिया है। *(1986)]* , औद्योगिक/श्रम न्यायाधिकरण *[*एल. सी. आई., *122* वीं रिपोर्ट *(1987)]* और शिक्षा न्यायाधिकरण *[*एल. सी. *1,123* वीं रिपोर्ट*]*

(1987)] .

88. आर. के. जैन के मामले में, *(1993)* ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. *1899*, इस न्यायालय ने

था, यह समझने के लिए कि कैसे विकल्प का सिद्धांत

संस्थागत तंत्र ने व्यवहार में काम किया था,

अनुशंसा की जाती है कि एल. सी. आई. या इसी तरह के किसी विशेषज्ञ निकाय को

इन न्यायाधिकरणों के कामकाज का सर्वेक्षण करना। यह था।

उम्मीद है कि इस तरह का अध्ययन, न्यायाधिकरणों के कामकाज का आकलन करने के बाद किया गया है पाँच साल से अधिक समय तक प्रश्नों का उत्तर मिलेगा।

सिद्धांत के आलोचकों द्वारा प्रस्तुत। दुर्भाग्य से, हमें इस तरह के अध्ययन का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन हम विज्ञापन दे सकते हैं।

बकाया समिति की रिपोर्ट *(1989-90)*।

मलिमथ समिति रिपोर्ट के रूप में लोकप्रिय, जो शीर्ष अदालत रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

इस पहलू पर विस्तार से चर्चा की है। रिपोर्ट में निहित टिप्पणियाँ, इस हद तक वे न्यायाधिकरणों के कार्यकरण की उनकी स्थापना के बाद तीन साल या उससे अधिक की अवधि की समीक्षा करती हैं, हमारे लिए उपयोगी होंगी। उद्देश्य। रिपोर्ट के दूसरे खंड के अध्याय *VIII*, "विवाद समाधान के लिए वैकल्पिक तरीके और मंच",

इस मुद्दे से विस्तार से निपटें। इसके विशिष्ट को अग्रेषित करने के बाद

'ग्राम' की स्थापना की व्यवहार्यता पर सिफारिशें

न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण और शैक्षिक न्यायाधिकरण,

समिति ने संविधान के अनुच्छेद *323*-ए और *323*-बी के तहत स्थापित न्यायाधिकरणों के मुद्दे पर विचार किया है। द.

इस संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियाँ, हमारे विश्लेषण के लिए काफी महत्वपूर्ण होने के कारण, नीचे पूरी तरह से निकाली गई हैं:

"न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली *8.63* देश में कई न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं।

हालाँकि, उनमें से सभी ने आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं किया है

जनता के मन में। कारण खोजने के लिए बहुत दूर नहीं हैं।

संविधान, उसमें कर्मियों की नियुक्ति की शक्ति और विधि, निम्नतम स्थिति और काम करने का अनौपचारिक तरीका। अंतिम उनकी वास्तविक संरचना है; क्षमता के पुरुष पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त होने के लिए तैयार नहीं हैं।

कार्यकाल की अनिश्चितता, असंतोषजनक स्थितियाँ

सेवा, मामलों में कार्यकारी अधीनता

न्यायिक कार्यप्रणाली में प्रशासन और राजनीतिक हस्तक्षेप। इन और अन्य कारणों से, न्याय की गुणवत्ता को पीड़ित बताया गया है और

ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना द्वारा सेवा प्रदान की गई। *8.64* यहाँ तक कि स्थापना का प्रयोग भी

प्रशासनिक के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण

न्यायाधिकरण अधिनियम, *1985* का व्यापक रूप से स्वागत नहीं किया गया है। इसके सदस्यों का चयन सभी प्रकार के एस बार एसोसिएशन से किया गया है।

भारतीय पुलिस सेवा सहित सेवाएँ। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्णय हैं -

संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत अपील योग्य नहीं है। भारी लागत के कारण और फोरम की दूरस्थता, अपील के अधिकार का आभासी निषेध है। इससे इनकार किया गया है

कई मामलों में न्याय और परिणामी

असंतोष। ऐसा लगता है कि एक चाल है

कुछ राज्य जहाँ वे रहे हैं

उनके उन्मूलन के लिए स्थापित। न्यायाधिकरण-उच्च न्यायालय सहित परीक्षण

· अधिकारिता

8.65 एक न्यायाधिकरण जो उच्च न्यायालय को प्रतिस्थापित करता है न्यायिक समीक्षा के लिए एक वैकल्पिक संस्थागत तंत्र उच्च न्यायालय से कम प्रभावी नहीं होना चाहिए।

अदालत। इस तरह के न्यायाधिकरण को विश्वास पैदा करना चाहिए और सार्वजनिक सम्मान है कि यह एक अत्यधिक सक्षम और

न्यायिक दृष्टिकोण के साथ विशेषज्ञ तंत्र और

निष्पक्षता। न्यायाधिकरण में क्या आवश्यक है, जो है उच्च न्यायालय को प्रतिस्थापित करने का इरादा, कानूनी है

प्रशिक्षण और अनुभव, और न्यायिक कौशल, उपकरण और दृष्टिकोण। जब ऐसा न्यायाधिकरण है

न्यायपालिका से लिए गए कर्मियों से बना

सेवाओं से या क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच से, सेवा के पक्ष में कोई भी महत्व

सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य और मूल्य

न्यायिक सदस्यों को छूट देने से उच्च न्यायालय की तुलना में कम प्रभावी और प्रभावी न्यायाधिकरण

अदालत। ऐसे न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाले अधिनियम को स्वयं ऐसे अधिनियम के तहत शून्य घोषित करना होगा।

परिस्थितियाँ। यह न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन्हें प्रभावित करने की प्रवृत्ति भी हो सकती है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया, खासकर जब

अधिकांश मामलों में सरकार एक वादी है। ऐसे न्यायाधिकरण के समक्ष आना। *(* एस. पी. संपत *3* देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

,

कुमार का मामला *(ऊपर))*। विशेषज्ञ न्यायाधिकरणों के नायक, जो एक साथ अपने

उच्च न्यायालयों को ऐसे न्यायाधिकरणों को न्यायनिर्णयन के लिए सौंपे गए मामलों के संबंध में इन महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसे होना ही चाहिए। यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जिसे दूसरे समान रूप से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुमति है और

प्रभावी संस्थागत तंत्र उच्च है

न्यायालय, न कि स्वयं न्यायिक समीक्षा। न्यायाधिकरण

अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि एक अंत का साधन है; भले ही तेजी के प्रशंसनीय उद्देश्य

न्याय, दृष्टिकोण की एकरूपता, की भविष्यवाणी

निर्णय और विशेषज्ञ न्याय प्राप्त किया जाना है,

उन्हें प्राप्त करने के लिए स्थापित किए जाने वाले न्यायाधिकरण के ढांचे को अभी भी अपने बुनियादी न्यायिक ढांचे को बनाए रखना चाहिए।

चरित्र और जनता के विश्वास को प्रेरित करें। कोई भी।

न्याय प्रशासन के विकेंद्रीकरण की योजना जो एक वैकल्पिक संस्थागत व्यवस्था प्रदान करती है

उच्च न्यायालयों के प्रतिस्थापन में तंत्र को संवैधानिक रूप से होने के लिए उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

वैध है।

8.66 न्यायाधिकरण के संबंध में समग्र तस्वीर

हमारे देश में न्याय संतोषजनक नहीं है और प्रोत्साहन देते हैं। एक नए रूप की आवश्यकता है और

समीक्षा और उससे पहले एक गंभीर विचार

उच्च न्यायालयों को एक साथ हटा दिया जाना है। उपरोक्त परीक्षणों को संतुष्ट करने वाले कई न्यायाधिकरण नहीं कर सकते हैं संभवतः स्थापित किया जा सकता है। "

इस तरह से खुद को व्यक्त करने के बाद, मलिमथ

समिति ने विशेष रूप से सिफारिश की कि

इसके बजाय, इसने अनुशंसा की कि संस्थागत परिवर्तन उच्च न्यायालयों के भीतर किया जाता है, उन्हें ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v* में विभाजित किया जाता है।

भारत संघ *147*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

89. मलिमथ समिति की रिपोर्ट दिए जाने के बाद से गुजरने वाले वर्षों में, उच्च न्यायालयों में काफी वृद्धि हुई है और हम

यह देखते हुए कि इसकी सिफारिश हमारे वर्तमान के अनुकूल नहीं है

संदर्भ। कि विभिन्न न्यायाधिकरणों ने कार्य नहीं किया है

अपेक्षाओं के लिए एक आत्म-स्पष्ट और व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है

सच। हालांकि, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि वे असंतोषजनक हैं

प्रदर्शन इंगित करता है कि वे एक पर आधारित हैं

मौलिक रूप से अस्पष्ट सिद्धांत सही नहीं होगा। द.

जिन कारणों से अभी भी न्यायाधिकरणों का गठन किया गया था

जारी है; वास्तव में, वे कारण और भी अधिक हो गए हैं

हमारे समय में घोषित। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि

हमारी संवैधानिक योजना ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना की अनुमति देती है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए उनके मानकों को ऊपर उठाने के लिए कठोर उपायों का सहारा लेना पड़ सकता है

कि वे निर्वहन में संवैधानिक जांच के लिए खड़े हैं

उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति। हमारे पास है। पहले से ही न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है। अनुच्छेद *226/227* के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता

इसे अलग नहीं किया जा सकता है। हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरणों को इस पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

जिन मामलों में विधानों की शक्तियों पर सवाल उठाया जाता है, और

कि उन्हें खुद को मामलों को संभालने तक सीमित रखना चाहिए

जहाँ संवैधानिक मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। हम नहीं ला सकते।

हम स्वयं इस प्रस्ताव से सहमत हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप हो सकता है

कार्यवाहियों को विभाजित करने में और इससे बचा जा सकता है

विलम्ब। यदि इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो यह खुला रहेगा।

वादियों के लिए संवैधानिक मुद्दों को उठाने के लिए, जिनमें से कई

उच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. से सीधे संपर्क करना काफी तुच्छ हो सकता है।

और इस प्रकार न्यायाधिकरणों की अधिकारिता को नष्ट कर देता है। इसके अलावा,

कानून की इन विशेष शाखाओं में भी, कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है

संवैधानिक प्रश्नों पर विचार करना शामिल है

नियमित आधार पर; उदाहरण के लिए, सेवा कानून के मामलों में, अधिकांश मामलों में अनुच्छेद *14* की व्याख्या शामिल है। *15* और संविधान के *16.* यह अभिनिर्धारित करना कि न्यायाधिकरणों को संवैधानिक मुद्दों से जुड़े मामलों को संभालने की कोई शक्ति नहीं है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जिसके लिए वे थे।

गठित किया गया। दूसरी ओर, यह मानने के लिए कि इस तरह के सभी

निर्णय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे

संविधान के अनुच्छेद *226/227* के तहत अदालतें उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर

संबंधित न्यायाधिकरण की अधिकारिता दो उद्देश्यों को पूरा करेगी। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बचाते हुए

अनुच्छेदों के तहत उच्च न्यायालयों में निहित विधायी कार्रवाई

226/227 संविधान के अनुसार, यह सुनिश्चित करेगा कि तुच्छ दावों को निर्णय की प्रक्रिया के माध्यम से फ़िल्टर किया जाए

न्यायाधिकरण में। उच्च न्यायालय को गुण-दोष पर तर्कपूर्ण निर्णय का भी लाभ मिलेगा जो उसके लिए उपयोगी होगा।

अंत में मामले को तय करने में।

91. हमारे सामने यह भी तर्क दिया गया है कि यहाँ तक कि

ऐसे मामलों से निपटना जो ठीक से न्यायाधिकरणों के समक्ष हैं, जिस तरह से उनके द्वारा न्याय दिया जाता है, वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। इसके अलावा, में प्रदान किया गया उपाय

संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील के माध्यम से मूल क़ानून बहुत महंगे हैं और

यह वास्तविक और प्रभावी होने के लिए दुर्गम है। इसके अलावा,

इस तरह का उपाय प्रदान करने का परिणाम यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिकरणों के निर्णयों से भरा हुआ है जिन्हें अपेक्षाकृत तुच्छ आधारों पर चुनौती दी जाती है और यह प्रथम अपीलीय न्यायालय की भूमिका निभाने के लिए मजबूर होता है। हम पहले ही यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दे चुके हैं कि उच्च न्यायालय न्यायिक कार्य करने में सक्षम हों

संविधान के अनुच्छेद *227* के तहत न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर पर्यवेक्षण। आर. के. जैन के मामले में *(ऊपर),*

इन तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, यह सुझाव दिया गया कि मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत का संघ *149*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

कानून के प्रश्नों पर न्यायाधिकरण से उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ में अपील की संभावना, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकरण आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है।

सुझाव के लिए। इस तरह के उपाय में सुधार हुआ होगा।

के अनुच्छेद *226/227* के तहत न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र संविधान, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष

जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर विशेष न्यायाधिकरण

गिरता है।

संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत उच्चतम न्यायालय को न्यायाधिकरण संविधान। उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए।

यह स्थिति भी बदल जाएगी। इस दृष्टि से कि हम

न्यायाधिकरण के निर्णय से कोई भी अपील अनुच्छेद *136* के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं होगी।

संविधान; लेकिन इसके बजाय, पीड़ित पक्ष होगा

के अनुच्छेद *226/227* के तहत उच्च न्यायालय में जाने का हकदार

संविधान और प्रभाग के निर्णय से

उच्च न्यायालय की पीठ पीड़ित पक्ष आगे बढ़ सकता है

संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत यह न्यायालय। *93.* अन्य पहलुओं पर आगे बढ़ने से पहले, हम संक्षेप में बता सकते हैं

इनकी अधिकारिता संबंधी शक्तियों पर हमारे निष्कर्ष

न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण उन मामलों की सुनवाई करने के लिए सक्षम हैं जहां वैधानिक प्रावधानों की शक्तियों पर सवाल उठाए जाते हैं।

हालाँकि, इस कर्तव्य के निर्वहन में, वे इस रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के लिए प्रतिस्थापन

जो हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत किए गए हैं

विशेष रूप से इस तरह के दायित्व के साथ सौंपा गया। उनके इस संबंध में कार्य केवल पूरक है और ऐसे सभी

न्यायाधिकरणों के निर्णय पहले जांच के अधीन होंगे।

संबंधित उच्च न्यायालयों की एक खंड पीठ।

परिणामस्वरूप न्यायाधिकरणों के पास अधीनस्थ विधानों और नियमों की शक्तियों का परीक्षण करने की शक्ति भी होगी। हालांकि, यह

अधिनियम उसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। में। अकेले ऐसे मामलों में, संबंधित उच्च न्यायालय से सीधे संपर्क किया जा सकता है। इन न्यायाधिकरणों के अन्य सभी निर्णय, उन मामलों में दिए जाते हैं जिनके लिए वे विशेष रूप से सशक्त हैं

अपने मूल कानूनों के आधार पर निर्णय लेना, उनकी एक खंड पीठ के समक्ष भी जांच के अधीन होगा। संबंधित उच्च न्यायालय। हम यह जोड़ सकते हैं कि न्यायाधिकरण करेंगे,

हालाँकि, वे कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में पहली बार के एकमात्र न्यायालयों के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं जिनके लिए वे कार्य कर रहे हैं।

गठित किया गया। इससे हमारा मतलब है कि यह इसके लिए खुला नहीं रहेगा।

वादियों को उन मामलों में भी सीधे उच्च न्यायालयों का रुख करना चाहिए जहां वे वैधानिक विधानों की शक्तियों पर सवाल उठाते हैं

(सिवाय, जैसा कि उल्लेख किया गया है, जहां कानून जो बनाता है

विशेष न्यायाधिकरण को चुनौती दी गई है*)*

संबंधित न्यायाधिकरण की अधिकारिता।

94. न्यायाधिकरणों के निर्णय लेने के संबंध में हमारे द्वारा जारी किए गए निर्देश एक के समक्ष जांच के लिए उत्तरदायी हैं

तथापि, संबंधित उच्च न्यायालयों की खंड पीठ,

संभावित रूप से प्रभावी होना अर्थात इसके बाद दिए गए निर्णयों पर लागू होगा। न्यायपालिका की पवित्रता बनाए रखने के लिए

कार्यवाही, हमने संभावित के सिद्धांत को लागू किया है

ओवररुलिंग ताकि संबंधित प्रक्रिया में बाधा न आए

पहले से ही दिए गए निर्णय "।

ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का यह तर्क था कि याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत की गई दलीलें पूरी तरह से अस्वीकृत होने के लिए उत्तरदायी हैं।

((ii) रिलायंस को भारत संघ बनाम पर सबसे पहले रखा गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, *(2002) 4* एस. सी. सी. *275*।

जैसा कि तत्काल निर्णय में उठाए गए विवाद का संबंध है, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि बैंक और वित्तीय

संस्थानों को ऋणों की वसूली और प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली की प्रक्रिया, जिसका पालन किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप धन अवरुद्ध हो गया था। उपरोक्त स्थिति को सुधारने के लिए, संसद ने अधिनियम बनाया

बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम के कारण ऋणों की वसूली,

1993. अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है और अपीलीय न्यायाधिकरण। उक्त न्यायाधिकरण दिए गए थे

वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आवेदनों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और प्राधिकरण

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण। अपीलीय न्यायाधिकरण, अधिकारिता और अधिकार के साथ निहित था,

अपीलों का मनोरंजन करें। न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान उपरोक्त अधिनियम के तहत किया गया था। कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि

वसूली अधिकारियों (अधिनियम के तहत नियुक्त) के माध्यम से ऋण की वसूली के तरीके। बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम के कारण ऋणों की वसूली की संवैधानिक वैधता,

1993 इस आधार पर उठाया गया था कि कानून था यह अनुचित और संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है। यह.

यह उन लोगों का भी दावा था जिन्होंने उक्त चुनौती उठाई थी, कि अधिनियम की विधायी क्षमता से परे था

संसद। विवाद की जांच की गई, पहले में उदाहरण के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा (दिल्ली उच्च न्यायालय बार में)

एसोसिएशन वी। भारत संघ, ए. आई. आर. *1975* दिल्ली *323)*। दिल्ली।

उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही न्यायाधिकरण का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है, और भले ही संविधान

न्यायाधिकरण का गठन संविधान के अनुच्छेद *323* ए और *323* बी के दायरे में था और इस तथ्य के बावजूद कि,

"न्याय का प्रशासन "की सूची *III* की प्रविष्टि *11* ए में दिखाई देता है

संविधान की सातवीं अनुसूची में न्याय का प्रशासन करने वाले न्यायाधिकरण भी शामिल होंगे, फिर भी विवादित अधिनियम था

असंवैधानिक, क्योंकि इसका तर्कहीन होने के अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रभाव पड़ा, भेदभावपूर्ण, अनुचित और मनमाना। इस प्रकार यह आयोजित किया गया था:

152 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था

संविधान के अनुच्छेद *14* में निहित जनादेश। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया। इस पर निर्णय लेते हुए

उपरोक्त विवाद में हमारे सामने उठाए गए कुछ मुद्दों के संदर्भ में, निम्नलिखित टिप्पणियों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया थाः

"21. ...... धारा *19* की उप-धारा *(20)* में प्रावधान है कि

आवेदक और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देते हुए न्यायाधिकरण इस तरह के अंतरिम या अंतिम फैसले को पारित कर सकता है।

न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जैसा वह उचित समझता है, आदेश दें। इस आदेश के बाद पीठासीन द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

धन की वसूली के लिए अधिकारी से वसूली अधिकारी। अधिनियम की धारा *22* में संशोधन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम की धारा *19* और *22* को एक साथ पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि

कि न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण को होना है

उनके समक्ष मामले की सुनवाई करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित। अधिनियम की धारा *22 (1)* में कहा गया है कि

न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण, जबकि निर्देशित किया जा रहा है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन होना चाहिए

अधिनियम और नियमों के अन्य प्रावधान। नियम *12 (7)* में प्रावधान है कि यदि कोई प्रतिवादी भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार करता है

आवेदक द्वारा किया गया दावा, न्यायाधिकरण उस आवेदक के शपथ पत्र पर कार्य कर सकता है जो तथ्यों से परिचित है

मामले से। इस नियम में, जो आवेदक के बैंक आवेदन पर विचार से संबंधित है, कोई संदर्भ नहीं है गवाहों की जाँच के लिए। यह उप-नियम केवल संदर्भित करता है

आवेदक के शपथ पत्र पर। दूसरी ओर, नियम *12 (6)* में प्रावधान है कि न्यायाधिकरण, किसी भी समय,

पर्याप्त कारण किसी तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित करने का आदेश देता है या

एक आदेश पारित कर सकते हैं कि किसी भी गवाह का शपथ पत्र सुनवाई में पढ़ें। यह इस उप-नियम के प्रावधान में है।

कि गवाहों की प्रतिपरीक्षा के लिए एक संदर्भ दिया जाता है। *22.* शुरुआत में हम पाते हैं कि नियम *12* संतोषजनक नहीं है।

शब्दबद्ध। बैंकिंग न्यायाधिकरण मद्रास बार एसोसिएशन की स्थापना का कारण *v.*

भारत का संघ *153*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

बैंकों द्वारा दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए, संसद ने केवल सिद्धांतों की आवश्यकता को उचित माना

प्राकृतिक न्याय का आवेदनों पर निर्णय लेने में न्यायाधिकरणों के लिए मार्गदर्शक कारक होना, जैसा कि अधिनियम की धारा *22* से स्पष्ट है। जबकि न्यायाधिकरण को, कोई संदेह नहीं, दिया गया है

की उपस्थिति को बुलाने और लागू करने की शक्ति

कोई भी गवाह और शपथ पर उसकी जाँच करता है, लेकिन अधिनियम करता है

इसमें कोई प्रावधान नहीं है जो इसे अनिवार्य बनाता है

जाँच किए जाने वाले गवाह, यदि ऐसा गवाह हो सकता है

उत्पादित किया। नियम *12 (6)* के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए

अधिनियम और नियमों के अन्य प्रावधान। जैसा कि हमारे पास है। नियम *12 (7)* न्यायाधिकरण को शक्ति देता है

आवेदक के शपथ पत्र पर कार्रवाई करने के लिए जहां

प्रतिवादी दावों का भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार करता है। नियम *12 (6),* यदि व्याख्या की जाती है, तो इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगाः

1. न्यायाधिकरण, किसी भी समय पर्याप्त के लिए

कारण, आदेश दें कि किसी विशेष तथ्य या तथ्य को शपथ पत्र द्वारा ऐसी शर्तों पर साबित किया जा सकता है जो न्यायाधिकरण उचित समझता है*; 2.* न्यायाधिकरण, किसी भी समय पर्याप्त कारण से, आदेश दे सकता है कि किसी भी गवाह का शपथ पत्र

सुनवाई में ऐसी शर्तों पर पढ़ा जा सकता है जैसे कि

न्यायाधिकरण उचित समझता है।

23. दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण के पास माँग करने की शक्ति है

कोई विशेष तथ्य जिसे शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाना है, या वह आदेश दे सकता है

कि किसी भी गवाह का शपथ पत्र सुनवाई में पढ़ा जा सके।

इस तरह का आदेश पारित करते समय, इसे पर्याप्त रूप से दर्ज करना चाहिए।

निश्चित रूप से केवल वहाँ लागू होता है जहाँ न्यायाधिकरण एक जारी करने का विकल्प चुनता है किसी विशेष तथ्य को साबित करने के लिए अपने दम पर निर्देश

शपथ-पत्र या किसी गवाह के शपथ-पत्र को पढ़ा जा रहा है सुनना। उक्त परंतुक एक की इच्छा को संदर्भित करता है

गवाह पेश करने के लिए आवेदक या प्रतिवादी

प्रतिपरीक्षा के लिए। जिस व्यवस्था में कहा गया है

परंतुक बनता है, यह हमें प्रतीत होता है कि एक बार पार्टियों *[2014] 10* एस. सी. आर.

4 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपने-अपने मामलों के समर्थन में शपथ पत्र दायर किए हैं, यह

इसके बाद ही गवाह से जिरह करने की इच्छा वैध रूप से उत्पन्न हो सकती है। यह उस समय है, यदि यह न्यायाधिकरण को दिखाई देता है, कि ऐसा गवाह हो सकता है

उत्पादित किया जाता है और ऐसा करना आवश्यक है और कोई नहीं है

इस मामले को लंबा करने की इच्छा कि इसके लिए गवाह को प्रतिपरीक्षा के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होगी और उसकी स्थिति में

उपस्थित नहीं होने पर शपथ पत्र में नहीं लिया जाएगा

सबूत। जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद *226* और अनुच्छेद के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

32 तथ्य के साथ-साथ कानून के प्रश्नों को केवल इस पर तय कर सकते हैं

उनके समक्ष दायर दस्तावेजों और शपथ पत्रों का आधार

आम तौर पर, इस बात का कोई कारण नहीं होना चाहिए कि क्यों एक न्यायाधिकरण, इसी तरह, केवल मामले का फैसला करने में सक्षम नहीं होना चाहिए

सामान्य ज्ञान है कि बैंक के साथ शायद ही कोई लेनदेन मौखिक और उचित प्रलेखन के बिना होगा। चाहे वह पत्रों के रूप में हो या औपचारिक समझौतों के रूप में। ऐसे में एक घटना जो एक गवाह की मौखिक परीक्षा के लिए प्रामाणिक रूप से आवश्यक है, शायद ही कभी उत्पन्न होनी चाहिए। बहुत अच्छा होना चाहिए

इस तरह के मामले में उस शपथ पत्र को रखने का कारण पर्याप्त नहीं होगा।

24. जिस तरीके से किसी विवाद का निर्णय लिया जाना है

उन प्रक्रियात्मक कानूनों द्वारा तय किया जाता है जो अधिनियमित किए जाते हैं

समय-समय पर। यह अधिनियम के कारण है

सिविल प्रक्रिया संहिता कि आम तौर पर सिविल प्रकृति के पक्षों के बीच सभी विवादों पर दीवानी अदालतों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। किसी को भी पूर्ण अधिकार नहीं है माँग कीजिए कि उसके विवाद का निर्णय केवल

एक दीवानी अदालत। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आगे बढ़ता है

ऋण वसूली अधिनियम के अधिनियमन से पहले, बैंकों द्वारा दायर वसूली के मुकदमों पर निर्णय लेना और वित्तीय संस्थान। यह मंच, अर्थात्, एक दीवानी न्यायालय का, आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *155*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

अब एक बैंकिंग न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

बैंक को देय ऋण। जब संविधान में अनुच्छेद *323*-ए और *323*-बी एक न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार करते हैं।

और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता है,

यह मानने का कोई कारण नहीं है कि बैंकिंग न्यायाधिकरणों और इस प्रकार गठित अपीलीय न्यायाधिकरणों को

स्वतंत्र, या कि न्याय से इनकार कर दिया जाएगा

प्रतिवादी या न्यायपालिका की स्वतंत्रता

सिकुड़ कर खड़े हो जाओ।

बिक्री कर या उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क या प्रशासन, अब इस मामले में न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। देश। इस तरह के विशेष संस्थान सख्ती से नहीं आ सकते हैं।

न्यायपालिका की अवधारणा के भीतर, जैसा कि अनुच्छेद *50* द्वारा परिकल्पित है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसे न्यायाधिकरण नहीं हैं

न्याय वितरण प्रणाली का एक प्रभावी हिस्सा, जैसे कानून की अदालतें। यह देखा जाएगा कि किसी व्यक्ति को किसी न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो

जिला न्यायाधीश बनने के लिए योग्य और, के मामले में

अपीलीय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न्यायाधिकरण वह न्यायाधीश होने के लिए योग्य है या रहा है

उच्च न्यायालय या भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो जिसने कम से कम तीन वर्षों तक प्रथम श्रेणी में पद संभाला हो।

कम से कम तीन वर्षों तक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य किया हो। ऐसे लोग जो

अपीलीय न्यायाधिकरण कानून में अच्छी तरह से पारंगत होगा स्वतंत्र रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से मामलों का निर्णय लेना। होना ही चाहिए।

यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय

यह अंतिम नहीं है, इस अर्थ में कि इसे अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है और

227 संविधान से। *26.* न्यायाधिकरणों की स्थापना के साथ, धारा *31*

लंबित मामलों को दीवानी अदालतों से न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने का प्रावधान है। हम इस तरह का प्रावधान नहीं पाते हैं।

कानून में किसी भी तरह से बुरा। एक बार ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पास *[2014] 10* एस. सी. आर. होते हैं।

6 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थापित किया गया है, और अधिनियम की धारा *18* द्वारा वर्जित न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, यह केवल तर्कसंगत होगा कि कोई भी

दीवानी अदालत में लंबित मामला न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ऐसा तब हुआ जब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। सभी मामले लंबित हैं।

उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण हो गया। अब वह अनन्य

अधिकारिता बैंकिंग न्यायाधिकरण में निहित है, यह केवल

वह मंच कि बैंक मामलों की सुनवाई की जा सकती है और इसलिए, ए

धारा *31* जैसा प्रावधान अधिनियमित किया गया था, *27.* न्यायाधिकरणों की आर्थिक अधिकारिता के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के संबंध में और

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह अधिनियम पूरे भारत के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिकांश राज्यों में, उच्च न्यायालय ऐसा करते हैं

मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह देखने के लिए कि

न्यायाधिकरण उन मामलों से भरा नहीं है जहां राशि

इसमें शामिल बहुत बड़े नहीं हैं, अधिनियम में प्रावधान है कि यह केवल तभी है जब धन की वसूली *10* लाख रुपये से अधिक है कि न्यायाधिकरण के पास इस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा

धारा *19* के तहत आवेदन। *10* लाख रुपये से कम की राशि की वसूली के लिए मुकदमों के संबंध में, यह है अधीनस्थ न्यायालय जो उन पर मुकदमा चलाते रहेंगे। में।

दूसरे शब्दों में, *10* लाख रुपये या उससे अधिक के दावे के लिए, न्यायाधिकरण को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, लेकिन किसी भी

10 लाख रुपये से कम राशि, यह सामान्य दीवानी अदालतें हैं।

जिसका अधिकार क्षेत्र होगा। मूल का विभाजन

दिल्ली उच्च न्यायालय और के बीच अधिकारिता

अधीनस्थ अदालतें एक ऐसा मामला है जिसमें कोई नहीं हो सकता है

न्यायाधिकरण की स्थापना की वैधता पर असर डालना। यह केवल उन उच्च न्यायालयों में है जिनके पास मूल हैं।

यह अधिकार क्षेत्र है कि एक विसंगत स्थिति उत्पन्न होती है जहां *10* लाख रुपये से कम की राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जाना है। उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय लिया जाता है जबकि न्यायाधिकरणों के पास रुपये से अधिक की वसूली के लिए मुकदमों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होता है।

10 लाख। यह असंगत स्थिति, जो हो सकती है

उच्च न्यायालय द्वारा मूल से खुद को अलग करते हुए सुधार किया गया

ऐसे दावों के संबंध में अधिकारिता और उक्त मद्रास बार एसोसिएशन को निहित करना।

भारत का संघ *157*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

अधीनस्थ न्यायालयों के साथ अधिकारिता या इसके विपरीत,

यह अभिनिर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता कि अधिनियम अमान्य है।

XXX

XXX

XXX

और आयकर *(*प्रमाणपत्र कार्यवाही*)* नियम, *1962*, द्वारा बकाया की वसूली के लिए लागू हो गए हैं

पुनर्प्राप्ति अधिकारी। पुनर्प्राप्ति के लिए विस्तृत प्रक्रिया है

अधिकारी मनमाने तरीके से कार्य करेगा। इसके अलावा, धारा *30*, संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन के बाद,

2000 , किसी आदेश से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है

पुनर्प्राप्ति अधिकारी का, न्यायाधिकरण में अपील को प्राथमिकता देना।

इस प्रकार अब इसके खिलाफ एक अपीलीय मंच प्रदान किया गया है।

वसूली अधिकारी का कोई आदेश जो इसमें नहीं हो सकता है

कानून के अनुसार। इसलिए, पर्याप्त है सुरक्षा जो की स्थिति में प्रदान की गई है

वसूली अधिकारी मनमाना या अनुचित तरीके से कार्य कर रहा है

तरीके से। धारा *25* और *28* के प्रावधान हैं -

इसलिए, कानून में बुरा नहीं है।

31. उपरोक्त कारणों से, अपीलों को अनुमति देते समय

भारत संघ और बैंकों का मानना है कि

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली

अधिनियम, *1993* एक वैध विधान है। इसके परिणामस्वरूप,

विभिन्न पक्षों द्वारा दायर रिट याचिकाएँ या अपीलें

उनके प्रावधान खारिज कर दिए जाते हैं। इसके लिए खुला रहेगा अपने गुण-दोष पर अन्य विवाद उठाने के लिए पक्षकार

संविधान के अनुच्छेद *226* और/या *227* के तहत। हस्तांतरित मामलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। पार्टियाँ

"158 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

(iii) रिलायंस को कर्नाटक राज्य बनाम पर रखा गया था। विश्वभारती हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य। ,

(2003) 2 एससीसी *412*। विचार के लिए जो प्राथमिक प्रश्न उठा वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, *1986* की संवैधानिक वैधता थी। चुनौती जमीन पर उठाई गई थी,

कि संसद को पदानुक्रम स्थापित करने का अधिकार नहीं था

जिला मंच, राज्य आयोग जैसे न्यायालयों और राष्ट्रीय आयोग, इसके तहत स्थापित न्यायालयों के अलावा, न्यायालयों के एक समानांतर पदानुक्रम का गठन करेगा।

संविधान, अर्थात् जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और

सुप्रीम कोर्ट। इस संबंध में स्पष्ट निवेदन यह था कि

संसद केवल अदालतों की स्थापना कर सकती थी, जिनसे निपटने की शक्ति थी।

विशिष्ट विषय, लेकिन ऐसा न्यायालय नहीं जो समानांतर चले

दीवानी अदालतों में। यह दावा किया गया कि संविधान के अनुच्छेद *323* ए और *323* बी के तहत भी संसद ऐसा कर सकती है।

उच्च न्यायालय सहित सिविल न्यायालयों के प्रतिस्थापन में ऐसा विधान अधिनियमित नहीं करना जिसके द्वारा वह न्यायाधिकरण स्थापित कर सके। यह,

चुनौती देने वालों के अनुसार, वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला करेंगे। उपरोक्त अभिकथनों के विपरीत, संसद की विधायी क्षमता और

राज्य विधानमंडलों को न्यायालयों के निर्माण का प्रावधान करना और

सातवीं अनुसूची का *1* और प्रविष्टियाँ *11* क और *46* संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची *III* में निहित है। उपभोक्ता के सामने उठाई गई चुनौती की जांच करते हुए

संरक्षण अधिनियम, *1986*, ऊपर निर्दिष्ट आधारों पर, यह न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 12. उपरोक्त प्रावधानों का एक नंगे अवलोकन करता है

विधायिका के संबंध में किसी भी तरह का संदेह न छोड़ें

के निर्माण के लिए संसद की क्षमता

विशेष न्यायालय और न्यायाधिकरण। न्याय का प्रशासन; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन पूरी तरह से शामिल है। भारत के संविधान की सूची *III* की प्रविष्टि *11-*ए द्वारा। उक्त प्रविष्टि मूल रूप से सूची *II* की प्रविष्टि *3* का एक हिस्सा थी। इसकी वजह से

संविधान *(*बयालीसवाँ संशोधन*)* अधिनियम, *1976* और ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *159*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

इसकी धारा *57 (*ए*) (vi)* द्वारा इसे सूची *III* में इस प्रकार जोड़ा गया था:

मद *11-*ए।

13. संविधान के अनुच्छेद *246* के खंड *(2)* के आधार पर, संसद के पास कानून बनाने की आवश्यक शक्ति है -

को छोड़कर सभी न्यायालयों के संगठन के गठन का सम्मान

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।

याचिकाकर्ता पूर्ण शक्ति पर गंभीरता से विवाद नहीं कर सके के संविधान के संबंध में एक कानून बनाने के लिए संसद

अदालतों ने लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया है, केवल आग्रह किया कि यह नहीं किया

15. कथित प्रस्तुतिकरण कथित रूप से किया गया है निम्नलिखित टिप्पणियों पर या उनके आधार पर

आंशिक रूप से असहमति जताते हुए शिंगल, जे. द्वारा बनाया गया

विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 में निर्णय, पुनः: (1979) 1 एससीसी

380 (एस. सी. सी. पी. 455, पैरा 152)

" 152. इस प्रकार संविधान ने पर्याप्त और एक मजबूत संगठन की स्थापना के लिए प्रभावी प्रावधान।

स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक प्रशासन

देश, नागरिक के आवश्यक पूरक के साथ

और आपराधिक अदालतें। इसकी अनुमति नहीं है

संसद या राज्य विधानमंडल को नजरअंदाज करना या

संविधान की उस योजना को दरकिनार करते हुए

दीवानी या आपराधिक न्यायालय की स्थापना के लिए किसी राज्य में उच्च न्यायालय के समानांतर, या

अतिरिक्त या अतिरिक्त या दूसरा उच्च न्यायालय, या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय

अदालत। ऐसा कोई भी प्रयास असंवैधानिक होगा।

जिसे इस तरह से प्रतिष्ठित किया गया है संविधान और इतने सावधानी से वर्षों से देखभाल की गई।

}

16. विद्वान वकील का तर्क गलत है

चूंकि उक्त अधिनियम के प्रावधान इसके अतिरिक्त हैं

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के लिए [2014] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

0

और उसके अपमान में नहीं जैसा कि धारा 3 से स्पष्ट है।

वहाँ से।

टी 17. उक्त अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि

इसे आम आदमी को गलतियों से बचाने की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था।

सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए सामान्य कानून भ्रामक हो गया था। उक्त अधिनियम के संदर्भ में, एक उपभोक्ता का अधिकार है

जिसके परिणामस्वरूप सीधे कार्यवाही में भाग लें एक शक्तिशाली व्यापारिक घराने के खिलाफ उसकी असहायता का ध्यान रखा जा सकता है।

18. इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में निर्णयों पर विचार किया

उक्त अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य। उक्त कानून के कारण, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण बनाए गए हैं

जिला, राज्य और केंद्रीय स्तरों पर ताकि उपभोक्ता अपनी शिकायतों को किसी ऐसे मंच के समक्ष व्यक्त कर सके जहां

न्याय बिना किसी प्रक्रियात्मक झगड़ों और अति तकनीकों के किया जा सकता है।

19. उक्त अधिनियम के उद्देश्यों में से एक प्रावधान करना है उपभोक्ता आंदोलन को गति। द सेंट्रल

उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन भी अधिनियम की धारा *4* के अनुसार किया जाना है ताकि उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके और उसकी रक्षा की जा सके।

उपभोक्ताक अधिकार जेना कि पहिने देखल गेल अछि।

XXX XXX

XXX

24. धारा *10* के अनुसार, किसी जिले का अध्यक्ष फोरम एक ऐसा व्यक्ति होगा जो योग्य है या रहा है या है।

जिला न्यायाधीश होने के लिए और फोरम में दो अन्य सदस्य भी शामिल होंगे जिनके लिए व्यक्ति होना आवश्यक है

क्षमता, सत्यनिष्ठा और स्थिति और पर्याप्त है

अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, सार्वजनिक मामलों से संबंधित समस्याओं का ज्ञान या अनुभव या उनसे निपटने की क्षमता दिखाई है या

प्रशासन और उनमें से एक महिला होगी। द.

जिला फोरम के सदस्यों का कार्यकाल तय है।

25. उक्त अधिनियम की धारा *13* एक विस्तृत ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.* निर्धारित करती है।

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

1

विधि और तरीके के संबंध में प्रक्रिया जिसमें

जिला फोरम द्वारा प्राप्त शिकायतों की आवश्यकता है -

निपटा लिया जाए। धारा *14* में ऐसे निर्देशों का प्रावधान है जो

पहुंचने पर जिला मंच द्वारा जारी किया जा सकता है

संतुष्टि कि माल के खिलाफ शिकायत से पीड़ित है

शिकायत में निर्दिष्ट दोषों में से कोई भी या कि

शिकायत में निहित आरोप

सेवाओं में कमियां साबित हुई हैं। *26.* धारा *15* में दिए गए आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान है।

जिला फोरम द्वारा राज्य आयोग को।

27. धारा *16* में राज्य के गठन का प्रावधान है। आयोग जो इस प्रकार हैः

" 16. (1) प्रत्येक राज्य आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे - *(क)* एक व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायालय, जो

इसके अध्यक्ष होंगेः

बशर्ते कि इस खंड के तहत कोई नियुक्ति प्रमुख के साथ परामर्श के बाद के अलावा नहीं की जाएगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;

((ख) दो अन्य सदस्य, जो -

क्षमता, सत्यनिष्ठा और स्थिति और पर्याप्त ज्ञान या अनुभव है, या दिखाया है

संबंधित समस्याओं से निपटने की क्षमता

अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन, जिनमें से कोई एक

एक महिला बनेंः

बशर्ते कि इस खंड के तहत प्रत्येक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी

चयन समिति की सिफारिश

जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः

(1) राज्य आयोग के अध्यक्षः

अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

((ii) विधि विभाग के सचिव

बताइएः सदस्य

((iii) विभाग के प्रभारी सचिव

राज्य में उपभोक्ता मामलों से निपटनाः

सदस्य

(2) वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते

देय, और अन्य नियम और शर्तें

राज्य आयोग के सदस्यों की सेवा

ऐसा होगा जो राज्य द्वारा निर्धारित किया जाए

सरकार।

(3) राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य

पाँच वर्ष की अवधि के लिए या साठ-सात वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करें और

पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(4) उप में कुछ भी निहित होने के बावजूद

धारा *(3),* राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति या शुरू होने से पहले एक सदस्य के रूप में

उपभोक्ता संरक्षण *(*संशोधन*)* अधिनियम, *1993*

सदस्य, जैसा भी मामला हो, के पूरा होने तक उसका कार्यकाल "।

राज्य आयोग के सदस्यों का चयन किया जाना है।

एक चयन समिति द्वारा, जिसके अध्यक्ष

राज्य आयोग के अध्यक्ष बनें। *28.* धारा *19* में राज्य आयोग के निर्णय के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में अपील करने का प्रावधान है।

धारा *20* राष्ट्रीय आयोग की संरचना से संबंधित है, जिसका अध्यक्ष एक व्यक्ति होगा।

जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और ऐसी नियुक्ति केवल उनके साथ परामर्श करने पर की जाएगी -

भारत के मुख्य न्यायाधीश। जहाँ तक सदस्यों की बात है

राष्ट्रीय आयोग का संबंध है, वे भी चयन *163* की सिफारिश पर किए जाने हैं।

समिति, जिसका अध्यक्ष एक व्यक्ति होगा जो

द्वारा नामित किया जाने वाला सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है

भारत के मुख्य न्यायाधीश। के कार्यालय का कार्यकाल

राष्ट्रीय आयोग भी उप के कारण तय किया जाता है

धारा *20* की धारा *(3)*।

29. अतः उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कारण,

स्वतंत्र प्राधिकरण बनाए गए हैं।

30. धारा *15,19* और *23* में पदानुक्रम का प्रावधान है - अपीलें करें। उप-धारा *(4), (5)* और *(6)* के कारण

धारा *13*, जिला फोरम के पास समान शक्तियाँ होंगी। जैसा कि उल्लिखित उद्देश्यों के लिए दीवानी न्यायालयों में निहित हैं

उसमें। उप-धारा *14* की धारा *(2)* और *(2-ए)* अधिदेश

कि कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा संचालित की जाएगी

जिला फोरम का और उसका कम से कम एक सदस्य

एक साथ बैठे। केवल किसी भी अंतर की स्थिति में

उन्हें किसी भी बिंदु या बिंदु पर, उसी को संदर्भित किया जाना है

उस पर सुनवाई के लिए अन्य सदस्य और उनकी राय

बहुमत जिला मंच का आदेश होगा। के द्वारा

धारा *18* का कारण, धारा *12,13* के प्रावधान

और *14* और उसके तहत बनाए गए नियम परिवर्तनशील होंगे।

द्वारा विवादों के निपटारे के लिए उत्परिवर्तन लागू होंगे

राज्य आयोग।

31. धारा *23* में एक सीमित अपील का प्रावधान है -

राष्ट्रीय द्वारा दिए गए एक आदेश से सर्वोच्च न्यायालय

आयोग अर्थात जब इसका प्रयोग किया जाता है

खंड के उपखंड *(1)* द्वारा प्रदत्त इसकी मूल शक्ति

(क*)* धारा *21 "*।

यह न्यायालय तब भारत संघ पर निर्भरता रखते हुए

दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन *(*ऊपर*)*, नवीनचंद्र

फतलाल, बॉम्बे बनाम। आयकर आयुक्त, एमबे सिटी, ए. आई. आर. *1955* एस. सी. *58*, और भारत संघ बनाम।

भजन सिंह ढिल्लों, *(1971) 2* एस. सी. सी. *779*, ने निष्कर्ष निकाला

लेयरः

"37. एक बार यह माना जाता है कि संसद में विधायी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. थी।

उक्त अधिनियम को अधिनियमित करने की क्षमता, विद्वान वकील ने कहा कि संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों में आवश्यक संशोधनों की उपेक्षा की जानी चाहिए।

38. उक्त विधान का दायरा और उद्देश्य इस न्यायालय के समक्ष सामान्य कारण, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम में विचार के लिए आया। भारत संघ, *(1997) 10* एस. सी. सी. *729*।

यह आयोजित किया गया थाः *(* एस. सी. सी पी. *730*, पैरा *2)*

"2. कानून का उद्देश्य, प्रस्तावना के रूप में

अधिनियम घोषणा करता है, *'*उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए*'* है। पिछले कुछ वर्षों में

अधिनियम से पहले इस देश में था

वस्तुओं के उपभोक्ताओं के बीच एक उल्लेखनीय जागरूकता कि उन्हें अपने पैसे का मूल्य नहीं मिल रहा था और दोनों व्यापारियों और व्यापारियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था

उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माता। इसकी आवश्यकता

इसलिए उपभोक्ता निवारण मंचों को तेजी से महसूस किया गया। जाहिर है, इसलिए, कानून था

काफी के साथ प्रस्तुत और अधिनियमित किया गया

एक पथ-प्रदर्शक के रूप में उत्साह और धूमधाम

संरक्षण के लिए हितकारी कानून

बेईमानों द्वारा शोषण से उपभोक्ता

उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माता और व्यापारी। ए.

जिला मंच को शामिल करते हुए तीन स्तरीय मंच निवारण के लिए अधिनियम के तहत राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की परिकल्पना की गई

उपभोक्ताओं की शिकायतें।

39. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कारण पक्षों के अधिकारों की पर्याप्त रूप से रक्षा की गई है।

यद्यपि यह संक्षिप्त परीक्षण पर उपभोक्ता अधिकार क्षेत्र की एक वैकल्पिक प्रणाली प्रदान करता है, वे हैं

कारणों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता है। यहां तक कि जब नुकसान की मात्रा निर्धारित की जाती है, तो उन्हें न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य न केवल व्यक्ति को फिर से मुआवजा देना है, बल्कि एक नुकसान भी उठाना है।

सेवा प्रदाता के दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन।

कारणों का निर्धारण शामिल नहीं करता है या किसी भी दर पर कम करता है। मनमानेपन की संभावनाएँ और उच्च मंच बनाए गए

अधिनियम के तहत इसकी शुद्धता का परीक्षण किया जा सकता है।

40. जिला फोरम, राज्य आयोग और

राष्ट्रीय आयोग का संचालन आम लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। द.

राष्ट्रपति न्यायिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति होगा।

और अन्य सदस्यों के पास विशेषज्ञता होनी आवश्यक है

अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य जैसे विषय,

लेखा, उद्योग, सार्वजनिक मामले, प्रशासन आदि। यह.

यह सच हो सकता है कि धारा की उप-धारा *(2-ए)* के कारण

14 अधिनियम के बीच मतभेद के मामले में

दो सदस्य, मामले को तीसरे को भेजा जाना है

सदस्य और, दुर्लभ मामलों में, बहुमत की राय

अधिनियम को निरस्त करने के लिए केवल संभावना ही अपर्याप्त है क्योंकि असंवैधानिक, विशेष रूप से, जब प्रावधान किए गए हैं

इसके विरुद्ध किसी उच्चतर मंच में अपील करने के लिए उसमें किया गया।

41. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कारण, शक्ति

उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा, जो एक बुनियादी विशेषता है

संविधान को न तो हटाया गया है और न ही हटाया जा सकता है।

XXX

XXX

XXX

49. प्रयोज्यता या अन्यथा के संबंध में प्रश्न संविधान के अनुच्छेद *323*-ए और *323*-बी

ऐसे न्यायाधिकरणों के गठन का मामला सामने आया

भारत संघ, *(1997) 3* एस. सी. सी. *261*। इस न्यायालय में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि संवैधानिक प्रावधान निहित हैं

संसद और राज्य विधानमंडल, जैसा भी मामला हो

एक के पारंपरिक न्यायालयों को विभाजित करने की शक्तियों के साथ

उनके न्यायिक कार्य का काफी हिस्सा। यह देखा गया

जो संसद और राज्य विधानमंडलों के पास है

मूल में परिवर्तनों को प्रभावित करने के लिए विधायी क्षमता

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अलावा

प्राधिकरण से जो अनुच्छेद *323*-ए और *166* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. से आता है।

323 - बी जहां तक संसद का संबंध है, सूची *I* की प्रविष्टियों *77,78,79* और *95* के संदर्भ में और प्रविष्टि *65* के संदर्भ में।

जहाँ तक राज्य का संबंध है, सूची *II* और सूची *III* की प्रविष्टि *46*

विधायिकाएँ चिंतित हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसकी मूल संरचना है

संविधान को हटाया नहीं जा सकता है।

50. अतः हमारा स्पष्ट मत है कि उक्त

अधिनियम को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है।

चौथा विवादः

52 (1) चौथे विवाद, अर्थात् याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई चुनौती के जवाब में,

एन. टी. टी. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रस्तुत करना था

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील, कि की दृष्टि में

तीसरे विवाद के संबंध में प्रस्तुतियाँ, यह स्पष्ट है कि संसद के पास विधायी क्षमता थी एन. टी. टी. अधिनियम को लागू करना। यह प्रस्तुत किया गया था कि एन. टी. टी. अधिनियम को इसके द्वारा निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था।

न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सुरक्षित रखते हुए

संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालयों के साथ-साथ इसमें निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति को भी सुरक्षित रखते हुए

संविधान के अनुच्छेद *32* और *136* के तहत न्यायालय। यह है,

इसलिए, प्रस्तुत किया कि तत्काल न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में अंतिम शब्द, कानून की अदालतों के साथ संरक्षित है। और

इसलिए, विद्वानों के हाथों प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ीं

के व्यक्तिगत प्रावधानों पर याचिकाकर्ताओं के लिए वकील

न्यायनिर्णायक की स्वतंत्रता से संबंधित एन. टी. टी. अधिनियम

प्रक्रिया को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा था।

((ii) उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करने के बावजूद,

भारत के अटॉर्नी जनरल ने निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से कहा कि

यदि इस न्यायालय को लगता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो उसके पास था यह बताने के लिए निर्देश कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सकारात्मक रूप से देखा जाएगा, और एन. टी. टी. में आवश्यक संशोधन

अधिनियम का पालन किया जाएगा।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *167*

[जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

बहस और विचारः

1. एनटीटी अधिनियम की संवैधानिक वैधता-क्या एनटीटी अधिनियम

संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन करता है*?*

53. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के हाथों दिया गया मुख्य तर्क इस पर आधारित था -

प्रस्तुत करना कि संविधान *(*बयालीसवां संशोधन*)* अधिनियम, *1976* द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद *323* ख, इस हद तक कि

"शक्तियों के पृथक्करण", "कानून के शासन" के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, और "न्यायिक समीक्षा" को निरस्त किया जा सकता था। यह चौंकाने वाली बात

नीचे "बुनियादी" के कथित उल्लंघन पर स्थापित किया गया था संरचना "सिद्धांत। इसी तरह, एन. टी. टी. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर हमला करने की मांग की गई थी। एनटीटी अधिनियम के प्रावधान थे

इस आधार पर चुनौती दी गई कि उनके पास एन. टी. टी. के साथ निहित न्यायिक प्रक्रिया पर कार्यकारी नियंत्रण का जाल था, और

इसलिए, असंवैधानिक के रूप में अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी थे।

54. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के हाथों पूर्वगामी प्रस्तुतियों के संदर्भ में, यह है

"कानून के शासन" और "शक्तियों के पृथक्करण" की अवधारणाओं की रूपरेखा और योजना में समीक्षा ", जिन्हें आयोजित किया गया है संविधान की "मूल संरचना" का गठन करता है। और साथ ही, एक स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया के आवश्यक तत्व।

इसलिए हम इतिहास और कानून की सीढ़ी की यात्रा करेंगे।

"न्यायिक समीक्षा" का सटीक दायरा निर्धारित करने के लिए, जो

यह संविधान की "मूल संरचना" का गठन करता है। यह हमें एक स्वतंत्र के मुख्य अवयवों को उजागर करने के लिए प्रेरित करेगा।

न्यायनिर्णायक प्रक्रिया। उसके आधार पर हम अपने निष्कर्ष दर्ज करेंगे। विश्लेषणः

55. निर्णय के लिए सबसे पहले संदर्भ दिया जाना चाहिए।

केशवानंद भारती बनाम में इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत। की स्थिति

केरल, (1973) 4 एससीसी 225। उपरोक्त उद्धृत मामले में, यह न्यायालय संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के साथ-साथ संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की वैधता के साथ जुड़ा हुआ था। पूर्व अधिनियम से संबंधित

संविधान के अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन, 168 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 10 एस. सी. आर.

जबकि बाद वाला, संविधान के अनुच्छेद 31 के संशोधन से संबंधित था। तत्काल निर्णय एक द्वारा दिया गया था

13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ। सात न्यायाधीशों ने बहुमत की राय व्यक्त की। इसके द्वारा अभिलिखित टिप्पणियाँ

"न्यायिक समीक्षा" को संविधान की "मूल संरचना" के एक घटक के रूप में मान्यता देने वाले न्यायालय को चार न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया था।

सबसे पहले संदर्भ दिया जा रहा है, द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के लिए

एस. एम. सीकरी, सीजे। :

"292. विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि प्रत्येक संविधान का प्रावधान आवश्यक है; अन्यथा यह होगा

संविधान में नहीं रखा गया है। यह बात सच है। लेकिन यह

संविधान के हर प्रावधान को नहीं रखता है

एक ही स्थिति। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रत्येक प्रावधान

संविधान में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि

संविधान की मूल नींव और संरचना समान है। कहा जा सकता है कि मूल संरचना में शामिल हैं -

निम्नलिखित विशेषताएँ:

(1) संविधान की सर्वोच्चता; (2) रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक रूप

सरकार;

(3) संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र;

(4) विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण,

कार्यपालिका और न्यायपालिका;

(5) संविधान का संघीय चरित्र।

293. उपरोक्त संरचना मूल नींव यानी व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता पर बनी है। यह बात है

सर्वोच्च महत्व। यह किसी भी रूप में नहीं हो सकता है

संशोधन को नष्ट कर दिया जाए। "

जे. एम. शेलट और ए. एन. ग्रोवर, जे. जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचार का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। , जिसने एक आम दिया

फैसलाः

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *169*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

न्यायिक समीक्षा के लिए "। *. XXX XXX*

XXX

577. ...... न्यायिक समीक्षा अदालतों द्वारा की जाती है।

एक योद्धा में विधायी प्राधिकरण पर झुकने की किसी भी इच्छा से

आत्मा, लेकिन स्पष्ट रूप से निर्धारित कर्तव्य के निर्वहन में

उन्हें संविधान द्वारा "। उत्तरदाताओं ने भी

तर्क दिया कि अदालत को न्यायिक समीक्षा करने दें संवैधानिक संशोधनों का अर्थ होगा अदालत को शामिल करना।

राजनीतिक मुद्दों पर। इसका जवाब दिया जा सकता है

ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल बनाम में लॉर्ड पोर्टर के शब्द।

बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स, *1950* एसी *235 310* पर*,:*

"हल की जाने वाली समस्या अक्सर इतनी नहीं होगी

राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से कानूनी, फिर भी यह होना चाहिए

न्यायालय द्वारा हल किया गया। जहाँ विवाद है, यहाँ के रूप में, न केवल राष्ट्रमंडल और

नागरिक लेकिन राष्ट्रमंडल और हस्तक्षेप के बीच

एक ओर राज्य और दूसरी ओर नागरिक और राज्य

दूसरा, यह केवल न्यायालय है जो निर्णय कर सकता है

इस मुद्दे पर, संसद की आवाज उठाना व्यर्थ है "।

इसका संकेत देने के लिए संविधान में ही पर्याप्त सबूत हैं कि यह कारण से नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली बनाता है

जिनमें से शक्तियाँ इतनी वितरित हैं कि तीनों में से कोई भी नहीं इसके द्वारा स्थापित अंग इतने प्रबल हो सकते हैं कि

दूसरों को शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन करने से अक्षम करें और उन्हें सौंपे गए कार्य। हालांकि संविधान

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत निर्धारित नहीं करता है

अपनी सभी कठोरता में जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है

संविधान लेकिन यह एक के लिए इस तरह के अलगाव की परिकल्पना करता है

डिग्री जैसा कि रणसिंघे के मामले, *1965* ए. सी. *172* में पाया गया था। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई न्यायिक समीक्षा

अनुच्छेद *226* और *32* के माध्यम से एक विशेषता है

जिस पर नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली निर्भर करती है।

इसके अलावा, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, न्यायिक ओ सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. की आवश्यकता है।

ऑस्ट्रेलिया बनाम. औपनिवेशिक चीनी शोधन कंपनी, *1914* एसी *237* और एक्स पार्टी वाल्श एंड जॉनसन; इन रे येट्स, *(1925) 37* सी. एल. आर. *36* पृष्ठ *58* पर। एक की व्याख्या का कार्य

इस प्रकार संविधान को न्यायिक शक्ति सौंपी जा रही है -

राज्य, सवाल यह है कि क्या कानून का विषय इसके भीतर है

विधानमंडल की एक या अधिक शक्तियों का दायरा

संविधान द्वारा प्रदत्त हमेशा एक सवाल होगा संविधान की व्याख्या। यह जोड़ा जा सकता है कि किसी भी स्तर पर उत्तरदाताओं ने विरोध नहीं किया है

प्रस्ताव है कि एक संवैधानिक संशोधन की वैधता

इस न्यायालय द्वारा समीक्षा का विषय हो सकता है। अधिवक्ता

महाराष्ट्र के जनरल ने न्यायिक समीक्षा की विशेषता बताई है

अलोकतांत्रिक। तथापि, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों के कारण हमारे संविधान में ऐसा नहीं हो सकता है।

मौलिक अधिकारों को विषय बनाया जाता है, जानबूझकर

अनुच्छेद *21* में नियत प्रक्रिया खंड का अपवर्जन और

अनुच्छेद *141* में पुष्टि कि न्यायाधीश घोषणा करते हैं लेकिन कानून नहीं बनाते हैं। इसमें कोई भी बहुत कठोर संशोधन प्रक्रिया नहीं जोड़ी जा सकती है जो *2/3* के माध्यम से संशोधन को अधिकृत करती है।

बहुमत और अनुसमर्थन की अतिरिक्त आवश्यकता।

XXXXX

XXX

XXX

582. संविधान की मूल संरचना अस्पष्ट नहीं है

अवधारणा और उत्तरदाताओं की ओर से व्यक्त की गई आशंकाएं कि न तो नागरिक और न ही संसद इसे समझ पाएगी, निराधार हैं। अगर

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, की पूरी योजना

संविधान, अनुच्छेद *368* सहित इसके प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है कि यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि निम्नलिखित को बुनियादी माना जा सकता है।

संवैधानिक संरचना के तत्व। *(* ये नहीं हो सकते

सूचीबद्ध लेकिन केवल सचित्र किया जा सकता है*):*

एड्वास बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ *171*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

(1) संविधान की सर्वोच्चता।

(2) सरकार का रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक रूप

और देश की संप्रभुता।

(3) संविधान का धर्मनिरपेक्ष और संघीय चरित्र।

(4) विधानमंडल के बीच शक्ति का सीमांकन,

कार्यपालिका और न्यायपालिका।

(5) द्वारा सुरक्षित व्यक्ति की गरिमा भाग *III* में विभिन्न स्वतंत्रताएँ और बुनियादी अधिकार और

आंशिक रूप से निहित एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का अधिदेश *IV.*

(6) राष्ट्र की एकता और अखंडता "।

इस संबंध में यह भी अनिवार्य है कि हम इसे दर्ज करें

पी. जगमोहन रेड्डी, जे., जिन्होंने इस रूप में देखा

एरः

" 1104 ...... ऐसा कोई संवैधानिक मामला नहीं है जिसमें

किसी न किसी तरह से राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक प्रश्न, और यदि संविधान निर्माताओं के पास है

इस न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है, और जबकि

संविधान के दिल और आत्मा के रूप में, हम नहीं होंगे उस कर्तव्य का निर्वहन करने से रोक दिया गया, केवल इसलिए कि

कानून की वैधता या अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा।

या इसमें अंतर्निहित सामाजिक नीति। इस का मूल दृष्टिकोण न्यायालय हमेशा से रहा है और होना चाहिए कि विधानमंडल

नीति निर्धारित करने की अनन्य शक्ति है और

इसे कानून में परिवर्तित करें, जिसकी संवैधानिकता होनी है

माना जाता है, जब तक कि इसके लिए मजबूत और ठोस कारण न हों

यह मानते हुए कि यह संवैधानिक जनादेश के साथ संघर्ष करता है। में।

न्यायपालिका सर्वोपरि साधन से बंधी होती है, और इसलिए, कोई भी अदालत और कोई भी न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करेगा।

पावर उस उपकरण को नापसंद करता है, और न ही यह *2* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के रूप में कार्य करेगा।

संविधान से ऊपर सर्वोच्च विधायिका। द बोना इन तीनों का विश्वास बुनियादी रहा है।

धारणा, और हालांकि वे सभी त्रुटि के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

इसे तरीके से और तरीके से ठीक किया जा सकता है।

संविधान के तहत निर्धारित और इस तरह के अधीन सीमाएँ जो उपकरण में निहित हो सकती हैं।

एच. आर. खन्ना, जे. की कुछ टिप्पणियाँ भी हैं -

हाथ में मुद्दे के लिए। वही नीचे दिए गए हैंः

" 1529. ...... हालाँकि, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है,

केवल यह तय करने तक सीमित नहीं है कि क्या बनाने में

केंद्रीय या राज्य विधानमंडलों के पास विवादित कानून हैं

विधायी सूचियों के चार कोनों के भीतर कार्य किया उनके लिए निर्धारित; अदालतें भी इस प्रश्न से निपटती हैं

के रूप में क्या कानून और के अनुरूप बनाए गए हैं संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं।

हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक प्रावधान किए हैं

भाग *III* में अधिकार और उन्हें न्यायसंगत बनाया। जब तक

संविधान, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी होनी चाहिए यह देखने के लिए प्रयोग किया जाता है कि संगरोध में रहने वाले लोग खर्च वहन कर सकते हैं

उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। मसौदे से निपटना

अनुच्छेद *25 (*वर्तमान अनुच्छेद *32* के अनुरूप*)*

संविधान*)* जिसके द्वारा स्थानांतरित करने का अधिकार दिया गया है

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय।

डॉ. अम्बेडकर संविधान सभा में बोलते हुए

9 दिसंबर, *1948* को मनाया गयाः

" अगर मुझसे इसमें किसी विशेष लेख का नाम बताने के लिए कहा जाए

सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में संविधान जिसके बिना यह संविधान एक शून्य होगा-*1*

इसे छोड़कर किसी अन्य अनुच्छेद का उल्लेख नहीं किया गया है यह संविधान की आत्मा और हृदय है और मुझे खुशी है कि सदन ने इस बात को महसूस किया है कि

महत्व *"(*संविधान सभा की बहस, खंड

VII, पी। *953) .*

इस प्रकार न्यायिक समीक्षा हमारा एक अभिन्न अंग बन गया है। संवैधानिक प्रणाली और एक शक्ति निहित की गई है

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निर्णय लेने के लिए

विधियों के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता।

हमारा संविधान कानून के शासन को इस अर्थ में प्रस्तुत करता है कि

संविधान और इसके विपरीत कानूनों की सर्वोच्चता

मनमानी करने के लिए। बहिष्करण की शक्ति निहित करना

राज्य विधानमंडल सहित किसी विधानमंडल में न्यायिक समीक्षा,

अनुच्छेद *31*-सी द्वारा अनुध्यात, मेरी राय में,

संविधान की मूल संरचना। इसका दूसरा भाग

अनुच्छेद *31*-सी इस प्रकार अनुमत सीमा से परे जाता है -

अनुच्छेद *368* के तहत संशोधन क्या है।

XXX

XXX

XXX

1533. स्थिति के रूप में यह उभरता है कि यह खुला है

किसी मौजूदा क़ानून की वैधता के संबंध में समीक्षा। यह है। इसी तरह न्यायिक समीक्षा को बाहर करने के लिए उक्त प्राधिकरण के लिए खुला है

किसी कानून की वैधता के संबंध में जिसे अधिनियमित किया जा सकता है

भविष्य में विधायिका द्वारा किसी निर्दिष्ट विषय के संबंध में। ऐसी स्थिति में न्यायिक समीक्षा को निष्कर्ष के लिए बाहर नहीं रखा जाता है

क्या कानून के संबंध में अधिनियमित किया गया है

निर्दिष्ट विषय। उपरोक्त दोनों प्रकार के संवैधानिक

अनुच्छेद *368* के तहत संशोधनों की अनुमति है। क्या है*?*

हालाँकि, अनुमति नहीं है, यह एक तीसरा प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है।

संशोधन, जिसके अनुसार संशोधन प्राधिकारी नहीं केवल एक की वैधता के संबंध में न्यायिक समीक्षा को बाहर करता है

कानून जो भविष्य में विधायिका द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है एक निर्दिष्ट विषय के संबंध में लेकिन न्यायिक भी शामिल नहीं है

यह पता लगाने के लिए समीक्षा कि क्या कानून द्वारा अधिनियमित किया गया है विधायिका उस विषय के संबंध में है जिसके लिए न्यायिक

समीक्षा को हटा दिया गया है।

XXX

XXX

XXX

1537. अब मैं सत्ता से संबंधित अपने निष्कर्षों का सारांश दे सकता हूं।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के रूप में संविधान के अनुच्छेद *368* के तहत संशोधन।

संविधान द्वारा किए गए संशोधन से पहले मौजूद

(चौबीसवाँ संशोधन*)* अधिनियम और साथ ही संविधान *(*चौबीसवाँ संशोधन*)* अधिनियम की वैधता के बारे में,

संविधान *(*पच्चीसवां संशोधन*)* अधिनियम और संविधान *(*उनतीसवां संशोधन*)* अधिनियमः

(i) अनुच्छेद *368* में न केवल प्रक्रिया शामिल है -

संविधान का संशोधन लेकिन यह भी प्रदान करता है

संविधान में संशोधन करने की शक्ति।

((ii) सातवीं अनुसूची की सूची *I* में प्रविष्टि *97*

संविधान इस विषय को शामिल नहीं करता है -

संविधान में संशोधन। *(iii)* अनुच्छेद *13 (2)* में *"*कानून*"* शब्द शामिल नहीं है।

संविधान में संशोधन। इसका संदर्भ है

कानून का सामान्य टुकड़ा। यह भी दिखाई देगा अनुच्छेद के खंड *(*क*)* में निहित परिभाषा

13 (3) इसमें एक अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम शामिल हैं। विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग

भारत का क्षेत्र कानून का बल है।

XXX

XXX

XXX

(vii) अनुच्छेद *368* के तहत संशोधन की शक्ति

निरस्त करने की शक्ति शामिल नहीं है

संविधान और न ही इसमें परिवर्तन करने की शक्ति शामिल है।

संविधान की मूल संरचना या ढांचा।

मूल संरचना के प्रतिधारण के अधीन या

संविधान की रूपरेखा, की शक्ति

संशोधन पूर्ण है और इसमें शामिल है - के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन करने की शक्ति

मौलिक से संबंधित संविधान सहित

अधिकारों के साथ-साथ वे भी जिन्हें संबंधित कहा जा सकता है

आवश्यक विशेषताओं के लिए। मौलिक अधिकार का कोई हिस्सा नहीं द्वारा संशोधन प्रक्रिया से प्रतिरक्षा का दावा कर सकते हैं

सार के रूप में वर्णित किया जा रहा है, या उस के मूल

सही है। संशोधन की शक्ति में शामिल होंगे -

अपने भीतर *175* को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की शक्ति

एस बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

विभिन्न लेख।

XXX

XXX

XXX

(xiv) अनुच्छेद *31*-सी के दूसरे भाग में शामिल हैं -

राष्ट्रीय विघटन का बीज और अमान्य है निम्नलिखित दो आधार हैंः

(1) यह विधायिका को एक कार्टे ब्लैंच देता है

किसी भी कानून को अनुच्छेद *14,19* और *31* का उल्लंघन करने वाला बनाना और

इसे अंतःस्थापित करके हमले से प्रतिरक्षित करें

इसका दूसरा भाग प्रभाव में शक्ति देता है राज्य विधानमंडल सहित विधानमंडल, संशोधन करने के लिए

महत्वपूर्ण मामलों में संविधान।

(2) विधायिका को अंतिम अधिकार दिया गया है।

यह तय करने के लिए कि क्या इसके द्वारा बनाया गया कानून इसके लिए है

अनुच्छेद *31*-ग में उल्लिखित उद्देश्य। की बुराई

अनुच्छेद *31*-सी का दूसरा भाग इस तथ्य में निहित है कि

यदि अधिनियमित कानून उल्लिखित उद्देश्य के लिए नहीं है अनुच्छेद *31*-सी में, द्वारा की गई घोषणा

विधायिका एक पार्टी को यह दिखाने से रोकती है कि

कानून उस उद्देश्य के लिए नहीं है और अदालत को रोकता है

इस सवाल पर कि क्या कानून

अधिनियमित वास्तव में उस उद्देश्य के लिए है। द्वारा बहिष्करण

एक राज्य विधानमंडल सहित विधानमंडल, कि सीमित न्यायिक समीक्षा बुनियादी पर हमला करती है

संविधान की संरचना। इसका दूसरा भाग

अनुच्छेद *31*-सी की अनुमेय सीमा से परे है

अनुच्छेद *368* के तहत संशोधन क्या है।

अनुच्छेद *31*-सी के दूसरे भाग को अलग किया जा सकता है।

अनुच्छेद *31*-ग के शेष भाग से और इसके

अयोग्यता की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी शेष भाग। इसलिए, मैं बंद कर दूंगा

अनुच्छेद *31*-सी में निम्नलिखित शब्द

" और ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें यह घोषणा हो कि यह सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के लिए है।

176

ऐसी नीति को प्रभावी बनाने पर किसी भी अदालत में इस आधार पर सवाल उठाया जाएगा कि वह ऐसा नहीं करती है। ऐसी नीति को प्रभावी बनाना "।

एससीसी *1.* तत्काल निर्णय में, इस न्यायालय ने संविधान की संवैधानिक वैधता की जांच की *(*उनतीस*)* संशोधन*)* अधिनियम, *1975*। संदर्भ के तहत मुद्दे में शामिल थे

अनुच्छेद *329* ए का सम्मिलन *(*और विशेष रूप से, दूसरा

खंड*)*, जिसमें से निकालने का प्रभाव पड़ा

"न्यायिक समीक्षा" की परिधि, एक व्यक्ति के चुनाव की वैधता जो धारण कर रहा था, या तो प्रधानमंत्री का पद या अध्यक्ष का, या नियुक्त/चुने जाने के लिए आया था

प्रधानमंत्री या अध्यक्ष, ऐसे चुनाव के बाद। जहाँ तक

मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, यह होगा

उल्लेख करने के लिए प्रासंगिक है कि आम संसदीय चुनावों में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से अपीलार्थी का चुनाव

1971 का, उच्च न्यायालय द्वारा अलग कर दिया गया था इलाहाबाद *(*इसके बाद उच्च न्यायालय के रूप में संदर्भित*)*, पर

12.6.1975 . अपीलार्थी ने पारित आदेश पर हमला किया था

संशोधन*)* अधिनियम पारित किया गया, जिसमें दो नए लागू किए गए संविधान के अनुच्छेद *71* और *329* ए। द.

अतः उपर्युक्त निर्दिष्ट अपील से उत्पन्न होने वाला विवाद,

वस्तुतः निष्फल हो गया। यह एक प्रति-अपील के माध्यम से था कि संशोधित की संवैधानिक वैधता

प्रावधानों पर हमला किया गया।

(ii) उपरोक्त प्रति-अपील में, प्रत्यर्थी के हाथों यह दावा किया गया था कि "न्यायिक समीक्षा" एक आवश्यक विशेषता थी।

संविधान की "मूल संरचना"। यह दावा "शक्तियों के पृथक्करण" के सिद्धांत के तहत था। नुकीला

प्रत्यर्थी के विद्वान वकील के हाथों प्रस्तुत किया गया था कि चुनाव के मामलों में "न्यायिक समीक्षा" थी

अनिवार्य है। मुद्दा यह था कि "न्यायिक समीक्षा" स्वतंत्र, निष्पक्ष और शुद्ध चुनाव सुनिश्चित करेगी।

इसे मद्रास बार एसोसिएशन *v* बनाने की मांग की गई थी। भारत संघ *177*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

जोर देकर कहा कि इस संदर्भ में *"*न्यायिक समीक्षा*"* की शक्ति

ऊपर उल्लिखित, अमेरिकी संविधान और ऑस्ट्रेलियाई संविधान दोनों के तहत उपलब्ध था। और इसलिए,

भले ही भारतीय संविधान के तहत इस विषय पर कोई स्पष्ट/स्पष्ट प्रावधान नहीं था, क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को गतिविधि के संबंधित क्षेत्रों को निर्धारित किया गया था *(*उन्हें अलग-अलग भागों में विभाजित करके और

अध्याय*)*, *"*न्यायिक समीक्षा*"* का आरोप और दायित्व इसके अंतर्गत आता है

न्यायपालिका की गतिविधि का क्षेत्र। यह दावा करने की कोशिश की गई थी,

कि संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत, सभी न्यायाधिकरण और अदालतें

वे इस न्यायालय की अधिकारिता के प्रति उत्तरदायी हैं। परिणाम यह खींचा जाना चाहा गया था कि यदि अनुच्छेद *329* ए के खंड *4* के तहत

संविधान की *"*न्यायिक समीक्षा*"* की शक्ति को छीन लिया गया था, यह *"*मूल संरचना*"* के विनाश के बराबर होगा।

5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया तत्काल निर्णय इस न्यायालय को इसके नीचे निकाला जा रहा है। ए. एन. रे, सी. जे. की निम्नलिखित टिप्पणियों का सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ दिया जा सकता हैः

केशवानंद भारती के बहुमत के दृष्टिकोण को चुनौती दें मामला, *(1973) 4* एस. सी. सी. *225*। की दलीलें

उत्तरदाता ये हैंः पहला, अनुच्छेद *368* के तहत केवल सामान्य राज्य के अंगों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत और बुनियादी

सिद्धांत निर्धारित किए जा सकते हैं। का एक संशोधन

संविधान इस संबंध में किसी भी निर्णय पर विचार नहीं करता है।

विशुद्ध रूप से न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जाए जो शामिल नहीं है अनुच्छेद *368* द्वारा प्रदत्त घटक शक्ति में।

XXX

XXX

XXX

20. पाँचवाँ, खंड *(4)* न केवल न्यायिक समीक्षा को नष्ट करता है बल्कि

शक्ति का पृथक्करण भी। उच्च न्यायालय का आदेश

चुनाव को अमान्य घोषित करना वैध घोषित किया जाता है। फैसले को रद्द करना राजनीतिक न्याय से इनकार है *3* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

जो संविधान की मूल संरचना है।

XXX

XXX

XXX

या तो संबंधित कानून के तहत आकर्षित किया जाए इस न्यायालय या अनुच्छेद *136* में अपील की जा सकती है। के तहत

अनुच्छेद *329 (*बी*)* में विचारित कानून को शक्ति निहित हो सकती है।

स्वयं सदन में चुनाव याचिकाओं पर विचार करने के लिए जो

एक विशेष समिति की रिपोर्ट। ऐसे मामलों में न्यायिक संशोधन को शामिल किए बिना समीक्षा को समाप्त किया जा सकता है

संविधान। ...... यदि न्यायिक समीक्षा को न्यायालय से बाहर रखा जाता है

यह निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं है कि समानता के सिद्धांत

उल्लंघन किया गया है।

XXX

XXX

XXX

153. प्रत्यर्थी की दलीलें कि

बुनियादी विशेषताओं या बुनियादी संरचना या बुनियादी का सिद्धांत फ्रेमवर्क। दूसरा, केशवानंद में बहुमत का दृष्टिकोण

भारती का मामला *(*ऊपर*)* यह है कि उनतीसवां संशोधन

जिसने दोनों कानूनों को नौवीं अनुसूची और अनुच्छेद में रखा

31 - बी दोनों के आधार पर चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है

बुनियादी विशेषताओं, बुनियादी संरचना को नुकसान या विनाश

या बुनियादी ढांचे या उल्लंघन के आधार पर

मौलिक अधिकार "।

एच. आर. खन्ना, जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचार अब किए जा रहे हैं।

नीचे लिखा हैः

"175. प्रस्ताव है कि संशोधन की शक्ति के तहत अनुच्छेद 368 संसद को बुनियादी आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन v को बदलने में सक्षम नहीं बनाता है।

भारत का संघ 179

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संविधान की रूपरेखा निर्धारित की गई थी इस न्यायालय द्वारा उसके मामले में 7 से 6 के बहुमत से

पवित्रता केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य, (1973)

4 एससीसी 225। अन्य कारणों के अलावा जो दिए गए थे

विद्वान न्यायाधीशों के कुछ निर्णयों में जो

बहुमत का गठन किया, बहुमत से निपटा गया "संशोधन" शब्द का अर्थ। यह माना गया कि

अनुच्छेद 368 में "संविधान का संशोधन" शब्द हो सकते हैं

बुनियादी को नष्ट करने या निरस्त करने का प्रभाव नहीं है संविधान की संरचना। हम में से कुछ जो पार्टियाँ थे

उस मामले में एक अलग दृष्टिकोण लिया और आया

निष्कर्ष है कि शब्द "संविधान का संशोधन"

अनुच्छेद 368 में किसी भी सीमा को स्वीकार नहीं किया गया था। हम में से जो लोग

जो केशवानंद भारती के मामले में अल्पमत में थे

(उपरि) अभी भी वही दृष्टिकोण रख सकता है जो दिया गया था

उस मामले में अभिव्यक्ति। वर्तमान के उद्देश्य के लिए

मामले में, हमें कानून के अनुसार आगे बढ़ना होगा जैसा कि उस मामले में बहुमत द्वारा निर्धारित किया गया था।

176. इस सवाल से निपटने से पहले कि क्या

विवादित की संवैधानिक वैधता से संबंधित है संशोधन।

XXX

XXX

210. यह संवैधानिक के समर्थन में तर्क दिया गया है खंड *(4)* की वैधता जो इस संशोधन के परिणामस्वरूप है।

एक चुनाव की वैधता बरकरार रखी गई है। तब से

संविधान की मूल संरचना के अनुसार

प्रस्तुत करना, वही बना रहता है, खंड *(4)* नहीं कर सकता है

संवैधानिक का एक अस्वीकार्य टुकड़ा कहा जाए

संशोधन।

इस तर्क में एक प्रतीत होने वाली संभाव्यता है*)* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

आर

इसके बारे में, लेकिन एक गहरा प्रतिबिंब दिखाएगा कि यह है

एक बुनियादी भ्रांति से दूषित। कानून आम तौर पर एक नियम को संदर्भित करता है।

या मानक जो सामान्य अनुप्रयोग का हो। यह सभी पर लागू हो सकता है।

व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या यहाँ तक कि एक के व्यक्ति

विशेष वर्णन। कानून सार निर्धारित करता है

तय किया। हालाँकि, कानून वह नहीं है जिसे ब्लैकस्टोन "ए" कहते हैं। वाक्य "। रोस्को पाउंड के अनुसार, कानून के रूप में

कानूनों से अलग, आधिकारिक प्रणाली है

न्यायिक आधार या मार्गदर्शन के लिए सामग्री और

में मान्यता प्राप्त या स्थापित प्रशासनिक कार्रवाई

राजनीतिक रूप से संगठित समाज *(*पी देखें। *106* , न्यायशास्त्र,

खण्ड. *III)*। कानून निर्णय के समान नहीं है। कानून तय करता है

एक जबरदस्त शक्ति के साथ अमूर्त शब्दों में मानक और

मानदंड का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा, जबकि

निर्णय द्वारा किए गए निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है

किसी मामले के ठोस तथ्यों पर कानून का अनुप्रयोग।

इसकी शक्तियों और विधियों और सिद्धांतों का वितरण उसका संचालन। भारत का संविधान इतना विस्तृत है कि

कुछ मामले जो एक संक्षिप्त संविधान में इस तरह के हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों द्वारा निपटा जाता है

हमारे विभिन्न लेखों का विषय-वस्तु

संविधान। हालाँकि, एक संवैधानिक कानून में, के रूप में है

कानून के विचार में ही, सामान्यता का कुछ तत्व है

या सामान्य अनुप्रयोग। यह अपने साथ एक अवधारणा भी रखता है भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्थितियों के लिए इसकी प्रयोज्यता

उस संदर्भ में। यदि कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है संविधान और संशोधन मामलों से संबंधित हैं

जो सामान्य रूप से स्वीकृत संवैधानिक कानून का गठन करता है।

अर्थ, न्यायालय वैधता के प्रश्न का निर्णय करते समय

संशोधन को देखते हुए यह पता लगाना होगा कि

केशवानंद भारती के मामले में बहुमत की राय *(ऊपर),*

कि क्या संशोधन मूल संरचना को प्रभावित करता है

संविधान से। संविधान संशोधन

खंड *(4)* में निहित है जिसके साथ हम मद्रास बार एसोसिएशन *v* में संबंधित हैं।

भारत का संघ *181*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया था और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील इस मामले में लंबित थी अदालत। हमारे प्रश्न के बावजूद, हमें किसी भी संविधान के समान संशोधन के किसी भी उदाहरण के लिए संदर्भित नहीं किया गया था

संसार को। विवादित संविधान की विशिष्टता

हालाँकि, संशोधन से इसकी वैधता प्रभावित नहीं होगी। अगर

घटक प्राधिकारी ने अपने विवेक से वैधता को चुना है

विषय के रूप में एक विवादित चुनाव का-एक संवैधानिक संशोधन, यह न्यायालय उस विवेक के पीछे नहीं जा सकता है। यह न्यायालय केवल संशोधन की वैधता से संबंधित है। मुझे इस सवाल में जाने की जरूरत नहीं है कि

क्या ऐसी कोई बात है, सामान्य अवधारणा को देखते हुए

संवैधानिक कानून, सख्ती से एक का विषय हो सकता है

संवैधानिक संशोधन। इसके लिए मैं

मामला यह मानता है कि ऐसा मामला वैध रूप से विषय हो सकता है संवैधानिक संशोधन का विषय। सवाल यह है कि

तय किया गया है कि यदि का आक्षेपित संशोधन संविधान उस सिद्धांत का उल्लंघन करता है जो मूल सिद्धांत का हिस्सा है।

संविधान की संरचना, क्या यह एक से प्रतिरक्षा का आनंद ले सकता है

इसकी वैधता पर हमला इस तथ्य के कारण कि भविष्य के लिए,

संविधान की मूल संरचना अप्रभावित बनी हुई है।

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर, मेरी राय में, होना चाहिए। नकारात्मक में रहें। ऐसे मामले में यह देखना होगा कि क्या संशोधन इसके विपरीत है या नहीं।

एक अनिवार्य नियम या अभिधारणा जो एक अभिन्न अंग है

संविधान की मूल संरचना। यदि ऐसा है तो

अस्वीकार्य संशोधन और यह नहीं करेगा

मामलों में। यदि संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करने वाले संशोधन की अनुमति नहीं है, तो यह अधिग्रहण नहीं करेगा। केवल एक मामले से संबंधित होने की वैधता। स्वीकार करने के लिए

की वैधता के समर्थन में तर्क आगे बढ़ाया गया

संशोधन यह अभिनिर्धारित करने के समान होगा कि भले ही मूल संरचना को बदलने की अनुमति नहीं है *2*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

संविधान का, जब भी संबंधित प्राधिकारी

इस तरह का संशोधन करना उचित समझता है, यह कर सकता है

इसे एक मामले तक सीमित करके संशोधन करें। क्या प्रतिबंधित है इसके सीमित होने के कारण इसकी अनुमति नहीं हो सकती है।

एक बात पर "।

के. के. मैथ्यू, जे. के विचार इस प्रकार थेः

"318. मानव समाज की प्रमुख समस्या संयोजन है।

इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के व्यावहारिक साधनों की खोज करने और अवसर खोजने में कठिनाई रही है इन साधनों को मानव मामलों की निरंतर बदलती उलझनों में लागू करने के लिए। सदियों से मनुष्य के प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस महान समस्या का समाधान खोजने में खर्च किया गया है। अत्याचार के विपरीत कानून का एक क्षेत्र

शक्ति का, केवल अलग करके प्राप्त किया जा सकता है उचित रूप से सरकार की कई शक्तियाँ। अगर

कानून निर्माताओं को कानून और न्याय के निरंतर प्रशासक और वितरक भी होना चाहिए, तब लोग होंगे

अन्याय के मामले में एक उपाय के बिना छोड़ दिया गया क्योंकि इस तरह की सर्वोच्चता के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। और, में

रहस्य के लिए राजनीतिक दार्शनिकों की यह सदियों पुरानी खोज

ठोस सरकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ संयुक्त, यह

मोंटेस्क्यू ने पहली बार प्रकाश देखा था। वह पहले थे।

राजनीतिक दार्शनिकों में से जिन्होंने न्यायिक शक्ति को कार्यपालिका से अलग करने की आवश्यकता देखी और

सरकार की विधायी शाखाएँ। मोंटेस्क्यू सरकार के तीन कार्यों की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो तीन अंगों द्वारा किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक अन्य के खिलाफ होता है। उन्होंने महसूस किया कि कुशल संचालन

सरकार में कुछ हद तक अतिव्यापीता शामिल थी और

कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के लिए प्रत्येक अंग की आवश्यकता होती है

द्वारा अधिकार की बहुत अधिक वृद्धि को बाधित करना

अन्य दो शक्तियाँ। जैसा कि होल्डस्वर्थ कहते हैं, मोंटेस्क्यू

दुनिया को आश्वस्त किया कि उन्होंने एक नए मद्रास बार एसोसिएशन *v* की खोज की थी।

भारत संघ *183.*

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

संवैधानिक सिद्धांत जो सार्वभौमिक रूप से मान्य था। द.

सरकारी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत एक नहीं है

केवल सैद्धांतिक, दार्शनिक अवधारणा। यह एक व्यावहारिक है,

कार्य-एक-दिवसीय सिद्धांत। सरकार का तीन भागों में विभाजन

शाखाओं का मतलब यह नहीं है, जैसा कि इसके आलोचक हमें सोचने के लिए कहते हैं,

तीन जलरोधक डिब्बे। अतः विधायी

कार्यकारी अधिकारियों या न्यायाधीशों, कार्यपालिका का महाभियोग

विधान पर वीटो, प्रशासनिक या न्यायिक समीक्षा

विधायी कार्यों को आंशिक अपवाद माना जाता है जो

स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। *(* आम तौर पर देखिए: "का सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण और इसका वर्तमान महत्व

टी. वेंडरबिल्ट।*)*

XXX

XXX

XXX

343. मुझे लगता है कि खंड *(4)* उन कारणों से खराब है जो मेरे पास हैं।

पहले से ही संक्षेपित। अनुच्छेद *329*-ए के खंड *(1)* से *(3)*

अलग किए जा सकते हैं लेकिन मैं उनकी वैधता पर कोई राय व्यक्त नहीं करता हूं

इस मामले को तय करने के लिए यह आवश्यक नहीं है।

XXX

XXX

361. इसलिए मेरा मानना है कि ये अधिनियम उत्तरदायी नहीं हैं -

वकील द्वारा तर्क दिए गए किसी भी आधार पर चुनौती दी गई।

57. जहाँ तक निर्णयों की श्रृंखला में तीसरे निर्णय की बात है

संबंधित है, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड को संदर्भ दिया जा सकता है।

ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। *, (1980) 2* एस. सी. सी. *591,* साथ ही,

मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। , *(1980) 3* एससीसी *625*। जहाँ तक उपरोक्त दो निर्णयों में से पूर्व का संबंध है - संबंधित, वही नुकीले विवाद को चित्रित करता है

इस न्यायालय के *5* न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा। इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया, जो संवैधानिक वैधता से संबंधित था

संविधान *(*बयालीसवां संशोधन*)* अधिनियम, *1976* और अधिक विशेष रूप से, इसकी धारा *4* और *55*, जिसके द्वारा अनुच्छेद *31* सी

और संविधान की धारा *368* में संशोधन किया गया। बहुमत का विचार *4* के अनुपात में व्यक्त किया गया थाः *1* , पी. एन. भगवती, जे.

वह तब*)* असहमति व्यक्त कर रहे थे। बहुमत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संविधान की धारा *4 (*चालीस सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

184

दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *1976* संशोधन से परे था। संसद की शक्ति और शून्य थी, क्योंकि इसका प्रभाव था

संविधान की बुनियादी या आवश्यक विशेषताओं का उल्लंघन करना और

संविधान की *"*मूल संरचना*"* को कुल मिलाकर नष्ट करना। किसी भी कानून को चुनौती देने का बहिष्कार, इस आधार पर भी कि

के साथ असंगत था, या ले जाया गया था, या किसी को संक्षिप्त किया था

संविधान के अनुच्छेद *14* या *19* द्वारा प्रदत्त अधिकारों का।

इसी तरह, संविधान की धारा *55 (42)*

संशोधन*)* अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि यह संसद की संशोधन शक्ति से परे था।

तत्काल निर्णय में दर्ज प्रासंगिक टिप्पणियाँ हाथ में मुद्दे से संबंधित, यहाँ नीचे निकाले जा रहे हैं।

वाई. वी. चंद्रचूड़, सीजे, ए. सी. गुप्ता द्वारा व्यक्त की गई राय,

एन. एल. उन्तवालिया और पी. एस. कैलासम, जे. जे. हाथ में विषय पर,

इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ाः

"68. हमें उल्लेख करना चाहिए, जो शायद पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है,

कि अनुच्छेद *31*-सी नीति को प्रभावी बनाने वाले कानूनों की बात करता है।

राज्य का "", सभी या किसी भी सिद्धांत को सुरक्षित करने की दिशा में

भाग *IV* में निर्दिष्ट किया गया है। चीजों की प्रकृति में अदालत के लिए यह निर्धारित करना मुश्किल है कि क्या कोई विशेष कानून देता है किसी विशेष नीति का प्रभाव। क्या कोई कानून राज्य की नीति को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त है

एक निर्देशक सिद्धांत को सुरक्षित करना हमेशा एक बहस का विषय होता है।

सवाल और अदालतें कानून को केवल इसलिए अमान्य नहीं मान सकतीं क्योंकि उनकी राय में कानून पर्याप्त नहीं है। एक निश्चित नीति को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में, हालांकि

अनुच्छेद *31*-सी का स्पष्ट इरादा सभी न्यायिक समीक्षा को बंद करना है, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर का तर्क

आम तौर पर अदालतों की अनुमति की तुलना में दोगुनी या चौड़ी व्यापक न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। वह हो जाए।

याद रखें कि प्रश्न की जांच करने की शक्ति

क्या दोनों के बीच कोई प्रत्यक्ष और उचित संबंध है कानून के प्रावधान और निर्देश सिद्धांत अदालतों को निर्णय में बैठने की शक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं।

स्वयं राज्य की नीति। उच्चतम स्तर पर, न्यायालय कर सकते हैं,

अनुच्छेद *31*-सी के तहत, आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v* की पहचान के बारे में खुद को संतुष्ट करें।

भारत संघ *185*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

कानून इस अर्थ में कि क्या यह प्रत्यक्ष और उचित है

एक निर्देशक सिद्धांत के साथ संबंध। यदि न्यायालय संतुष्ट है

इस तरह की सांठगांठ के अस्तित्व के लिए, अपरिहार्य परिणाम

अनुच्छेद *31*-सी द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान का पालन करना चाहिए। वास्तव में, यदि

यह एक ऐसा विषय है जिस पर केशवानंद के सभी *13* न्यायाधीश भारती, *(1973) 4* एस. सी. सी. *225* पर सहमति बनी, यह हैः कि

न्यायिक समीक्षा के लिए एकमात्र प्रश्न खुला है

असंशोधित अनुच्छेद *31*-सी यह था कि क्या कोई प्रत्यक्ष और

अनुच्छेद *39 (* बी *)* और *(* सी *)* के प्रावधान उचित हैं स्पष्ट रूप से सांठगांठ के बारे में और कानून के बारे में नहीं। यह.

इसलिए इस तर्क को स्वीकार करना असंभव है कि यह है

इस तरह की जांच करने के लिए अदालतों के लिए खुला

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए। यह प्रयास

इसलिए अनुच्छेद *31*-सी को एक लोकतांत्रिक संगठन में शामिल करना।

जिसके तहत एक व्यापक न्यायिक समीक्षा की जाएगी अनुमेय विफल होना चाहिए।

XXX

XXX

XXX

73. अंततः विद्वान महान्यायवादी ने आग्रह किया कि

यदि हम अनुच्छेद *31*-सी की वैधता को चुनौती देते हैं।

अनुच्छेद *19* के खंड *(2)* से *(6)* की वैधता गंभीर होगी।

संकटग्रस्त क्योंकि वे खंड भी तब उत्तरदायी होंगे

द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निरस्त करने के रूप में निरस्त किया जाना अनुच्छेद *19 (1)* जो एक अनिवार्य विशेषता है

केवल तभी अधिरोपित किया जाता है जब वे उचित हों और फिर, वे विषयों के एक निर्दिष्ट वर्ग के हित में थोपा जा सकता है

केवल। यह अदालतों को तय करना है कि क्या प्रतिबंध हैं उचित और क्या वे हित में हैं

विशेष विषय। अन्य बुनियादी विषमताओं के अलावा, अनुच्छेद *31*-सी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को हटा देता है

एक हद तक जो तुलना की झलक को भी नष्ट कर देता है

इसके प्रावधानों और इसके खंड *(2)* से *(6)* के प्रावधानों के बीच

अनुच्छेद *19.* मानव की सरलता, भले ही असीम हो, फिर भी एक ऐसी प्रणाली तैयार नहीं की जिसके द्वारा लोगों की स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

अदालतों के हस्तक्षेप के अलावा संरक्षित किया जा सकता है

कानून से।

XXX

XXX

XXX

75. ये आदेश के लिए हमारे कारण हैं *(*मिनर्वा देखें*)*

मिल्स लिमिटेड बनाम. भारत संघ, *(1980) 2* एस. सी. सी. *591)*

हम *9* मई, *1980* को निम्नलिखित प्रभाव से पारित हुएः *(* एससीसी

पीपी। *592-593* , पैरा *1* और *2)*

"संविधान की धारा *4 (42)* संशोधन*)* अधिनियम की संशोधन शक्ति से परे है

संसद और शून्य है क्योंकि यह नुकसान पहुँचाता है

संविधान की बुनियादी या आवश्यक विशेषताएँ और

कुल अपवर्जन द्वारा अपनी मूल संरचना को नष्ट कर देता है इस आधार पर किसी भी कानून को चुनौती दें कि यह है

के साथ असंगत, या दूर ले जाता है या घटाता है

संविधान के अनुच्छेद *14* या अनुच्छेद *19* द्वारा प्रदत्त अधिकार

संविधान, यदि कानून को प्रभावी बनाने के लिए है

सभी या किसी को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति संविधान के भाग *IV* में निर्धारित सिद्धांत।

संविधान की धारा *55 (42)*

संशोधन*)* अधिनियम की संशोधन शक्ति से परे है संसद और शून्य है क्योंकि यह सभी को हटा देता है

संसद की संशोधन करने की शक्ति पर सीमाएँ

संविधान और इसे शक्ति प्रदान करता है

संविधान में संशोधन करें ताकि नुकसान हो या नष्ट हो इसकी मूल या आवश्यक विशेषताएँ या इसकी मूल संरचना।

इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक दृष्टिकोण की सराहना करने के लिए,

पी. एन. की निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दिया जा सकता है।

इग्वाती, जे। *;*

योजना, और मैंने इसे पूर्ववर्ती में इंगित किया है अनुच्छेद, कि राज्य का प्रत्येक अंग, प्रत्येक प्राधिकरण

संविधान के तहत, अपनी शक्ति प्राप्त करता है

संविधान और ऐसी शक्ति की सीमाओं के भीतर कार्य करना है।

एड्वास बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ *187*

[जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

तय करें कि प्रदत्त शक्ति की सीमाएँ क्या हैं राज्य का प्रत्येक अंग या साधन और क्या ऐसा है

सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है या उन्हें पार किया जाता है। अब राज्य में तीन मुख्य विभाग हैं जिनमें से

सरकार विभाजित है; कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमारे संविधान के तहत हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं है, लेकिन एक व्यापक सीमांकन है, हालांकि, इसे ध्यान में रखते हुए

सरकारी कार्यों की जटिल प्रकृति के लिए, कुछ हद तक अतिव्यापी होना अपरिहार्य है। इसका कारण यह है

शक्तियों का व्यापक पृथक्करण यह है कि "किसी एक अंग में शक्तियों की एकाग्रता" के शब्दों को उद्धृत करने के लिए

चंद्रचूड़, जे., (जैसा कि वे उस समय थे) इंदिरा गांधी के मामले में,

लोकतांत्रिक सरकार जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं "। उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला लें जहाँ कार्यपालक प्रभारी हो। प्रशासन एक नागरिक के पूर्वाग्रह के लिए कार्य करता है और एक सवाल उठता है कि कार्यपालिका की शक्तियां क्या हैं

और क्या कार्यपालिका ने अपनी शक्तियों के दायरे में काम किया है। इस तरह का सवाल स्पष्ट रूप से इन पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

कार्यकारी निर्णय लेने के लिए और दो बहुत अच्छे कारणों से। सबसे पहले,

प्रश्न का निर्णय इस पर निर्भर करेगा कि

संविधान और कानूनों की व्याख्या और यह

यह पहले से ही न्यायपालिका द्वारा तय किया जाने वाला एक उपयुक्त मामला होगा, क्योंकि यह केवल न्यायपालिका ही होगी

इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले और दूसरी बात,

नागरिकों को संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई

यह भ्रमपूर्ण हो जाएगा, अगर इसे कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाए

अपनी कार्रवाई की वैधता का निर्धारण करें। इसलिए भी यदि विधायिका कोई कानून बनाती है और कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या कानून बनाने में विधायिका ने अपनी विधायी क्षमता के क्षेत्र से बाहर काम किया है या कानून का उल्लंघन है मौलिक अधिकार या इसके किसी अन्य प्रावधान

संविधान, इसका संकल्प, उन्हीं कारणों से नहीं हो सकता है, विधायिका के निर्धारण पर छोड़ दिया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

इसलिए संविधान ने इन विवादों को हल करने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र बनाया है और यह स्वतंत्र तंत्र न्यायपालिका है जो इसके साथ निहित है

कार्यकारी कार्रवाई की वैधता और पारित विधान की वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति

विधायिका। यह न्यायपालिका का गंभीर कर्तव्य है

राज्य के विभिन्न अंगों को बनाए रखने के लिए संविधान

संविधान द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति। यह न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की जाती है -

संविधान के वर्तमान अनुच्छेद *32* के अनुरूप अनुच्छेद *25* का मसौदा डॉ. अम्बेडकर, हमारे संविधान के प्रमुख वास्तुकार

संविधान सभा में कहा गया है कि *9* दिसंबर, *1948:*

"अगर मुझसे इस संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में नामित करने के लिए कहा जाए जिसके बिना यह संविधान अमान्य हो जाएगा -

यह संविधान की आत्मा और हृदय है और मुझे खुशी है कि सदन ने इसे महसूस किया है इसका महत्व। *(* सीएडी, वॉल्यूम। *7, p.953) "*

यह हमारे संविधान का एक प्रमुख सिद्धांत है कि कोई भी नहीं कितना भी ऊँचा और कोई भी अधिकार कितना भी ऊँचा क्यों न हो सकता है

के तहत अपनी शक्ति का एकमात्र न्यायाधीश होने का दावा संविधान या क्या इसकी कार्रवाई की सीमा के भीतर है

संविधान द्वारा निर्धारित ऐसी शक्ति। न्यायपालिका है

संविधान के दुभाषिया और न्यायपालिका को यह निर्धारित करने का नाजुक कार्य सौंपा गया है कि शक्ति क्या है

सीमित, और यदि ऐसा है, तो सीमाएँ क्या हैं और क्या कोई कार्रवाई है उस शाखा की सीमा ऐसी सीमाओं का उल्लंघन करती है। यह न्यायपालिका के लिए है

संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और संवैधानिक सीमाओं को लागू करना। यही कानून के शासन का सार है, जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ "शक्तियों के प्रयोग"की आवश्यकता होती है।

सरकार द्वारा चाहे वह विधायिका हो या ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

कार्यपालक या कोई अन्य प्राधिकारी, द्वारा सशर्त संविधान और कानून "। न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारी संवैधानिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और इसके बिना कानून की सरकार और कानून का शासन नहीं होगा

एक चिढ़ाने वाला भ्रम और एक वादा बन जाएगा

अवास्तविक। मेरा विचार है कि अगर हमारी एक विशेषता है

संविधान जो किसी भी अन्य संविधान से अधिक बुनियादी है और

लोकतंत्र और शासन के रखरखाव के लिए मौलिक

कानून की, यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और यह है

निर्विवाद रूप से, मेरे विचार से, मूल संरचना का हिस्सा

संविधान। बेशक, जब मैं यह कहता हूं तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए

यह सुझाव देने के लिए लिया गया कि प्रभावी वैकल्पिक संस्थागत

न्यायिक समीक्षा के लिए तंत्र या व्यवस्था नहीं हो सकती है

संसद द्वारा किया जाता है। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है

और इसे मूल को प्रभावित किए बिना निरस्त नहीं किया जा सकता है।

संविधान की संरचना। यदि संवैधानिक रूप से

संशोधन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को हटा दिया जाता है और यह प्रावधान किया जाता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, भले ही वह विधायी क्षमता से बाहर हो।

विधायिका का या किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला, यह संविधान के विध्वंस से कम नहीं होगा।

क्योंकि यह वितरण का मजाक बनाएगा

संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियाँ और

मौलिक अधिकारों को अर्थहीन और व्यर्थ बना दें। तो। यदि कोई संवैधानिक संशोधन किया जाता है जिसमें

किसी भी आधार पर पूछताछ के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही ऐसा संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन है और,

इसलिए, संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर।

यह संसद को एकमात्र न्यायाधीश बनाएगा

इसने जो किया है उसकी संवैधानिक वैधता और वह होगा, प्रभाव और सार में, पर सीमा को रद्द करें

संसद की शक्ति में संशोधन करना और मूल को प्रभावित करना

संविधान की संरचना।

इसलिए निष्कर्ष *0* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. होना चाहिए।

अनिवार्य रूप से अनुच्छेद *368* के खंड *(4)* का पालन करें

असंवैधानिक और संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुँचाने के रूप में अमान्य। *88.* यह हमें अनुच्छेद *368* के खंड *(5)* पर ले जाता है। यह खंड "शंकाओं को दूर करने के लिए" शब्दों के साथ शुरू होता है और

यह घोषणा करने के लिए आगे बढ़ता है कि कोई सीमा नहीं होगी

संसद की संशोधन शक्ति पर जो कुछ भी हो

अनुच्छेद *368*। इसका अर्थ समझना मुश्किल है

प्रारंभिक शब्द "संदेह को दूर करने के लिए" क्योंकि

केशवानंद भारती मामले में बहुमत निर्णय *(ऊपर)*

स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया और इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा गया कि संविधान की मूल संरचना संसद और इंदिरा गांधी की संशोधनकारी शक्ति की क्षमता से बाहर थी मामला *(ऊपर)*, सभी न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सिद्धांत को स्वीकार किया

एक सिद्धांत के रूप में मूल संरचना की वैधता जिसके द्वारा

उनके समक्ष आक्षेपित संशोधन, अर्थात् अनुच्छेद *329*-ए *(4)* पर निर्णय लिया जाना था। इसलिए, निर्णयों के बाद

संसद की शक्ति सीमित थी और यह संविधान की मूल संरचना को बदलने के लिए संसद के लिए सक्षम नहीं थी। और खंड *(5)* उस संदेह को दूर नहीं कर सका जो नहीं था

मौजूद है। खंड *(5)* वास्तव में क्या करना चाहता था, वह था हटाने का प्रयास।

संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा और

इसे सीमित शक्ति से असीमित शक्ति में परिवर्तित करें। यह

स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से एक व्यर्थ अभ्यास था

संसद। मुझे यह समझ में नहीं आता कि कैसे संसद, जिसके पास संशोधन की केवल सीमित शक्ति है और जो संविधान को बदल नहीं सकती है। संविधान की बुनियादी संरचना अपनी शक्ति का विस्तार कर सकती है।

संशोधन का ताकि स्वयं को शक्ति प्रदान की जा सके

संविधान को निरस्त या निरस्त करना या इसकी मूल संरचना को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना। यह स्पष्ट रूप से अधिक होगा।

संसद के पास सीमित संशोधन शक्ति।

संविधान ने केवल एक सीमित संशोधन प्रदान किया है।

संसद को शक्ति ताकि वह नुकसान या विनाश न कर सके

संविधान और संसद की मूल संरचना आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *191*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

उस सीमित संशोधन शक्ति का प्रयोग करके उस शक्ति को एक पूर्ण और असीमित शक्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा है

संसद को सीमा का विस्तार करने की अनुमति थी

संशोधन की पूर्ण शक्ति में इसे प्रदान की गई शक्ति को संशोधित करना, तो इसे रखना अर्थहीन था

संशोधन का प्रयोग करके सीमा से छुटकारा पाया जा सकता है बहुत शक्ति और इसे एक पूर्ण शक्ति में परिवर्तित करें। खंड

(5) अनुच्छेद *368* जो पर सीमा को हटाने की मांग की

अतः इसे निरपेक्ष बनाकर संसद की संशोधन शक्ति को संशोधन शक्ति से बाहर माना जाना चाहिए।

संसद से। एक और आधार भी है जिस पर

इस खंड की वैधता पर सफलतापूर्वक हमला किया जा सकता है। यह

खंड एक नियंत्रित संविधान को एक में बदलने का प्रयास करता है

पर सीमा को हटाकर अनियंत्रित

संसद की शक्ति में संशोधन करना, जैसा कि बताया गया है ऊपर, अपने आप में संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है और

इसलिए यह मूल संरचना का उल्लंघन है। मैं उस में परिस्थितियों के अनुसार अनुच्छेद *368* का खंड *(5)*

असंवैधानिक और अमान्य "।

58. अब *7* न्यायाधीशों की पीठ, अर्थात् एस. पी. गुप्ता यूनियन ऑफ इंडिया, *1981 (*सप*.)* द्वारा दिए गए न्यायालय के एक अन्य निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। एस. सी. सी *87.* पी. एन. भगवती, जे. तब*)* निम्नलिखित रूप में राय दी गई थीः

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा

27. याचिकाकर्ताओं के लोकस स्टैंड के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति का निपटारा करने के बाद, हम अब आगे बढ़ सकते हैं निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर विचार करें

ये रिट याचिकाएँ। सवाल बड़े हैं।

के सिद्धांत को प्रभावित करने वाला संवैधानिक महत्व

न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो एक बुनियादी विशेषता है

इसलिए संविधान और हम कुछ प्रारंभिक टिप्पणियों को उजागर करके चर्चा शुरू करना पसंद करेंगे।

किसी देश में न्यायपालिका का वास्तविक कार्य क्या होना चाहिए *2* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

भारत की तरह जो सामाजिक न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है

लोकतंत्र और कानून के शासन के झंडे के साथ,

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक जीवित विश्वास है जिसे इसके अपने निहितार्थ प्राप्त करने चाहिए।

संवैधानिक चार्टर से प्रेरणा और इसके

संवैधानिक मूल्यों से पोषण और पोषण। प्रत्येक न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक है कि वह लगातार और

लगातार कि हमारा संविधान गैर-संरेखित नहीं है

राष्ट्रीय चार्टर। यह सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज है जो

सहित प्रत्येक साधन पर एक दायित्व डालता है

न्यायपालिका, जो राज्य की एक अलग लेकिन समान शाखा है,

पूर्व की स्थिति को एक नई मानव व्यवस्था में बदलना

जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगी और समानता होगी -

सभी के लिए स्थिति और अवसर। ...... अब न्यायिक कार्य के लिए यह दृष्टिकोण एक स्थिर और स्थिर कार्य के लिए ठीक हो सकता है।

समाज के लिए नहीं, लेकिन लिंग के आग्रह के साथ स्पंदित होने वाले समाज के लिए नहीं

न्याय, श्रमिक न्याय, अल्पसंख्यक न्याय, दलित न्याय और

समान न्याय, दीर्घकालिक असमानताओं के बीच। कहाँ का प्रतियोगिता उन लोगों के बीच होती है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से सक्षम हैं।

असमान, न्यायिक प्रक्रिया विनाशकारी साबित हो सकती है

सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण, यदि न्यायाधीश एक

केवल निष्क्रिय या नकारात्मक भूमिका निभाता है और एक को नहीं अपनाता है

सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण। न्यायपालिका ऐसा नहीं कर सकती। केवल एक दर्शक या दर्शक बने रहें लेकिन यह होना चाहिए

न्यायिक प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार जो एक सक्रिय लक्ष्य के माध्यम से सामाजिक न्याय की सेवा में कानून का उपयोग करने के लिए तैयार हो उन्मुख दृष्टिकोण। लेकिन यह तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि हमारे पास न्यायिक कैडर नहीं हैं जो संविधान की लड़ाई की आस्था को साझा करते हैं और जो संवैधानिक नियमों से ओत-प्रोत हैं।

मूल्य। संविधान के सामाजिक दर्शन के अनुरूप न्यायपालिका की आवश्यकता कहीं भी नहीं रही है

न्यायमूर्ति कृष्ण लायर के शब्दों की तुलना में बेहतर जोर दिया गया, जिसे हम उद्धृत करते हैं:

"न्यायाधीशों की नियुक्ति एक गंभीर प्रक्रिया है।

जहाँ न्यायिक विशेषज्ञता, कानूनी शिक्षा, जीवन का ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *193*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

वर्ग हितों, निजी पूर्वाग्रहों द्वारा दबाव, सरकारी धमकियाँ और निन्दाएँ, पार्टी की वफादारी और विपरीत आर्थिक और राजनीतिक

घोषणाओं में प्रस्तुत की जाने वाली विचारधाराएँ।

(मुख्यधारा, *22* नवंबर, *1980) "*

कृष्ण लायर अपनी अनूठी शैली में आगे कहते हैं:

"न्यायमूर्ति कार्डोजो ने राष्ट्रपति थियोडोर का हवाला दिया

न्यायाधीशों के सामाजिक दर्शन पर रूजवेल्ट का जोर,

जो एक राष्ट्र की दिशा को हिलाता और आकार देता है और,

इसलिए, उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों का चयन जो

देश का कानून बनाता है और घोषित करता है, सुसंगत होना चाहिए

संविधान के सामाजिक दर्शन के साथ। महारत हासिल नहीं

केवल कानून का, लेकिन सामाजिक दृष्टि और रचनात्मकता का

शिल्प कौशल सफल न्याय में महत्वपूर्ण निवेश हैं।

(मुख्यधारा, 22 नवंबर, 1980) "

आवश्यक है कि ऐसे न्यायाधीश हों जो तैयार हों नए उपकरण बनाने के लिए, नए तरीके बनाने के लिए, नए तरीके अपनाने के लिए

रणनीतियाँ बनाएं और एक नया न्यायशास्त्र विकसित करें, जो न्यायिक हैं एक सामाजिक दृष्टि और एक रचनात्मक संकाय के साथ राजनेता और

जिनके पास, सबसे बढ़कर, प्रतिबद्धता की गहरी भावना है

न सत्ता में किसी दल के प्रति और न ही किसी के प्रति जवाबदेही विरोध और न ही उन वर्गों के लिए जो मुखर हैं लेकिन

भारत के आधे-भूखे लाखों लोग जिन्हें लगातार अस्वीकार किया जाता है

उनके बुनियादी मानवाधिकार। हमें ऐसे न्यायाधीशों की आवश्यकता है जो जीवित हों। भारतीय जीवन की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के लिए, जो हैं

हर आँख से हर आँसू पोंछने के लिए उत्सुक, जो विश्वास रखते हैं

संवैधानिक मूल्यों में और जो कानून का उपयोग करने के लिए तैयार हैं

संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में। यह नियुक्ति *4* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. का व्यापक खाका होना चाहिए।

यह अधिकार कि हमारे पास वास्तव में एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो सकती है जो केवल संविधान और भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा एक है महान अवधारणा जो संवैधानिक योजना को प्रेरित करती है और उस नींव का गठन करती है जिस पर इमारत टिकी हुई है।

हमारी लोकतांत्रिक राजनीति। अगर एक सिद्धांत है जो चलता है

संविधान के पूरे ताने-बाने के माध्यम से, यह है

कानून के शासन के सिद्धांत और संविधान के तहत, यह है

न्यायपालिका जिसे राज्य के प्रत्येक अंग को कानून की सीमाओं के भीतर रखने का कार्य सौंपा गया है और

जिससे कानून के शासन को सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके। यह.

इस कार्य में न्यायपालिका की सहायता करना है कि न्यायपालिका की शक्ति

न्यायपालिका को समीक्षा प्रदान की गई है और इसके द्वारा

इस शक्ति का प्रयोग करना जो कानून के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, कि न्यायपालिका

नागरिक को उसके उल्लंघन से बचाने की कोशिश करता है

राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा संवैधानिक या कानूनी अधिकार या शक्ति का दुरुपयोग या दुरुपयोग। न्यायपालिका के बीच खड़ा है

नागरिक और राज्य कार्यकारी ज्यादतियों और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग या दुरुपयोग के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में और इसलिए यह बिल्कुल आवश्यक है कि न्यायपालिका

कार्यकारी दबाव या प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और यह

संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में विस्तृत प्रावधान करके सुरक्षित किया गया है जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

भारत संघ के निर्णयों में संदर्भ दिया गया है

संकलचंद हिम्मतलाल सेठ बनाम *(1977) 4* एस. सी. सी. *193*। लेकिन यह याद दिलाना आवश्यक है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा केवल इन तक ही सीमित नहीं है -

कार्यकारी दबाव या प्रभाव से स्वतंत्रता लेकिन यह

यह एक बहुत व्यापक अवधारणा है जो कई अन्य दबावों और पूर्वाग्रहों से अपनी व्यापक स्वतंत्रता लेती है। इसके कई आयाम हैं, अर्थात् अन्य की निर्भीकता। सत्ता केंद्र, आर्थिक या राजनीतिक, और उस वर्ग द्वारा अर्जित और पोषित पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता जिसके लिए ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *195*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

न्यायाधीश संबंधित हैं। अगर हम फिर से वाक्पटुता को उद्धृत कर सकते हैं

न्यायमूर्ति कृष्ण लायर के शब्दः

सरकार। यह न तो विपक्ष के उपाय के लिए बनाई गई न्यायपालिका है और न ही सरकार की खुशी। *(मुख्यधारा, 22 नवंबर, 1980)*

टाइकून, सांप्रदायिक, संकीर्णतावादी, उन्मादी, चरमपंथी और कट्टरपंथी प्रतिक्रियावादी झूठ बोल रहे हैं और अवचेतन रूप से न्यायपालिका को आकार दे रहे हैं।

सलाह देना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है

जब वे भाग *III* और *IV* के साथ भिन्न होते हैं

पैरामाउंट चर्मपत्र "।

न्यायाधीशों को कठोर और कठोर फाइबर का होना चाहिए।

सत्ता से पहले, चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक, और उन्हें बनाए रखना चाहिए

कानून के शासन का मूल सिद्धांत जो कहता है, "आप बनो।

जो भी इतना ऊँचा है, कानून आपके ऊपर है। यह सिद्धांत है कि

न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो इसके लिए महत्वपूर्ण है

वास्तविक सहभागी लोकतंत्र की स्थापना,

एक गतिशील अवधारणा के रूप में कानून के शासन का रखरखाव और

कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना समुदाय। यह स्वतंत्रता का यह सिद्धांत है

न्यायपालिका जिसे हमें व्याख्या करते समय ध्यान में रखना चाहिए

संविधान के प्रासंगिक प्रावधान "।

एस. मुर्तजा फजल अली, जे., "न्यायिक समीक्षा" के मुद्दे पर

"मूल संरचना" के बारे में निम्नलिखित राय दी गई है:

"*332.* ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे संविधान ने एक नियुक्ति के लिए पूर्ण और प्रभावी तंत्र

न्यायाधीश जो न्यायपालिका के बीच न्यायसंगत संतुलन बनाते हैं और कार्यकारी शक्तियाँ ताकि अंतिम नियुक्ति के दौरान

कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकार में निहित, शक्ति

एक अनिवार्य परामर्श प्रक्रिया के अधीन है जिसके द्वारा कन्वेंशन राष्ट्रपति द्वारा बहुत महत्वपूर्ण होने का हकदार है।

इन सुरक्षा वाल्वों के अलावा, जाँच और संतुलन

प्रत्येक चरण, जहाँ राष्ट्रपति की शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

6

न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बल्कि इसे कार्यपालिका की अनिश्चितताओं से रोकने के लिए भी। हमारे संविधान द्वारा अपनाई गई पद्धति का एक अन्य लाभ यह है कि राष्ट्रपति को पूरी शक्ति सौंपकर, निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्वों को पेश किया जाता हैः

न्याय की, *(2)* न्यायिक प्रणाली के गतिशील लक्ष्यों के साथ जोड़ना

सिद्धांतों के अधीन एक प्रगतिशील समाज

निर्देश द्वारा निर्देशित होने वाला शासन राज्य नीति के सिद्धांत,

(3) न्यायपालिका को प्रभावी बनाने के लिए और शक्तिशाली तंत्र, संविधान में एक शामिल है

सबसे कठिन और जटिल प्रणाली जिसके द्वारा न्यायाधीशों को अनुच्छेद *124 (4)* के तहत हटाया जा सकता है।

व्यवहार में लगभग असंभव है,

(4) लोकतांत्रिक बनाने और बनाए रखने के लिए

न्यायपालिका की नियुक्ति की शक्ति को संसाधित करता है

कार्यपालिका में इतना निहित किया गया है कि प्रमुख कार्यकारिणी जो परिषद के माध्यम से कार्य करती है

मंत्रियों का, जो विशुद्ध रूप से निर्वाचित निकाय है,

जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया।

XXX

XXX

XXX

336. इस न्यायालय ने कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्यपाल को परामर्श की जिस शर्त का प्रयोग करना है, उसका तात्पर्य है

कि उसे उच्च न्यायालय की सिफारिशों का सम्मान करना होगा और बिना ठोस कारणों के इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है

और यदि वह ऐसा करता भी है, तो यह स्पष्ट है कि उसका आदेश हमेशा दुर्भावनापूर्ण आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

या उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *197*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

XXX

XXX

XXX

345. इसलिए, यह सभी विवादों का निपटारा करता है

पक्षकारों के लिए अब तक के विभिन्न पहलुओं के लिए परामर्श

अनुच्छेद *222* की व्याख्या का संबंध है। ए. पर अतः तथ्यों, परिस्थितियों और

अधिकारियों की स्थिति इस प्रकार हैः

(1) कि अनुच्छेद *222* स्पष्ट रूप से *'*सहमति*'* को बाहर करता है और

*'*सहमति*'* शब्द को पढ़ना संभव नहीं है।

अनुच्छेद *222* और इस प्रकार शक्ति को कम कर देता है

इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रदान किया गया,

(2) कि किसी न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सी. जे. का स्थानांतरण

अनुच्छेद *222* के तहत अदालत को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय हित,

सजा देना या कोई कलंक शामिल करना, *(4)* कि उपयुक्त मामलों में जहां दुर्भावनापूर्ण रूप से लिखा जाता है

इसके चेहरे पर बड़ा, स्थानांतरण का आदेश दिया गया

राष्ट्रपति द्वारा न्यायिक समीक्षा की जाएगी,

(5) कि एक उच्च न्यायालय से एक न्यायाधीश का स्थानांतरण

दूसरे के लिए पहले या नए के बराबर नहीं है

कार्यकाल के किसी भी अर्थ में नियुक्ति, *(6)* कि अनुच्छेद *222* के तहत किया गया स्थानांतरण

शर्तों और परिस्थितियों का पालन करना

ऊपर वर्णित परिवर्तन या क्षरण नहीं करता है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

XXX

XXX

XXX

402. श्री सीरवई ने इसका जोरदार तर्क दिया है कि

चिंता यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए हर कीमत पर बनाए रखें। वास्तव में, अगर वे वास्तव में चिंतित हैं

कि हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण करना चाहिए तो यह *[2014] 10* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3

बिल्कुल आवश्यक है कि बाहर से नई प्रतिभाओं को आना चाहिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में या तो इसे चलाने के लिए या प्रमुख के लिए आयात किया जाए

ताकि वे बहुत अधिक विश्वास पैदा कर सकें

स्थानीय न्यायाधीशों की तुलना में लोग। सी. जे. का पद है

वास्तव में एक बहुत ही उच्च संवैधानिक स्थिति और हमारे संविधान में दोनों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं।

उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया और उनका कार्यकाल। यह एक कुआँ है।

ज्ञात कहावत है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट करता है। जिस तरह मनुष्य अचूक नहीं है, उसी तरह एक प्रमुख भी अचूक है।

न्याय, हालांकि एक उच्च न्यायिक पद धारण करने वाला व्यक्ति है

संयम की गुणवत्ता के कारण अविनाशी होने की संभावना

एक सी. जे. राज्य के बाहर से है, उसकी अपनी शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना पूरी तरह से कम हो जाती है। हमने बताया है कि तैयार करने या विकसित करने की शक्ति

यह नीति स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *222* के चार कोनों में निहित है।

स्वयं जिसमें एक बहुत व्यापक शक्ति है जो केवल सी. जे. आई. के परामर्श से सशर्त है जो सर्वोच्च न्यायिक है देश में सत्ता। यह राष्ट्रपति के लिए हमेशा खुला रहता है।

जिसका व्यवहार में अर्थ है केंद्र सरकार,

एक नीति, मानदंड और दिशा-निर्देश जिसके अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किया जाना है और एक बार इन मानदंडों का पालन करने के बाद, राष्ट्रपति की शक्तियां

यह न्यायिक समीक्षा से परे होगा।

इस मुद्दे पर, वी. डी. तुलजापुरकर, जे. ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:

"624. जहां तक संवैधानिक परंपरा या प्रथा और उस उपक्रम का संबंध है जिसे आधार बनाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में बार भर्तियों के संबंध में सेवा में लगाया गया है।

भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी ने अपने प्रारंभिक कार्यकाल की समाप्ति पर उनके बने रहने के लिए विचार किए जाने के उनके अधिकार को दो गुना उठाया

विवाद। पूर्व के बारे में उन्होंने आग्रह किया कि ए

संवैधानिक परिपाटी या प्रथा, चाहे जो भी हो

स्वस्थ, मैदान को प्रभावित, बदल या नियंत्रित नहीं कर सकता है

अनुच्छेद *224 (1)* का अर्थ जो उनके अनुसार ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v* देता है।

भारत संघ *199*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

राष्ट्रपति को पूर्ण शक्ति और पूर्ण विवेकाधिकार

वर्तमान अतिरिक्त न्यायाधीशों के बने रहने के मामले में

उनके प्रारंभिक कार्यकाल की समाप्ति पर, बकाया राशि का बकाया केवल यह तय करने के लिए प्रासंगिक होना कि अतिरिक्त

न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए और इस संबंध में प्रासंगिक नहीं होना चाहिए। किसी विशेष व्यक्ति को नियुक्त किया जाना। जहां तक बात है

उपक्रम करते हुए उन्होंने बताया कि सामान्य उपक्रम

सभी उच्च न्यायालयों में बार के सदस्य से प्राप्त

और उस मामले के लिए भी अतिरिक्त उपक्रम जो है

बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्राप्त किया जा रहा है यदि ठीक से पढ़ा जाए

यह दिखाएगा कि यह केवल एक बाध्यकारी दायित्व बनाता है

नियुक्ति की ओर से दायित्व या प्रतिबद्धता उसे स्थायी न्यायाधीश का प्रस्ताव देने का अधिकार।

इनमें से किसी भी तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है।

विद्वान महान्यायवादी। यह हमारे सामने विवादित नहीं था।

कि संवैधानिक सम्मेलनों और प्रथाओं में है

अलिखित और लिखित संविधानों के तहत महत्व

और वह स्थिति जिसमें सम्मेलनों की भूमिका होती है

संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या कई से स्पष्ट है

मामलों का फैसला किया। यू. एन. आर. राव बनाम इंदिरा गांधी, *(1971) 2*

एस. सी. सी. *63*, मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने इस प्रकार टिप्पणी कीः *(* एस. सी. सी पी. *64* ,

पैरा *3)*

"यह कहा गया था कि हमें अनुच्छेद *75 (3)* की व्याख्या करनी चाहिए।

यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित सम्मेलनों की परवाह किए बिना अपनी शर्तों के अनुसार। यदि किसी लेख के शब्द स्पष्ट हैं, तो भी

कोई भी प्रासंगिक परिपाटी, प्रभाव निस्संदेह दिया जाएगा

शब्दों के लिए। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि हम एक संविधान की व्याख्या कर रहे हैं न कि एक अधिनियम की।

संसद, एक संविधान जो एक

के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली

कैबिनेट। समझने की कोशिश में कोई व्यक्ति अच्छा रख सकता है

उस समय प्रचलित परंपराओं को ध्यान में रखते हुए

संविधान बनाया गया था।

राजस्थान राज्य में *v.*

भारत संघ, *(1977) 3* एस. सी. सी. *592,0* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

किसी अनुच्छेद में पाई जाने वाली शक्ति की अन्यथा अस्पष्ट और ढीली सामग्री को स्पष्ट करने के माध्यम से एक संवैधानिक परंपरा या अभ्यास का महत्व भी है

उच्च न्यायालय में उनके अधीनस्थ न्यायालयों को सक्रिय किया गया था इतिहास को ध्यान में रखते हुए सम्मेलनों और प्रथाओं द्वारा,

उद्देश्य और उद्देश्य जो प्रासंगिक के समूह के पीछे है लेख, मुख्य उद्देश्य है, की सुरक्षा

जनरल की धारा *14* के साथ लेख को सबसे अधिक पढ़ना खंड अधिनियम में यह कहा जा सकता है कि उस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग समय-समय पर अवसर के रूप में किया जा सकता है।

आवश्यकता है लेकिन इस सवाल पर कि क्या कब

वर्तमान अतिरिक्त न्यायाधीश के कार्यकाल की समाप्ति पर नियुक्ति करने का अवसर उत्पन्न होता है कि क्या उसे होना चाहिए

बकाया होने पर भी पूर्ववर्ती की उपेक्षा करना उस उच्च न्यायालय में यह प्राप्त करना जारी रखें कि लेख मौन है और बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और इसलिए सिद्धांत द्वारा लागू किया गया है

विद्वान महान्यायवादी आवेदन नहीं करेंगे। दूसरी ओर,

ऐसी स्थिति में अन्य सुव्यवस्थित सिद्धांत का आह्वान करना उचित होगा कि किसी संवैधानिक प्रावधान का अर्थ लगाने में संविधान की संरचना से उत्पन्न होने वाले निहितार्थ

संविधान स्वयं या इसकी योजना से वैध रूप से हो सकता है इस कोण से अनुच्छेद *224 (1)* को बनाया और देखा गया

पूर्ण संवैधानिक परंपरा या प्रथा जिसके पास है

इस तरह के निहितार्थों के कारण विकसित होने वाले लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा जब यह बुनियादी विशेषताओं में से एक की रक्षा करने के लिए काम करता है जो कि हमारे मूल विश्वास में अंतर्निहित है।

संविधान, अर्थात् न्यायपालिका की स्वतंत्रता। में।

एड्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *201*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

अन्य शब्दों में अन्यथा निरपेक्ष शक्ति पर एक सीमा

और अनुच्छेद *224 (1)* में निहित विवेकाधिकार को इसमें पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि उक्त मूल विश्वास से उत्पन्न होने वाले स्पष्ट निहितार्थ जो एक मौलिक स्तंभ बनाते हैं।

संविधान की मूल संरचना का समर्थन करना, अन्यथा पूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग करना।

जैसा कि सुझाव दिया गया है, उसी के लिए विनाशकारी होगा। कि ऐसा नहीं है

किसी भी संवैधानिक प्रावधान की *'* सख्त शाब्दिक पहुंच *'* शुरू करने के लिए ठोस दृष्टिकोण ताकि इसकी सच्चाई का निर्धारण किया जा सके।

अनुच्छेद के मामले में परिधि और प्रभाव को आश्चर्यजनक रूप से चित्रित किया गया है। *368* जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था

केशवानंद भारती मामला, *(1973) 4* एस. सी. सी. *225*, जहाँ यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मूल या आवश्यक विशेषताएँ

संविधान उस अनुच्छेद में निहित अन्यथा व्यापक संशोधन शक्ति पर बंधन या सीमाओं के रूप में कार्य करता है। ऑस्ट्रेलिया में

संसद की कानून बनाने की शक्तियों पर सीमाएँ

राज्यों पर संघीय राष्ट्रमंडल को संविधान के संबंधित प्रावधानों में पढ़ा गया क्योंकि

संविधान की संघीय प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्रभावः *(* लार्ड मेयर पार्षदों और नागरिकों के माध्यम से

मेलबर्न शहर बनाम। राष्ट्रमंडल, *74*

राष्ट्रमंडल एल. आर. *31*, और विक्टोरिया राज्य बनाम। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल, *122* राष्ट्रमंडल एल. आर. *353)*।

उल्लिखित प्रकारों के उपक्रमों के संबंध में

ऊपर, यह सच है कि सख्ती से और कानूनी रूप से इन बातों को बोलते हुए

उपक्रम केवल बार के संबंधित सदस्य पर एक बाध्यकारी दायित्व पैदा करते हैं न कि नियुक्ति पर। अधिकार लेकिन यह नहीं भुलाया जा सकता है कि जब इस तरह

उपक्रमों के बारे में सोचा गया था, अंतर्निहित अभिधारणा

यही बात थी कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्थायी न्यायाधीश का प्रस्ताव नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं था।

बार के संबंधित सदस्य लेकिन ऐसा प्रस्ताव

किया जाएगा और उसी पर बैठक की जाएगी

बार से नियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश को मना नहीं करना चाहिए

इसे स्वीकार करने और बार को वापस करने के लिए। इसलिए मेरा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उपरोक्त परिपाटी या प्रथा और

उपक्रम दो *2* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. में जनहित के उद्देश्य की पूर्ति करता है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है और उन दो पहलुओं के संबंध में इन वर्तमान अतिरिक्त न्यायाधीशों को लोकहित प्रदान किया जाता है

बार से एक वैध प्रत्याशा की भर्ती और

प्रवर्तनीय अधिकार जिसे अवैध रूप से या नियुक्ति प्राधिकारी की सनक या इच्छा पर नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन उस पर विचार किया जाना चाहिए।

उस उच्च न्यायालय में या तो विस्तार के माध्यम से बने रहने के लिए

उनका कार्यकाल या वरीयता में उन्हें स्थायी बनाना

फ्रेशर्स या आउटसाइडर्स और इसका अर्थ लगाना असंभव है

अनुच्छेद *224 (1)* नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्ण शक्ति और पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करता है। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसा कि सुझाव दिया गया है और सुझाए गए निर्माण के लिए

अस्वीकार कर दिया। उपरोक्त चर्चा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि

प्रारंभिक भर्ती के लिए प्रस्तावित नियुक्तियों और वर्तमान अतिरिक्त नियुक्तियों के बीच एक वैध वर्गीकरण है।

न्यायाधीश जिनके मामले समाप्ति के बाद जारी रहने के लिए हैं

उनके प्रारंभिक कार्यकाल का फैसला किया जाना है और दोनों नहीं हैं

उसी स्थिति में "।

डी. ए. देसाई, जे. की टिप्पणियाँ यहाँ व्यक्त की गई हैं:

1981 का सं. *274* इस न्यायालय में दायर किया गया और हस्तांतरित मामले नं. *2* , *6* और *1981* के *24* को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था

दोनों समूहों के लिए सामान्य बिंदुओं पर तर्कों की पुनरावृत्ति से बचने की दृष्टि से मामलों के वर्तमान समूह के साथ

मामलों में। मामलों के पहले समूह में अनुच्छेद *217,224* और अन्य संबंधित लेखों के निर्माण का प्रश्न प्रमुखता से परिपत्र के संदर्भ में सामने आया।

कानून मंत्री दिनांक *18* मार्च, *1981*, स्थायी रूप से नियुक्त होने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की सहमति मांगते हुए

अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अल्पकालिक विस्तार

श्री ओ. एन. वोहरा, श्री एस. एन. कुमार और श्री एस. बी. वाड, दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों को दिया गया और श्री ओ. एन. वोहरा और श्री एस. एन. कुमार की अंतिम गैर-नियुक्ति।

निवेदन यह था कि कानून मंत्री का परिपत्र

अतिरिक्त न्यायाधीशों के स्थानांतरण का एक गुप्त प्रयास प्रकट करता है

ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन से परामर्श किए बिना एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में।

भारत का संघ *203*

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

अनुच्छेद *222 (1)* द्वारा अपेक्षित भारत के मुख्य न्यायाधीश और इस प्रकार संघ में बहुमत के निर्णय को दरकिनार करते हुए

केंद्रीय विषय था परामर्श का दायरा, दायरा और विषय-वस्तु जो राष्ट्रपति के पास तीनों के साथ होना चाहिए। अनुच्छेद *217 (1)* में निर्धारित संवैधानिक पदाधिकारी। मामलों के दूसरे समूह में, सवाल इस संदर्भ में उठा

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री के. बी. एन. सिंह का मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण

श्री एम. एम. इस्माइल, प्रमुख के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप

केरल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए *19* जनवरी, *1981* को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा

अनुच्छेद *222*। विवाद उस दायरे, दायरे और परामर्श की सामग्री पर केंद्रित था जो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ करना चाहिए। अनुच्छेद *222* के तहत हस्तांतरण की शक्ति। इस प्रकार, दायरा, परिधि

और अनुच्छेद *217* के तहत परामर्श की सामग्री भी एक

अनुच्छेद *222* का जो, जैसा कि श्री सीरवई ने कहा, अधिक या

कम समान हालांकि विभिन्न पहलू जिन पर

परामर्श पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए मामले में भिन्न हो सकता है

स्थानांतरण और नियुक्ति के मामले में, अनुमान लगाया गया

मामलों के दोनों समूहों में प्रमुखता से। दोनों के तहत परामर्श के दायरे, दायरे और विषय-वस्तु के मापदंड

अनुच्छेद *217 (1), 222* और *224* को व्यापक आधार पर तैयार किया गया था।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कसौटी पर परखा जाने वाला कैनवास लड़ाई का विश्वास और मौलिक और

संविधान की मूल विशेषता। यह कहा गया था कि यदि

परामर्श स्वयं एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए है

न्यायपालिका के खिलाफ शक्ति का मनमाना और नग्न प्रयोग, परामर्श की प्रक्रिया इतनी व्यापक होनी चाहिए कि

मामले के सभी पहलुओं को शामिल करें और इसे इतना दृढ़ बनाया जाना चाहिए और कठोर कि इसका कोई भी उल्लंघन या उल्लंघन होगा

की स्वतंत्रता के दुर्भावनापूर्ण या विध्वंसक के रूप में माना जाए

न्यायपालिका और निर्णय को न्यायिक समीक्षा द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसलिए, शुरुआत में यह आवश्यक है कि

[2014] 10 एस. सी. आर. की स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में ठीक से जानकारी दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान में निर्धारित न्यायपालिका।

697. तर्कों का पूरा सरगम मुख्य रूप से घूमता था।

याचिकाओं के एक समूह में अनुच्छेद *217* और *224* का निर्माण और दूसरे समूह में अनुच्छेद *222* का निर्माण।

के विभिन्न अन्य लेखों को कवर करते हुए व्यापक रूप से फैला हुआ था

प्रमुख पर केंद्रित निर्माण यह धारणा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक बुनियादी और

संविधान की मौलिक विशेषता जिसकी उत्पत्ति न्यायिक समीक्षा की शक्ति में है जो

कार्यपालिका और विधायी कार्यों को संविधान के बाहर घोषित करने के लिए अदालत। इस संबंध में हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं।

इस रूप में और एक के लिए विवाद के रूप में एक साफ स्लेट उत्कीर्ण वस्तु का व्यापक रूप से सांकलचंद में प्रचार किया गया था।

हिमतलाल सेठ बनाम। भारत संघ, *(1976) 17* गुजरात एल. आर. *1017* (एफ. बी.*)*, और भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ *(*ऊपर*)*। इसमें कुछ अतिरिक्त आयाम जोड़े गए थे।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बुनियादी अवधारणा जबकि दोनों दलों ने अतीत की तरह एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की *(*बयान देखें*)*

श्री एस. वी. गुप्ते, सेठ मामले में तत्कालीन महान्यायवादी *(*ऊपर*)*, स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करने पर

यद्यपि न्यायपालिका के दायरे और विषय-वस्तु और दृष्टिकोण में एक स्पष्ट विचलन था।

XXX

XXX

XXX

771. अब, राष्ट्रपति को बनाने की शक्ति प्रदान की गई है परामर्श के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति

उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ, जिन्हें राष्ट्रपति समझे आवश्यक है। निवेदन यह है कि 'आवश्यक समझ सकता है' अभिव्यक्ति 'परामर्श' अभिव्यक्ति को योग्य बनाती है और यदि वह अन्यथा समझता है तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ सकता है।

उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के साथ परामर्श ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *205*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

और उच्च न्यायालयों से। दूसरे शब्दों में, यह प्रस्तुत किया गया था

उत्तरदाताओं की ओर से, राष्ट्रपति के पास है न्यायाधीशों से परामर्श करने या न करने का विवेकाधिकार

बनाने से पहले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यह बताया गया था

कि जहाँ परामर्श अनिवार्य है वह विशेष रूप से है

प्रदान किया गया और ऊपर निकाले गए परंतुक का संदर्भ दिया गया जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले

भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायालय। निसन्देह,

परंतुक राष्ट्रपति के पास नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है।

मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

भारत का, लेकिन उत्तरदाताओं की ओर से सुझाए गए निर्माण को स्वीकार करना मुश्किल है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति है बड़े पैमाने पर और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले राज्य की न्यायिक शाखा में किसी भी पदाधिकारी से परामर्श नहीं कर सकते हैं। अभिव्यक्ति 'आवश्यक समझ सकता है'

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को योग्य बनाता है और

उच्च न्यायालयों से परामर्श किया जाना चाहिए। चयन वैकल्पिक है।

न्यायाधीशों की संख्या जिनसे परामर्श किया जाना है न कि

परामर्श के बाद परामर्श अनिवार्य होगा। एक चरम सीमा निवेदन कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पूरी तरह से हटा देना नहीं है

हमें बधाई, क्योंकि 'उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों' के साथ परामर्श

यह स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि परामर्श के साथ होना चाहिए

उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीश। 'और' का संयोजन स्पष्ट रूप से सूचक है।

संविधान निर्माताओं का इरादा। यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच असंगत 'या' था

अनुच्छेद *124* के उप-अनुच्छेद *(2)* में न्यायालय हो सकते हैं -

यह निवेदन करने में कुछ बल था कि राष्ट्रपति अदालत की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. की अध्यक्षता कर सकते हैं।

प्रासंगिक सामग्री जो उसे निर्णय लेने में मदद करेगी प्रक्रिया। श्री सीरवई ने कहा कि इस न्यायालय को इससे बचना चाहिए

अनुच्छेद *124* का ऐसा निर्माण जो राष्ट्रपति किसी भी न्यायिक पदाधिकारी के परामर्श के बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा है

सही है। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसे निर्माण का सुझाव दिया जहां, एक संवैधानिक सम्मेलन द्वारा, इसकी कोई आवश्यकता हो।

परामर्श को समाप्त कर दिया जाएगा और फिर भी कार्यकारी शक्ति प्रमुख की नियुक्ति में चयनात्मक और चयनात्मक होगी भारत के न्याय को नियंत्रित या विफल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि

एक संवैधानिक सम्मेलन को पढ़ा जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के कनिष्ठ न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठ

न्यायालय को एक नियम के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, सिवाय तब जब वह कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य हो।

जिम्मेदारियाँ। यह कहा गया था कि जब अनुच्छेद *124 (2)* में पढ़ा जाएगा तो यह संवैधानिक परिपाटी किसी भी आवश्यकता को दूर कर देगी।

न्यायिक शाखा में किसी भी पदाधिकारी के साथ परामर्श करना।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले और

कार्यपालिका को अपने झुकाव और सोच वाले व्यक्ति को चुनने में सक्षम बनाने के लिए नहीं। इसी संदर्भ में यह बताया गया था कि अनुच्छेद *126* राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के सबसे कनिष्ठ न्यायाधीश को भी भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति देता है और यह कहा गया था कि ऐसा दृष्टिकोण या अनुच्छेद *126* का ऐसा निर्माण न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। कहा जाता है कि अगर

कनिष्ठतम को भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, प्रत्येक न्यायाधीश पक्ष लेने के लिए आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन के पक्ष में निर्णय लेगा।

भारत का संघ *207*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

कार्यपालक। और जहाँ तक अनुच्छेद *124* का संबंध है, यह था

कहा कि यदि वरिष्ठता की परंपरा को अनुच्छेद में नहीं पढ़ा जाता है

124 (2) , उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश एक होगा

भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए संभावित उम्मीदवार

और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण अयोग्य ठहराया जाएगा परामर्श लिया जा रहा है। इस तरह के चरम के लिए कोई वारंट नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर स्थिति और प्रतिबिंब

ऊपर इंगित किया गया है कि सकारात्मक सीमा होगी प्रमुख की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति की शक्ति

भारत का न्याय और किसी भी सीमा को पढ़ना आवश्यक नहीं है

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के रूप में भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अवलोकन यह है कि

प्रस्तुतिकरण के लिए आकस्मिक और एक में जांच की जा सकती है

उपयुक्त मामला। और निर्माण का सवाल रखा जाता है।

खोलें।

XXX

XXX

XXX

परिपत्र में जबरदस्ती का तत्व होता है और सहमति समाप्त हो जाती है सहमति होना यदि यह जबरदस्ती के तहत प्राप्त किया जाता है। कहा गया है।

कि सहमति और जबरदस्ती एक साथ बीमार हो जाते हैं क्योंकि जबरन

कानून की नजर में सहमति सहमति नहीं होगी। कहा गया है।

कि परिपत्र में निहित खतरा स्पष्ट हो जाता है

क्योंकि मुख्यमंत्री, कार्यपालिका की मजबूत भुजा

सहमति लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर हर छोटी चीज़

संदेह के साथ और हमले के रूप में देखा गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह पूरी तरह से बन जाती है

गुमराह कर रहे हैं। कानून मंत्री, अगर वह सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं

न्याय या संबंधित न्यायाधीश, कार्रवाई का औचित्य

सवाल करने के लिए खुला रहें। चंद्रचूड़, जे. ने चेतावनी दी है

शेठ मामला *(ऊपर)* कि कार्यपालिका नहीं कर सकती और न ही होनी चाहिए

न्यायाधीशों के साथ संबंध स्थापित करना *(*एस. सी. आर. पी. *456* सीडीः एससीसी

पी। *230* , पैरा *43)*। इस दिशा को अपने अक्षर और भावना में लेते हुए,

कानून मंत्री ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। मुखिया।

मंत्री बदले में मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने के लिए बाध्य थे।

3 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ एक उचित संचार माध्यम के रूप में भी जाना जाता है। इस संदर्भ में *'*प्राप्त*'* अभिव्यक्ति का अर्थ केवल न्यायाधीश से देने का अनुरोध करना होगा।

यदि वह चाहे तो सहमति दें। यदि वह सहमति देता है, अच्छा और अच्छा, और यदि नहीं देता है, तो कोई बुरा परिणाम होने की संभावना नहीं है।

आगे बढ़ने के लिए। मैं विद्वान महान्यायवादी की इस दलील से प्रभावित नहीं हूं कि जो सहमति देता है वह दे सकता है

किसी भी दूरस्थ लाभ को देखें और यदि ऐसा कोई लाभ दिया जाता है और यदि पीड़ित होने का आरोप लगाया जाता है न्यायाधीश सहमति नहीं दे रहे हैं, न्यायिक समीक्षा का हाथ कार्यकारी त्रुटि को सुधारने के लिए पर्याप्त मजबूत है।

XXX

XXX

XXX

815. सार्वजनिक नीति की तरह जनहित एक अनियंत्रित घोड़ा है और किसी भी सटीक परिभाषा में असमर्थ है और इसलिए, यह आग्रह किया गया था कि यह सुरक्षा बहुत अस्पष्ट है और

संदिग्ध उपयोगिता। यह आग्रह किया गया कि ये सुरक्षा उपाय *1976* में सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोकने में विफल रहे। यह दृष्टिकोण इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि लक्ष्मण रेखा जब उल्लंघन या पार किया जाता है तो सुरक्षा उपायों द्वारा खींचा जाता है,

न्यायिक समीक्षा शरारत को शून्य कर देगी। यह सच है कि

कि उच्च न्यायालय के व्यक्तिगत न्यायाधीश के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटाना लगभग असंभव है क्योंकि न्याय तक पहुंच दुर्गम पहाड़ के माध्यम से होती है।

लागत और व्यय। यह हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम

उच्च, शक्तिशाली और समृद्ध लोगों की रक्षा करना। लेकिन इन तीनों सुरक्षा उपाय, अर्थात्, के साथ ईंधन और प्रभावी परामर्श

भारत के मुख्य न्यायाधीश, और यह कि हस्तांतरण की शक्ति कर सकती है

लोक हित में प्रयोग किया जाएगा, और न्यायिक समीक्षा, कार्यपालिका द्वारा इसे नियंत्रित करने के प्रयास के खिलाफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निश्चित रूप से सुरक्षित करें।

अंत में, ए. डी. आर. ए. एस. बी. ए. आर. एसोसिएशन *v.* की टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है।

भारत संघ *209*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

इसके अंतर्गतः *"1245.* नीति का सवाल पूरी तरह से एक मामला है

राष्ट्रपति तय करें। भले ही नीति के बाद से राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से उस ओर से परामर्श किया जाता है उच्च न्यायालयों से संबंधित, उनकी राय बाध्यकारी नहीं है

राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति के लिए किसी को भी अपनाने के लिए खुला है

नीति जो केवल न्यायिक समीक्षा के अधीन है

अदालत। संविधान के अनुच्छेद *222* के तहत प्रमुख

इस सवाल पर भारत के न्यायधीश से सलाह लेनी होगी।

क्या किसी विशेष न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाना चाहिए और जहाँ उक्त को लागू करते समय उसका स्थानांतरण किया जाना चाहिए।

नीति। यदि सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करती है

उक्त को लागू करने के लिए स्थानांतरण पर अपनी राय देने के लिए

नीति जो वास्तव में लोक हित में है, वह ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकता। भले ही मुख्य न्यायाधीश ने विरोध किया था न्यायाधीशों के 'थोक स्थानान्तरण' पर सरकार द्वारा स्थानांतरण की सिफारिशों पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक भाग के रूप में बनाया गया

अपनी नीति का कार्यान्वयन। कि श्री के. बी. एन. का स्थानांतरण। सिंह सरकार की नीति के कारण कर सकते थे

शपथ-पत्रों में निम्नलिखित कथनों से एकत्र किया जाए इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गयाः श्री के. बी. एन. सिंह के *16* सितंबर, *1981* के शपथ पत्र के पैरा *8* में कहा गया हैः

"जब प्रतिनिधि जानना चाहता था कि वह क्यों हो सकता है मद्रास में स्थानांतरित, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश

केवल यह कहा कि यह सरकार की नीति थी, लेकिन दी

इस बात का कोई सुराग नहीं है कि किस वजह से उन्हें पटना से पटना स्थानांतरित किया गया। मद्रास "। मुख्य न्यायाधीश के शपथ पत्र के पैरा *2 (*जी*)* में

भारत के बारे में उन्होंने कहा हैः मैं इस बात से इनकार करता हूं कि जब श्री के. बी. एन. सिंह ने *5* जनवरी, *1981* को टेलीफोन पर जानना चाहा, तो मैंने केवल इतना कहा कि यह 'सरकारी नीति' थी। *16* अक्टूबर को दिए गए जवाबी-हलफनामे के पैराग्राफ *8* में,

1981 श्री के. बी. एन. सिंह के बारे में यह कहा गया है कि "एक समय पर उन्होंने यह भी कहा था कि हस्तांतरण को प्रभावी बनाना सरकार की नीति थी।

दो या तीन "के बैच।

[2014] 10 एस सी आर।

210 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. निर्णयों का क्रम अब हमें इस ओर ले जाएगा

एस. पी. संपत कुमार बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। भारत संघ, *(1987) 1* एस. सी. सी. *124*। *5* सदस्यीय पीठ द्वारा व्यक्त किया गया विचार

उपरोक्त मामले में इस न्यायालय के माननीय न्यायाधीश इस संबंध में थे

हाथ में एक के समान एक विवाद। तत्काल निर्णय में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, *1985* के संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दी गई थी। उपरोक्त अधिनियम बनाया गया था

संविधान के अनुच्छेद *323* ए के तहत। संविधान में अनुच्छेद *323* ए को संविधान द्वारा पेश किया गया था *(42)*।

संशोधन*)* अधिनियम, *1976*। मुख्य निर्णय दिया गया था

रंगनाथ मिश्रा, जे. *(*जैसा कि वे तब थे*)* अपनी ओर से और

वी. खालिद, जी. एल. ओझा और एम. एम. दत्त, जे. जे. जहाँ तक सहमति की बात है

मुख्य न्यायाधीश पी. एन. भगवती द्वारा प्रस्तुत विचार का संबंध निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्ज निष्कर्ष से है।

वर्तमान विवाद पर।

इसकी घटक शक्ति का प्रयोग इसे निरस्त कर सकता है या ले सकता है। दूर। यदि न्यायिक समीक्षा की शक्ति को निरस्त कर दिया जाता है या छीन लिया जाता है तो संविधान वैसा ही नहीं रहेगा जैसा वह है। यह एक

हमारी संवैधानिक योजना का मूल सिद्धांत यह है कि राज्य का प्रत्येक अंग, प्रत्येक प्राधिकरण

संविधान, संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और

ऐसी शक्ति की सीमाओं के भीतर कार्य करना होगा। यह एक सीमित है

सरकार जो हमारे पास संविधान के तहत है और दोनों

कार्यपालिका और विधायिका को संविधान के तहत उन्हें प्रदत्त शक्ति की सीमाओं के भीतर कार्य करना होगा।

अब एक सवाल उठ सकता है कि कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या हैं और क्या कार्यपालिका ने अपनी शक्ति के दायरे में काम किया है। इस तरह के सवाल को स्पष्ट रूप से कार्यपालिका पर निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है और दो बहुत अच्छे लोगों के लिए।

कारणों से। सबसे पहले प्रश्न का निर्णय संविधान और कानूनों की व्याख्या पर निर्भर करेगा और

यह पहले से ही निर्णय लेने के लिए उपयुक्त मामला होगा

भारत का संघ

211

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

न्यायपालिका, क्योंकि यह केवल न्यायपालिका है जो

इस क्षेत्र में विशेषज्ञता होनी चाहिए और दूसरा,

नागरिकों को संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई

यह भ्रमपूर्ण हो जाएगा, अगर इसे कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाए अपनी कार्रवाई की वैधता का निर्धारण करें। तो भी अगर

कानून बनाते हुए, विधायिका ने क्षेत्र के बाहर काम किया है इसकी विधायी क्षमता या कानून का उल्लंघन है

मौलिक अधिकार या इसके किसी अन्य प्रावधान

संविधान, इसका संकल्प, उन्हीं कारणों से नहीं हो सकता है,

विधायिका के निर्धारण पर छोड़ दिया जाए। द.

इन विवादों को हल करने के लिए तंत्र और यह स्वतंत्र तंत्र न्यायपालिका है जो इसके साथ निहित है

की वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति

द्वारा पारित कार्यकारी कार्रवाई और विधान की वैधता

विधायिका। न्यायपालिका का गठन अंतिम होता है।

विस्तार और दायरा क्या है, यह निर्धारित करने का नाजुक कार्य सरकार की प्रत्येक शाखा को प्रदत्त शक्ति।

ऐसी शक्ति के प्रयोग की क्या सीमाएँ हैं?

संविधान और क्या किसी शाखा की कोई कार्रवाई

इस तरह की सीमाओं का उल्लंघन करता है। यह भी एक बुनियादी सिद्धांत है

कानून का शासन जो प्रत्येक प्रावधान में व्याप्त है

संविधान और जो इसका मूल और सार है

कि कार्यपालिका या किसी अन्य द्वारा शक्ति का प्रयोग

प्राधिकार केवल संविधान द्वारा सशर्त नहीं होना चाहिए

लेकिन कानून के अनुसार भी होना चाहिए और यह न्यायपालिका है

जिसे यह सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन किया जाए और वहाँ है कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन

कार्यकारी और अन्य प्राधिकरण। इस कार्य का निर्वहन किया जाता है

न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके

जो न्यायपालिका के हाथों में सबसे शक्तिशाली हथियार है कानून के शासन को बनाए रखने के लिए। न्यायपालिका की शक्ति

समीक्षा हमारी संवैधानिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और

इसके बिना, कानून और शासन की कोई सरकार नहीं होगी

कानून एक चिढ़ाने वाला भ्रम और *[2014] 10* एस. सी. आर. का वादा बन जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवास्तविक। यही कारण है कि मैंने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड मामले *(ऊपर)* में अपने फैसले में पी. *287* और *288: (* एस. सी. सी पी. *678* , पैरा *87)*

संविधान जो किसी भी अन्य संविधान से अधिक बुनियादी है। और लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए मौलिक, यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति है

और यह निर्विवाद रूप से, मेरे विचार से, इसका हिस्सा है

संविधान की मूल संरचना। बेशक, जब मैं यह कहता हूं कि मुझे यह सुझाव देने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा के लिए प्रभावी वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

संसद द्वारा। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है

और इसे प्रभावित किए बिना निरस्त नहीं किया जा सकता है

संविधान की मूल संरचना। यदि ए.

संवैधानिक संशोधन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीन लिया जाता है और यह प्रावधान किया जाता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। भले ही यह विधायिका की विधायी क्षमता से बाहर हो या किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, यह कानून के विध्वंस से कम नहीं होगा।

संविधान, क्योंकि यह एक मजाक बना देगा

और राज्य और मौलिक अधिकारों को अर्थहीन और व्यर्थ बना देते हैं। तो भी अगर एक संवैधानिक संशोधन किया जाता है जिसका प्रभाव न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीनने और यह प्रावधान करने का होता है कि

संविधान में किए गए किसी भी संशोधन पर किसी भी आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, भले ही

संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन है और,

इसलिए, की संशोधनकारी शक्ति के बाहर

संसद ने जो कुछ किया है उसकी संवैधानिक वैधता के लिए वह संसद को एकमात्र न्यायाधीश बनाएगी और वह प्रभावी और सारतः रद्द कर देगी।

संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा आई. ए. डी. आर. ए. एस. बी. ए. आर. एसोसिएशन *v.*

भारत का संघ *212*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

और संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करता है। इसलिए इस निष्कर्ष का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए कि अनुच्छेद *368* का खंड *(4)* असंवैधानिक है और संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुँचाने के रूप में अमान्य है।

संविधान "।

यह निस्संदेह सच है कि मिनर्वा मिल्स लिमिटेड में मेरा निर्णय सही है।

पहलू का संबंध है, बहुमत न्यायाधीशों ने भी लिया एक ही दृष्टिकोण और यह माना कि न्यायिक समीक्षा एक बुनियादी और

संविधान की अनिवार्य विशेषता और यह नहीं हो सकता है

मूल संरचना को प्रभावित किए बिना निरस्त किया गया

संविधान और यह एक ही निर्णय से समान रूप से स्पष्ट है

कि हालांकि न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता है

संसद द्वारा संविधान में संशोधन करके

अपनी घटक शक्ति के बिना, संसद निश्चित रूप से किसी भी तरह से मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, स्थापित

प्रभावी वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या

न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था। बुनियादी और आवश्यक

न्यायिक समीक्षा की विशेषता को समाप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन यह

संशोधन करने के लिए संसद की क्षमता के भीतर होगा संविधान ताकि उच्च के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जा सके

न्यायालय, एक अन्य वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या

न्यायालय, यह एक अन्य संस्थागत तंत्र होगा या प्राधिकरण जो न्यायिक शक्ति का प्रयोग करेगा

संवैधानिक सीमाओं को लागू करने और कानून के शासन को बनाए रखने की दृष्टि से समीक्षा। अतः यदि कोई संसद द्वारा किया गया संवैधानिक संशोधन वापस लिया गया

उच्च न्यायालय से किसी भी मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति

तंत्र या प्राधिकरण, यह उल्लंघनकारी नहीं होगा बुनियादी संरचना सिद्धांत, जब तक कि आवश्यक शर्त

पूरा किया जाता है, अर्थात्, कि वैकल्पिक संस्थागत संसद द्वारा स्थापित तंत्र या प्राधिकरण

संशोधन उच्च न्यायालय से कम प्रभावी नहीं है।

4. यहाँ, वर्तमान मामले में, विवादित अधिनियम को संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है।

न्यायालयों की, अनुच्छेद *136* के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर, विवादों के संबंध में या खंड *(1)* में निर्दिष्ट शिकायतें। का बहिष्करण

अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता

अनुच्छेद के खंड *(1)* के अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा

323 - ए, इसलिए, विशेष रूप से अधिकृत है उस अनुच्छेद के खंड *(2) (घ)* में अधिनियमित संवैधानिक संशोधन। पूर्ववर्ती पैरा में की गई चर्चा से यह स्पष्ट है।

कि यह संवैधानिक संशोधन बहिष्करण को अधिकृत करता है

अनुच्छेद *226* के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता और

अनुच्छेद *323* का खंड *(1)*-ए की अधिकारिता को छोड़कर अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालय को एक प्रभावी वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या प्राधिकरण प्रदान करना चाहिए।

न्यायिक समीक्षा के लिए। यदि यह संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद *323*-ए के खंड *(1)* के तहत बनाए गए कानून की अनुमति देता है

न्यायिक समीक्षा के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या व्यवस्था स्थापित किए बिना अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाहर करना, यह मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन होगा और इसलिए संसद की घटक शक्ति के बाहर होगा। यह होना ही चाहिए,

इसलिए, इस संवैधानिक संशोधन में निहित के रूप में पढ़ा जाए कि कानून की अधिकारिता को छोड़कर

उच्च न्यायालय अनुच्छेद *226* और *227* के तहत अनुज्ञेय है

इसे एक शून्य नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इसे एक और प्रभावी संस्थागत तंत्र या प्राधिकरण स्थापित करना चाहिए और इसकी शक्ति निहित करनी चाहिए।

इसमें न्यायिक समीक्षा। नतीजतन, विवादित अधिनियम

अनुच्छेदों के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर

226 और सेवा मामलों के संबंध में और प्रशासनिक न्यायाधिकरण में ऐसी अधिकारिता निहित करने के लिए आई. ए. डी. आर. ए. एस. बी. ए. आर. एसोसिएशन *v.* के दायरे और कवरेज के भीतर होने के रूप में संवैधानिकता की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं।

भारत का संघ *215*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

अनुच्छेद *323*-क के खंड *(2) (*घ*)* का, केवल तभी जब यह दिखाया जा सके कि आक्षेपित के अधीन स्थापित प्रशासनिक न्यायाधिकरण

जहाँ तक उच्च न्यायालय का संबंध है, अधिनियम भी उतना ही प्रभावी है। सेवा मामलों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का संबंध है। इसलिए, हमें इस प्रश्न पर खुद को संबोधित करना चाहिए

क्या प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तहत स्थापित किया गया है

विवादित अधिनियम को समान रूप से प्रभावी माना जा सकता है और

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने में प्रभावी

संविधान। " रंगनाथ मिश्रा द्वारा दिए गए निर्णय से उद्धरण,

जे. *(*जैसा कि वे तब थे*)* को सबसे पहले पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

इसके नीचेः

"10. प्रस्तुत रिट आवेदनों में, मुख्य

इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के उन्मूलन को चुनौती दी गई थी

निर्दिष्ट सेवा विवादों के संबंध में अनुच्छेद *32* के तहत। को हटाने के खिलाफ भी चुनौती दी गई थी

अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता।

यह आगे बताया गया कि पीठों की स्थापना

इलाहाबाद, बैंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता में न्यायाधिकरण,

गुवाहाटी, मद्रास और नागपुर में प्रमुख सीट के साथ

दिल्ली अभी भी उन पक्षों के प्रति पूर्वाग्रह रखेगी जिनके मामले थे

संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष पहले से ही लंबित

इन स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित और जब तक कि

की प्रस्तुति के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय सुविधाओं का स्थान

आवेदनों और उनकी सुनवाई के लिए प्रदान किया गया था

पक्षकारों और उनके वकीलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। *31* अक्टूबर, *1985* को दिए गए अंतरिम आदेश में प्रावधान किया गया था

काम की कठिनाइयों का सामना करने के लिए। विद्वान महान्यायवादी

केंद्र सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया कि

कानून में संशोधन के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे ताकि बचत हो सके।

अनुच्छेद *32* के तहत अधिकार क्षेत्र, अन्य नाबालिगों को हटा दें

विसंगतियाँ और प्रत्येक उच्च न्यायालय की पीठ पर न्यायाधिकरण की एक पीठ की स्थापना। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा *(* संशोधन*)* अध्यादेश, *1986*, ये संशोधन थे -

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. का एक उपयुक्त अधिनियम लाया गया और अब तक।

संसद ने अध्यादेश को बदल दिया है। हमले के अधिकांश मूल आधार इस प्रकार जीवित नहीं रहते हैं और

विभिन्न पक्षों की ओर से पेश वकील द्वारा सुनवाई में जिन दलीलों का प्रचार किया गया था, वे ये हैंः

(1) न्यायिक समीक्षा एक मौलिक पहलू है

हमारे संविधान की बुनियादी संरचना और

अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता और *227* अधिनियम की धारा *28* में निहित के रूप में नहीं कर सकते हैं

न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय का विकल्प होने के कारण, इसका संविधान और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि

और विश्वासः *(3)* न्यायाधिकरण की पीठों की स्थापना न केवल प्रत्येक उच्च न्यायालय की पीठ पर की जानी चाहिए, बल्कि

हर उस स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए जहाँ उच्च

अदालतों में स्थायी पीठ होती हैं।

(4) जहाँ तक केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित या स्थापित किए जाने वाले न्यायाधिकरणों का संबंध है,

उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी या सदस्य अधीनस्थ न्यायपालिका और इसमें काम करने वाले कर्मचारी

इस तरह के प्रतिष्ठानों का अभ्यास

न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र इसमें हस्तक्षेप करेगा

नियंत्रण पूरी तरह से संबंधित उच्च में निहित

न्यायिक और अन्य के संबंध में न्यायालय

अनुच्छेद *235* के तहत अधीनस्थ अधिकारी संविधान।

11. मौखिक दलीलें समाप्त होने के बाद, विद्वान वकील

2 ((क) अधिनियम में उचित संशोधन किया जाएगा ताकि - ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v* के नियोजन में अधिकारियों और सेवकों को बाहर करना।

भारत का संघ *217*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ के सदस्य और कर्मचारी

अधिनियम के दायरे से न्यायपालिका। उसी में

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सरकार

न्यायाधिकरण की पीठों की बैठकों की व्यवस्था करेंगे

प्रत्येक उच्च न्यायालय की सीट या सीटों पर इस आधार पर कि *'* बैठकों में 'सर्किट बैठक*'* और उसका विवरण शामिल होगा।

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा तैयार किया जाएगा

अध्यक्ष चिंतित हैं।

12. विद्वान वकील द्वारा दी गई इन रियायतों के साथ

सामान्य तौर पर, केवल दो पहलुओं पर हमें विचार करना है,

अर्थात्, जो पहले और दूसरे द्वारा कवर किए गए हैं

विवाद। *13.* के निर्णय पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी

भगवती, जे. *(*हम में से एक वर्तमान में विद्वान प्रमुख हैं।

न्याय*)* मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ, *(1980) 3*

एस. सी. सी. *625,* जहाँ कहा गया थाः *(* एस. सी. सी पी. *678,* पैरा *87)*

*"*न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक अभिन्न अंग है -

हमारी संवैधानिक प्रणाली और इसके बिना, कानूनों की कोई सरकार नहीं होगी और कानून का शासन होगा एक चिढ़ाने वाला भ्रम और एक वादा बन जाता है

अवास्तविक। मेरा विचार है कि अगर कोई एक विशेषता है

हमारे संविधान का, जो किसी भी अन्य संविधान से अधिक है

रखरखाव के लिए बुनियादी और बुनियादी

लोकतंत्र और कानून का शासन, यह शक्ति है न्यायिक समीक्षा और यह निर्विवाद रूप से, मेरे विचार से,

संविधान की मूल संरचना का हिस्सा। बेशक, जब मैं यह कहता हूं तो मुझे ऐसा नहीं मानना चाहिए

सुझाव दें कि प्रभावी वैकल्पिक संस्थागत

न्यायिक समीक्षा के लिए तंत्र या व्यवस्थाएँ

संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि न्यायिक समीक्षा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है

हमारे संविधान और इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है

मूल संरचना को प्रभावित किए बिना

संविधान। यदि एक संवैधानिक संशोधन द्वारा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन ली जाती है और यह सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

बी.

बशर्ते कि द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की वैधता

विधायिका किसी भी आधार पर प्रश्न में बुलाए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, भले ही वह इसके बाहर हो।

विधायिका की विधायी क्षमता या है

किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, यह संविधान के विध्वंस से कम नहीं होगा, क्योंकि यह संघ और संघ के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का मजाक बनाएगा।

राज्य और मौलिक अधिकार प्रदान करना

अर्थहीन और व्यर्थ। तो भी अगर एक संवैधानिक संशोधन किया जाता है जिसका प्रभाव लेने का होता है

न्यायिक समीक्षा की शक्ति को हटा दें "।

स्थिति यह है कि हालांकि अनुच्छेद *323*-ए *(2) (डी)* अधिकृत अनुच्छेद *32* और मूल के तहत अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार

अधिनियम की धारा *28* में इसके लिए प्रावधान किया गया था, अनुच्छेद *32* के तहत अधिकार क्षेत्र में संशोधन द्वारा इसे अछूता छोड़ दिया गया है। द.

इस प्रकार अधिनियम दोनों अनुच्छेदों के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बचाता है।

32 मूल कार्यवाहियों के संबंध में और अनुच्छेद *136* के तहत भी निर्णयों के खिलाफ अपीलों पर विचार करने के लिए

विशेष अवकाश देने पर न्यायाधिकरण। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखा गया है।

15. हालाँकि, जो प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होता है

क्या अनुच्छेद *226* और *227* के तहत अधिकारिता का प्रतिबंध है

न्यायिक समीक्षा के प्रावधान को प्रभावित करता है। उच्च न्यायालय को उसके रिट अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने का अधिकार-इसके विपरीत

अनुच्छेद *32* मौलिक अधिकार नहीं है। फिर भी, साढ़े तीन दशकों के कार्य अनुभव के रूप में उच्च न्यायालयों ने न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया है। मौलिक और अन्य अधिकारों के संरक्षण के मामले में समीक्षा ने एक निश्चित और सकारात्मक भूमिका निभाई और

प्रशासनिक कार्रवाई को उचित नियंत्रण में रखना। में।

इन छत्तीस वर्षों के प्रवर्तन के बाद

संविधान, न केवल भारत की जनसंख्या अधिक आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.* रही है।

भारत का संघ *219*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

दुगुना हो गया है, लेकिन उच्च न्यायालयों सहित न्यायालयों के समक्ष मुकदमों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। के रूप में उच्च न्यायालयों में विचाराधीनता बढ़ गई और जल्द ही

बैकलॉग की दबाव वाली समस्या बन गई, देश की

इस पहलू पर ध्यान दिया गया। उच्च न्यायालयों को बोझ से मुक्त करने के तरीकों और साधनों ने केंद्र में सरकार का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया

विभिन्न राज्यों में भी। *1969* की शुरुआत में, एक समिति

केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था

इस न्यायालय के श्री न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता में

के लिए तरीके और साधन सुझाने वाली सिफारिशें

मामलों का प्रभावी, त्वरित और संतोषजनक निपटान

सरकारी कर्मचारियों के सेवा विवादों से संबंधित

यह पाया गया कि लंबित मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा इस श्रेणी से संबंधित है। समिति ने की सिफारिश

से निपटने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले।

जबकि यह रिपोर्ट अभी भी ध्यान आकर्षित कर रही थी

सरकार, प्रशासनिक सुधार आयोग भी स्थिति पर ध्यान दिया और अपीलों से निपटने के लिए सिविल सेवा न्यायाधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की

अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ सरकारी कर्मचारी। निश्चित रूप से इस प्रकार के राज्य, न्यायाधिकरण अस्तित्व में आए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने गौर किया

मामला आगे जब यह सामने आया कि सेवा मुकदमों का प्रमुख हिस्सा अनुशासनात्मक मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित है

कार्रवाई। मई *1976* में राज्यों के मुख्य सचिवों के एक सम्मेलन में इस समस्या पर चर्चा की गई। फिर चालीस आए

संविधान का दूसरा संशोधन अनुच्छेद *323*-ए लाता है जो संसद को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या परीक्षण के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है।

भर्ती के संबंध में विवाद और शिकायतें और

जनता के लिए नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें

के मामलों के संबंध में सेवाएं और पद

संघ का या किसी राज्य का या भारत के क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण का

भारत का या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी निगम का।

सरकार "। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस अनुच्छेद में सभी न्यायालयों की अधिकारिता के बहिष्करण की परिकल्पना की गई है, सिवाय इसके कि -

खंड *(1)* में निर्दिष्ट विवादों या शिकायतों के संबंध में अनुच्छेद *136* के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता। हालांकि संविधान में अब सक्षम करने वाला शामिल था

बिजली, किसी भी स्थापित करने के लिए कोई तत्काल कदम नहीं उठाए गए थे न्यायाधिकरण जैसा कि अनुच्छेद *323*-ए द्वारा विचार किया गया है। एक संविधान

के. के. दत्ता बनाम मामले में इस न्यायालय की पीठ। भारत संघ, *(1980)*

4 एस. सी. सी. *38* ने कहाः *[* एस. सी. सी पी. *39* , पैरा *1:* एससीसी *(*एल एंड एस*)* पी। *486]*

"विवादों के अलावा कुछ अन्य मुकदमेबाजी के क्षेत्र हैं

विभिन्न सेवाओं के सदस्यों के बीच,

जहाँ सार्वजनिक नीति के सिद्धांत की आवश्यकता है कि

सभी मुकदमों का अंत होना चाहिए जो अधिक से अधिक के साथ लागू हो सकता है

बल देते हैं। लोक सेवकों को अपने समय और शक्ति को नष्ट करने के लिए प्रेरित या मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

अदालती लड़ाई। इस प्रकार उनका ध्यान है

सार्वजनिक से निजी मामलों और उनके अंतर की ओर मोड़ दिया गया

विवाद उनकी एकता की भावना को प्रभावित करते हैं जिसके बिना कोई भी संस्था प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती है। द.

राज्य द्वारा सेवा न्यायाधिकरणों का गठन केंद्र में एक शीर्ष न्यायाधिकरण वाली सरकारें,

जो मामलों की व्यापकता में अंतिम होना चाहिए शर्तों से संबंधित विवादों का मध्यस्थ

ऐसे न्यायाधिकरणों की कार्यवाहियों में योग्यता हो सकती है अनौपचारिकता और यदि उन्हें सख्त नियमों से नहीं बांधा जाएगा

साक्ष्य के नियम, वे ऐसे समाधान तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं जो कई लोगों को संतुष्ट करेंगे।

इस बीच मामलों के बैकलॉग की समस्या

उच्च न्यायालय अधिक कठोर और दबावपूर्ण हो गए और संसद में और संसद में आगे चर्चा की जाने लगी।

सम्मेलन और सेमिनार। अंततः जनवरी *1985* में,

संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को मद्रास बार एसोसिएशन *v* के साथ पारित किया।

भारत का संघ *221*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

27 फरवरी, *1985* को राष्ट्रपति की मंजूरी, कानून

लंबे समय से प्रतीक्षित न्यायाधिकरण के गठन को सक्षम बनाना अस्तित्व में आया। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को लागू होने के लिए अधिसूचित किया है

1 नवंबर, *1985*।

16. उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन

सेवा संबंधी मामलों और इसकी औचित्य के साथ-साथ वैधता भी इस प्रकार है

ऊपर दर्शाई गई पृष्ठभूमि में जांच की जानी चाहिए। हम.

पहले ही देख चुके हैं कि इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा बाकी है

पूरी तरह से अप्रभावित और इस प्रकार एक ऐसा मंच है जहां मामले हैं

महत्व और गंभीर अन्याय लाया जा सकता है निर्धारण या सुधार। अतः अपवर्जन

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है। मिनर्वा मिल्स के मामले *(*ऊपर*)* में इस अदालत ने इशारा किया

कि "प्रभावी वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या

न्यायिक समीक्षा के लिए व्यवस्था "द्वारा की जा सकती है

संसद। इस प्रकार एक विकल्प स्थापित करना संभव है।

न्यायिक समीक्षा प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय के स्थान पर संस्था। राहत के तरीके और साधनों की खोज के लिए लगभग दो दशकों में बहस और विचार-विमर्श हुए।

उच्च न्यायालयों को मामलों के बैकलॉग के भार का और ब्याज में सेवा विवादों के त्वरित निपटान का आश्वासन देने के लिए

लोक सेवकों के साथ-साथ देश को भी खोया नहीं जा सकता है

इस पहलू पर विचार करते समय देखें। ऐसा नहीं हुआ है।

हमारे सामने विवाद हुआ-और शायद नहीं हो सकता था -

कि अधिनियम की योजना के तहत न्यायाधिकरण लेगा

मौजूदा बैकलॉग के एक हिस्से और इसके एक हिस्से पर

उच्च न्यायालयों का सामान्य भार। न्यायाधिकरण को न्याय प्रशासन की योजना में उच्च न्यायालय के पूरक के रूप में नहीं बल्कि एक विकल्प के रूप में माना गया है।

न्यायाधिकरण को एक अतिरिक्त मंच के रूप में प्रदान करना जहाँ से पक्षकार उच्च न्यायालय जा सकते हैं निश्चित रूप से होगा

जिस स्थिति और परिस्थितियों से निपटने के लिए नवाचार किया गया है, उस पर विचार करते हुए यह एक प्रतिगामी कदम है लाया गया। इस प्रकार उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर प्रतिबंध

न्यायालय वास्तव में हमले का एक वैध आधार नहीं हो सकता है।

2 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 10 एस. सी. आर.

17. हालाँकि, जो बात ध्यान में रखी जानी चाहिए वह यह है कि

न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालय का वास्तविक विकल्प होना चाहिए-न केवल रूप और न्यायिक रूप में बल्कि सामग्री और वास्तविक रूप में भी। जैसा कि मिनर्वा के मिल्स मामले (ऊपर) में बताया गया था,

वैकल्पिक व्यवस्था को प्रभावी और कुशल होने के साथ-साथ संवैधानिक सीमाओं को बनाए रखने में भी सक्षम होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 16 समानता की गारंटी देता है -

सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

जाति, लिंग या जन्म स्थान। अनुच्छेद 14 में निहित समानता का स्पर्श-पत्थर सबसे बड़ी गारंटी है

इस देश में एक सेवा न्यायशास्त्र पहले ही विकसित हो चुका है। अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत सभी शक्तियां मामलों के संबंध में इस न्यायालय के न्यायालयों को छोड़कर

न्यायाधिकरण में निहित उसमें विनिर्दिष्ट-या तो केंद्रीय या

राज्य। इस प्रकार न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय का स्थानापन्न है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार है।

18. उच्च न्यायालय एक सदी से अधिक समय से काम कर रहे हैं।

और एक चौथाई और संघीय न्यायालय की स्थापना होने तक भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत,

अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उच्चतम न्यायालय

एक सीमित श्रेणी में प्रिवी काउंसिल को अपील करने के लिए

मामले। लगभग छह वर्षों की इस लंबी अवधि में, उच्च न्यायालयों ने अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से, कुशलता से निभाया है। संतोषजनक भी। इस देश में वादी अनुभवी है

स्वयं उच्च न्यायालय को असफल के रूप में देखने के लिए

अपने व्यक्ति, संपत्ति और सम्मान का रक्षक। संस्था

अपने उद्देश्य को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है और आम आदमी ने

इस प्रकार आप उसमें बहुत विश्वास रखते हैं। अनुशासित, स्वतंत्र और प्रशिक्षित न्यायाधीश कानून में अच्छी तरह से पारंगत हैं और एक असंबद्ध और उद्देश्यपूर्ण तरीके से सभी खुलेपन के साथ काम करते हैं। जिस तरह से वर्षों से न्याय का वितरण सुनिश्चित किया गया है। पीड़ित लोग अदालत का रुख करते हैं-सामाजिक

मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए तंत्र-कानूनी दायित्व के तहत नहीं

लेकिन इस विश्वास और विश्वास के तहत कि मद्रास बार एसोसिएशन के साथ न्याय किया जाएगा।

भारत का संघ 223

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उन्हें और राज्य के अधिकारी लागू करेंगे

न्यायालय का निर्णय। इसलिए यह सर्वोपरि है।

यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्थापन संस्थान-न्यायाधिकरण-सभी मामलों में उच्च न्यायालय का एक योग्य उत्तराधिकारी होना चाहिए।

सम्मान करते हैं। यह न्यायालय ठीक यही बताना चाहता था जब उसने मिनर्वा में एक वैकल्पिक तंत्र की बात की थी

मिल्स का मामला। (ऊपर) "।

60. दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया जा सकता है।

एल. चंद्र कुमार बनाम में इस न्यायालय द्वारा। भारत संघ, (1997) 3

एससीसी 261। तत्काल निर्णय एक संविधान द्वारा दिया गया था

7 न्यायाधीशों की पीठ। वह सवाल जो दृढ़ संकल्प के लिए उठा था

तत्काल निर्णय में यह था कि क्या संसद और राज्य विधानसभाओं को अनुच्छेदों के माध्यम से शक्ति प्रदान की गई है

323 ए (2) (डी) और 323 बी (3) (डी) पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र को छोड़कर

"संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों ने संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन किया। दूसरे शब्दों में, सवाल यह था कि क्या रद्द करना/वापस लेना

उच्च न्यायालयों (संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत) और सर्वोच्च न्यायालय (संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) को प्रदत्त "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति का उल्लंघन था -

संविधान की "मूल संरचना"। इसके अलावा, क्या संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत गठित न्यायाधिकरणों के पास वैधानिक प्रावधानों/नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता है? और यह भी कि क्या न्यायाधिकरण

संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत गठित

निहित क्षेत्राधिकार के प्रभावी विकल्प कहा जा सकता है

उच्च न्यायालयों में? और यदि नहीं, तो किन परिवर्तनों की आवश्यकता थी?

उपरोक्त विवाद को संविधान के पास भेजा गया

पीठ ने एल. चंद्र कुमार बनाम मामले में पारित आदेश को आगे बढ़ाया। भारत संघ, *(1995) 1* एस. सी. सी. *400*, एस. पी. संपत कुमार के बाद के मामलों *(*उपरोक्त*)* में दिए गए निर्णयों के कारण,

अर्थात् जे. बी. चोपड़ा बनाम भारत संघ *(1987) 1* एस. सी. सी. *422*, एम. बी.

मजूमदार बनाम। भारत संघ, *(1990) 4* एस. सी. सी. *501*, अमूल्य चंद्र कलीता बनाम। भारत संघ, *(1991) 1* एस. सी. सी. *181*, आर. के. जैन

वी. भारत संघ, *(1993) 4* एस. सी. सी. *119*, और डॉ. महाबल राम बनाम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद *(1994) 2* एस. सी. सी. *410*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर *[2014] 10* एस. सी. आर.

ना.

वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक मुद्दे, यह

यू. आर. टी. निम्नानुसार देखा गयाः

"76. इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए कि क्या शक्ति

उच्च न्यायालयों में निहित न्यायिक समीक्षा और

सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद *226/227* और *32* के तहत संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, हमें पहले प्रयास करना चाहिए यह समझने के लिए कि मूल संरचना क्या है

संविधान। बुनियादी संरचना का सिद्धांत विकसित किया गया था

केशवानंद भारती मामले में, *(1973) 4* एस. सी. सी. *225*। हालाँकि, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, वह मामला तय नहीं था

कि उस में उल्लिखित विशिष्ट और विशेष विशेषताएं केवल निर्णय ही हमारी मूल संरचना का गठन करेगा।

संविधान। वास्तव में, शेलत और ग्रोवर के निर्णयों में,

जे जे। , हेगड़े और मुखर्जी, जेजे। और जगमोहन रेड्डी, जे., इस प्रभाव के लिए विशिष्ट अवलोकन हैं कि उनके

मूल संरचना सहित आवश्यक विशेषताओं की सूची

संविधान उदाहरणात्मक है और इसका उद्देश्य संपूर्ण होना नहीं है। इंदिरा गांधी के मामले में, *1975* सप. एस. सी. सी. *1*, जे. चंद्रचूड़ ने अभिनिर्धारित किया कि एक न्यायाधीश के लिए उचित दृष्टिकोण जिसका सामना इस प्रश्न से किया जाता है कि क्या कोई विशेष

संविधान का पहलू मूल संरचना का हिस्सा है, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, हमारे संविधान की योजना में विशेष विशेषता के स्थान, इसके उद्देश्य की जांच करें और

उद्देश्य, और इस पर इसके इनकार के परिणाम एक मौलिक साधन के रूप में हमारे संविधान की अखंडता

देश का शासन। *(* पी. पी. पर ऊपर। *751-752) .* यह

विधि विशेष रूप से भगवती, जे. इन द्वारा अपनाई गई थी। मिनर्वा मिल्स मामला, *(1980) 3* एस. सी. सी. *625, (*पीपी. *671-672)* और इस क्षेत्र में निश्चित परीक्षण के रूप में नहीं माना जाता है

संवैधानिक कानून।

इस न्यायालय की विभिन्न पीठों के निर्णयों द्वारा जिन्हें हमारे विश्लेषण के दौरान संदर्भित किया गया है। हुनकासँ निष्कर्ष, जिनमें से कई हमारे द्वारा पूरी तरह से निकाले गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने हमेशा आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v* पर विचार किया है।

भारत संघ *225*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

उच्च न्यायालयों में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति और

इस न्यायालय ने क्रमशः अनुच्छेद *226* और *32* के तहत,

उपराज्यपाल की जांच के अधीन विधायी कार्रवाई

अदालतें, हमारी संवैधानिक योजना का अभिन्न अंग हों। जबकि कई निर्णयों ने इस पहलू का विशिष्ट संदर्भ दिया है *[*गजेंद्रगढ़कर, सी. जे. केशव सिंह मामले में, ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *745,* जे. बेग, और खन्ना, जे. केशवानंद में।

भारती मामला *(*ऊपर*),* चंद्रचूड़, सी. जे. और भगवती, जे. मिनर्वा मिल्स *(*ऊपर*),* चंद्रचूड़, सी. जे. उर्वरक कामगर में, *(1981) 1* एस. सी. सी. *568,* के. एन. सिंह, जे. दिल्ली में

न्यायिक सेवा एसोसिएशन। , *(1991) 4* एस. सी. सी. *406]* बाकी ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए सामान्य टिप्पणियां की हैं।

यह विशेषता।

78. न्यायालयों की शक्ति की वैधता

संवैधानिक लोकतंत्रों ने विधायी कार्रवाई की समीक्षा की है

जिस समय से इसकी पहली कल्पना की गई थी, तब से पूछताछ की जा रही है। द.

भारत का संविधान, इस तरह की आलोचनाओं के लिए जीवित है,

उच्च न्यायपालिका को ऐसी शक्ति प्रदान करते हुए, महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया। हमारे संविधान के निर्माताओं के तरीके का विश्लेषण

न्यायपालिका से संबंधित निगमित प्रावधानों से संकेत मिलता है कि वे सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित थे।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किए गए थे कि न्यायपालिका सक्षम होगी

न्यायिक समीक्षा की अपनी व्यापक शक्तियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करना।

जबकि संविधान इसे निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय पर कानून, यह भी

कार्यकाल से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल हैं,

न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति की आयु के साथ-साथ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन के लिए तंत्र। इस तरह के विस्तृत प्रावधानों को शामिल करना प्रतीत होता है

प्रावधानों के अनुसार, उच्च न्यायालयों को किसी भी मामले से अलग किया जाएगा उनके निर्णय लेने में हस्तक्षेप करने के लिए कार्यकारी या विधायी प्रयास। वरिष्ठ के न्यायाधीश

अदालतों को संविधान को बनाए रखने का काम सौंपा गया है और इसके लिए उन्हें *6* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. से सम्मानित किया गया है।

इसकी व्याख्या करने की शक्ति। यह उन्हें ही सुनिश्चित करना है कि

संविधान द्वारा परिकल्पित शक्ति संतुलन है -

यह बनाए रखा और कि विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों के निर्वहन में उल्लंघन नहीं करते हैं संवैधानिक सीमाएँ। समान रूप से देखरेख करना भी उनका कर्तव्य है।

कि अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का संचालन करने वालों द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय कानूनी शुद्धता और न्यायिक स्वतंत्रता के सख्त मानकों के खिलाफ नहीं हैं।

संवैधानिक सुरक्षा उपाय जो सुनिश्चित करते हैं

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध नहीं है या

उन लोगों के लिए जो साधारण द्वारा बनाए गए न्यायाधिकरणों का संचालन करते हैं

कानून। नतीजतन, बाद की श्रेणी के न्यायाधीश

के कार्य के निर्वहन में उच्च न्यायपालिका के लिए कभी भी पूर्ण और प्रभावी विकल्प नहीं माना जा सकता है

संवैधानिक व्याख्या। इसलिए हम मानते हैं कि

विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित

अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत इस न्यायालय में एक अभिन्न और आवश्यक है।

संविधान की विशेषता, जो इसकी मूल संरचना का हिस्सा है। सामान्यतः, इसलिए, उच्च न्यायालयों की शक्ति

और विधानों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को कभी भी अपदस्थ या बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है।

79. हम यह भी मानते हैं कि शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है

के निर्णयों पर न्यायिक अधीक्षण का प्रयोग करना

अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों यह संविधान की मूल संरचना का भी हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति है जहां उच्च न्यायालयों को अलग कर दिया जाता है

के अलावा अन्य सभी न्यायिक कार्यों का

संवैधानिक व्याख्या से भी उतना ही बचना चाहिए।

XXX

XXX

96. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि इन न्यायाधिकरणों के अक्षम रूप से काम करने का एक कारण यह है कि

क्योंकि पर्यवेक्षण के लिए कोई प्राधिकरण नहीं है और

अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके लिए यह

सुझाव दिया कि न्यायाधिकरणों को जादरस बार एसोसिएशन *v* के अधीन बनाया जाए।

भारत का संघ *227*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

उच्च न्यायालयों की पर्यवेक्षी अधिकारिता जिनके भीतर

वे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, हमारा मानना है कि यह समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। हमें नहीं लगता कि हमारी संवैधानिक योजना के लिए यह आवश्यक है कि

सभी न्यायिक निकाय जो क्षेत्रीय निकायों के अंतर्गत आते हैं

उच्च न्यायालयों की अधिकारिता उनके पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अधीन होनी चाहिए। अगर विचार उच्च को अलग करने का है

उनके भारी बोझ की अदालतें, फिर उनके बोझ में वृद्धि

पर्यवेक्षी कार्य किसी भी तरह से नहीं हो सकते हैं

उनकी सहायता करें। वर्तमान में स्थिति अलग है।

विभिन्न अधिनियमों के तहत गठित न्यायाधिकरण हैं -

विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रशासित

केंद्र और राज्य सरकारें। यह समस्या इस तथ्य से और बढ़ गई है कि कुछ न्यायाधिकरणों ने

केंद्रीय विधानों के अनुसार बनाए गए हैं और कुछ अन्य राज्य विधानों द्वारा बनाए गए हैं। हालांकि,

संसद द्वारा बनाए गए न्यायाधिकरणों के मामले में

कानून, प्रशासन में कोई एकरूपता नहीं है। हम हैं। इस दृष्टिकोण से कि जब तक ऐसे सभी न्यायाधिकरणों के प्रशासन के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना नहीं की जा सकती है, तब तक

वांछनीय है कि ऐसे सभी न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, एक एकल नोडल मंत्रालय के तहत होने चाहिए जो इन न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख करने की स्थिति में होगा। ए के लिए

मंत्रालय को उचित रूप से होने वाले कारणों की संख्या

कानून मंत्रालय। यह मंत्रालय के लिए खुला रहेगा। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी निकाय नियुक्त करने के लिए

न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख करना। इससे यह सुनिश्चित होगा कि

यदि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष कुछ लोगों के लिए है

के काम में पर्याप्त रुचि लेने में असमर्थ होने का कारण

न्यायाधिकरण, पूरी प्रणाली सुस्त नहीं होगी और

न्याय के अंतिम उपभोक्ता को नुकसान नहीं होगा। की रचना एक एकल छत्र संगठन, हमारे विचार में, वर्तमान प्रणाली की कई बुराइयों को दूर करेगा। जरूरत पड़ने पर,

अलग-अलग छत्र संगठन हो सकते हैं

केंद्रीय और राज्य स्तर पर। ऐसा पर्यवेक्षी प्राधिकरण

यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसे सभी न्यायाधिकरणों के सदस्यों की स्वतंत्रता बनी रहे।

इस हद तक, *3* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

सदस्यों के चयन की प्रक्रिया

न्यायाधिकरणों, न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए धन आवंटित करने का तरीका और अन्य सभी परिणामी विवरणों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना होगा।

97. जिनके संबंध में हमने सुझाव दिए हैं

न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों और उनके प्रशासनिक कार्यों के पर्यवेक्षण पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है

जिन्हें इस संबंध में नीति तैयार करने का कर्तव्य सौंपा गया है। उस निकाय को भी ध्यान में रखना होगा

इस संबंध में एल. सी. आई. और मलिमथ समिति जैसे विशेषज्ञ निकायों की टिप्पणियां। इसलिए हम,

अनुशंसा करें कि भारत संघ इस मामले में कार्रवाई शुरू करे

सभी संबंधितों की ओर से और उनसे परामर्श करने के बाद, इन सभी न्यायाधिकरणों को एक ही नोडल विभाग के तहत रखें, अधिमानतः

कानूनी विभाग।

98. चूंकि हमने संवैधानिक मुद्दे का विश्लेषण किया है अधिनियम की धारा *5 (6)* की वैधता, अब हम कर सकते हैं

इस पहलू पर हमारी राय व्यक्त करें। यद्यपि उनके अधिकार

डॉ. महाबल राम में इस प्रावधान पर कोई सवाल नहीं था।

मामला, *(1994) 2* एस. सी. सी. *401*, हम मानते हैं कि दृष्टिकोण

उस मामले में अपनाया गया, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस फैसले के पहले भाग में निकाला गया है, सही है क्योंकि यह सामंजस्यपूर्ण तरीके से हल करता है

धारा *5 (2)* और *5 (6)* एक साथ काम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि

यह स्पष्ट करें कि जहाँ एक प्रश्न शामिल है

संविधान के संबंध में किसी वैधानिक प्रावधान या नियम की व्याख्या प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एकल सदस्य पीठ के विचार के लिए उत्पन्न होती है,

धारा *5 (6)* स्वतः लागू हो जाएगी और सभापति

या संबंधित सदस्य इस मामले को कम से कम दो सदस्यों वाली पीठ को भेजेगा, जिनमें से एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वैधानिक प्रावधान या नियम की शक्तियों से जुड़े प्रश्न कभी भी एकल सदस्य पीठ या किसी ऐसी पीठ के समक्ष निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं होंगे जिसमें कोई न्यायिक सदस्य न हो। तो।

इसका अर्थ यह है कि धारा *5 (6)* अब मद्रास बार एसोसिएशन *v* के प्रति अतिसंवेदनशील नहीं रहेगी।

भारत संघ *229*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

99. हमारे द्वारा अपनाए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि अनुच्छेद *323*-ए के खंड *2* (डी) और अनुच्छेद *323* बी के खंड *3* (डी), इस हद तक कि वे उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाहर करते हैं।

अनुच्छेद *226/227* के तहत न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और

32 संविधान असंवैधानिक है। की धारा *28* अधिनियम और अनुच्छेद *323*-क के तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी विधानों में "अधिकारिता का अपवर्जन" खंड और

323 - बी, उसी हद तक, असंवैधानिक होगा। द.

अनुच्छेदों के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र

226/227 और के अनुच्छेद *32* के तहत सर्वोच्च न्यायालय पर

संविधान अलंघनीय बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है

हमारा संविधान। जबकि इस अधिकार क्षेत्र को हटाया नहीं जा सकता है, अन्य न्यायालय और न्यायाधिकरण एक पूरक भूमिका निभा सकते हैं।

अनुच्छेद *226/227* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करने में

और संविधान के *32.* के तहत बनाए गए न्यायाधिकरण

संविधान के अनुच्छेद *323*-ए और अनुच्छेद *323*-बी हैं -

संवैधानिक परीक्षण करने की क्षमता रखने वाले

वैधानिक प्रावधानों और नियमों की वैधता। सभी निर्णय हालाँकि, ये न्यायाधिकरण पहले जांच के अधीन होंगे।

उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ जिसके अधिकार क्षेत्र में

संबंधित न्यायाधिकरण गिरता है। न्यायाधिकरण करेंगे,

फिर भी, पहली बार की अदालतों की तरह काम करना जारी रखें

कानून के उन क्षेत्रों का सम्मान जिनके लिए वे किए गए हैं

सीधे उच्च न्यायालयों से संपर्क करें, उन मामलों में भी जहां वे वैधानिक विधानों के अधिकारों पर सवाल उठाते हैं (सिवाय इसके कि कहाँ

वह विधान जो विशेष न्यायाधिकरण का निर्माण करता है

चुनौती दी गई) न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की अनदेखी करके

चिंतित हैं। अधिनियम की धारा *5 (6)* वैध है और

संवैधानिक है और हम तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए

संकेत दिया है "।

61. इसके बाद भारत संघ v का संदर्भ दिया गया। मद्रास

एसोसिएशन, (2010) 11 एस. सी. सी. 1. तत्काल निर्णय 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया था। विवाद

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 10 एस. सी. आर. को चुनौती देने से संबंधित इस मामले में उनका परीक्षण किया गया।

230

कंपनी अधिनियम के भाग 1 बी और 1 सी की संवैधानिक वैधता,

1956. इन भागों को कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा कंपनी अधिनियम में शामिल किया गया था। इस प्रकार, राष्ट्रीय संविधान के लिए प्रावधान किया गया था

कंपनी विधि न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि

अपीलीय न्यायाधिकरण। वर्तमान विवाद में उठाए गए प्रासंगिक प्रश्नों पर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले, क्या संसद ऐसा करती है

अधिकार क्षेत्र/विधायी क्षमता नहीं है, आंतरिक निहित करने के लिए

न्यायिक कार्य, जो पारंपरिक रूप से उच्च न्यायालय द्वारा किए गए हैं

न्यायपालिका के बाहर किसी भी न्यायाधिकरण में? दूसरा, क्या

अब तक पूरे कंपनी कानून क्षेत्राधिकार का हस्तांतरण

उच्च न्यायालयों में निहित होने से पहले, राष्ट्रीय कंपनी कानून के लिए

न्यायाधिकरण, जो न्यायपालिका के नियंत्रण में नहीं था, "शक्तियों के पृथक्करण" के सिद्धांतों का उल्लंघन था और

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता "? तीसरा, क्या धारा 10-एफ. बी. 10 - कंपनी अधिनियम के भाग I-B और 1-C में निहित FD, 10-FE, 10-FF, 10-FL (2), 10-FO, 10-FR (3), 10-FT, 10 FX

उपरोक्त संशोधन के कारण, "कानून के शासन", "के सिद्धांतों का उल्लंघन करना असंवैधानिक था

शक्तियाँ "और" न्यायपालिका की स्वतंत्रता "? इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए प्रासंगिक कथन और निष्कर्षों को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

इसके नीचेः

"धारा 10-एफ. डी. (3) (एफ): तकनीकी सदस्य की नियुक्ति

एनसीएलटी

16. उच्च न्यायालय ने माना है कि एक की नियुक्ति

धारा *10* में निर्दिष्ट श्रेणी के तहत सदस्य

एफ. डी. *(3) (*एफ*)* की भूमिका केवल पुनरुद्धार से संबंधित मामलों में हो सकती है।

और बीमार औद्योगिक कंपनियों का पुनर्वास और न कि

अन्य मामलों के संबंध में। इसलिए उच्च न्यायालय ने

वस्तुतः संकेत दिया कि एन. सी. एल. टी. के दो प्रभाग होने चाहिए, कि

एक न्यायनिर्णयन प्रभाग और एक पुनर्वास प्रभाग है और निर्दिष्ट श्रेणी के तहत चुने गए व्यक्ति

खंड *()* को केवल सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए

पुनर्वास प्रभाग।

17. केंद्र सरकार का तर्क है कि इसी तरह का प्रावधान ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

भारत का संघ-*232*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

(विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985;* कि प्रावधान केवल एक सक्षम करने वाला ताकि सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन किया जा सके

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में चयन समिति

भारत या उसके मनोनीत व्यक्ति*;* और यह सलाह नहीं दी जा सकती है कि

की शक्ति पर विभाजन या सीमा या प्रतिबंध है

न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को उचित गठन करने के लिए

बेंच। यह भी बताया गया है कि एक तकनीकी सदस्य

हमेशा एक न्यायिक सदस्य के साथ एक पीठ में बैठेंगे।

तीन से पांच साल का अनुभव होना चाहिए निर्धारित किया गया है कि श्रम कानूनों में उनके विशेषज्ञ ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए।

19. केंद्र सरकार प्रस्तुत करती है कि यह हो सकता है

सबसे अधिक चयन का विकल्प छोड़ने की सलाह दी जाती है।

की अध्यक्षता वाली समिति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत।

20. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि व्यक्तियों के रूप में

जो धारा *10* में निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं

प्रावधान किया जाना चाहिए कि इसके साथ एक "न्यायिक सदस्य" योग्यता विशेष पीठ का सदस्य होगा।

से संबंधित मामलों के लिए धारा *10*-एफएल *(2)* में निर्दिष्ट

कंपनियों का पुनर्वास, पुनर्गठन या समापन।

21. केंद्र सरकार ने इन्हें स्वीकार नहीं किया है

निष्कर्ष निकालते हैं और तर्क देते हैं कि उच्च के अवलोकन

न्यायालय न्यायिक विधान के बराबर होगा।

2 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

धारा *10*-एफडी *(3) (एच):* तकनीकी सदस्य की योग्यता एनसीएलटी

22. उच्च न्यायालय ने कहा है कि खंड *(एच)* का उल्लेख करते हुए

विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की श्रेणी के लिए

और श्रम से संबंधित मामलों में अनुभव, कम के लिए नहीं

15 वर्ष से अधिक का समय अस्पष्ट है और इसमें उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

ताकि निश्चित रूप से योग्यता का वर्णन किया जा सके जो ए

खंड *(एच)* के तहत नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास होना चाहिए।

23. केंद्र सरकार का तर्क है कि व्यापक रूप से

और श्रम मामलों में संभव विविध अनुभव, अनुभव की प्रकृति को निर्धारित करना उचित नहीं हो सकता है या

की प्रकृति के संबंध में कोई प्रतिबंध लागू करें

अनुभव। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चयन समिति

भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में

खंड *(ज)* में उल्लिखित श्रेणी के तहत चयनित सदस्य को अपनी भागीदारी केवल पीठों तक ही सीमित रखनी चाहिए। बीमार कंपनियों के पुनरुद्धार और पुनर्वास से निपटना और उन्हें एकल कंपनी के रूप में काम करने से भी बाहर रखा जाना चाहिए।

किसी भी मामले के लिए सदस्य पीठ।

25. केंद्र सरकार का तर्क है कि यह नहीं हो सकता है

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को बाधित करने की सलाह दी जाती है

न्यायाधिकरण उपलब्ध सदस्यों का उपयोग करके पीठों का गठन करेगा। यह भी बताया गया है कि यह मान लेना उचित नहीं हो सकता है कि श्रम मामलों में अच्छी तरह से पारंगत व्यक्ति ऐसा करेगा।

समापन मामलों के निर्णय के संबंध में न्यायिक सदस्य के साथ जुड़े रहने के लिए अनुपयुक्त होना।

xXXXX

XXX

XXX

धारा *10*-एफएक्सः अध्यक्ष के लिए चयन प्रक्रिया / अध्यक्ष

31. उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत का संघ *233*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

अध्यक्ष/अध्यक्ष का चयन एक द्वारा किया जाना चाहिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति

उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ परामर्श।

32. केंद्र सरकार ने कहा है कि यह नहीं होगा

इस संबंध में ऐसा प्रावधान करने की सलाह दी जाए कि वैधानिक के अध्यक्ष/अध्यक्ष की नियुक्ति

न्यायाधिकरण। यह बताया गया है कि कोई अन्य कानून नहीं

न्यायाधिकरणों के गठन में ऐसा प्रावधान है। निकाले गए प्रावधानों को चुनौती देने के लिए

इसके ऊपर, भारत संघ ने जोर देकर कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय *(*जिसके निर्णय को भी चुनौती दी गई थी*)* ने यह अभिनिर्धारित किया था कि संसद के पास क्षमता और शक्ति थी -

रिट याचिका। भारत संघ के हाथों दावा यह था कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में निहित कुछ निर्देशों ने भागों को फिर से तैयार और पुनर्गठित किया

1 बी और *1* सी को संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया और यह *"*न्यायिक समीक्षा*"* को न्यायिक विधान में परिवर्तित करने के बराबर था। यह था,

हालाँकि, यह देखा गया कि भारत संघ उच्च न्यायालय द्वारा इंगित कई दोषों को सुधारने के लिए सहमत हो गया है, अपील

भारत संघ का उच्च के निष्कर्षों तक ही सीमित था

धारा *10*-एफ. डी. *(3) (*एफ*), (*जी*), (*एच*)* और *10*-एफ. एक्स. से संबंधित न्यायालय। को।

उस मुद्दे के सार को समझें जो विषय था

कंपनी अधिनियम, *1956* के अनुसार कंपनियों द्वारा संशोधित *(* संविधान से संबंधित दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2002*

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी

विधि अपीलीय न्यायाधिकरण*)*। इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"भाग *I-B*

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण

10 - एफ. बी. राष्ट्रीय कंपनी कानून का गठन

न्यायाधिकरण। - केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

आधिकारिक राजपत्र में, एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाता है और

ऐसी शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करना जो हैं, या हो सकते हैं - इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया

बल में समय।

10 - एफ. सी. न्यायाधिकरण की संरचना। - न्यायाधिकरण करेगा

एक राष्ट्रपति और इतनी संख्या में न्यायिक और

तकनीकी सदस्य जो केन्द्र के रूप में बासठ से अधिक न हों।

सरकार उचित समझती है, जिसके द्वारा नियुक्त किया जाए सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा।

योग्यताएँ

के लिए

10 - एफ. डी.

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। - *(1)* द सेंट्रल

सरकार एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करेगी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या होने के योग्य हो। न्यायाधिकरण का।

(2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह

(क*)* कम से कम पंद्रह वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो। भारत के क्षेत्र में कार्यालय*;* या

(ख*)* कम से कम दस वर्षों से अधिवक्ता रहा है

उच्च न्यायालय*,* या आंशिक रूप से न्यायिक पद धारण किया है और

कुल के लिए एक वकील के रूप में आंशिक रूप से व्यवहार में रहा है

पंद्रह वर्ष की अवधि*;* या

(ग*)* कम से कम पंद्रह वर्षों तक समूह ए का पद धारण किया हो। या केंद्र सरकार के तहत एक समकक्ष पद

या कम से कम तीन सहित एक राज्य सरकार

भारतीय सदस्य के रूप में सेवा के वर्ष

वरिष्ठ में कंपनी विधि सेवा *(*कानूनी शाखा*)*

उस सेवा में प्रशासनिक श्रेणी*;* या

(घ*)* कम से कम पंद्रह वर्षों तक समूह ए का पद धारण किया हो।

या केंद्र सरकार के तहत एक समकक्ष पद *(* ए*.* डी*.* आर*.* ए*.* एस*.* बार एसोसिएशन के रूप में कम से कम तीन साल की सेवा सहित।

भारत का संघ *235*

[जगदीश सिंह खेहर*,* जे।*]*

ग्रेड *I* में भारतीय कानूनी सेवा के सदस्य

वह सेवा*)*।

तकनीकी सदस्य जब तक कि वह *(* क*)* कम से कम पंद्रह वर्षों तक समूह क का पद धारण किया हो या

केंद्र सरकार या किसी राज्य के अधीन समकक्ष पद सरकार *[*कम से कम तीन साल की सेवा सहित*]*

भारतीय कंपनी विधि सेवा के सदस्य *(*लेखा*)* शाखा*)* उस सेवा में वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में*]* या

*((*ख*)* सरकार का संयुक्त सचिव है या रहा है।

केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत भारत का, या किसी भी आयोजित केंद्र सरकार या किसी राज्य के अधीन अन्य पद

सरकार वेतन का एक पैमाना वहन करती है जो इससे कम नहीं है

भारत सरकार के एक संयुक्त सचिव के लिए

कंपनी कानून से संबंधित समस्याओं से निपटने का अनुभव; या *(* ग*)* कम से कम पंद्रह वर्षों से व्यवहार में है या रहा है

सनदी लेखाकारों के अधीन एक सनदी लेखाकार

अधिनियम, *1949 (1949* का *38);* या

(घ*)* कम से कम पंद्रह वर्षों से व्यवहार में है या रहा है

लागत और कार्य लेखाकार के तहत एक लागत लेखाकार

अधिनियम, *1959 (1959* का *23);* या *(* ई*)* कम से कम पंद्रह वर्षों से काम कर रहा है या कर रहा है।

पूर्णकालिक अभ्यास में सचिव के रूप में अनुभव

इस अधिनियम की धारा *2* के खंड *(45-*ए*)* में परिभाषित किया गया है और कंपनी सचिव अधिनियम, *1980 (56)* के तहत गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य

1980 का*);* या

(च*)* क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है।

विशेष ज्ञान, और नहीं के पेशेवर अनुभव

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र में बीस वर्ष से कम, *6*

बैंकिंग, उद्योग, कानून, औद्योगिक वित्त से संबंधित मामले,

प्रशासन, निवेश, लेखा, विपणन या कोई अन्य अन्य विषय, विशेष ज्ञान, या पेशेवर

में अनुभव, जो केंद्र की राय में होगा

न्यायाधिकरण के लिए उपयोगी सरकार; या

(छ*)* श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है या रहा है,

औद्योगिक के तहत गठित न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण विवाद अधिनियम, *1947 (1947* का *14);* या

(ज*)* विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, और

मामलों में कम से कम पंद्रह वर्षों का अनुभव

श्रम से संबंधित। स्पष्टीकरण। इस भाग के प्रयोजनों के लिए,

((i) 'न्यायिक सदस्य*'* का अर्थ है - उप-धारा *(2)* के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण

धारा *10*-एफ. डी. और इसके अध्यक्ष शामिल हैं

न्यायाधिकरण*;*

((ii) 'तकनीकी सदस्य*'* का अर्थ है -

उप-धारा *(3)* के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण

धारा *10*-एफ. डी.

10 - एफ. ई. अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। द. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य

तारीख से तीन साल की अवधि के लिए इस तरह का पद

जिसके लिए वह अपने पद पर प्रवेश करता है, लेकिन पात्र होगा

पुनर्नियुक्तिः

बशर्ते कि कोई भी अध्यक्ष या अन्य सदस्य

पद प्राप्त करने के बाद इस तरह से पद धारण करें,

(ख*)* किसी अन्य सदस्य के मामले में, आयु साठ-पाँच वर्षः

बशर्ते कि अध्यक्ष या अन्य सदस्य ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *237*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

अपने मूल संवर्ग या मंत्रालय के साथ अपना ग्रहणाधिकार बनाए रख सकता है या विभाग, जैसा भी मामला हो, पद धारण करते हुए

इस तरह।

10 - एफ. एफ. सदस्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ

प्रशासन। केंद्र सरकार नामित करेगी

प्रशासनिक शक्तियाँ जो उसके अधीन निहित की जा सकती हैं केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमः

बशर्ते कि सदस्य *(*प्रशासन*)*

अधिकारी, ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय सदस्य *(*प्रशासन*)* के निर्देश, अधीक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य करना जारी रखें।

*

*

10 - एफ. के. न्यायाधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी। — *(1)* द.

केंद्र सरकार न्यायाधिकरण को इस तरह का प्रावधान करेगी

अधिकारी और अन्य कर्मचारी जो उचित समझें।

(2) न्यायाधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

सदस्य प्रशासन का पर्यवेक्षण। *(3)* वेतन और भत्ते और अन्य शर्तें और

अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

10 - एफ. एल. न्यायाधिकरण की पीठें। - *(1)* प्रावधानों के अधीन इस धारा की, न्यायाधिकरण की शक्तियाँ हो सकती हैं -

राष्ट्रपति द्वारा गठित पीठों द्वारा प्रयोग किया गया

न्यायाधिकरण, जिसमें से एक न्यायिक सदस्य होगा और

अन्य एक तकनीकी सदस्य होगा जो धारा *10*-एफ. डी. की उप-धारा *(3)* के खंड *(*ए*)* से *(*एफ*)* में निर्दिष्ट हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

3

बशर्ते कि यह सदस्यों के लिए सक्षम होगा

इस संबंध में एक पीठ के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत

एकल सदस्य का और अधिकार क्षेत्र, शक्तियों का प्रयोग करना

और ऐसे वर्ग के संबंध में न्यायाधिकरण का अधिकार ऐसे वर्ग के मामलों से संबंधित मामले या ऐसे मामले,

न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, सामान्य या विशेष द्वारा आदेश दें, निर्दिष्ट करेंः

बशर्ते कि सुनवाई के किसी भी चरण में

ऐसा कोई मामला या मामला, यह सदस्य को दिखाई देता है

न्यायाधिकरण कि मामला या मामला ऐसी प्रकृति का है कि यह

दो सदस्यों की पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए, मामले या मामले को राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, उसके लिए निर्दिष्ट किया गया है

ऐसी न्यायपीठ को स्थानांतरण जो राष्ट्रपति उचित समझे।

(2) न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, कंपनियों के पुनर्वास, पुनर्गठन या समापन से संबंधित किसी भी मामले के निपटारे के लिए, एक या अधिक विशेष इकाइयों का गठन करेगा।

तीन या अधिक सदस्यों वाली पीठ, जिनमें से प्रत्येक

जो अनिवार्य रूप से एक न्यायिक सदस्य, के किसी भी खंड *(ए)* से *(एफ)* के तहत नियुक्त एक तकनीकी सदस्य होगा

धारा *10*-एफ. डी. की उप-धारा *(3)* और एक सदस्य

उप-धारा *(3)* के खंड *(जी)* या खंड *(एच)* के तहत नियुक्त

धारा *10*-एफ. डी.*:*

बशर्ते कि यदि कोई विशेष पीठ एक पारित करती है

किसी कंपनी को बंद करने के संबंध में आदेश, समापन

ऐसी कंपनी की कार्यवाही एक द्वारा संचालित की जा सकती है

एकल सदस्य से युक्त पीठ।

(3) यदि किसी पीठ के सदस्यों की किसी भी मुद्दे पर राय भिन्न है।

या बिंदु, यह बहुमत के अनुसार तय किया जाएगा, यदि

बहुमत है, लेकिन यदि सदस्य समान रूप से विभाजित हैं, तो वे उस बिंदु या बिंदु को बताएँगे जिस पर वे भिन्न हैं, और मामले को न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा ऐसे बिंदु या बिंदुओं पर सुनवाई के लिए एक या अधिक द्वारा भेजा जाएगा।

न्यायाधिकरण के अन्य सदस्य और ऐसे बिंदु या बिंदु ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v* के बहुमत की राय के अनुसार निर्णय लिया जाए।

भारत का संघ

239

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इसे पहली बार सुना था। *(4)* इतनी संख्या में पीठों का गठन किया जाएगा कि

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(5) अन्य पीठों के अलावा, एक होगा

नई दिल्ली में प्रधान पीठ की अध्यक्षता में

न्यायाधिकरण के अध्यक्ष।

(6) न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के पास शक्तियाँ होंगी।

किसी भी पीठ से दूसरी पीठ में कार्यवाही के हस्तांतरण का

किसी भी पीठ की असमर्थता की स्थिति में न्यायाधिकरण की पीठ

किसी भी कारण से ऐसी किसी भी कार्यवाही की सुनवाई सेः

बशर्ते कि किसी भी कार्यवाही का कोई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा

इस उप-धारा के तहत कारणों को दर्ज करने के बाद को छोड़कर

ऐसा लिखित रूप में करने के लिए।

*

+

10 - एफ. ओ. शक्तियों का प्रत्यायोजन। न्यायाधिकरण, द्वारा

सामान्य या विशेष आदेश, प्रतिनिधि, इस तरह के अधीन शर्तों और सीमाओं, यदि कोई हो, जैसा कि में निर्दिष्ट किया जा सकता है

के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी को आदेश न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति

किसी भी औद्योगिक कंपनी या औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन करना

या किसी संचालन अभिकरण के अधीन ऐसी शक्तियाँ और कर्तव्य

यह अधिनियम जो वह आवश्यक समझे।

भाग *I-C*

अपीलीय न्यायाधिकरण

*

10 - एफ. आर. अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन। - *(1)* द.

केंद्र सरकार, आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा राजपत्र, ऐसी तारीख से प्रभावी होता है जो हो सकता है

उसमें विनिर्दिष्ट, एक अपीलीय न्यायाधिकरण जिसे कहा जाएगा

' राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण *'*जिसमें -

एक अध्यक्ष और दो से अधिक सदस्य नहीं, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

उसके विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त

इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के आदेश।

(2) अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष एक होगा

वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो।

(3) अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य एक व्यक्ति होगा।

विशेष ज्ञान रखने की क्षमता, सत्यनिष्ठा और स्थिति

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, बैंकिंग में कम से कम पच्चीस वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।

उद्योग, कानून, श्रम से संबंधित मामले, औद्योगिक वित्त,

औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, प्रशासन, निवेश, लेखा, विपणन या कोई अन्य

अन्य विषय, विशेष ज्ञान या व्यावसायिक अनुभव जिसमें केंद्र की राय होगी

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए उपयोगी सरकार।

*

10 - एफ. टी. अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य तीन साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेगा।

जिस तारीख को वह अपने पद पर प्रवेश करता है, लेकिन पात्र होगा तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए:

बशर्ते कि कोई भी अध्यक्ष या अन्य सदस्य पद धारण नहीं करेगा।

पद प्राप्त करने के बाद, *(क)* अध्यक्ष के मामले में सत्तर वर्ष की आयु

वर्षों से*;*

(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में, साठ-सात वर्ष की आयु

वर्षों से।

10 - एफएक्स। चयन समिति। *- (1)* अध्यक्ष और अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य और अध्यक्ष और

न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी। चयन जादरास बार एसोसिएशन की सिफारिशों पर सरकार *v.*

भारत संघ *241*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

समिति जिसमें

(क*)* भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत

अध्यक्ष*;*

(ख*)* वित्त मंत्रालय में सचिव और

कंपनी मामलों के सदस्य*; (* ग*)* श्रम मंत्रालय में सचिव सदस्य*;*

*((*घ*)* विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव

(कानूनी कार्य या विधायी विभाग

विभाग*)* सदस्य*;*

(ई*)* वित्त मंत्रालय में सचिव और

कंपनी कार्य *(*कंपनी कार्य विभाग*)* सदस्य।

चयन समिति के संयोजक। *(5)* नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य

और न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, चयन समिति स्वयं को संतुष्ट करेगी कि ऐसा व्यक्ति नहीं करता है

वित्तीय या अन्य ब्याज है जो प्रभावित होने की संभावना है

न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो। *(6)* अध्यक्ष और सदस्यों की कोई नियुक्ति नहीं

अपीलीय न्यायाधिकरण और न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल किसी कारण से अमान्य कर दिया जाएगा

चयन के गठन में कोई रिक्ति या कोई दोष

समिति।

** ?*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

10 - जी. अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। - अपीलीय न्यायाधिकरण के पास समान अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और

उच्च न्यायालय के रूप में स्वयं की अवमानना के संबंध में प्राधिकरण

न्यायालय अवमानना अधिनियम, *1971 (1971* का *70)* के प्रावधानों के तहत इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया है और कर सकता है।

1971) , जिनका प्रभाव संशोधनों के अधीन होगा

कि

(क) उसमें उच्च न्यायालय को दिए गए निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा।

अपीलीय न्यायाधिकरण को एक संदर्भ शामिल करने के रूप में;

उक्त अधिनियम का अर्थ ऐसे विधि अधिकारियों के लिए एक संदर्भ के रूप में किया जाएगा जो केंद्र सरकार इसमें निर्दिष्ट करे। की ओर से।

10 - जीबी। दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं होना चाहिए। - *(1)* कोई सिविल नहीं

न्यायालय के पास किसी भी वाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा या किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाही जो न्यायाधिकरण या

अपीलीय न्यायाधिकरण को या द्वारा निर्धारित करने का अधिकार है

इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत

और इस मामले में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का अनुसरण करना या

उस समय लागू कोई अन्य कानून।

न्यायाधिकरण निर्णय की सूचना की तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। या ऐसे निर्णय या आदेश से उत्पन्न कानून के किसी भी प्रश्न पर उसे अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेशः

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को मद्रास बार एसोसिएशन *v* दाखिल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

भारत संघ *243*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

उक्त अवधि के भीतर अपील, इसे भीतर दायर करने की अनुमति दें

एक और अवधि जो साठ दिनों से अधिक न हो। *'*

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय

"के बीच अंतर" से संबंधित विस्तृत टिप्पणियाँ

हमारा और न्यायाधिकरण "", पुनः: न्यायपालिका की स्वतंत्रता ",

शक्तियों का विभाजन ", और" क्या सरकार कर सकती है

न्यायालयों द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाले न्यायिक कार्यों को,

इबुनाल्स ", निम्नानुसारः

" 70. लेकिन भारत में, दुर्भाग्य से न्यायाधिकरणों को सफलता नहीं मिली है

पूर्ण स्वतंत्रता। "प्रायोजक" के सचिव

संबंधित विभाग चयन समिति में बैठता है

नियुक्ति। जब न्यायाधिकरणों का गठन किया जाता है, तो वे हैं

ज्यादातर धन, बुनियादी ढांचे और यहां तक कि काम करने के लिए जगह के लिए अपने प्रायोजक विभाग पर निर्भर हैं। द.

न्यायाधिकरणों का गठन करने वाले कानून नियमित रूप से प्रायोजक विभागों से सिविल सेवाओं के सदस्यों के लिए प्रदान करते हैं।

न्यायाधिकरण के सदस्य बनना और अपने ग्रहणाधिकार को जारी रखना

अपने मूल कैडर के साथ। जब तक कि व्यापक सुधारों को यूनाइटेड किंगडम में लागू नहीं किया गया था और जैसा कि थे

एल. चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ द्वारा सुझाए गए,

(1997) 3 एस. सी. सी. *261,* भारत में न्यायाधिकरण बनाए गए हैं।

स्वतंत्र नहीं माना जाएगा।

क्या सरकार अदालतों द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाले न्यायिक कार्यों को न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित कर सकती है*? 71.* यह अच्छी तरह से तय है कि अदालतें सभी न्यायिक कार्य करती हैं।

उदाहरण के लिए, यह प्रावधान है कि न्यायालयों के पास अधिकार क्षेत्र होगा सिविल प्रकृति के सभी सूटों को आजमाने के लिए, सिवाय उन सूटों के जिनमें से उनके

संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।

72. अनुच्छेद *32* में यह प्रावधान है कि शक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

उक्त अनुच्छेद के खंड *(1)* और *(2)* द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त, संसद कानून द्वारा किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. को सशक्त बना सकती है।

न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर सभी का प्रयोग करेगा

या अनुच्छेद *32* के खंड *(2)* के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में से कोई भी।

73. अनुच्छेद *247* में प्रावधान है कि किसी भी चीज के बावजूद

संविधान के भाग *11* के अध्याय *1* में निहित, संसद कानून द्वारा किसी की स्थापना के लिए प्रावधान कर सकती है

कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें बनाई गईं संसद द्वारा या संघ सूची में सूचीबद्ध किसी मामले के संबंध में किसी मौजूदा कानून द्वारा। अनुच्छेद *245* प्रदान करता है

जो संविधान के प्रावधानों के अधीन हो,

संसद पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है।

भारत का राज्यक्षेत्र और किसी राज्य का विधानमंडल पूरे या राज्य के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है।

74. अनुच्छेद *246* बनाए गए कानूनों के विषय से संबंधित है।

संसद द्वारा और राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। संघ सूची *(*सातवीं अनुसूची की सूची *I)* में गणना की गई है -

उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ। सूची *I* की प्रविष्टि *78* संविधान को संदर्भित करती है और उच्च न्यायालयों का संगठन। सूची *I* की प्रविष्टि *79* किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के विस्तार या बहिष्करण को संदर्भित करती है,

किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से। सूची *I* की प्रविष्टि *43* व्यापार के निगमन, विनियमन और समापन को संदर्भित करती है।

मैं संघ सूची के किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों का उल्लेख करता हूं। *75.* समवर्ती सूची *(*सातवीं अनुसूची की बीमार सूची*)*

उन मामलों की गणना करता है जिनके संबंध में किसी राज्य की संसद और विधानमंडल के पास समवर्ती शक्ति होगी।

कानून बनाने के लिए। प्रविष्टि *11*-सूची *III* का ए न्याय के प्रशासन, संविधान और सभी न्यायालयों के संगठन को संदर्भित करता है सिवाय इसके कि

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।

सूची ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन की प्रविष्टि *46 v.* भारत का संघ *245*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

III सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को संदर्भित करता है, सिवाय इसके कि

उच्चतम न्यायालय, सूची में किसी भी मामले के संबंध में

III.

76. भाग *XIV-A* को संविधान में प्रभावी रूप से जोड़ा गया था।

संविधान द्वारा *3-1-1977* से *(*बयालीसवां*)*

संशोधन*)* अधिनियम, *1976*। उक्त भाग में दो लेख हैं।

अनुच्छेद *323*-ए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है और

संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है,

विवादों के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या परीक्षण

और भर्ती और शर्तों के संबंध में शिकायतें

लोक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा और

सरकार के मामलों के संबंध में पद या

किसी राज्य या उसके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के

भारत का क्षेत्र या सरकार के नियंत्रण में

भारत या उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी निगम का

सरकार।

XXX

XXX XXXX

80. प्रदान करने के लिए संसद की विधायी क्षमता

अदालतों और न्यायाधिकरणों के निर्माण के लिए प्रविष्टियों का पता लगाया जा सकता है

अनुसूची. इन अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए, यह न्यायालय दो भागों में मामले, अर्थात्, भारत संघ बनाम। दिल्ली उच्च न्यायालय बार

एस. एन. , *(2002) 4* एस. सी. सी. *75* और कर्नाटक राज्य बनाम

विश्वभारती हाउस बिल्डिंग कॉप। सोसायटी, *(2003) 2*

एस. सी. सी. *412* ने माना कि अनुच्छेद *323*-ए और *323*-बी सक्षम कर रहे हैं।

ऐसे प्रावधान जो न्यायाधिकरणों की स्थापना को सक्षम बनाते हैं

उन लोगों द्वारा कवर नहीं किए गए न्यायाधिकरणों की स्थापना से विधायिका अनुच्छेद, जब तक इसके तहत विधायी क्षमता है

सातवीं अनुसूची में उपयुक्त प्रविष्टि।

XXX XXX

XXX

90. लेकिन जब हम कहते हैं कि विधायिका के पास *[2014] 10* एस. सी. आर. है।

न्यायाधिकरणों द्वारा, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किए बिना संवैधानिक सीमाओं के अधीन है और कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए। यदि न्यायाधिकरणों को निहित किया जाना है

न्यायिक शक्ति अब तक न्यायालयों में निहित या उनके द्वारा प्रयोग की जाती थी,

ऐसे न्यायाधिकरणों को स्वतंत्रता, सुरक्षा मिलनी चाहिए और न्यायालयों से जुड़ी क्षमता। यदि न्यायाधिकरण हैं

एक ऐसे क्षेत्र की सेवा करने का इरादा है जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है

ज्ञान या विशेषज्ञता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी हो सकती है

न्यायिक सदस्यों के अलावा सदस्य। जहां हालांकि कुछ श्रेणी के मामलों की सुनवाई करने की अधिकारिता केवल सुनवाई में तेजी लाने के लिए अदालतों से न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित की जाती है और

साक्ष्य अधिनियम की कठोरता से निपटान या राहत

और प्रक्रियात्मक कानूनों में, स्पष्ट रूप से किसी गैर-न्यायिक तकनीकी सदस्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में

न्यायाधिकरण, केवल न्यायपालिका के सदस्य होने चाहिए

पीठासीन अधिकारी/सदस्य। इस तरह के विशेष न्यायाधिकरणों के विशिष्ट उदाहरण हैं किराया न्यायाधिकरण, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कई के तहत विशेष अदालतें।

अधिनियम। इसलिए, अधिकार क्षेत्र का हस्तांतरण करते समय

न्यायालयों द्वारा न्यायाधिकरणों को प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता शामिल नहीं होती है और

केवल उद्देश्य, इसके अतिरिक्त तकनीकी सदस्यों के लिए एक प्रावधान न्यायिक सदस्यों को या उनके प्रतिस्थापन में स्पष्ट रूप से कमजोर करने और अतिक्रमण का मामला होगा

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून का शासन असंवैधानिक होगा।

91 आर. के. जैन बनाम भारत संघ, *(1993) 4* एस. सी. सी. *119*, इस न्यायालय ने कहाः *(* एससीसी पीपी। *169-70* , पैरा *67)*

" 67. संविधान के अनुच्छेद *323*-ए और *323*-बी के तहत या किसी अधिनियम के तहत स्थापित न्यायाधिकरण विधायिका कानून के प्राणी हैं और नहीं

मामला उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में स्थिति का दावा करता है *IADRAS BAR ASSOCIASIAN v.*

भारत संघ *247*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

या समानता या विकल्प के रूप में। हालांकि, कर्मचारियों ने

राज्य के अधीन उन पदों को धारण करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं

न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निर्वहन के लिए बुलाया गया

उस विशेष में ज्ञान और विशेषज्ञता भी संवैधानिक, प्रशासनिक और कर कानूनों की शाखा।

पर्याप्त वजन और दांत निश्चित रूप से होंगे न्यायपालिका की प्रभावशीलता और प्रभावशीलता में कमी

न्यायनिर्णयन। इसलिए यह आवश्यक है कि

जो इन मामलों पर निर्णय लेते हैं

कानूनी विशेषज्ञता, न्यायिक अनुभव और कुछ हद तक

कानूनी प्रशिक्षण कई अवसरों पर अलग और

कानून के जटिल प्रश्न जो लोगों के दिमाग को चौंका देते हैं यहाँ तक कि उच्च न्यायालय में प्रशिक्षित न्यायाधीश और

उच्चतम न्यायालय चर्चा के लिए उठेगा और

निर्णय "।

92. यह मानते हुए कि कानून कुछ क्षेत्रों को स्थानांतरित कर सकता है न्यायालयों से न्यायाधिकरणों तक मुकदमेबाजी और यह स्वीकार करते हुए कि

विधायिका तकनीकी सदस्यों के लिए प्रदान कर सकती है

ऐसे न्यायाधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के अलावा, आइए हम मुड़ें

हमारा ध्यान इस सवाल पर है कि कौन हो सकता है

और एक तकनीकी सदस्य, क्या इसका मतलब यह है कि कोई नहीं है निर्धारित करने की विधायिका की शक्ति पर सीमाएँ

ऐसे तकनीकी पटल के लिए योग्यताएँ क्या हैं? सवाल यह है

यह भी होगा कि क्या किसी भी सीमा को पढ़ा जा सकता है

योग्यता निर्धारित करने के लिए विधायिका की क्षमता

न्यायिक सदस्य के लिए? जवाब, ज़ाहिर है, निर्भर करता है

अधिकारिता की प्रकृति पर जिसे स्थानांतरित किया जा रहा है

न्यायालयों से लेकर न्यायाधिकरणों तक। तार्किक और आवश्यक रूप से, निर्भर करता है

इस बात पर कि क्या अधिकार क्षेत्र को उच्च से स्थानांतरित किया जा रहा है

न्यायालय, या जिला न्यायालय या सिविल न्यायाधीश, मानदंड

अलग होगा। यह अदालत के लिए है जो चुनौती पर विचार करती है

1 3 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

योग्यता के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विधायी

शक्ति का प्रयोग इसके अनुरूप तरीके से किया गया है

संवैधानिक सिद्धांत और संवैधानिक गारंटी।

XXX

XXX

XXX

101. के निर्धारण के लिए स्वतंत्र न्यायिक न्यायाधिकरण

नागरिकों के अधिकार, और नागरिकों के विवादों और शिकायतों के निर्णय के लिए, एक आवश्यक सहवर्ती है

कानून का शासन। कानून के शासन के कई पहलू हैं, जिनमें से एक

जो यह है कि नागरिकों के विवादों का फैसला न्यायाधीश करेंगे

सरकार के कार्यों की वैधता का निर्णय इसके द्वारा किया जाएगा ऐसे न्यायाधीश जो कार्यपालिका से स्वतंत्र हों। कानून के शासन का एक अन्य पहलू कानून के समक्ष समानता है। सार है।

समानता की बात यह है कि इसे एक स्वतंत्र न्यायिक मंच द्वारा लागू करने और निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक शक्ति का पृथक्करण

कार्यपालिका हमारे जैसे संविधान में निहित सामान्य कानून परंपराओं का हिस्सा है जो वेस्टमिंस्टर पर आधारित है। मॉडल।

102. कानून के समक्ष समानता और समानता का मौलिक अधिकार

संविधान के अनुच्छेद *14* द्वारा गारंटीकृत कानूनों के संरक्षण में स्पष्ट रूप से व्यक्ति का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।

न्यायिक कार्य करने वाले मंच द्वारा निर्णय लिए गए अधिकार

एक निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से शक्ति, सुसंगत

न्यायनिर्णयन के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के साथ। इसलिए जहां भी ऐसे अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों तक पहुंच की मांग की जाती है उसे एक वैकल्पिक मंच से संपर्क करने का निर्देश देकर संक्षिप्त, परिवर्तित, संशोधित या प्रतिस्थापित किया जाना, जैसे

विधायी अधिनियम चुनौती देने के लिए खुला है यदि यह अधिकार का उल्लंघन करता है

एक स्वतंत्र मंच द्वारा निर्णय लेने के लिए। इसलिए, हालांकि एमबीए द्वारा चुनौती उल्लंघन के आधार पर है

मूल संरचना का हिस्सा बनने वाले सिद्धांत, वे एक या अधिक स्पष्ट प्रावधानों से संबंधित हैं

संविधान जिसने ऐसे सिद्धांतों को जन्म दिया। हालांकि

विधायी अधिनियम के प्रावधानों की वैधता ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v* नहीं हो सकती है।

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

जमीन पर चुनौती दी गई यह मूल संरचना का उल्लंघन करती है

संविधान, इसे उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जा सकती है

संवैधानिक प्रावधान जो सिद्धांतों को स्थापित करते हैं -

कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और स्वतंत्रता

न्यायपालिका से।

XXX

XXX XXX

106. हम स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं:

(उन लोगों के अलावा जो अदालतों में व्यक्त रूप से निहित हैं संविधान के प्रावधान*)* किसी भी न्यायाधिकरण को।

((ख) सभी न्यायालय न्यायाधिकरण हैं। कोई भी न्यायाधिकरण जिसके लिए कोई

न्यायालयों के मौजूदा अधिकार क्षेत्र को भी हस्तांतरित किया जाना चाहिए

एक न्यायिक न्यायाधिकरण। इसका मतलब है कि ऐसे न्यायाधिकरण को सदस्यों के रूप में, एक पद, क्षमता और स्थिति के व्यक्ति हैं

जितना संभव हो सके रैंक, स्थिति और के बराबर

न्यायाधिकरण के मामलों और सदस्यों के पास होना चाहिए संबंधित कार्यकाल की स्वतंत्रता और सुरक्षा

न्यायिक न्यायाधिकरण।

(ग*)* जब भी "न्यायाधिकरणों" की आवश्यकता होती है, कोई नहीं होता है।

यह धारणा कि इसमें तकनीकी सदस्य होने चाहिए

न्यायाधिकरण। जब कोई क्षेत्राधिकार न्यायालयों से स्थानांतरित किया जाता है न्यायाधिकरण, न्यायालयों में विचाराधीनता और विलंब के आधार पर।

और इस प्रकार हस्तांतरित अधिकारिता में कोई शामिल नहीं है

विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता वाले तकनीकी पहलू,

न्यायाधिकरणों में आम तौर पर केवल न्यायिक सदस्य होने चाहिए। केवल जहाँ अधिकारिता के प्रयोग में जाँच शामिल है और

तकनीकी या विशेष पहलुओं में निर्णय, जहाँ तकनीकी सदस्यों की उपस्थिति उपयोगी होगी और

आवश्यक है, न्यायाधिकरणों में तकनीकी सदस्य होने चाहिए।

सभी में तकनीकी सदस्यों की अविवेकी नियुक्ति

न्यायाधिकरण स्वतंत्रता को कमजोर और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे

न्यायपालिका से।

(घ) विधायिका न्यायिक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र का पुनर्गठन कर सकती है। उदाहरण के लिए, यह प्रदान कर सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने वाले मामलों की एक निर्दिष्ट श्रेणी निचली अदालत द्वारा या इसके विपरीत मुकदमा चलाया जाता है *(*एक मानक उदाहरण अदालतों की आर्थिक सीमाओं में भिन्नता है*)*। इसी तरह न्यायाधिकरणों का गठन करते समय, विधायिका निर्धारित कर सकती है -

योग्यता/पात्रता मानदंड। लेकिन ऐसा ही है न्यायिक समीक्षा के अधीन। यदि न्यायालय न्यायिक अभ्यास में

समीक्षा का विचार है कि इस तरह के न्यायाधिकरण

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या

न्यायपालिका के मानकों में, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मानकों की रक्षा करना।

इस तरह की कवायद नियंत्रण और संतुलन का हिस्सा होगी

शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखने के उपाय और

विधायिका या कार्यपालिका द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किए गए किसी भी अतिक्रमण को रोकें।

XXX

XXX XXX

113. जब प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का गठन किया गया था, तो तकनीकी रूप से सिविल सेवाओं के सदस्यों की उपस्थिति *(* प्रशासनिक*)* सदस्यों को आवश्यक माना जाता था, जैसे -

वे सरकारी कामकाज में अच्छी तरह से पारंगत थे

सरकारी कर्मचारी। लेकिन तथ्य यह है कि सिविल के वरिष्ठ अधिकारी सेवाएँ प्रशासनिक सदस्यों के रूप में कार्य कर सकती हैं

प्रशासनिक न्यायाधिकरण, आवश्यक रूप से उन्हें कंपनी में तकनीकी सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं बनाते हैं।

विशेषज्ञता। न्यायाधिकरण सिविल सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति करके उन्हें अनिश्चित सेवा प्रदाता नहीं बना सकते हैं। तकनीकी सदस्यों के रूप में, हालांकि उनके पास उस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता नहीं हो सकती है जिससे न्यायाधिकरण संबंधित हैं, या इससे भी बदतर,

जहाँ विशुद्ध रूप से न्यायिक कार्य शामिल हैं। जबकि नागरिक सदस्यों की उपस्थिति को समझा जा सकता है

न्यायाधिकरण, या सैन्य अधिकारी सशस्त्र के सदस्य होने के नाते बल न्यायाधिकरण, या विद्युत इंजीनियर जो आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन के सदस्य हैं।

भारत संघ *251*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, या दूरसंचार इंजीनियरों

सामान्य सिविल सेवाओं के सदस्य होने के नाते कंपनी विधि न्यायाधिकरण।

114. आइए अब हम स्वतंत्रता को कमजोर करने का उल्लेख करें। अगर

न्यायाधिकरण के किसी भी सदस्य को अपना ग्रहणाधिकार बनाए रखने की अनुमति है।

अपनी पूरी अवधि के लिए सिविल सेवा में विभाग न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में सेवा, वह जारी रहेगा

सिविल सेवाओं के सदस्य के रूप में सोचें, कार्य करें और कार्य करें। एक वादी वैध रूप से सोच सकता है कि ऐसा सदस्य ऐसा नहीं करेगा

स्वतंत्र और निष्पक्ष रहें। हम दोहराते हैं कि हमारे

टिप्पणियों का उद्देश्य इस बारे में कोई संदेह पैदा करना नहीं है ईमानदारी और अखंडता या क्षमता और क्षमता

सिविल सेवाओं के अधिकारी, विशेष रूप से वे जो

संयुक्त सचिव का पद या उस मामले में कनिष्ठ भी

अधिकारी। हम जिसका उल्लेख कर रहे हैं वह धारणा है

स्वतंत्रता या आचरण के बारे में वादियों और जनता न्यायाधिकरण के सदस्य। स्वतंत्रता, निष्पक्षता

न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले सदस्यों की स्वतंत्रता न्यायाधिकरण को कमजोर नहीं किया जा सकता है।

XXX

XXX

XXX

120. हम सही करने के लिए आवश्यक सुधारों को सारणीबद्ध कर सकते हैं।

अधिनियम के भाग *I-B* और *I-C* में दोषः

(1) केवल न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं पर विचार किया जा सकता है

न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति। केवल उच्च

केंद्र या राज्य के तहत समूह ए या समकक्ष पद भारतीय कंपनी कानून में अनुभव के साथ सरकार *2* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

सेवा *(*कानूनी शाखा*)* और भारतीय कानूनी सेवा *(*ग्रेड *I)* को न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है जैसा कि उप-धारा *(2) (*सी*)* और *(*डी*)* में प्रदान किया गया है।

धारा *10*-एफ. डी. कंपनी विधि सेवा या भारतीय विधि सेवा में विशेषज्ञता उन्हें सर्वोत्तम रूप से सक्षम बनाएगी तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए माना जाता है।

((ii) चूंकि एन. सी. एल. टी. उच्च न्यायालय के कार्यों को संभालता है, सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान पद और दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यह हो सकता है

सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते देकर नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करके कि वे व्यक्ति

जो पद, अनुभव या योग्यता में लगभग बराबर हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के रूप में नियुक्त किया जाता है सदस्य। इसलिए, केवल वे अधिकारी जो संभाल रहे हैं

सचिवों या अतिरिक्त सचिवों के पद अकेले कर सकते हैं

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। उप-धारा *(2)* के खंड *(*सी*)* और *(*डी*)* और धारा *10*-एफ. डी. की उप-धारा *(3)* के खंड *(*ए*)* और *(*बी*)* जो *15* के साथ व्यक्तियों के लिए प्रावधान करते हैं।

समूह ए पद में वर्षों का अनुभव या केंद्र या राज्य में संयुक्त सचिव या समकक्ष पद धारण करने वाले व्यक्ति।

राज्य सरकार, के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य है

न्यायाधिकरण के सदस्य अमान्य हैं।

(iii) एक *"*तकनीकी सदस्य*"* में अनुभव की आवश्यकता होती है।

वह क्षेत्र जिससे न्यायाधिकरण संबंधित है। भारतीय कंपनी विधि सेवा का एक सदस्य जिसके साथ काम किया है

लेखा शाखा या अन्य विभागों के अधिकारी जिन्होंने संयोग से कंपनी के किसी पहलू से निपटा हो कानून को तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के योग्य "विशेषज्ञ" नहीं माना जा सकता है। अतः खंड *(ए)*

और *(ख)* उप-धारा *(3)* वैध नहीं हैं।

((iv) उप-धारा *(3)* के खंड *(च)* का पहला भाग कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास विशेष ज्ञान या पेशेवर है

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, बैंकिंग उद्योग में *20* वर्षों के अनुभव को आई. ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन वाले व्यक्ति माना जा सकता है।

भारत संघ *253*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

तकनीकी के रूप में नियुक्त होने के लिए कंपनी कानून में विशेषज्ञता

कंपनी विधि न्यायाधिकरण के सदस्य अमान्य हैं।

(v) क्षमता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और विशेष क्षमता वाले व्यक्ति।

कम से कम का ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन में पंद्रह वर्ष,

हालाँकि विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों के रूप में माना जाता है कंपनियों का पुनर्वास/पुनरुद्धार और इसलिए, पात्र

तकनीकी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना

सदस्य।

(vi) खंड *(छ)* में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में

(vii) धारा *10*-एफ. डी. की उप-धारा *(3)* में केवल खंड *(सी)*, *(डी)*, *(ई)*, *(जी)*, *(एच)* और खंड *(एफ)* का उत्तरार्द्ध और अधिकारी सचिव या अतिरिक्त रैंक की सिविल सेवाओं की

भारतीय कंपनी विधि सेवा में सचिव और भारतीय कानूनी सेवा पर इन उद्देश्यों के लिए विचार किया जा सकता हैः

न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्ति।

(viii) पाँच सदस्यीय चयन समिति के बजाय

अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश *(*या उनके नामित*)*

और वित्त मंत्रालय के दो सचिव और

कंपनी कार्य और मंत्रालय में सचिव

श्रम और विधि मंत्रालय में सचिव और धारा *10*-एफएक्स में उल्लिखित सदस्यों के रूप में न्याय,

चयन समिति व्यापक रूप से निम्नलिखित पर होनी चाहिए:

पंक्तियाँ:

(क*)* भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत

अध्यक्ष *(*निर्णायक मत के साथ*);*

(ख*)* उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-सदस्य*;*

(ग*)* वित्त मंत्रालय में सचिव और

कंपनी मामले-सदस्य*;* और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

*((*घ*)* विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव

सदस्य।

(ix) तीन साल के कार्यकाल को बदल दिया जाएगा एक और कार्यकाल के लिए नियुक्ति के लिए पात्रता के अधीन सात या पाँच वर्ष का कार्यकाल। ऐसा इसलिए है क्योंकि

विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए काफी समय चाहिए

संबंधित क्षेत्र। तीन साल की अवधि बहुत कम होती है और जब तक सदस्य आवश्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं,

विशेषज्ञता और दक्षता, एक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा *65* वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के साथ तीन वर्ष की उक्त अवधि ऐसा माना जाता है कि यह उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं और इन्हें प्रोत्साहित करते हैं

न्यायाधिकरणों को सेवानिवृत्ति के बाद के आश्रय के रूप में माना जाएगा। यदि इन न्यायाधिकरणों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करना है तो वे

युवा सदस्यों को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए जो

सेवा की उचित अवधि।

(x) धारा *10* का दूसरा प्रावधान-एफ. ई. राष्ट्रपति और सदस्यों को अपने माता-पिता के साथ ग्रहणाधिकार बनाए रखने में सक्षम बनाता है। कैडर/मंत्रालय/विभाग के रूप में पद धारण करते हुए

अध्यक्ष या सदस्य सदस्यों की स्वतंत्रता के लिए अनुकूल नहीं होंगे। के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति

सदस्य को कार्यपालिका से पूरी तरह से अलग होने के लिए तैयार रहना चाहिए। अतः ग्रहणाधिकार एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है।

राष्ट्रपति/सभापति का निलंबन या न्यायाधिकरण का सदस्य केवल निम्नलिखित की सहमति से हो सकता है -

भारत के मुख्य न्यायाधीश।

(xii) सभी न्यायाधिकरणों के लिए प्रशासनिक सहायता होनी चाहिए

कानून और न्याय मंत्रालय से। न ही न्यायाधिकरणों

न ही उनके सदस्य संबंधित प्रायोजक या मूल मंत्रालयों या संबंधित विभाग से सुविधाएं मांगेंगे या उन्हें प्रदान किए जाएंगे।

(xiii) न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठों को हमेशा मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत का संघ *255*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

एक न्यायिक सदस्य रखें। जब भी कोई बड़ा या विशेष

पीठों का गठन किया जाता है, तकनीकी सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों से अधिक नहीं होगी।

62. हाथ में विवाद की जांच करने का साहस करने से पहले यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुछ दावे उठाए गए हैंवर्तमान विवाद में याचिकाकर्ताओं के हाथ तब से हैं

हल किया गया। इन्हें एक पारित आदेश में देखा गया है। इस न्यायालय द्वारा मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ,

(2010) 11 एस. सी. सी. *67,* जिसे नीचे निकाला जा रहा है:

" 1. इन सभी याचिकाओं में, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, *2005 (*संक्षेप में *"*अधिनियम*")* की संवैधानिक वैधता है -

चुनौती दी। *2006* के टी. सी. नंबर *150* में, अतिरिक्त रूप से एक संविधान की धारा *46* को चुनौती *(42)*

संशोधन*)* अधिनियम, *1976* और भारत के संविधान का अनुच्छेद *323*-बी। यह तर्क दिया जाता है कि धारा *46*

संविधान *(*बयालीसवां संशोधन*)* अधिनियम, अधिकार से बाहर है।

संविधान की मूल संरचना जो इसे सक्षम बनाती है

न्यायाधिकरण प्रणाली का प्रसार और गंभीर बनाता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता में प्रवेश प्रदान करके

न्याय प्रशासन की एक समानांतर प्रणाली, जिसमें

कार्यपालिका ने नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र, प्रक्रिया आदि जैसे मामलों पर व्यापक नियंत्रण बनाए रखा है। यह दावा किया जाता है

कि अनुच्छेद *323*-बी संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है क्योंकि यह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र को छीन लेता है उच्च न्यायालयों और उन्हें राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण में निहित करता है,

अपराधों की सुनवाई और शुद्ध न्यायनिर्णयन सहित

कानून के प्रश्न, जो हमेशा अनन्य रहे हैं

न्यायपालिका का क्षेत्र।

2. जब ये मामले तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आई. डी. *1* पर आए, तो संविधान की विभिन्न धाराओं को चुनौती दी गई।

अधिनियम देखा गया।

3. पहली चुनौती धारा *13* के लिए थी जिसने अनुमति दी थी "राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए विधिवत अधिकृत कोई भी व्यक्ति

कर न्यायाधिकरण।

भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि *6* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

अधिनियम में उचित संशोधन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंटों और पक्षों को व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय कर के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

न्यायाधिकरण।

4. दूसरी चुनौती अधिनियम की धारा *5 (5)* के लिए थी।

जो प्रदान करता है किः

"5. (5) केंद्र सरकार अध्यक्ष के परामर्श से किसी सदस्य का स्थानांतरण कर सकती है।

एक राज्य में एक पीठ के मुख्यालय से दूसरे राज्य में दूसरी पीठ के मुख्यालय तक या

क के भीतर किसी अन्य पीठ के मुख्यालय में

बयान देंः "

5. भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि

न्यायाधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति और शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक योजना और

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति "परामर्श"

अधिनियम की धारा *5 (5)* में आने वाले अध्यक्ष को पढ़ा जाना चाहिए और उनकी सहमति के रूप में समझा जाना चाहिए।

6. तीसरी चुनौती धारा *7* को दी गई थी जिसमें *(क)* मुख्य न्यायाधीश वाली एक चयन समिति का प्रावधान था। भारत का या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसके द्वारा नामित किया गया हो

(ख) विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव, और

याचिकाकर्ताओं द्वारा कि दो सदस्य जो बहुमत बनाने वाली सरकार के सचिव हैं मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की राय को ओवरराइड करें जो अनुचित थी। यह संघ की ओर से कहा गया था

भारत का कहना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत व्यक्ति की राय पर दो सचिवों के हावी होने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि अध्यक्ष की प्रधानता में अंतर्निहित था

प्रणाली और इस पहलू को विधिवत स्पष्ट किया जाएगा।

7. अधिनियम में कुछ अन्य दोषों के संबंध में, मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *257*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

याचिकाकर्ताओं द्वारा, यह प्रस्तुत किया गया था कि संघ

सरकार उनकी जांच करेगी और जहां भी आवश्यक होगा उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे।

8. इन प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, *9-1-2007* पर, यह न्यायालय

केंद्र सरकार को स्वतंत्रता सुरक्षित रखने का आदेश दिया

उचित के बाद सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख करना

अधिनियम में संशोधन किए गए।

9. 21-1-2009 पर, जब *2004* के *CA* नंबर *3067* में तर्क दिए जाते हैं

और *2005* का सीए नंबर *3717,* जो चुनौती से संबंधित है

कंपनी अधिनियम, *1956* के भाग *I-B* और *I-C* में

संविधान पीठ के समक्ष प्रगति, इसे प्रस्तुत किया गया था

कि इन मामलों में एक समान मुद्दा शामिल था और वे कर सकते थे

में निर्णय के संदर्भ में टैग और निपटान किया जाए

उन अपीलों को। इसलिए संविधान पीठ ने निर्देश दिया

इन मामलों को उन अपीलों के साथ सूचीबद्ध किया जाना है, भले ही

इन मामलों में संदर्भ का कोई आदेश नहीं है। सीए नं.

3067 2004 का और *2005* का सीए नंबर *3717* थे

बाद में विस्तार से सुना गया और इसके लिए आरक्षित थे

निर्णय। जिन मामलों को टैग किया गया था वे भी थे

निर्णय के लिए आरक्षित।

10. हमने *2004* के सीए नंबर *3067* और सीए का निपटारा कर दिया है।

2005 का सं. *3717* आज *(*भारत संघ बनाम। मद्रास बार

एसोसिएशन, *(2010) 11* एस. सी. सी. *1)*, एक अलग आदेश द्वारा।

जहाँ तक इन मामलों का संबंध है, हम पाते हैं कि टी. सी.

(सिविल*) 2006* की संख्या *150* में अनुच्छेद को चुनौती शामिल है। *323* - संविधान का बी। उक्त लेख सक्षम बनाता है

न्यायनिर्णयन के लिए विधि द्वारा उपबंध करने के लिए उपयुक्त विधायिकाएँ

या न्यायाधिकरणों द्वारा मुकदमा या कोई विवाद, शिकायत या अपराध

खंड में निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के संबंध में

(2) वहाँ से। अनुच्छेद *323*-बी के खंड *(2)* का उपखंड *(i)* ऐसे न्यायाधिकरणों को कानूनों के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चलाने में सक्षम बनाता है -

उपखंड *(*क*)* में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में

उक्त अनुच्छेद के खंड *(2)* के *(*ज*)* तक।

11. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के समर्थन में आग्रह की गई दलीलों में से एक।

3

अनुच्छेद *323*-बी को चुनौती इस तथ्य से संबंधित है कि न्यायाधिकरण

साक्ष्य अधिनियम, *1872* में निहित साक्ष्य के सामान्य नियमों का पालन न करें. आपराधिक मुकदमों में, एक अभियुक्त है

उचित संदेह से परे दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, और साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य की सराहना के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और

तथ्यों के परिणामी निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं। मुकदमा चलेगा आपराधिक कानून में अनुभव और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो

इसका अर्थ है कि न्यायाधीश या न्यायनिर्णायक को कानूनी रूप से प्रशिक्षित किया जाना है। न्यायाधिकरण जो अपने सारांश का पालन करते हैं

प्रक्रिया, साक्ष्य के सख्त नियमों से बाध्य नहीं हैं और सदस्यों को कानूनी रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा। इसलिए यह

साक्ष्य के आधार पर व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है जो है संभाव्य मूल्य में या के आधार पर पर्याप्त नहीं है

अस्वीकार्य सबूत। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार यह कार्यपालिका को उससे अलग करने के लिए एक प्रतिगामी कदम होगा।

न्यायपालिका।

12. कानून पर मुद्दों पर अपील पारंपरिक रूप से द्वारा सुनी जाती है

अदालतें। अनुच्छेद *323*-बी न्यायाधिकरणों के गठन को सक्षम बनाता है जो कानून के शुद्ध प्रश्नों पर अपीलों की सुनवाई करेंगे। न्यायालयों का कार्य। एल. चंद्र कुमार बनाम। संघ का

भारत, *(1997) 3* एस. सी. सी. *261*, इस न्यायालय ने वैधता पर विचार किया

अनुच्छेद *323*-बी के केवल खंड *(3) (*डी*)* पर विचार नहीं किया गया

अनुच्छेद *323*-बी के अन्य प्रावधानों की वैधता।

13. की संवैधानिक वैधता से संबंधित अपीलें

कंपनियों के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण

अधिनियम, *1956* में अनुच्छेद *323* पर विचार शामिल नहीं था।

ख. *2006* के टी. सी. *(*सिविल*)* संख्या *150* में उठाए गए संवैधानिक मुद्दों को स्थापित करने की शक्ति के रूप में नहीं छुआ गया था। कंपनी न्यायाधिकरण अनुच्छेद *323*-बी के लिए पता लगाने योग्य नहीं था लेकिन

सातवीं अनुसूची की सूची *I* और *III* की कई प्रविष्टियों के लिए और इसके परिणामस्वरूप इस अनुच्छेद को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

14. भाग *I-B* और *I-C* के संबंध में हमले का आधार

कंपनी अधिनियम और एन. टी. टी. अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह से अलग हैं। मद्रास बार एसोसिएशन के भाग *I-B* और *I-C* को चुनौती *v.*

कंपनी अधिनियम, *1956* से समर्थन प्राप्त करना चाहता है अनुच्छेद *323*-बी यह तर्क देते हुए कि अनुच्छेद *323*-बी के लिए एक बाधा है

मामलों के संबंध में किसी भी न्यायाधिकरण का गठन नहीं

उसमें गणना की गई है। दूसरी ओर चुनौती

एन. टी. टी. अधिनियम स्वयं अनुच्छेद *323*-बी को चुनौती देने पर आधारित है।

15. अतः हम पाते हैं कि इन याचिकाओं से संबंधित

एन. टी. टी. अधिनियम की वैधता और अनुच्छेद *323*-बी को चुनौती

वे मुद्दे उठाएँ जो दो दीवानी अपीलों में उत्पन्न नहीं हुए थे।

इसलिए इन मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता है -

दीवानी अपीलों में निर्णय लेकिन सुनवाई की आवश्यकता है

अलग से। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि ये मामले

सुनवाई के लिए अलग से सूचीबद्ध और सूचीबद्ध किया गया। *"63 (i)* केशवानंद में दिए गए निर्णय का अवलोकन

भारती मामले *(*उपरोक्त*)* से पता चलता है कि *"*शक्तियों का पृथक्करण*"* नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली बनाता है, जिसके कारण,

शक्तियाँ इतनी वितरित हैं कि तीनों अंगों में से कोई भी नहीं दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करता है। अवधारणा सुनिश्चित करती है

व्यक्ति की गरिमा। *"*न्यायिक समीक्षा*"* की शक्ति

यह सुनिश्चित करता है कि कार्यकारी कार्यप्रणाली स्वयं को इसके भीतर सीमित करती है

विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून की रूपरेखा। तदनुसार,

विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्तियों का सीमांकन

और न्यायपालिका को मूल तत्व माना जाता है संवैधानिक योजना। जब न्यायिक प्रक्रिया को रोका जाता है

कानून द्वारा, यह निर्धारित करने से कि क्या कार्रवाई की गई थी या नहीं

नहीं, अधिनियमित कानून के ढांचे के भीतर, यह होगा न्यायनिर्णायक/निर्धारक के उल्लंघन के लिए राशि

विधायिका द्वारा प्रक्रिया। इसलिए, बहिष्करण

"न्यायिक समीक्षा" की शक्ति, "मूल संरचना" पर प्रहार करेगी

संविधान से।

((ii) इंदिरा नेहरू गांधी मामले *(*ऊपर*)* में, यह न्यायालय आया।

निष्कर्ष पर, अनुच्छेद *329* ए का वह खंड *(4)* संविधान ने न केवल "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति को नष्ट कर दिया,

लेकिन "शक्तियों के पृथक्करण" का नियम भी। उपरोक्त के अनुसार

विधायी प्रावधान, एक चुनाव शून्य घोषित, पर

एक न्यायिक प्रक्रिया की पराकाष्ठा को वैध माना गया।

[2014] 10 एस सी आर।

260 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट इसका अर्थ यह है कि न्यायिक प्रक्रिया को विधायी घोषणा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुद्दा होना चाहिए

इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि क्या संशोधन की मांग की गई थी हमला किया जाए, एक सिद्धांत का उल्लंघन किया जाए जो "संविधान की मूल संरचना" का गठन करता है। विपक्ष में यह तर्क दिया गया कि एक दृढ़ संकल्प जिसका केवल एक *(*या कुछ*)* व्यक्ति *(*ओं*)* पर प्रभाव पड़ता है, इस तरह के मुद्दे को नहीं उठाएगा। पूछताछ

इसका उत्तर यह निष्कर्ष निकालकर दिया गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक मामले से संबंधित है या बड़ी संख्या में मामलों से।

संविधान के "मूल ढांचे" पर अतिक्रमण अमान्य होगा, चाहे वह सीमित संख्या से संबंधित हो या नहीं।

व्यक्तियों या बड़ी संख्या में लोगों का। व्यक्त विचार

था, कि अगर सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी जानी थी

उन कानूनों को प्रशासित करने और न्याय देने के लिए, फिर वे

ऐसे कानूनों द्वारा शासित होने पर उन्हें अन्याय के अधीन होने की स्थिति में बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाएगा। उपरोक्त कारण से, खंड

(4) अनुच्छेद *329* ए को अमान्य घोषित कर दिया गया था। यह न्यायालय बहुमत से

अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *329* ए के खंड *(4)* और *(5)* थे असंवैधानिक और अमान्य।

(iii) मिनर्वा मिल्स लिमिटेड मामले *(ऊपर)* में, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण,

इस न्यायालय ने केशवानंद में व्यक्त विचार की पुष्टि की

भारती मामला *(ऊपर)* और इंदिरा नेहरू गांधी मामला *(ऊपर)*, कि संसद की संशोधन शक्ति निरपेक्ष नहीं थी। द.

यह कहा गया था कि संसद के पास संविधान के "मूल ढांचे" में संशोधन करने की शक्ति नहीं थी। एक विधायी दावा,

कि अधिनियमित कानून बनाया गया था, एक नीति को प्रभावी बनाने के लिए संविधान के भाग *IV* में किए गए प्रावधानों को सुरक्षित करने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया को बाहर करने का प्रभाव पड़ा। मामले में

उधर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि

संविधान *(*बयालीसवां संशोधन*)* अधिनियम संसद की संशोधन शक्ति से परे था, और वह शून्य था।

क्योंकि इसका प्रभाव संविधान की बुनियादी और आवश्यक विशेषताओं को नुकसान पहुँचाने और इसकी "बुनियादी संरचना" को नष्ट करने का था।

किसी भी कानून के लिए किसी भी चुनौती को पूरी तरह से बाहर करके, यहां तक कि जमीन पर भी, चाहे वह असंगत हो या संक्षिप्त हो, संविधान के अनुच्छेद *14* और *19* द्वारा प्रदत्त अधिकारों का।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *261*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

इसके अलावा, संविधान की धारा *55 (42)*

संशोधन*)*, अधिनियम को संशोधन शक्ति से परे माना गया था

संसद से। इसे अमान्य माना गया था, क्योंकि इसका संसद की शक्तियों पर सभी सीमाओं को हटाने का प्रभाव था, संशोधन करने के लिए

संविधान सहित, इसके मूल को बदलने की शक्ति और आवश्यक विशेषताएँ, अर्थात, इसकी "मूल संरचना"। इस न्यायालय के अनुसार, संविधान के तहत व्यापक रूप से "शक्तियों के पृथक्करण" का कारण था, क्योंकि किसी एक में शक्तियों का केंद्रीकरण।

सरकार के अंगों में से, नींव को नष्ट कर देगा

एक लोकतांत्रिक सरकार का आधार। निर्णय में वर्णित चित्र कुछ प्रासंगिक हैं। इसलिए हम करेंगे,

उन्हें हमारे अपने शब्दों में यहाँ वर्णन करें:

(क*)* उदाहरण के लिए एक मामला लें जहाँ कार्यपालिका, जो

प्रशासन का प्रभारी है, एक नागरिक के पूर्वाग्रह के लिए कार्य करता है।

और एक सवाल उठता है कि कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या हैं, और क्या कार्यपालिका ने इसके भीतर काम किया था

अपनी शक्तियों का दायरा। जाहिर है कि इस तरह के सवाल का फैसला दो बहुत अच्छे कारणों से कार्यपालिका पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले, क्योंकि निर्णय संविधान या कानूनों की व्याख्या पर निर्भर करेगा, जो पहले से ही उपयुक्त हैं।

न्यायपालिका द्वारा निर्णय लिया जाता है, क्योंकि यह केवल न्यायपालिका है जिसके पास निर्णय लेने में विशेषज्ञता होगी। और

दूसरा, क्योंकि संविधान या कानूनों द्वारा नागरिकों को दिया गया कानूनी संरक्षण भ्रामक हो जाएगा, अगर यह था

कार्यपालिका को अपने कार्यों की वैधता निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया।

(ख) उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला लें जिसमें विधायिका ऐसा करती है -

उत्पन्न होता है, क्या कानून बनाने में विधायिका ने कार्य किया था अपनी विधायी क्षमता के क्षेत्र से बाहर, या क्या

कानून नागरिक के मौलिक अधिकारों या कानून के किसी अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता था। इसका समाधान इस पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

विधायिका को दो बहुत अच्छे कारणों से निर्णय लेना है। सबसे पहले, क्योंकि निर्णय की व्याख्या पर निर्भर करेगा

संविधान या कानून, जो न्यायपालिका द्वारा तय किए जाने के लिए पहले से ही उपयुक्त हैं, क्योंकि केवल न्यायपालिका के पास ही निर्णय लेने में विशेषज्ञता होगी।

दूसरा, क्योंकि संविधान या कानूनों द्वारा नागरिकों को दिया गया कानूनी संरक्षण भ्रामक हो जाएगा, अगर इसे अपने कार्यों की वैधता निर्धारित करने के लिए विधायिका पर छोड़ दिया जाए।

ऊपर उद्धृत उदाहरणों के आधार पर, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक स्वतंत्र तंत्र का निर्माण,

विवादों को हल करना, संवैधानिक रूप से न्यायपालिका के पास निहित था।

विधायिका द्वारा अधिनियमित। यह आगे माना गया कि यह गंभीर था संविधान के तहत न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह राज्य के विभिन्न अंगों, जैसे कार्यपालिका और विधायिका को बनाए रखे।

संविधान द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों की सीमाओं के भीतर। तदनुसार यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि

"न्यायिक समीक्षा "भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग था। व्यवस्था, और इसके बिना, "कानून का शासन" एक चिढ़ाने वाला भ्रम और अवास्तविकता का वादा बन जाएगा। उपरोक्त पर आधारित

निष्कर्ष निकालते हुए, इस न्यायालय ने अंत में निष्कर्ष निकाला कि यदि भारतीय संविधान की एक विशेषता थी, जो किसी भी अन्य से अधिक थी, क्या इसकी "बुनियादी संरचना" लोकतंत्र के रखरखाव और "कानून के शासन" के लिए मौलिक थी, यह "न्यायिक" की शक्ति थी।

समीक्षा "। उपरोक्त निष्कर्ष को दर्ज करते हुए, यह

न्यायालय ने एक स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी भी दर्ज की, जिसका नाम है, कि उसे

यह नहीं लिया गया कि "न्यायिक समीक्षा" के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या व्यवस्था नहीं की जा सकी संसद। हालाँकि, इस बात पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया था कि "न्यायिक

समीक्षा "भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, और यह

"बुनियादी संरचना" को प्रभावित किए बिना इसे निरस्त नहीं किया जा सकता था

संविधान से। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक संवैधानिक संशोधन, जिसका प्रभाव हटाने का था

"न्यायिक समीक्षा" की शक्ति, यह प्रावधान करके कि यह नहीं होगा किसी भी आधार पर प्रश्न किए जाने योग्य को संसद की संशोधन शक्ति से परे माना गया था। क्योंकि ऐसा करने से

संसद ने जो किया था उसकी संवैधानिक वैधता का एकमात्र न्यायाधीश, और इस प्रकार, उसे वैधता निर्धारित करने की अनुमति देता है।

अपने स्वयं के कार्यों से। उपरोक्त निर्णय में, आलोचनात्मक प्रतिबिंब,

हमारे सुविचारित दृष्टिकोण को इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया था, "ह्यूमन मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *263*

[जगदीश। सिंह खेहर, जे।*]*

सरलता, असीम हालांकि यह हो सकता है, अभी तक एक तैयार नहीं किया है

प्रणाली, जिसके द्वारा लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है, सिवाय अदालतों के हस्तक्षेप के। *(iv)* एस. पी. गुप्ता मामले *(* उपरोक्त*)* में, "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" की अवधारणा पहले विचार के लिए सामने आई थी।

यह न्यायालय। यह न्यायालय इस मुद्दे की जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा।

न्यायालय के न्यायाधीश। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उनकी नियुक्ति और निष्कासन, उनके हस्तांतरण के रूप में भी, संरक्षित होने के योग्य, के भीतर

न्यायिक बिरादरी का ढांचा। इसी तरह, बाहरी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की नींव इसी तरह से बनाई गई थी

उद्देश्य। उसी के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी मानदंड निर्धारित किए गए थे। द.

स्वायत्तता। यह महसूस किया गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को तभी संरक्षित किया जा सकता है जब उपरोक्त कारणों में प्रधानता के साथ न्यायपालिका स्वयं, कार्यपालिका की न्यूनतम भागीदारी के साथ

और विधायिका। इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता

"न्यायिक समीक्षा" की शक्ति का उचित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय को प्रमुख माना जाता था। यह उल्लेख करना उचित होगा कि

एस. पी. गुप्ता मामले *(ऊपर)* में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर सुभाष शर्मा बनाम में संदेह किया गया। भारत संघ,

(1991) पूरक। *1* एससीसी *574*। इसके बाद नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले पर पुनर्विचार किया।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन *v.* संघ का भारत, *(1993) 4* एससीसी *441*। संरक्षण के विषय में

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्रता, साथ ही उनके स्थानांतरण, में पहले दर्ज स्थिति *S.P.Gupta* मामला *(ऊपर)* काफी हद तक अपरिवर्तित रहा। इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों और

सुप्रीम कोर्ट। यह दोहराया गया कि न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए

इन सभी मामलों में स्वतंत्रता, प्रधानता के साथ होना चाहिए

न्यायपालिका।

(v) इस *264* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. द्वारा दिए गए दृढ़ संकल्प को दर्ज करने के बाद।

इस आशय का न्यायालय कि "शक्तियों का पृथक्करण", "कानून का शासन" और "न्यायिक समीक्षा" एक स्वतंत्र न्यायपालिका के हाथों में,

संविधान की "बुनियादी संरचना" का गठन करते हैं, हम एक में हैं

अब यह निर्धारित करने की स्थिति है कि इस न्यायालय द्वारा वैधता पर निर्णय लेते समय उपरोक्त अवधारणाओं को कैसे अपनाया गया

उन प्रावधानों के समान, जो विचाराधीन हैं, मामले में। पहला विवाद खड़ा हुआ प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, *1985* के संदर्भ में, जो

इसे संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत अधिनियमित किया गया था। एस. पी. संपत कुमार मामले (ऊपर) में, यह निष्कर्ष निकालने की मांग की गई थी, कि "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति को उपरोक्त अधिनियम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि निवारण का मार्ग

उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत

इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय के स्थानापन्न होने के नाते, होना चाहिए था

इसका गठन इस तरह से किया गया था कि यह उसी तरीके से कार्य करने में सक्षम होगा जैसे स्वयं उच्च न्यायालय करता है। इन्सुलेशन के बाद से

न्यायपालिका को सभी प्रकार के हस्तक्षेप से, यहां तक कि सरकार की समन्वित शाखाओं से भी, अब तक माना जा रहा था

संविधान की एक बुनियादी अनिवार्य विशेषता, यह महसूस किया गया कि

कार्यकारी दबाव की संभावना से समान स्वतंत्रता या

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए प्रभाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। में।

अपने निष्कर्षों को दर्ज करते हुए, भले ही यह कहा गया था कि "न्यायिक समीक्षा" संविधान की "मूल संरचना" का एक अभिन्न अंग था, फिर भी यह माना गया कि संसद सक्षम थी।

संविधान में संशोधन करना, और उच्च के स्थान पर प्रतिस्थापित करना

न्यायालय, एक अन्य वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या व्यवस्था। हालाँकि, इस न्यायालय ने आगाह किया कि यह था

यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि वैकल्पिक व्यवस्था, उच्च न्यायालय से कम स्वतंत्र और कम विवेकपूर्ण न हो

(जिसे बदलने की मांग की गई थी) स्वयं। यह बताया गया था

यह देखते हुए कि "यदि संसद द्वारा किया गया कोई संवैधानिक संशोधन उच्च न्यायालय से इसकी शक्ति छीन लेता है

"न्यायिक समीक्षा "किसी विशेष क्षेत्र में, और इसे किसी अन्य क्षेत्र में निहित करती है। संस्थागत तंत्र या प्राधिकरण, यह मद्रास बार एसोसिएशन v का उल्लंघन नहीं होगा।

भारत का संघ 265

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

बुनियादी संरचना सिद्धांत जब तक आवश्यक शर्त पूरी हो जाती है, अर्थात्, संसद द्वारा संशोधन द्वारा स्थापित वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या प्राधिकरण कम नहीं है।

उच्च न्यायालय से प्रभावी "। संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटाकर, यह

आयोजित किया गया था, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, *1985* को प्रस्तुत करेगा

असंवैधानिक, जब तक कि के प्रावधानों में संशोधन इस न्यायालय द्वारा सुझाए गए अनुसार, इसकी धारा *4,6* और *8* को लागू किया गया था। जहाँ तक धारा *4* का संबंध है, यह सुझाव दिया गया था

कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि नियुक्ति के मामलों में कार्यपालिका को पूर्ण और निरंकुश विवेकाधिकार प्रदान न किया जा सके।

के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य

प्रशासनिक न्यायाधिकरण। धारा *6 (1) (सी)* को अमान्य माना गया था और इसलिए इसे हटाने की आवश्यकता थी। यह भी था

इंगित किया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति और

प्रशासनिक सदस्य कार्यपालिका द्वारा केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से बनाए जाने चाहिए और यह कि इस तरह का परामर्श सार्थक और प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश होती है।

इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा न करने के ठोस कारण न हों। यदि कोई कारण थे, स्वीकार नहीं करने के लिए

सिफारिश, उन्हें प्रमुख को प्रकट करने की आवश्यकता थी

न्याय। वैकल्पिक रूप से, यह सराहना की गई कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति या एक बैठक इस तरह के चयन के लिए उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय *(*भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित*)* के न्यायाधीश की स्थापना की जा सकती है। यदि नियुक्ति के इन दो तरीकों में से कोई एक था

अपनाया गया, यह माना जाता था कि विवादित अधिनियम बचा लिया जाएगा

अमान्यीकरण से। यह भी उल्लेख किया गया था कि धारा *6 (2)*

जिला न्यायाधीश या न्यायाधीश बनाने के लिए संशोधन की आवश्यकता

अधिवक्ता, जिन्होंने एक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं को पूरा किया

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। धारा *8* के संदर्भ में यह महसूस किया गया कि एक शब्द

पांच साल का कार्यकाल बहुत छोटा होगा और इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा महसूस किया गया था, क्योंकि वर्तमान में

निर्धारित कार्यकाल न तो नौकरी के लिए चुने गए व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होगा और न ही *266* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. की योजना के लिए समीचीन होगा।

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के तहत विचार किया गया निर्णय

एक्ट करें। यह भी राय दी गई कि सरकार को एक स्थायी पीठ का गठन करना चाहिए जहां कहीं भी उच्च न्यायालय का स्थान हो। और अगर यह संभव नहीं था, तो कम से कम एक सर्किट बेंच

ऐसे व्यक्तियों का सामना करना पड़ सकता है, जो उन स्थानों के पास नहीं रह रहे थे जहां न्यायाधिकरण की पीठें स्थापित की गई थीं। इस संबंध में, यह केवल यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए सभी सुझाव

स्वीकार किए गए।

(vi) एस. पी. संपत कुमार मामले के बाद *(ऊपर),* अलग

इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों में विचार व्यक्त किए गए। इसलिए एस. पी. में निर्णय दिया गया है।

संपत कुमार मामला *(ऊपर),* में पुनर्विचार के लिए आया

एल. चंद्र कुमार मामला *(ऊपर)*। पुनर्विचार पर, यह न्यायालय

घोषित किया, कि विधायी पर "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति

अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालयों में और संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कार्रवाई निहित थी। न्यायिक

समीक्षा को फिर से एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता माना गया संविधान, इसकी "मूल संरचना" का गठन करता है। यह आगे था

निष्कर्ष निकाला कि आम तौर पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, विधानों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए,

उन्हें कभी भी निष्कासित या बहिष्कृत नहीं किया जा सकता था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायिक अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर,

यह संविधान की "बुनियादी संरचना" का भी हिस्सा था। और

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करना। यह राय दी गई थी कि इस बीमारी को एक एकल छत्र संगठन बनाकर ठीक किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे न्यायाधिकरणों के सदस्यों की स्वतंत्रता, और उनकी प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन प्रदान करना।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *267*

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

हालाँकि इस तरह की भूमिका के निर्वहन के लिए सरकारी संगठन के दृढ़ संकल्प को खुला छोड़ दिया गया था, लेकिन यह सिफारिश की गई थी कि इसे अधिमानतः विधि विभाग के पास निहित किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरणों के समक्ष उत्पन्न हुए विवादों के संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वे ऐसे मामले हैं जिनमें

वैधानिक प्रावधान या नियम, या जहां संविधान के प्रावधानों का अर्थ लगाया जाना अपेक्षित था, वही होगा

कम से कम दो सदस्यीय पीठ द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए

सदस्य, जिनमें से एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए। यह पाते हुए कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रावधानों ने "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति को बाधित किया था

उच्च न्यायालय, अनुच्छेद *323* क खंड *(2) (*घ*)* आ अनुच्छेद *323* क खंड *(3) (*घ*)*

अनुच्छेद *323* बी, इस हद तक कि वे अनुच्छेद *226/227* के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाहर रखते हैं और *32* संविधान को असंवैधानिक माना गया। इसी प्रकार, अनुच्छेद *323* क के तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी विधानों में "अधिकारिता का अपवर्जन" खंड और

323 बी, को भी असंवैधानिक माना गया था। इसे ध्यान में रखते हुए ऊपर, यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अधिकारिता को प्रदान किया गया था

संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत न्यायालय, का एक हिस्सा था संविधान की अलंघनीय "मूल संरचना"। जब से कहा गया है

अधिकारिता को समाप्त नहीं किया जा सकता था, न्यायाधिकरणों में निहित अधिकार क्षेत्र को एक पूरक का निर्वहन माना जाएगा

अनुच्छेद *226/*द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भूमिका

227 और संविधान के *32.* हालांकि यह पुष्टि की गई थी कि

ऐसे न्यायाधिकरणों को स्वामित्व में माना जाएगा

वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता, यह प्रदान की गई थी कि सभी निर्णय

न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण ने आदेश पारित किया था। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायाधिकरण पहले की अदालतों की तरह कार्य करेंगे।

उदाहरण के लिए, कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में, जिनके लिए वे थे

गठित किया गया। न्यायाधिकरणों के हाथों निर्णय लेने के बाद, वादियों के लिए सीधे उच्च न्यायालयों का रुख करना खुला रहेगा।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा *5 (6)*, जिसकी व्याख्या *268* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. में की गई है।

ऊपर बताए गए तरीके को वैधता प्रदान की गई थी।

(vii) भारत संघ में *v.* मद्रास बार एसोसिएशन मामला

(उपर्युक्त*)*, ऊपर वर्णित सभी निष्कर्षों/प्रस्तावों को दोहराया गया और उनका पालन किया गया, जिसके बाद मौलिक

अदालतों से न्यायाधिकरणों में न्यायिक कार्यों को स्थानांतरित करते समय जिन आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, उन्हें और स्पष्ट किया गया। यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया कि न्यायाधिकरण

न्यायिक शक्ति के साथ निहित *(*अब तक निहित, या

न्यायिक कार्यों का निर्वहन, केवल स्रोतों से लिया जा सकता है कानून में विशेषज्ञता रखने वाले, और निर्वहन के लिए सक्षम

न्यायाधिकरण जहाँ निपटान के लिए तकनीकी विशेषज्ञता आवश्यक है मायने रखता है और अन्यथा नहीं। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां न्यायनिर्णायक प्रक्रिया न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित की गई थी, उसमें शामिल नहीं था

कोई विशेष कौशल, ज्ञान या विशेषज्ञता, तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक प्रावधान *(*इसके अलावा, या

न्यायिक सदस्यों का प्रतिस्थापन*)* की स्वतंत्रता पर भ्रम और अतिक्रमण का एक स्पष्ट मामला होगा।

न्यायपालिका, और "कानून का शासन"। न्यायाधिकरण का गठन करने वाले सदस्यों का कद अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करेगा।

जिसे न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में, यदि

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक न्यायाधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया था,

नवगठित न्यायाधिकरण के सदस्यों का कद,

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान योग्यताएँ होनी चाहिए। जबकि मामले में, अधिकार क्षेत्र और हस्तांतरण किए जाने वाले कार्यों का प्रयोग/निष्पादन किया जा रहा था

जिला न्यायाधीशों, न्यायाधिकरण में नियुक्त सदस्यों को समकक्ष योग्यताएँ और अनुरूप योग्यताएँ होनी चाहिए

जिला न्यायाधीशों का दर्जा। सदस्यों की सेवा की शर्तें ऐसी होनी चाहिए कि वे इस स्थिति में हों कि -

अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करें। उनकी नियुक्ति और हटाने का तरीका जिसमें वे भी शामिल हैं

स्थानांतरण और उनके रोजगार की अवधि में पर्याप्त मद्रास बार संगठन होना चाहिए।

भारत संघ *269*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

विधायी और कार्यपालिका से संरक्षण छीनने के लिए हस्तक्षेप। न्यायाधिकरणों का कार्य, उनकी आधारभूत संरचना और उनकी प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी

कानून और न्याय मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिए। न ही

न्यायाधिकरणों और न ही उनके सदस्यों को संबंधित मूल मंत्रालयों या विभागों से कोई सुविधा लेने की आवश्यकता होनी चाहिए।

भले ही विधायिका अधिकार क्षेत्र का पुनर्गठन कर सकती है

न्यायिक न्यायाधिकरण, और इसके सदस्यों की योग्यता/पात्रता निर्धारित कर सकते हैं, वे "न्यायिक" के अधीन होंगे।

समीक्षा "जिसमें यह अभिनिर्धारित करने के लिए न्यायालय के लिए खुला होगा कि न्यायाधिकरण न्यायनिर्णायक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा मानकों, जिसके बाद यह अदालत के लिए हस्तक्षेप करने के लिए खुला होगा

इसके साथ। इस तरह का अभ्यास स्वाभाविक रूप से इसका एक हिस्सा होगा

संविधान द्वारा प्रदत्त नियंत्रण और संतुलन उपाय

न्यायपालिका पर, विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किसी भी अतिक्रमण को रोकने के लिए "शक्तियों के पृथक्करण" के नियम को बनाए रखने के लिए।

64. पूर्वगामी में संक्षेपित कानून की स्थिति

पैराग्राफ "बुनियादी" की अवधारणा पर एक घोषणा का गठन करता है।

"शक्तियों के पृथक्करण", "कानून के शासन" और "न्यायिक समीक्षा" की अवधारणाओं के संदर्भ में संरचना। के आधार पर

ऊपर संक्षेपित निष्कर्ष, हमारे लिए हमारे सामने पेश किए गए पहले मुद्दे का उत्तर देना संभव होगा, अर्थात्, क्या

"न्यायिक समीक्षा "न्यायपालिका की मूल संरचना" का एक हिस्सा है।

संविधान। जवाब अनिवार्य रूप से सकारात्मक होना चाहिए। उपरोक्त निर्धारण से, याचिकाकर्ता चाहते हैं कि हम

आगे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति बनी हुई है

एन. टी. टी. अधिनियम की घोषणा के साथ उल्लंघन। इस न्यायालय में

मिनर्वा मिल्स लिमिटेड मामले *(ऊपर)* ने अभिनिर्धारित किया कि यह नहीं लिया जाना चाहिए कि एक प्रभावी वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या

"न्यायिक समीक्षा" के लिए व्यवस्था नहीं की जा सकी

संसद। एस. पी. संपत कुमार मामले *(उपरोक्त)* में भी यही स्थिति दोहराई गई थी, अर्थात् "न्यायिक समीक्षा" संविधान की "मूल संरचना" का एक अभिन्न अंग था। इन सभी

उसी प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संसद संविधान में संशोधन करने के लिए सक्षम है, और उच्च न्यायालय के स्थान पर, अन्य

वैकल्पिक संस्थागत तंत्र *(न्यायालय या न्यायाधिकरण)*।

यह *270* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. होगा।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस निष्कर्ष में, इस न्यायालय ने जोड़ा

एक पूर्व चेतावनी, कि वैकल्पिक संस्थागत तंत्र निर्धारित करता है

संसद द्वारा एक संशोधन के माध्यम से, स्वयं उच्च न्यायालय से कम प्रभावी नहीं होना था। एल. चंद्र कुमार मामले में

(ऊपर), भले ही इस न्यायालय ने माना कि विधायी कार्रवाई पर "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित थी, एक हिस्सा था

"बुनियादी संरचना" के बारे में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि "आम तौर पर" उच्च न्यायालयों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की शक्ति

कानूनों को कभी हटाया नहीं जा सकता था। फिर भी यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालयों में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक पर्यवेक्षण का प्रयोग करने की शक्तियां निहित हैं। उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र भी "बुनियादी" का एक हिस्सा थे

संविधान की संरचना। यह स्थिति कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने और अदालत बनाने की शक्ति थी /

भारत संघ बनाम में उच्च न्यायालय द्वारा किए जा रहे कार्यों के निर्वहन के लिए न्यायाधिकरण को दोहराया गया था। मद्रास बार

एसोसिएशन मामला *(ऊपर)*। यह निष्कर्ष निकाला गया कि संसद अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित करते हुए एक कानून बनाने में सक्षम थी।

उच्च न्यायालयों द्वारा, किसी भी निर्दिष्ट विषय के संबंध में, किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण को प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि संसद संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों में निहित शक्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकती है

इस न्यायालय द्वारा घोषित मानदंड। एतऽ हस्तांतरित अधिकारिता अछि। एन. टी. टी. अधिनियम द्वारा कर संबंधी कानूनों के तहत निर्दिष्ट विषयों के संबंध में था। कि, हमारी राय में, अनुमति होगी

ऊपर व्यक्त स्थिति की शर्तें। एन. टी. टी. अधिनियम है संविधान द्वारा न्यायालयों में निहित कोई शक्ति हस्तांतरित की गई? द.

जवाब नकारात्मक है। "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति उच्च न्यायालय में अनुच्छेद *226* और *227* के तहत निहित है।

संविधान अक्षुण्ण रहा है। इस मामले का यह पहलू है, हाथ में मुद्दे के लिए एक महत्वपूर्ण असर। और नेतृत्व भी करेंगे।

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों के लिए। इसलिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।

इस बात की अनदेखी की गई कि चूंकि मद्रास बार एसोसिएशन *v* के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालय द्वारा "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति का प्रयोग किया गया है।

संविधान अपरिवर्तित रहा है, उच्च न्यायालयों में निहित शक्ति को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर एन. टी. टी. की पीठों पर न्यायिक पर्यवेक्षण का प्रयोग करने के लिए सचेत रूप से संरक्षित किया गया है। इस स्थिति की पुष्टि की गई थी

सुनवाई के दौरान भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी।

चूँकि उच्च न्यायालय के उपरोक्त अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया गया है, इसलिए एन. टी. टी. को एक

मामले का दृष्टिकोण, यह निवेदन कि एन. टी. टी. अधिनियम का उल्लंघन करता है "संविधान की मूल संरचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

65. भले ही हमने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो

याचिकाकर्ताओं की ओर से "बुनियादी संरचना" सिद्धांत पर आधारित, हम महसूस करते हैं कि यह अभी भी हमारे लिए आवश्यक है कि हम उत्तरदाताओं की ओर से अग्रिम प्रस्तुतिकरण से निपटें।

प्रतिक्रिया दें। हम पहले आगे बढ़े विवाद को दर्ज कर सकते हैं

उत्तरदाताओं की ओर से। यह तर्क दिया गया था कि एक कानून

(संविधान में संशोधन नहीं होने के कारण), संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अधिनियमित, संबंधित विधानमंडल के दायरे में आने वाले विषय पर हमला नहीं किया जा सकता है।

इस आधार पर कि यह "मूल संरचना" का उल्लंघन करता है

इसके अलावा, संघ सूची की 77 से 79,82 से 84,95 और 97 प्रविष्टियों पर भी सातवीं अनुसूची की प्रविष्टियों 11 क और 46 पर

सातम अनुसूचीक समवर्ती सूची। इसके आधार पर यह

इस बात पर जोर दिया कि संसद एन. टी. टी. अधिनियम को लागू करने के लिए सक्षम है। तत्काल विवाद की जांच करने के लिए, आइए हम मान लें कि ऐसा ही है।

उपरोक्त को स्वीकार करने के बाद, हमारा विचार इस प्रकार है।

संविधान शासन के तरीके को नियंत्रित करता है

सभा, और राज्य विधानसभाओं वाले राज्यों में (और कुछ राज्यों में, राज्य विधान परिषदों में भी)। तत्काल विधायी शक्ति को "भाग XI" द्वारा विनियमित किया जाता है

संविधान। प्रस्तुतिकरण [2014] 10 एस. सी. आर. के हाथों आगे बढ़ा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

272

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील, जहाँ तक तत्काल

मामले के पहलू का संबंध इस दावे पर है कि एन. टी. टी. अधिनियम को सख्ती से लागू किया गया है

संविधान के "भाग 11" में दर्शाई गई प्रक्रिया। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का यह भी तर्क है कि

उक्त शक्ति का प्रयोग उस विषय के अनुरूप सख्ती से किया गया है जिस पर संसद कानून बनाने के लिए अधिकृत है।

तत्काल प्रस्तुतिकरण से निपटने के दौरान उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के हाथ, जो कुछ भी कहने की आवश्यकता है, वह यह है कि "भाग" के तहत प्रदत्त विधायी शक्ति

संविधान के 11 में एक समग्र अपवाद है, जो

निस्संदेह यह है कि संविधान की "मूल संरचना", चाहे कुछ भी हो, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तत्काल पहलू पर, कुछ

इस न्यायालय की संवैधानिक पीठों द्वारा दिए गए प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख ऊपर किया गया है। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ

याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या है और उत्तरदाता क्या पेश करना चाहते हैं, इसमें एक अच्छा अंतर है। प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाया गया

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के हाथ नहीं हैं

अधिकारिता की कमी या अधिकारिता के अनुचित प्रयोग से संबंधित है। प्रस्तुतिकरण के हाथों में आगे बढ़ा

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील स्पष्ट रूप से यह है कि इस तरह से कानून बनाना अस्वीकार्य है जो कानून का उल्लंघन करेगा।

"संविधान की मूल संरचना। इस अदालत ने बार-बार

यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के प्रावधानों में संशोधन स्थायी नहीं होगा यदि यह संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन करता है, भले ही संशोधन किया गया हो।

"भाग *XI*" के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन करके संविधान से। यह दृढ़ संकल्प की ओर ले जाता है, कि

"मूल संरचना "अलंघनीय है। हमारे विचार में, यही बात अन्य सभी विधानों (संशोधनों के अलावा) पर भी लागू होगी।

संविधान) के साथ-साथ, भले ही कानून था

निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अधिनियमित किया गया, और अधिनियमित करने वाले विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र के भीतर था, कोई भी उल्लंघन

इसलिए, उत्तरदाताओं को अनुमति नहीं दी जा सकती है। और हैं भी। तदनुसार अस्वीकार कर दिया।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *273*

*[*जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

II. क्या न्यायनिर्णायक कार्यों का हस्तांतरण निहित है

उच्च न्यायालय ने एन. टी. टी. को मान्यता प्राप्त संवैधानिक उल्लंघन का निर्देश दिया

III. चाहे वह नए बनाए गए क्षेत्राधिकार को हस्तांतरित करते समय हो न्यायालय/न्यायाधिकरण, मानकों को बनाए रखना आवश्यक है और

अदालत का दर्जा बदला गया?

66. मूल संरचना की अवधारणा पर वर्तमान विवाद के निर्णय पर निर्धारण के अलावा,

तत्काल पदार्थ की स्थिरता पर एक निर्धारण की आवश्यकता है

एन. टी. टी. अधिनियम, अन्य दृष्टिकोणों से भी। अब हम विज्ञापन देंगे।

वैकल्पिक विवादों के लिए। सबसे पहले, यह था

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का निवेदन, कि विधायिका के लिए मुख्य न्यायिक को निरस्त/विभाजित करने की अनुमति नहीं है

अपीलीय कार्य, विशेष रूप से, पारंपरिक रूप से एक उच्च न्यायालय में निहित कार्य, एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के लिए जो

सर्वोच्च न्यायालय के आवश्यक तत्व। वह क्षण प्रस्तुतिकरण फाउंडेशन पर आधारित था, कि ऐसी कार्रवाई

संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

67. यह निर्धारित करने के लिए कि अपील की जाए या नहीं

वे कार्य जो अब एन. टी. टी. के पास निहित हैं, गठित किए गए

मुख्य न्यायिक अपीलीय कार्य पारंपरिक रूप से निहित है

क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों में, हमने "ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य" शीर्षक के तहत, विधायी विवरण दर्ज किए हैं।

आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम। हम.

ऐसा करना पड़ा, क्योंकि इससे निपटने का यही एकमात्र तरीका था

विवाद का तत्काल पहलू। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि प्रारंभिक मूल्यांकन के विपरीत

कर/शुल्क देयता, चुनौती के लिए पहला मंच पारंपरिक रूप से एक कार्यकारी अपीलीय न्यायिक प्राधिकरण के साथ रहा है।

विधायी विवरणों से पता चलता है कि कुछ समय के लिए संदर्भ की शक्ति थी, जिसका प्रयोग "कानून के प्रश्नों" पर किया जा सकता था। निर्णय

इसका अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों के पास था। दूसरा।

अपीलीय उपचार हमेशा एक अर्ध-न्यायिक के समक्ष रहा है। अपीलीय प्राधिकरण, एक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में शैलीबद्ध। इसके पार

बोर्ड, उन सभी अधिनियमों के तहत जो वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक हैं, अपीलीय न्यायाधिकरण *274* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के समक्ष कार्यवाही।

विधायी रूप से "न्यायिक कार्यवाही" के रूप में वर्णित किया गया है। यह.

इसलिए, यह स्पष्ट है कि शुरू से ही, स्पष्ट है

विधायी समझ यह थी कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के चरण से, कार्यवाही "न्यायिक कार्यवाही" की प्रकृति की थी। एक बार फिर इसके पार

बोर्ड, सभी अधिनियमों के तहत, वर्तमान के लिए प्रासंगिक। विवाद, कानून के प्रश्नों को मूल रूप से छोड़ दिया गया था क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय लिया गया। संदर्भ

अधिकारिता, सभी अधिनियमों में प्रतिस्थापित किया गया था, और

अपीलीय क्षेत्राधिकार में परिवर्तित। तत्काल अपील

अधिकारिता क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के पास निहित थी। आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *260* ए के तहत एक अपील का प्रावधान किया गया है।

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से उपचार,

क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय। इसी तरह सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *129* ए और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा *35* जी

अधिनियम, *1944*, संबंधित से एक अपीलीय उपचार के लिए प्रदान किया गया

उच्च न्यायालय में अपीलीय न्यायाधिकरण। अधिकार क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय आदेशों के खिलाफ कानून के प्रश्नों पर अपीलों की सुनवाई करेगा।

अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा पारित। अतः यह स्पष्ट है कि

शुरू से ही, संविधान की घोषणा से बहुत पहले, मुख्य न्यायिक अपीलीय कार्य, के लिए

कर संबंधी विवादों का निर्णय, के साथ निहित थे

अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों ने पारंपरिक रूप से,

कानून के प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है,

उपरोक्त सभी कर कानूनों के तहत। मामले के इस दृष्टिकोण से, यह

हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के लिए यह तर्क देना उचित नहीं था कि मूल

कर मामलों में न्यायिक अपीलीय कार्य, कानून के प्रश्नों पर,

निर्बाध रूप से अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के पास निहित किया गया है। *68.* इससे पहले कि हम मामले को आगे बढ़ाएँ, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि उन न्यायिक अधिकारियों की संरचना को ध्यान में रखा जाए जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न होने वाले मामलों से निपटा है

कर कानूनों से बाहर। सबसे पहले, हम अपीलीय न्यायाधिकरणों की संरचना पर विचार करेंगे। सभी अपीलीय न्यायाधिकरण जो प्रासंगिक हैं वर्तमान विवाद के लिए अनिवार्य रूप से शामिल थे

लेखाकार या तकनीकी सदस्यों के अलावा न्यायिक सदस्य।

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *275*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, यह था

यह आवश्यक है कि पदधारी ने *10* साल की अवधि के लिए भारत में न्यायिक पद संभाला था, या इसी अवधि के लिए एक अधिवक्ता के रूप में काम किया था। यह उपरोक्त योग्यता है, जिसने सक्षम किया

कानून की एक कल्पना द्वारा, यह प्रदान करने के लिए अधिनियम कि सभी उक्त अपीलीय न्यायाधिकरण "न्यायिक कार्यवाही" का निर्वहन कर रहे थे।

अपीलीय निर्धारण का अगला चरण पारंपरिक रूप से उच्च न्यायालयों के पास निहित है। आय-कर

कानून, सीमा शुल्क कानून, साथ ही साथ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून समान रूप से प्रदान किया गया है, कि इसके अभ्यास में

अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न अपीलों पर निर्णय लेगा

संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण। उक्त अपील एक द्वारा की गई थी विधायी निर्धारण, जिसमें शामिल पीठों द्वारा सुना जाएगा

उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीश। कम से कम दो न्यायाधीशों वाली पीठ के हाथों निर्णय लेना, अपने आप में कानूनी जटिलताओं का संकेत है, जहाँ तक अपील का संबंध है।

चिंतित हैं। इसलिए, के हाथों अग्रिम प्रस्तुतियों को स्वीकार करके निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील, कि संविधान की घोषणा से पहले और बाद में, एनटीटी के अधिनियमन तक

अधिनियम, सभी विधायी प्रावधानों ने आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क से उत्पन्न निर्णय की अपीलीय शक्ति निहित की

अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम, कानून के प्रश्नों पर, अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के साथ।

69. उपरोक्त निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, निर्धारित किया जाने वाला अगला मुद्दा यह है कि क्या विवादों का निर्णय

संदर्भ के तहत प्रावधानों से उत्पन्न होना, इसके भीतर रहना चाहिए

अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों का क्षेत्र*?* वह क्षण

प्रस्ताव के दो दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले, क्या दुनिया भर में संवैधानिक व्याख्या को स्वीकार किया गया है *(*जिसका विवरण हमारे द्वारा शीर्षक के तहत सुनाया गया है-"

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रचार किए गए मुद्दे, उप शीर्षक *GEVEN* "दूसरा विवाद*")* के तहत, कर मामलों से संबंधित अपीलीय क्षेत्राधिकार के लिए, उच्च न्यायालय के साथ बने रहने के लिए एक संवैधानिक जनादेश होगा।

दूसरा, क्या एक्सप्रेस *276* सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. संविधान के प्रावधानों का आदेश है कि कर के मुद्दों को

संबंधित क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा*?*

70. हम पहले पहले परिप्रेक्ष्य पर विचार करेंगे, अर्थात्, क्या संवैधानिक व्याख्या को उस तरीके से स्वीकार किया गया है

दुनिया भर में, कर मामलों पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र के लिए एक संवैधानिक जनादेश होगा, जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।

अदालत। जहाँ तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, उससे निकलने वाले निर्णयों पर निर्भरता रखी गई थी

जमैका, सीलोन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधान,

या तो प्रिवी काउंसिल या संबंधित देशों के सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किया गया। विद्वान वकील का तर्क याचिकाकर्ताओं के लिए यह था कि उपरोक्त के संविधान

देश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित थे। यह भी बताया गया कि भारतीय संविधान भी इस पर आधारित था -

वेस्टमिंस्टर मॉडल, और यह कि, तत्काल स्थिति भारत संघ बनाम में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में मान्यता प्राप्त है। मद्रास बार एसोसिएशन मामला *(*ऊपर*)*। संयोगवश, यह

यह उल्लेख किया जा सकता है कि हमने उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद *101* को यहाँ ऊपर निकाला है, जिसमें इसे इस प्रकार दर्ज किया गया है। यह तदनुसार विद्वान वकील का तर्क है

याचिकाकर्ताओं, कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया

मामले का तत्काल पहलू, हाथ में विवाद पर पूरी तरह से लागू होगा। संवैधानिक समझौते के तहत,

की ओर से निर्दिष्ट निर्णयों में

याचिकाकर्ताओं, यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायिक शक्ति जो निहित थी

संविधान के अधिनियमन के समय निश्चित न्यायालयों के साथ

वेस्टमिंस्टर मॉडल के आधार पर, संविधान के प्रभावी होने के बाद भी, उन्हें उन्हीं अदालतों के साथ रहना पड़ा और

कार्यात्मक। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायिक शक्ति का प्रयोग पहले की तरह ही किया जाना था, यानी कि अकेले बैठे न्यायाधीश द्वारा या अन्य न्यायाधीशों के साथ। और इसलिए यह दावा किया

गया कि संवैधानिक सम्मेलनों पर दुनिया भर में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार

कर संबंधी मामलों को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहना होगा

न्यायालय, और कम से कम एक पीठ द्वारा निर्धारित किया जाना होगा

उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश, जैसा कि पहले पद था

"मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *277 [*जगदीश सिंह खेहर, जे.*]*

संविधान का अधिनियमन, और, जैसा कि उसके बाद स्थिति रही है, एन. टी. टी. अधिनियम की घोषणा तक। *71.* जहां तक पहले परिप्रेक्ष्य का संबंध है, हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के हाथों दिए गए प्रस्तुतिकरण पर विचारपूर्वक विचार किया है। हम.

के हाथों अग्रिम प्रस्तुतिकरण में पदार्थ ढूंढें

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील, लेकिन विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए प्रारूप में बिल्कुल नहीं। का एक करीबी परीक्षण

जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, वे हमें इस निष्कर्ष पर ले गए कि हर मामले में

नया संविधान, जो इसके लिए अलग प्रावधान करता है

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसे इस रूप में लिया जाता है

यह स्वीकार/स्वीकार किया गया कि "शक्तियों के पृथक्करण" का मूल सिद्धांत लागू होगा। और यह कि शासन की तीन शाखाएँ अपने निर्धारित क्षेत्र में काम करेंगी /

प्रांत। न्यायिक कार्यों के निर्वहन की शक्ति, जो थी

उच्च न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला, उस समय जब संविधान लागू हुआ था, सामान्य रूप से उस न्यायालय के पास रहना चाहिए, जो नए संविधान की घोषणा के समय उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता था। लेकिन न्यायिक शक्ति

एक अनुरूप/समान अदालत द्वारा प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है /

न्यायाधिकरण, एक अलग नाम के साथ। हालांकि, के आधार पर संवैधानिक परिपाटी, समान न्यायालय/न्यायाधिकरण का गठन करते समय, यह सुनिश्चित करना होगा कि नियुक्ति और

उस न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा समान होगी,

न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की मांग की गई। यह एक्सप्रेस था हिंड्स मामले *(*ऊपर*)* में निष्कर्ष निकाला गया। हिंड्स के मामले में यह था

स्वीकार किया, कि संसद से वर्जित नहीं थी

एक नए नाम के तहत एक अदालत की स्थापना, प्रयोग करने के लिए

अधिकारिता जिसका प्रयोग उच्च के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था न्यायपालिका, उस समय जब संविधान लागू हुआ था। लेकिन

जब ऐसा किया गया था, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि ऐसे न्यायालय/न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को उसी तरीके से नियुक्त किया जाना चाहिए, और वे इसके हकदार होने चाहिए -

न्यायिक पद के धारक के रूप में कार्यकाल की समान प्रतिभूति

वह समय जब संविधान लागू हुआ। यहां तक कि पीटर डब्ल्यू. हॉग के ग्रंथ "कनाडा के संवैधानिक कानून" में भी, यह *278* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. है।

यह देखा गया था कि यदि किसी प्रांत ने किसी प्रकार के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण का निवेश किया है, जो उचित रूप से किसी वरिष्ठ, जिला या काउंटी न्यायालय से संबंधित होना चाहिए, तो वह न्यायालय/न्यायाधिकरण (उसके स्थान पर बनाया गया), संवैधानिक उद्देश्यों के लिए इसका आधिकारिक नाम जो भी हो,

एक वरिष्ठ, जिला या काउंटी न्यायालय को प्रतिस्थापित करते समय, प्रतिस्थापित न्यायालय की आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करता है। इसका मतलब यह होगा कि नवगठित न्यायालय/न्यायाधिकरण को माना जाएगा। अमान्य रूप से गठित किया जाना, जब तक कि इसके सदस्यों को उसी तरीके से नियुक्त नहीं किया जाता है, और जब तक कि इसके सदस्य इसके हकदार नहीं हैं

सेवा की शर्तें, जो न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध थीं

अदालत ने प्रतिस्थापित करने की मांग की। संदर्भ के तहत निर्णयों में यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि उपरोक्त का उल्लंघन

संवैधानिक परंपरा को अच्छे इरादे से माफ नहीं किया जा सकता था (जिसके द्वारा विधायी शक्ति का प्रयोग किया गया था)

कानून दिया गया)। हम संतुष्ट हैं कि उपरोक्त व्याख्या

विधि, इस न्यायालय द्वारा व्यक्त स्थिति के अनुरूप है,

"शक्तियों के पृथक्करण" की अवधारणाओं से निपटने के दौरान,

साथ ही, भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसोसिएशन मामला (ऊपर)। इसमें, इस न्यायालय ने मान्यता दी है कि

अधिकारिता अनुमत है, लेकिन इस तरह के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने में,

जिस न्यायालय को न्यायनिर्णयन की शक्ति हस्तांतरित की जाती है, उसे मुख्य विशेषताओं के साथ सहन किया जाना चाहिए, जो उनके पास थीं

वह न्यायालय जिससे न्यायनिर्णायक शक्ति प्राप्त की गई है

स्थानांतरण किया गया। प्रस्तुतिकरण पर हमारे निष्कर्षों को दर्ज करने में

पहले परिप्रेक्ष्य के रूप में उन्नत, हम केवल यह कह सकते हैं कि हमारे निष्कर्ष ठीक वैसा ही है जैसा हमारे द्वारा निकाला गया था जबकि

याचिकाकर्ताओं के पिछले निवेदन की जांच करना, अर्थात्, कि हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है, कि मान्यता प्राप्त है

संवैधानिक सम्मेलन, न्यायिक शक्ति उच्चतर में निहित

न्यायालयों को न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के समन्वय के लिए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति है। लेकिन जब भी ऐसा स्थानांतरण होता है, अदालत के सभी सम्मेलनों/रीति-रिवाजों/प्रथाओं

प्रतिस्थापित किए जाने की मांग की गई है, जिसे न्यायालय में शामिल किया जाना है /

न्यायाधिकरण बनाया गया। नवनिर्मित न्यायालय/न्यायाधिकरण की स्थापना मद्रास बार एसोसिएशन *v* की मुख्य विशेषताओं के अनुरूप की जानी चाहिए।

भारत संघ *279*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

72. अब हम दूसरे परिप्रेक्ष्य पर विचार करेंगे, अर्थात्, क्या भारतीय संविधान के प्रावधान स्वयं हैं। आदेश, कि अपीलीय स्तर पर कर के मुद्दों को सुना जाना चाहिए

संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय द्वारा। जहां तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने संविधान के अनुच्छेद *50* और *225* पर भरोसा जताया।

संविधान। संविधान के अनुच्छेद *50* पर भरोसा किया गया था -

संविधान निर्माताओं के इरादे को प्रदर्शित करें,

अर्थात्, कि वे विशिष्टता सुनिश्चित करना चाहते थे और

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। यह आवश्यक नहीं है। हमारे लिए मामले के तत्काल पहलू से निपटने के लिए, इस कारण से कि, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में जो

ऊपर हमारे द्वारा संदर्भित, मुद्दा पहले से ही किया जा चुका है संविधान के अनुच्छेद *50* के संदर्भ में बहस की गई।

73. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा जिस अन्य प्रावधान पर भरोसा किया गया है, वह संविधान का अनुच्छेद *225* है। द टेनर

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा आगे की गई प्रस्तुति, हमारे द्वारा दर्ज की गई है दूसरा विवाद (याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे बढ़ाया गया)। द.

ऐसा ही कहा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संविधान का अनुच्छेद *225* स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि मौजूदा उच्च न्यायालयों और संबंधित न्यायालयों की अधिकारिता

उसके न्यायाधीशों की शक्तियाँ "तत्काल समान होंगी।

संविधान के प्रारंभ से पहले "। यह भी है स्पष्ट रूप से, कि इसके लिए परंतुक स्पष्ट रूप से आदेश देता है, कि कोई भी प्रतिबंध जिसके लिए किसी भी द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है

राजस्व से संबंधित किसी मामले के संबंध में या संग्रह में आदेशित या किए गए किसी कार्य से संबंधित उच्च न्यायालयों के

संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इसका विषय था जो अब ऐसी अधिकारिता के प्रयोग पर लागू नहीं होगा। जहाँ तक विवाद से बाहर निकलने की बात है

परंतुक का संबंध है, यह इंगित करने की आवश्यकता है कि यह "किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग" से संबंधित है। अतः यह स्पष्ट है कि मुद्दा हाथ में है,

अर्थात्, अपीलीय अधिकारिता अधिकारिता *[2014] 10* एस. सी. आर. के साथ निहित है।

280 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत,

सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम का संदर्भ के तहत प्रावधान से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम रिकॉर्ड करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि

याचिकाकर्ताओं की ओर से त्वरित प्रस्तुतिकरण, संविधान के अनुच्छेद *225* से नहीं बनाया गया है।

IV. क्या कंपनी सचिवों को उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए एन. टी. टी. के समक्ष उसी में एक अपील के लिए एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए

फैशन, और लेखाकारों के साथ समानता पर *' V.* क्या एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *13 (1)* जहां तक लेखाकारों को एन. टी. टी. के समक्ष अपील में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देती है।

वैध है*?*

74. हम पहले विचार के लिए विचार कर सकते हैं, रिट याचिका (सिविल) नं। *621 2007* से। सदस्यों द्वारा भी यही दायर किया गया है।

भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान, की मांग

किसी पक्ष के प्रतिनिधियों के रूप में एन. टी. टी. के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार

एक अपील के लिए। उत्तरदाता नं. *5* उक्त रिट याचिका में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स है। यह उपस्थिति में प्रवेश कर गया है

और प्रचार किया कि कंपनी सचिवों का दावा और चार्टर्ड एकाउंटेंट की तुलना नहीं की जा सकती है। इंगित करते हुए कि

किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट की अनुमति

उनके विशेष कौशल के कारण एनटीटी के समक्ष एक अपील, उनका दावा है कि यह मुद्दा कंपनी की ओर से उठाया गया है

सचिव नीति का विषय है। और इसलिए यह नहीं होगा

समानता के कारण, इस न्यायालय को अधिकार प्रदान करने के लिए खुला है

75. उपरोक्त विवाद की जांच करते समय, हम वास्तव में एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *13* पर विचार करेंगे, जो पहले से ही लागू है। अग्रिम प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड करते समय निकाला गया

चौथे विवाद के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की ओर से। उक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि अपील का एक पक्ष *(*राजस्व के अलावा*)* या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है, या हो सकता है

एक या अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट, या कानूनी को अधिकृत करें

व्यवसायियों, या उनके द्वारा विधिवत अधिकृत कोई भी व्यक्ति, मद्रास बार एसोसिएशन *v* प्रस्तुत करने के लिए।

भारत संघ *281*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

एन. टी. टी. के समक्ष उसका मामला। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से दिया गया स्पष्ट निवेदन था,

कि एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *13* के तहत, चार्टर्ड एकाउंटेंट

एन. टी. टी. के समक्ष उपस्थित होने के हकदार हैं, क्योंकि उनके

पहचानी गई कुशाग्रता। यह प्रस्तुत किया गया था कि व्यक्तियों का निर्धारण करना विधायिका का विशेषाधिकार और नीति का विषय है

जो एन. टी. टी. के समक्ष उपस्थित होने के हकदार हैं। यह बताया गया था,

कि न्यायालयों को आम तौर पर ऐसे नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

इसलिए, यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड के लिए विद्वान वकील है

भारत के लेखाकारों ने निर्णय पर भरोसा रखा है

दिल्ली प्रदेश पंजीकृत चिकित्सा में इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत

प्रैक्टिशनर वी। स्वास्थ्य निदेशक, दिल्ली प्रशासन सर्विसेज, *(1997) 11* एस. सी. सी. *687*, जहाँ से हमारा ध्यान गया है।

निम्नलिखित टिप्पणियों के लिए आमंत्रित किया गया थाः

"2. जारी की गई सार्वजनिक सूचना की औचित्य और वैधता निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, दिल्ली प्रशासन द्वारा

यह दर्शाता है कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद ने मान्यता प्राप्त आयुर्वेद रत्न और वैद्य विशारद उपाधियाँ

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा सम्मानित,

इलाहाबाद केवल *1967* तक और आयुर्वेद का प्रमाण पत्र

किसी भी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा के रूप में प्राप्त पंजीकरण अतः ऐसी डिग्री के आधार पर व्यवसायी

मान्यता प्राप्त नहीं है और कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसा है

योग्यता दिल्ली में अभ्यास करने की हकदार नहीं होगी

इन अपीलों में आरोपित। यह भी बताया गया है कि सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि कोई भारतीय विश्वविद्यालय या बोर्ड नहीं

स्नातक देने के लिए एक साल का पाठ्यक्रम आयोजित करता है

आयुर्वेदिक चिकित्सा में या पत्राचार के माध्यम से डिग्री

आयुर्वेद में एम. डी. की डिग्री किसी भी पाठ्यक्रम द्वारा प्रदान की गई थी।

विश्वविद्यालय या बोर्ड। बड़े पैमाने पर जनता को आगाह किया गया था

अखबार में प्रकाशित उक्त सार्वजनिक सूचना के बारे में

कानून में ऐसी स्थिति।

XXX

XXX

XXX!

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

5. लेकिन हम इस तरह के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

यह परिकल्पना की गई है कि जहां उक्त अधिनियम के अधिनियमन से पहले भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, *1970* अपेक्षित योग्यता के आधार पर, जिसे तब मान्यता दी गई थी, एक व्यक्ति

स्वयं को चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत किया

उक्त अधिनियम के तहत विचार किए गए विषय या पंजीकरण के लिए किसी भी आवश्यकता के अभाव में ऐसा व्यक्ति पाँच साल से अभ्यास कर रहा था या होने का इरादा था

पंजीकृत था और पंजीकृत होने का भी हकदार था, अधिकार

संबंधित अनुशासन में अभ्यास करने के लिए ऐसे व्यक्ति का

एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के विशेषाधिकारों सहित

संरक्षित था, भले ही इस तरह के व्यवसायी ने नहीं किया था *1970* के उक्त अधिनियम के तहत अपेक्षित योग्यता रखने वाले।

यह संकेत दिया जा सकता है कि हमारे बारे में ऐसा दृष्टिकोण उप परिचय के लिए इंगित वस्तुओं और कारणों से परिलक्षित होता है।

अधिनियम की धारा *17* की धारा *(3)*। वस्तुओं में और

कारणों का उल्लेख किया गया था:

"[समिति की राय है कि भारतीय व्यवसायियों के मौजूदा अधिकार और विशेषाधिकार दवाइयों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय दिए जाने चाहिए।

समिति ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उप-धारा में तीन नए पैराग्राफ जोड़े हैं।

(3) (1) अभ्यास करने के अधिकारों की रक्षा करने वाले खंड का

भारतीय चिकित्सा के उन चिकित्सकों में से जिनके पास, प्रस्तावित कानून के तहत, नहीं हो सकता है

मान्यता प्राप्त योग्यता इस शर्त के अधीन कि

वे शुरू होने की तारीख से ही भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामांकित हैं।

इस अधिनियम, *(ii)* को प्रदत्त विशेषाधिकार उस राज्य में लागू किसी भी कानून के तहत राज्य रजिस्टर में नामांकित भारतीय चिकित्सा के चिकित्सक, और

((iii) उन राज्यों में अभ्यास करने का अधिकार।

अभ्यासकर्ता जो भारतीय अभ्यास कर रहे हैं

उस राज्य में कम से कम पाँच वर्षों के लिए चिकित्सा-एड्रस बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *283*

[जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

जहाँ भारतीय चिकित्सा का कोई रजिस्टर नहीं था

पहले रखा गया "।

चूंकि यह किसी भी रिट याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि उन्होंने *1957 (*एस. आई. सी. *1967)* के बीच डिग्री प्राप्त की थी और

1970 या प्रावधानों के प्रवर्तन की तारीख को उक्त अधिनियम की धारा *17 (2)* और स्वयं को प्राप्त किया

पंजीकृत होने का पंजीकृत या अर्जित अधिकार, की उप-धारा *(3)* के तहत संरक्षण प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं है।

उक्त अधिनियम की धारा *17*। यहाँ यह कहा जाना चाहिए कि उक्त केंद्र की वैधता के बारे में भी कोई चुनौती नहीं है।

अधिनियम, *1970*। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

अपीलार्थियों द्वारा हमला नहीं किया जा सकता है। हम संकेत दे सकते हैं

यहाँ यह श्री मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसके द्वारा भी

सुश्री सोना खान से उत्पन्न अपील में उपस्थित हुईं *1993* की विशेष अनुमति याचिका सं. *6167* जो उचित है।

मानक पर विचार नहीं किया गया था

उक्त हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दी गई शिक्षा,

धारक द्वारा अर्जित प्रयाग और विशेषज्ञता

उक्त संस्थान द्वारा प्रदत्त उपरोक्त उपाधियाँ। किसी भी स्थिति में, जब उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी गई हों समाज के गरीब वर्गों की एक बड़ी संख्या के लिए उपलब्ध, रिट की तरह चिकित्सकों पर लगाया गया प्रतिबंध

जरूरतमंदों और गरीबों को उपयोगी सेवा प्रदान करने वाले याचिकाकर्ता

न्यायालय इस तरह की दलीलों पर विचार करेगा क्योंकि अन्य के नीतिगत निर्णय के दायरे में रहता है

संवैधानिक कार्यकर्ता। हम यहाँ यह भी संकेत दे सकते हैं कि

उचित शिक्षा और अपेक्षित विशेषज्ञता क्या है

भारतीय चिकित्सा में एक चिकित्सक के लिए, इस विषय में आवश्यक ज्ञान रखने वाले उचित प्राधिकारी पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय उक्त केंद्रीय अधिनियम से बहने वाली कानूनी स्थिति के सामने उचित है

1970, हमें नहीं लगता कि इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया गया है

बुलाया जाता है। इसलिए ये अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।

लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

ians को राजस्थान राज्य *v* पर भी रखा गया था। लता अरुण,*02) 6* एस. सी. सी. *252*, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

"*4.* इस मामले में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है

क्या प्रत्यर्थी के पास पात्रता योग्यता थी

जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी और स्टाफ में प्रवेश के लिए

नर्स पाठ्यक्रम (इसके बाद "नर्सिंग पाठ्यक्रम" के रूप में संदर्भित)

इसकी शुरुआत *1990* में हुई थी। निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं ने *15-12-1989* द्वारा आवेदन आमंत्रित किए थे।

नर्सिंग में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों से पाठ्यक्रम जनवरी *1990* से शुरू किया जाएगा। में कहा गया है कि

अधिसूचना कि उम्मीदवारों को पहले उत्तीर्ण होना चाहिए था

तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (टी. डी. सी.) या *10 + 2* का वर्ष; और वह

विज्ञान विषयों (जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान,

भौतिकी) को वरीयता दी जाएगी। इस अवधि में,

भारतीय नर्सिंग परिषद ने पाठ्यक्रम का एक सेट जारी किया था और

सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी में पाठ्यक्रमों के लिए नियम

जिसमें निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

सभी उम्मीदवारों के लिए *12* वीं कक्षा-उत्तीर्ण या इसके समकक्ष था

अधिमानतः विज्ञान विषयों के साथ।

XXX

XXX

XXX

10. मामले में शामिल बिंदु दो गुना हैंः एक संबंधित

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए

पाठ्यक्रम में प्रवेश और अन्य संबंधित

द्वारा जारी मध्यमा प्रमाणपत्र की मान्यता

हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद के समतुल्य या

के उद्देश्य के लिए *+ 2* या टी. डी. सी. के पहले वर्ष से अधिक

प्रवेश। ये दोनों बिंदु क्षेत्र के मामलों से संबंधित हैं। राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले नीतिगत निर्णय का या

किसी भी कानून के तहत शक्ति के साथ निहित प्राधिकरण। यह नहीं है।

अदालतों के लिए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष शैक्षिक उम्मीदवार के पास योग्यता होनी चाहिए या होनी चाहिए

निर्धारित के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है

मामले में योग्यता। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे मामले

न्यायसंगत नहीं हैं। एक उपयुक्त मामले में अदालत कर सकती है

जांच करें कि क्या नीतिगत निर्णय या प्रशासनिक मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *285*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

मामले से निपटने का आदेश एक निष्पक्ष, तर्कसंगत और उचित आधार पर आधारित है*;* क्या निर्णय लिया गया है

मामले के प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया गया*;* क्या शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्राप्त किया गया है*;* क्या निर्णय भर्ती किए गए उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य को पूरा करता है या यह आधारित है।

अप्रासंगिक और तर्कहीन विचारों पर या करने का इरादा किसी व्यक्ति या उम्मीदवारों के समूह को लाभान्वित करें।

76. उपरोक्त प्रस्तुतियों के अलावा यह तर्क दिया गया था,

कि सनदी लेखाकारों को पहले उपस्थित होने की अनुमति है

बड़ी संख्या में न्यायाधिकरण/मंच। सचित्र रूप से यह प्रस्तुत किया गया था,

कि आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *288* के तहत,

आयकर नियम, *1962* का नियम *50*, चार्टर्ड एकाउंटेंट

आयकर मामलों में उपस्थित होने की अनुमति है। इसी तरह, यह दावा किया गया कि चार्टर्ड एकाउंटेंट इसमें उपस्थित होने के हकदार हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क मामले केंद्रीय अधिनियम की धारा *35Q* के तहत

उत्पाद शुल्क अधिनियम, *1944*। उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, *1962 (*जिसके लिए सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *146* ए पर निर्भरता रखी गई थी*)* से उत्पन्न मामलों में भी पेश होने की अनुमति है। नियम *9 (*ए*)*, सीमा शुल्क *(*अपील*)* नियम, *1982)*। उपरोक्त प्रावधानों के अलावा, यह तर्क दिया गया था कि चार्टर्ड

लेखाकार विभिन्न न्यायाधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने के हकदार थे / विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत मंच, जैसे कि

प्रतिभूति अनुबंध *(*विनियमन*)* अधिनियम, *1956*, दूरसंचार भारतीय विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, *1991*, कंपनी अधिनियम,

2013 , कंपनी विधि बोर्ड विनियम, *1991*

प्रतिस्पर्धा *(*संशोधन*)* अधिनियम, *2007* और विशेष

आर्थिक क्षेत्र नियम, *2006*। हमें सूचित किया गया था कि चार्टर्ड

लेखाकार दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष उपस्थित होने के भी हकदार थे

27.8.1999 . यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि चार्टर्ड एकाउंटेंट जटिल विवादों का प्रचार करने में सक्षम हैं जो इसके तहत उत्पन्न होते हैं

ऊपर उल्लिखित प्रावधान, नहीं होना चाहिए

उन्हें एन. टी. टी. के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति देने में कठिनाई, और साथ ही,

उन्हें *286* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य मानना।

एनटीटी। इसलिए यह दावा किया गया कि एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *13* ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी है।

एन. टी. टी. के समक्ष अपील के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी

सचिवों की उनके साथ तुलना नहीं की जाती थी, और इसलिए,

नीतिगत रूप से, उनके पास एन. टी. टी. के समक्ष किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति का कोई वैध दावा नहीं था।

77. यह अभिलिखित करना उचित है कि इस दौरान

सुनने के लिए हमें प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील की आवश्यकता थी याचिकाकर्ता, मामलों का एक संकलन दायर करने के लिए, जिसमें प्रावधान हैं

विभिन्न विषयों पर विभिन्न कानूनों को शामिल करना पड़ा

कर संबंधी विवादों का निर्णय लेते समय विचार करना। में।

अनुपालन, विद्वान वकील ने मद्रास बार एसोसिएशन (स्थानांतरित मामले में) की ओर से एक संकलन प्रस्तुत किया है

(सिविल) नहीं। 150 2006 का), चित्रण के माध्यम से सारणीबद्ध, रिपोर्ट किया गया

हमारा नोटिस संक्षेप में नीचे दिया गया हैः 1 : हिंदू कानूनः

संबद्ध विषय/न्यायनिर्णित कानून

एस. एल. नहीं।

नाम और मामले का उद्धरण

उस पर

हिंदू मूर्ति एक न्यायिक इकाई है।

1

श्री श्री श्रीधर

ज्यू वी. आईटीओ.

जिसे एक का दर्जा दिया जाता है

(1967) 63 आईटीआर

मनुष्य सक्षम है

192 (कैल)

संपत्ति होना और यह हो सकता है जिसे 'व्यक्ति' कहा जाता है।

हालाँकि एक विधवा सह-भागीदार नहीं हो सकती है, लेकिन उसने

2

सी. ई. डी. वी. अल्लादी

कुप्पुस्वामी

(1977) 108 आईटीआर

सहकारी हित और वह

439 (एससी*)*

के आधार पर सह-पार्टी का सदस्य भी है

हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों द्वारा प्रदत्त अधिकार

अधिनियम, *1937*।

बार एसोसिएशन के रूप में *v.* भारत संघ *287*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

नरेंद्रनाथ बनाम।

कोई भेद नहीं है

सी. डब्ल्यू. टी. *(1969)*

सदस्य द्वारा प्राप्त संपत्ति

74 आईटीआर *190 (*एससी*)*

एक विभाजन पर एच. यू. एफ. और

ऐसी संपत्ति जो एक

एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में

के अधिकार से सह-भागीदार

उत्तरजीविता।

गोली ईश्वरिया बनाम।

एक एकतरफा घोषणा

सी. जी. टी. *(1970) 76*

हिंदू सह-भागीदार, जिसके द्वारा वह

अपने आत्म-अर्जित को फेंक देता है

आईटीआर *675 (*एससी*)*

सामान्य स्टॉक में संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति,

हस्तांतरण के लिए राशि नहीं है

और, इसलिए, इस तरह के एक अधिनियम

यह एक उपहार नहीं है।

सी. आई. टी. वी. संध्या

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

रानी दत्ता *(2001)*

पत्नी और बेटियाँ

एक की संपत्ति को विरासत में लेना

248 आईटीआर *201 (*एससी*)*

पुरुष हिंदू एचयूएफ नहीं बनाते हैं।

और यह कि वे भी समझौते से ऐसा परिवार नहीं बना सके

आपस में फेंक कर

उनके संबंधित विरासत में मिले

हॉटस्पॉट में शेयर करें।

सी. आई. टी. वी. भारत

एच. यू. एफ. की संपत्ति का उपहार

परिवार के सदस्य हैं

प्रसाद अंशु

कुमार *(2001) 249*

शून्य नहीं बल्कि शून्य है।

आईटीआर *755 (*दिल्ली*)*

यहाँ तक कि यह तथ्य कि पत्नी ने अपना अधिकार छोड़ दिया था

सी. डब्ल्यू. टी. वी. एम. ए. आर. राजकुमार *(1997) 226* आई. टी. आर. *804 (*एपी*)*

रखरखाव का मतलब यह नहीं है कि वह अब सदस्य नहीं है

अपने पति के परिवार से।

288 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

सी. जी. टी. वी. बी. एस

एक हिंदू द्वारा खर्च की गई राशि

8

पिता अपनी बेटी पर

अप्पाराव *(2001) 248* आईटीआर *103 (*एपी*)*

विवाह के रूप में माना जाता है

रखरखाव *(*और उपहार नहीं*)*

हिंदू गोद लेने के तहत और

रखरखाव अधिनियम, *1956*।

गौली बुद्धन्ना बनाम।

एकमात्र जीवित सह-भागीदार

9

हिंदू बन सकता है

सी. आई. टी. *60* आई. टी. आर. *293*

अविभाजित परिवार।

(एससी*)*

सी. डब्ल्यू. टी. वी. चंदर

की अलग संपत्ति

10

पिता को निर्वसीयतता पर विरासत में मिला

सेन *161* आईटीआर *370 (*एससी*)*

पुत्र के रूप में व्यवहार किया जाना है

पुत्र की अलग संपत्ति और

उसकी संयुक्त संपत्ति के रूप में नहीं

परिवार।

11 सी. आई. टी. वी. राधे

यदि परिवार के विभाजन पर,

अलग-अलग शेयर आवंटित किए जाते हैं

श्याम अग्रवाल *230* आईटीआर *21*

कर्ता, उसकी पत्नी और बच्चे, हिंदुओं का अस्तित्व

(पटना*)*

अविभाजित परिवार आता है

पूर्व कर्ता उसका बन जाता है अलग संपत्ति।

12

कनीराम

एक संयुक्त हिंदू परिवार, जैसे,

हज़ारीमुल बनाम। सी. आई. टी. *27* आई. टी. आर. *294 (*कैल*)*

किसी फर्म में भागीदार नहीं हो सकता है। हालांकि, यह एक में प्रवेश कर सकता है

अपने कर्ता के माध्यम से साझेदारी।

13 सी. आई. टी. वी. बैनिक

एक महिला सदस्य के रूप में

एक संयुक्त परिवार के सदस्य, कर सकते हैं

उद्योग

119 आई. टी. आर. *282* पैट*)*

किसी फर्म में भागीदार बनें

उसके परिवार का प्रतिनिधि।

सी. जी. टी. वी. गेटी।

के बीच असमान विभाजन

14

एच. यू. एफ. में सह-भागीदार नहीं होते हैं

चेट्टियार *82* आई. टी. आर. मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *289*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

599 (एससी*)*

उपहार के लिए राशि।

एक एचयूएफ के पुनर्मिलन में, सभी

परमानंद

15

बजाज वी. सी आई टी।

मूल रूप से विभाजित परिसंपत्तियाँ

135 आईटीआर *673 (*कर*)*

वापस जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

:

पुष्पा देवी बनाम।

16

के सिद्धांत का दायरा

हिंदू कानून में सम्मिश्रण था

सी. आई. टी. *109* आई. टी. आर

विस्तार से चर्चा की।

730 (एससी*)* सी. आई. टी. वी. बी.

द्वारा निष्पादित उपहार विलेख

17

उसके पक्ष में निर्धारिती

इंदिरा देवी

बेटी अपने भविष्य को सुरक्षित करेगी

238 आईटीआर *846*

(केर*)*

शादी के बाद नहीं हुआ था

कोई भी कानूनी दायित्व

के आधार पर निर्धारिती पर हिंदू की धारा *20*

गोद लेने और रखरखाव

अधिनियम, लेकिन अन्य के लिए

विचार करें। इसलिए,

दान के भीतर स्वैच्छिक होना

धारा *2 (xii)* का अर्थ उपहार कर अधिनियम, *1964*, उत्तरदायी था -

कर।

18 सत्यप्राना

"सह-सहभागी", "एच. यू. एफ". और "उत्तरजीविता" का अर्थ

मंजूनाथ

चर्चा की।

गौड़ा बनाम। सी. ई. डी. *227* आईटीआर *130 (*एससी*)*

19

सी. आई. टी. वी.

द्वारा रखे गए शेयरों से आय

शकुंतला

एच. यू. एफ. के सदस्य नहीं हो सकते

(1961) 43 आईटीआर

इसे एच. यू. एफ. की आय कहा जाता है।

352 (एससी*)*

विभाजित सदस्य एक से शादी करता है

20

सी. डब्ल्यू. टी. वी. स्वर्गीय आर.

श्रीधरन *104* आईटीआर

विशेष के तहत ईसाई

436 (एससी*)*

विवाह अधिनियम, *1956*।

एच. यू. एफ. वा *290* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

विभाजित जीवन जीने का अभ्यास सदस्य और बेटा-जारी रखें

बी एच. यू. एफ.-शब्द का अर्थ

" हिंदू "चर्चा की।

II: कंपनी कानूनः

संबद्ध विषय/न्यायनिर्णित कानून

एस. एल. कोई नाम नहीं और

मामले का उद्धरण

उस पर

सी. आई. टी. वी. रोशनी।

1

एक निजी कंपनी के आधार पर एक सार्वजनिक कंपनी बन रही है

प्रकाशन लिमिटेड

(2001) 251 आईटीआर

की धारा *43* ए के प्रावधान

0120 (गुज.*)*

कंपनी अधिनियम*, 1956* अभी भी एक ऐसी कंपनी नहीं बन सकती है जिसमें जनता है।

अपने शेयरधारकों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण काफी रुचि रखते हैं

इसके शेयरों की हस्तांतरणीयता

अन्य सदस्यों ने

सार्वजनिक।

2

सी. आई. टी. वी. सुनारो

अनुमान है कि एक पंजीकृत

लिमिटेड *(2012) 345*

शेयरधारक हिस्सेदारी रखता है

आईटीआर *0163 (*डेल*)*।

उसका अपना अधिकार और कोई भी दावा कि

शेयर एक के रूप में रखे जा रहे थे

उम्मीदवार को साबित करना होगा

ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति।

राजस्थान

एकल प्रकार के शेयर जारी किए गए

3

वित्तीय

एक राज्य वित्तीय द्वारा

निगम बनाम।

निगम प्रदान करता है

सी. आई. टी. *163* आई. टी. आर

न्यूनतम और अधिकतम लाभांश को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

278 *(* राज*)*

*'*वरीयता शेयर *'*।

4

बाचा एफ.

(i) साझेदारी केवल एक

व्यक्तियों का संगठन

गुज़दार बनाम। सी आई टी।

ऑन वी. भारत संघ *291* एच. खेहर, जे. जे.

साझेदारी और, कानून में, फर्म नाम एक संग्रह है

वर्णन करने की विधि भागीदार। लेकिन ऐसा नहीं है

एक कंपनी का मामला जो

एक अलग न्यायिक के रूप में खड़ा है

इकाई से अलग शेयरधारक।

((ii) शेयरधारकों का कंपनी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।

वे केवल इसके हकदार हैं

अधिशेष, यदि कोई हो, के बाद कंपनी का विघटन।

हालांकि कंपनी एक है

अलग कानूनी इकाई, में

कुछ अपवादात्मक मामले,

न्यायालय उठा सकता है

निगमित इकाई का पर्दा

और ध्यान रखें कि

इसके पीछे की आर्थिक वास्तविकताएँ

कानूनी अग्रभाग।

शेयरों का मूल्यांकन-उचितः मूल्यांकन स्वीकार किया जाना चाहिए।

जब तक मूल्यांकन के झटके न लगें

अदालत का विवेक।

कंपनी कानून में, कोई नहीं है

शेयर का हस्तांतरण जब वहाँ हो

एक अंतर्निहित हस्तांतरण है संपत्ति। उठाने के विभिन्न मुद्दे

कॉर्पोरेट घूंघट की चर्चा की गई।

संक्षेप में इस पर भी चर्चा की गई

शेयरधारकों की प्रवर्तन क्षमता *[2014] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

292

समझौते।

20 प्रमुख भागीदारों की एक फर्म और

8

सी. आई. टी. वी. सुलेमान

खान और

3 छोटे भागीदार नहीं करते हैं

धारा *11 (2)* का उल्लंघन

महबूब खान

एंड कंपनी *(2002)*

कंपनी अधिनियम, *1956*

क्योंकि नाबालिगों को नहीं होना चाहिए

257 आईटीआर *070* (एपी)

के लिए भागीदारों के रूप में माना जाता है

गणना के उद्देश्य। विलय-तिथि

9

मार्शल सन्स

एंड कंपनी *(भारत)*

हस्तांतरण/समामेलन की तिथि

/स्थानांतरण निर्दिष्ट तिथि है

लिमिटेड वी. आई. टी. ओ. *(1997) 223* आईटीआर

हस्तांतरण के रूप में योजना में

809 (एससी*)*

तिथि.

10

सी. आई. टी. वी. श्रीमती.

a) समामेलन पर एक है

ग्रेस कोलिस

अधिकारों का उन्मूलन और,

इसलिए, एक स्थानांतरण है

और अन्य *248* आईटीआर *323 (*एससी*)*

ख*)* समामेलन योजना

अदालत ने दी मंजूरी

के भीतर एक साधन बनें

धारा *2 (1)* का अर्थ बॉम्बे स्टाम्प एक्ट, *1958* और

मुद्रांक शुल्क के लिए उत्तरदायी। ए.

दस्तावेज़ बनाना या

एक अधिकार का हस्तांतरण एक है यंत्र।

वरीयता का विमोचन

11

अनारकली

साराभाई बनाम। सी आई टी।

हस्तांतरण के लिए शेयरों की राशि और

227 आईटीआर *260 (*एससी*)*

पूँजीगत लाभ के लिए उत्तरदायी है।

12

सी. आई. टी. वी. आर्टेक्स

बिक्री में गिरावट से हुए लाभ

विनिर्माण कंपनी।

एक चालू चिंता के रूप में व्यवसाय

227 आईटीआर *260 (*एससी*)*

धारा के तहत कर के लिए उत्तरदायी है

41 (2) मदबद्ध आधार पर यदि गिरावट आती है

बिक्री का निर्धारण मूल्यांकन पर किया जाता है।

प्रत्येक परिसंपत्ति/देयता।

बार एसोसिएशन के रूप में *v.* भारत संघ *293*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

बोनस शेयरों का मूल्यांकन -

सी. आई. टी. वी. सोना

आवेदन करने का सही तरीका

मोहोर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

ऐसे मामले जहां बोनस शेयर

(1970) 78 आईटीआर *16*

रैंक परी पासू लेना है

मूल शेयरों की लागत और

(एससी*)*

इसे सभी मूल में फैलाने के लिए

और औसत का पता लगाने के लिए सभी शेयरों की कीमत।

हंसूर प्लाईवुड

जब किसी शेयरधारक को एक

वर्क्स लिमिटेड *v.* सी आई टी।

बोनस का मूल्य साझा करें

(1998) 229 आईटीआर

उनके द्वारा रखा गया मूल हिस्सा जाता है

112 (एससी*)*

नीचे। वास्तव में, शेयरधारक

उसके पास एक हिस्सा था और बाजार मूल्य और साथ ही

दोनों शेयरों का आंतरिक मूल्य

एक साथ रखना समान होगा या

मूल्य के लगभग समान

इससे पहले का मूल हिस्सा

बोनस का मुद्दा।

श्री गोपाल

शेयर जारी किया जाता है

पेपर मिल्स लिमिटेड

नाम की प्रविष्टि करते समय

वी. सी. आई. टी. *(1967)*

अभिदाता या सफल

64 आई. टी. आर. *233* (कैल*)*

प्रस्तावक रजिस्टर में किया जाता है

सदस्यों का।

डालमिया निवेश

हालांकि कोई नकद भुगतान नहीं किया जाता है के आवंटन के लिए शेयरधारक

कं. लिमिटेड बनाम। सी आई टी।

(1961) 41 आईटीआर *705*

बोनस शेयर, सेट-ऑफ

(पैट)

लाभांश के लिए जो देय था

शेयरधारक को भुगतान किया जाए के अविभक्त लाभ

कंपनी के रूप में माना जा सकता है बोनस के लिए विचार

शेयर।

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. की वास्तविक लागत।

294

जैसा कि लेखा पुस्तकों में दिखाया गया है कंपनी से।

अनारकली साराभाई

वरीयता का विमोचन

17

शेयर "हस्तांतरण" है और इसके लिए उत्तरदायी है

वी. सी. आई. टी. *227* आई. टी. आर *260 (* एससी*)*

पूँजीगत लाभ। "मंदी" से होने वाले लाभ

18

सी. आई. टी. वी. आर्टेक्स विनिर्माण कंपनी।

किसी व्यवसाय की बिक्री

चिंता कर के लिए उत्तरदायी है

227 आईटीआर *260 (*एससी*)*

मदबद्ध पर धारा *41 (2)*

आधार अगर मंदी की बिक्री है प्रत्येक के मूल्यांकन पर निर्धारित

संपत्ति/दायित्व।

III: मोहम्मडन कानूनः

संबद्ध विषय/न्यायनिर्णित कानून

एस. एल. कोई नाम नहीं और

मामले का उद्धरण

उस पर

एक उपहार दिया गया था

के न्यासी

1

साहेबज़ादी ओआलिया

अपने पिता द्वारा अनुदानित निर्धारिती

कुसलसम ट्रस्ट बनाम।

उसे जीवन संपत्ति और

सी. ई. डी. *[1998] 233*

बाकी अपने बच्चों के लिए। कार्य

आईटीआर *434 (*एससी*)*

के तहत शून्य माना गया था

मुसलमान कानून। यह आयोजित किया गया था

एक पूर्ण उपहार होना।

मुसलमान कानून के सिद्धांत

एस. एम.

2

उपहार के बारे में-विश्लेषण और

मोहम्मद बनाम।

लागू-सीमित के साथ उपहार

सी. आई. टी. *[1999] 235* आई. टी. आर. *75 (*मैड*)*

एक पूरे का उपहार होना दस्तावेज़ के बावजूद संपत्ति

उसे केवल एक सीमित अधिकार दिया।

गियासुद्दीन बाबू

3

ए. डी. आर. ए. एस. बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ *295*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

द्वारा विवाह का विघटन

खान बनाम। सी आई टी।

[1985] 153 आई. टी. आर. *707* में मृत्यु या तलाक का मामला नहीं है।

(एपी*)*

आकस्मिक ऋण क्योंकि एक

दोनों घटनाएँ बाध्य हैं

होता है। पत्नी माँग नहीं सकती

आस्थगित शुल्क का भुगतान

घटना से पहले, लेकिन पति पहले भी भुगतान कर सकते हैं।

जियाउद्दीन अहमद बनाम।

पारिवारिक व्यवस्था वैध है।

सी. जी. टी *(1976) 102*

मुसलमानों के बीच।

आई. टी. आर. *253* *(*गौ*)*

सी. आई. टी. वी. पुथिया

एक वक्फ भागीदार नहीं हो सकता है, लेकिन

पोनमनिचिन्तकम

वक्फ का मुतवल्ली हो सकता है।

वक्फ, *44* आईटीआर *172*

(एससी*)*

आयोजित, जिस क्षण एक वक्फ है

अहमद जी एच

संपत्ति के सभी अधिकार बनाए

एरीफ वी. सी. डब्ल्यू. टी

76 आईटीआर *471* *(*एससी*)*

वक्फ और बनियान से बाहर निकलें सर्वशक्तिमान-संपत्ति एक शब्द है

सबसे व्यापक आयात और इसके अधीन

कोई भी सीमा जो संदर्भ

संभावित ब्याज जो ए व्यक्ति स्पष्ट रूप से पकड़ सकता है या आनंद ले सकता है।

पारिवारिक व्यवस्थाः

संबद्ध विषय/न्यायनिर्णित कानून

कोई नाम नहीं और

मामले का उद्धरण

उस पर

सी. आई. टी. वी. आर.

भले ही समझौते के लिए एक पक्ष का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन परिवार के तहत

पोन्नम्मल

(1987) 164 आईटीआर

व्यवस्था, दूसरा पक्ष अपने सभी दावों को छोड़ देता है या

706 (पागल)

ऐसे व्यक्ति के पक्ष में शीर्षक

और उसे स्वीकार करता है

एकमात्र मालिक, फिर *[2014] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

296

माना जाता है और परिवार व्यवस्था कायम रखी जाएगी।

एक के माध्यम से अर्जित संपत्ति

2

सी. आई. टी. वी. शांति

होने वाली पारिवारिक व्यवस्था

चंद्रन

(2000) 241 आईटीआर

एक संपत्ति के रूप में माना जाता है

371 (पागल)

विभाजन या अन्य पर प्राप्त किया गया

उत्तराधिकार।

वीः साझेदारी का कानूनः

संबद्ध विषय/न्यायनिर्णित कानून

एस. एल. नहीं।

नाम और

मामले का उद्धरण

उस पर

सी. आई. टी. वी. पलानीअप्पा

साझेदारी फर्म की संपत्ति

1

द्वारा भागीदार को हस्तांतरण

उद्यम

(1998) 234 आईटीआर

समझौता-वैध नहीं है

-

635 (पागल*)*

पंजीकृत विलेख आवश्यक।

ए द्वारा पूँजी का योगदान

सरलादेवी

2

एक फर्म के लिए भागीदार

साराभाई बनाम। सी एल टी।

"स्थानांतरण "।

(2001) 250 आईटीआर *745 (* गुज*)*

एक अनन्य का रूपांतरण

सुनील

3

सिद्धार्थभाई बनाम।

साझा हित में ब्याज

एक "हस्तांतरण" के बराबर होगा

सी आई टी।

(1985) 156 आईटीआर

और ए की राशि नहीं है बिक्री के माध्यम से परिवहन।

509 (एससी*)*

सी. आई. टी. वी. एस. राजामणि और

भागीदार के साथ लेन-देन

4

फर्म, के निर्वाह के दौरान

फर्म को एक पंजीकृत की आवश्यकता है

थंगाराजन

यंत्र, जहाँ

उद्योग

(2000) 241 आईटीआर

लेन-देन में अचल शामिल हैं।

668 (पागल*)*

संपत्ति।

मालाबार मत्स्य पालन

परिसंपत्तियों का वितरण

5

1 , बार एसोसिएशन के रूप में *v.* भारत का संघ *297*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

वी. सी आई टी।

विघटन द्वारा हस्तांतरण नहीं किया जाता है

(1979) 120 आईटीआर *49* फर्म

(एससी*)*

सी. आई. टी. वी. गुप्ता

साझेदारी की वैधता -

भाईयों।

भागीदार के योगदान की आवश्यकता नहीं है

(1981) 131 आईटीआर

चाहे वह नकदी हो या संपत्ति। कौशल और

492 (सभी*)*

श्रम का गठन होगा योगदान दें।

सी. जी. टी. वी. प्रणय

नाबालिग जिन्हें भर्ती किया गया था

साझेदारी के लाभ

क्र. सहरिया

(1993) 204 आईटीआर

अपने हिस्से का दावा नहीं कर सके

78 (गौ*)*

पुनर्निर्माण पर सद्भावना

नाबालिगों को छोड़कर फर्म

और परिणामस्वरूप वे नहीं थे

उपहार-कर के लिए उत्तरदायी।

केवल यह तथ्य कि दो व्यक्ति

बेनिराम

एक कमीशन एजेंसी लें

मूलचंद बनाम.

सी आई टी।

संयुक्त रूप से व्यवसाय नहीं होगा

25 आईटीआर *287 (*एआईआई*)*

अनिवार्य रूप से एक का गठन करें

उनके बीच साझेदारी।

अगर कोई साझेदारी हुई है

सी. आई. टी. वी. चंद्रा

दो व्यक्तियों के बीच प्रवेश किया

शेखर पवन

कुमार

जिनमे से एक बेनामीदार है

दूसरा, कोई संबंध नहीं है

203 आईटीआर *435*

दोनों के बीच साझेदारी

(राज.*)*

व्यक्ति और एक व्यक्ति

एक फर्म का गठन नहीं कर सकते।

एडल्ट। सी. आई. टी. वी.

से एक साथी की सेवानिवृत्ति पर

फर्म, का कोई हस्तांतरण नहीं है

मोहनभाई

पामाभाई

भागीदार का हित *I*

सहित उनकी परिसंपत्तियाँ

165 आईटीआर *166*

सद्भावना। प्राप्त राशि

(एससी*)*

कैपिटल सुपर कोर्ट रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के रूप में कोई आकलन योग्य नहीं है।

298

लाभ होता है। यह मामला कानून वैध है। संशोधन के बाद भी

धारा *45 (4)* जो की बात करती है

विघटन या अन्यथा

स्थानांतरण किया गया।

11

मनोहरदास

यह भागीदारों के लिए खुला है

केदारनाथ बनाम.

सब कुछ नहीं लेने के लिए सहमत हैं

सी आई टी।

उनके लिए कंपनी का लाभ

25 आईटीआर *287 (*सभी*)*

कंपनी के मुनाफे का हिस्सा परोपकार।

भागीदार की कोई रुचि नहीं है

12

सी. आई. टी. वी. भरानी पिक्चर्स *(*पागल*)*

फर्म की संपत्ति। एक मामले में

(1981) 129 आईटीआर

जहाँ दो भागीदार हैं

244

और एक रिहाई विलेख पर हस्ताक्षर करता है

किसी संपत्ति के पक्ष में

अन्य, यह वास्तव में से एक स्थानांतरण है

उस साथी के लिए साझेदारी।

VI: प्रादेशिकताः

संबद्ध विषय/न्यायनिर्णित कानून

एस. एल. कोई नाम नहीं और

मामले का उद्धरण

उस पर

1

सी. आई. टी. वी. एच. ई. एच.

यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर का है

मीर उस्मान अली

कानून, नगरपालिका कानून और ए

बहादुर

के बीच संयोजक

(1966) 59 आईटीआर

भारत सरकार और

666 (एससी*)*

हैदराबाद के निजाम। आयोजित, कि हैदराबाद राज्य कभी नहीं

एक अंतरराष्ट्रीय प्राप्त किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तित्व

कानून और उसके शासक इसके हकदार नहीं थे।

कराधान से छूट का दावा करना

अपनी आय से।

इलेक्ट्रॉनिक्स

2

ओ. एन. वी. की विधायी शक्तियाँ।

आई खेहर, जे।*]*

संसद ऐसे कानून बनाएगी जो

अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन के प्रावधान हैं, जो संसद की क्षमता के भीतर है।

लेकिन किसी चीज़ के साथ संबंध भारत या भारत से संबंधित वस्तु

आवश्यक है।

संसद संवैधानिक रूप से है। अधिनियमित करने से प्रतिबंधित

अतिरिक्त के संबंध में कानून

क्षेत्रीय पहलू या कारण जिनके पास नहीं है और न ही हैं

अपेक्षित है, कोई प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष, मूर्त या अमूर्त,

(ए) के लिए परिणाम भारत का राज्यक्षेत्र या भारत का कोई भाग; या *(ख)* भारत के निवासियों के हित, कल्याण, कल्याण या सुरक्षा।

और भारतीय। व्यावसायिक संबंध-वहाँ

निरंतरता भी होनी चाहिए

वास्तविक और घनिष्ठ संबंध

की गई व्यापारिक गतिविधि के बीच

कर योग्य के बाहर

क्षेत्र और व्यापारिक गतिविधि क्षेत्रों के भीतर, दोनों के बीच संबंध में योगदान

आय अर्जित करना

अपने व्यापार में अनिवासी

गतिविधि। संबद्ध विषय/विधि न्यायनिर्णित *[2014] 10* एस. सी. आर.

300 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले का उद्धरण

उस पर

एक निश्चित *(*विशिष्ट*)* के न्यासी

एल. आर. पटेल परिवार

1

ट्रस्ट वी। आईटीओ.

विश्वास नहीं माना जा सकता है

व्यक्तियों का एक संघ या

262 आईटीआर *520*

व्यक्तियों का शरीर।

(बम*)* सी. आई. टी. वी. थांथी

के सिद्धांत पर चर्चा

2

ट्रस्ट *(1982) 137*

साइप्रस जैसा कि जनता पर लागू होता है

आई. टी. आर. *735 (*मैड*)*

परोपकार।

सी. आई. टी. वी. स्वाश्रय

न्यासियों की अनुबंध करने की शक्ति

3

286 आईटीआर *265 (*गुजरात*)*

विश्वास की ओर से। की सहमति

यदि आवश्यक हो तो लाभार्थी। अंतिम की संख्या

पंडित वी. सी आई टी।

4

(1972) 83 आईटीआर *136*

न्यास के लाभार्थी कर सकते हैं

कारण से वृद्धि या कमी

(बम*)*

प्रासंगिक तिथि, केवल आकस्मिक और हो सकता है

बहुत बाद की तारीख में निहित। अगर

उस तारीख को, लाभार्थी कर सकते हैं

मान लीजिए कि लाभार्थी हैं निर्धारित और ज्ञात और

कि परिसंपत्तियाँ धारित हैं

न्यासी अपने लाभ के लिए।

के तहत पंजीकृत एक सोसायटी

5

सी. आई. टी. वी. अखिल भारतीय

हिंदू महासभा

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम मे

140 आईटीआर *748 (*डेल*)*

एक संगठन के रूप में माना जाए

लोग।

तुलसीदास

भारत न्यास अधिनियम, *1882*-न्यासी

6

लाभार्थी भी हो सकते हैं।

किलाचंद बनाम। सी आई टी।

42 आईटीआर *1 (*एससी*)*

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *301*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

(1984) 147 एक अजन्मे व्यक्ति का आई. टी. आर. *500* यदि *(* पागल*)*

में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है

लाभार्थी अनिश्चित है। एक ट्रस्ट कर्म के लिए बुरा नहीं हो सकता

:

अनिश्चितता या अस्पष्टता।

II: अनुबंध कानूनः

संबद्ध विषय/न्यायनिर्णित कानून

. कोई नाम नहीं और

मामले का उद्धरण

उस पर

सी. आई. टी. वी. शांतिलाल

उल्लंघन की प्रकृति-चाहे

प्रा. लिमिटेड *(1983)*

क्षति के भुगतान के परिणामस्वरूप

144 आईटीआर *57* (एससी*)*

अनुबंध। प्राप्त हुआ मुआवजा

सी. आई. टी. वाई. सर्वश्रेष्ठ *&*

अभिकरण की समाप्ति और

कं. पी. लिमिटेड *60* आईटीआर *11 (*एससी*)*

प्रतिबंधात्मक संयोजक-प्रकृति

प्राप्ति-राजस्व या पूँजी -

प्रतिबंधात्मक संयोजक-चाहे

एक स्वतंत्र दायित्व -

क्या क्षतिपूर्ति

अलग किया जा सकता है।

एन. सुंदरेश्वरन

अनुबंध का उल्लंघन-मध्यस्थता

वी. सी. आई. टी. *(1997)*

धारा *73* का खंड-दायरा -

226 आई. टी. आर. *142 (*केरल*)*

परिसमाप्त और असंपादित

हर्जाना-कोई कटौती नहीं की जा सकती

संभावित दायित्व पर दावा किया जाए

नुकसान के लिए।

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियमः

संबद्ध विषय/न्यायनिर्णित कानून

1. कोई नाम और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नहीं

[2014] 10 एस सी आर।

302

मामले का उद्धरण

उस पर

1

बंशीधर

के साथ बिक्री के बीच अंतर

सेवाभोगवन

पुनः खरीदने की शर्त और

सशर्त बिक्री द्वारा एक बंधक।

& को. वी. सी आई टी।

(1996) 222 आईटीआर

16 (गौ*)*

2

जगदीशचन्द्रन

क्या स्व-निर्मित बंधक

वी. सी आई टी।

या पिछले मालिक द्वारा बंधक

227 आईटीआर *240 (*एससी*)*

यह अधिग्रहण की लागत को प्रभावित करता है।

अरुणाचलम बनाम। सी आई टी।

227 आईटीआर *222 (*एससी*)*

3

सी. आई. टी. वी. ब्रिगेडियर कपिल

हालांकि एक स्थानांतरण नहीं हो सकता है

मोहन *252* आईटीआर *830*

सीधे एक अजन्मे बच्चे को दिया गया

व्यक्ति, के तहत से

(डेल*)*

अनुभाग में "स्थानांतरण" की परिभाषा

5 संपत्ति के हस्तांतरण का

अधिनियम, *1882*, एक हस्तांतरण सीमित है

जीवित व्यक्तियों को, एक में स्थानांतरण

अजन्मा व्यक्ति केवल हो सकता है यंत्रों द्वारा निर्मित

ट्रस्ट।

सी. जी. टी. वी. अलोका

4

यदि दो पंजीकृत दस्तावेज

उसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया

लता सेट

(1991) 190 आईटीआर

एक ही संपत्ति का सम्मान

556 (कैल*)*

दो अलग-अलग व्यक्ति

एक समय था जो

निष्पादित पहले प्राथमिकता है

इसके बाद पंजीकृत किया गया था बाद वाला। दूसरे शब्दों में,

दस्तावेज़ का पंजीकरण

इसकी तारीख से संबंधित है

निष्पादन।

5

क्या विलेख के साथ बिक्री

सी. आई. टी. वी. एनआर.

ऑन वी. भारत संघ *303*

एच. खेहर, जे.*]*

संपत्ति के पुनः हस्तांतरण के लिए राशि सामान्य कानून और आय-कर दोनों के तहत हस्तांतरण के लिए है।

कानून*?*

संबद्ध विषय/न्यायनिर्णित कानून

उस पर

एक पेटेंट का असाइनमेंट पूंजी खाते पर एक लेनदेन है,

खरीद और बिक्री में एक व्यापार पेटेंट का या आदतन उसे बेच देता है

स्वयं के पेटेंट, या एक आविष्कारक के व्यवसाय पर चलते हैं, बिक्री आय व्यवसाय होगी

आय।

यदि मालिक को दूसरों को जानकारी देने के लिए एकमुश्त या आवधिक भुगतान मिलता है-कैसे, इसके मूल्य को काफी कम किए बिना

स्वयं के लिए, भुगतान आम तौर पर कर योग्य होगा

व्यावसायिक आय और

इस आधार पर कि ज्ञान का दोहन-व्यवसाय और प्रदान करने के क्रम में कैसे है

एक व्यवसाय से अधिक नहीं

यद्यपि विशेष सेवा दयालु।

एक लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी

ईंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को छीनने का अधिकार या साल्टपीटर निकालना आय है।

तथ्य यह है कि मिट्टी को हटाना

स्वयं शामिल होने से सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. नहीं बनती है।

304

मामला इससे अलग है

रॉयल्टी के मामले

भूमिगत कोयला और खदानें

XI: व्याख्याः

संबद्ध विषय/न्यायनिर्णित कानून

एस. एल. कोई नाम नहीं और

मामले का उद्धरण

उस पर

एस. सी. ने फैसला सुनाया कि व्याख्या

1

प्रकाश नाथ

एक के खतरे से बचना चाहिए

खन्ना बनाम। सी आई टी।

(2004) 266 आईटीआर

पूर्व निर्णय

1 (एससी*)*

मतलब खुद के साथ

पूर्वकल्पित धारणाएँ "और वह

न्यायालय कानून की व्याख्या करता है और

कानून नहीं बना सकते। इसका उल्लेख किया गया है

दो अन्य सिद्धांत

निर्माण, एक संबंधित

केसस ओमिसस और दूसरा

एक क़ानून को पढ़ने की आवश्यकता है

समग्र रूप से। अदालत की अवमानना-कानून

2

I.T.A.T. बनाम. वीके.

आई. टी. ए. टी. पर लागू।

अग्रवाल

235 आईटीआर *175 (*एससी*)*

सी. आई. टी. वी. भोगीलाल

3

स्पेसेस सक्सेशनिस-स्थानांतरण

मंगीलाल *69* आईटीआर

संपत्ति अधिनियम से निपटा गया।

288 (गुज*)*

एलर्मन लाइन्स

बाध्यकारी प्रकृति पर चर्चा करता है

4

सी. बी. डी. टी. के निर्देश

लिमिटेड वी. सी आई टी।

(1971) 82 आईटीआर

राजस्व विभाग।

913 (एससी*)*

सी. आई. टी. वी. केपी.

वर्गीज *(1981) 131* आईटीआर

597 (एससी*)*

बार एसोसिएशन के रूप में *v.* भारत संघ *305*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

सेलेनियसः

संबद्ध विषय/न्यायनिर्णित कानून

नाम और

मामले का उद्धरण

उस पर

श्री मीनाक्षी

बेनामी-बेनामीदारों में कराधान का अर्थ और प्रभाव

मिल्स वी। सी आई टी।

31 आईटीआर *25 (*एससी*)*

हाथों से चर्चा की।

लियो मचाडो बनाम।

नाव जायजों सोमोन्दो दं

सी आई टी।

निर्धारिती एक दुर्घटना का शिकार हो गया और गहरे समुद्र में डूब गया;

172 आईटीआर *744*

से प्राप्त मुआवजा

(पागल*)*

बीमा कंपनी संपत्ति के विनाश के कारण थी, इस प्रकार कोई "हस्तांतरण" नहीं जैसा कि विचार किया गया था धारा *45* को धारा *48* के साथ पढ़ा जाता है। प्राप्त बीमा राशि पर विचार नहीं किया जा सकता है

प्रतिफल और प्राप्त राशि के रूप में जो पूँजी के लिए उत्तरदायी नहीं है

कर लाभ।

गंगाधर बेरा

एक स्पष्टीकरणात्मक सूचना मात्र एक

वी. आसिस्टेंट। सी. आई. टी. *(2004) 190* आई. टी. आर. *467 (*कैल*)*

मूल सूचना में परिशिष्ट

और स्पष्टीकरण का प्रभाव है

हमेशा पूर्वव्यापी इसलिए यह होना चाहिए

मूल सूचना से संबंधित है। ए.

खंड सूचना नहीं देता है कानून में बुरा।

सी. आई. टी. वी. आंध्र प्रदेश

"धर्मार्थ उद्देश्य" अभिव्यक्ति अपने आयाम में बहुत व्यापक है। वस्तु की आवश्यकता नहीं है

चैंबर ऑफ

व्यापार

55 आईटीआर *722 (*एससी*)*

संपूर्ण मानव जाति या यहाँ तक कि किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को भी लाभ पहुँचाना।

विशेष देश या प्रांत। यह.

यदि इरादा अदालत की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. को शीर्ष पर रखने का है तो यह पर्याप्त है।

306

जनता के एक वर्ग को लाभ पहुँचाना

से अलग

निर्दिष्ट व्यक्ति। फर्क समझाया।

डेक्कन वाइन एंड

5

जनरल स्टोर्स वी।

संघ के बीच

सी आई टी।

व्यक्तियों और 'के शरीर

(1977) 106 आईटीआर

व्यक्तियों '।

111 (एपी*)*

सी. आई. टी. वी

एक कृषि क्या है

6

गतिविधि*?*

महाराष्ट्र

शुगर मिल्स लिमिटेड

भूमि की खेती होनी चाहिए।

(1971) 82 आईटीआर

शब्द के सख्त अर्थ में जिसका अर्थ है भूमि को जोतना।

452 (बम*)*

7

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास रोक लगाने की अंतर्निहित शक्ति है

आई. टी. ओ. बनाम एम. के

मोहम्मद कुन्ही

करों का संग्रह और

(1968) 71 आईटीआर

कार्यवाही।

815 (एससी*)*

8

व्यक्तियों का संगठन जब

सी. आई. टी. वी. इंदिरा बालकृष्ण *(1960) 39* आईटीआर *546 (*एससी*)*

लोग एकजुट नहीं होते हैं।

आय उत्पन्न करने के लिए,

उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है

एओपी।

नोट-कानून ने किया है *1.4.2002* के बाद संशोधित

सी. आई. टी. वी. एच. एच.

9 .

एक शासक के व्यक्तिगत प्रभाव

(विरासत के आभूषण*)* नहीं है

महारानी उषा देवी।

एकर बिक्री पर कर योग्य

231 आईटीआर *793 (*एमपी*)* लाभ।

जब कोई व्यक्ति उसे फिर से महत्व देता है

10

सी. आई. टी. वी. बाई।

पूँजीगत परिसंपत्ति और उसके ऋण

श्रीनभाई कूका मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *307*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

46 आईटीआर *86 '(*एससी*)*

पूँजी खाते में कोई लाभ नहीं है।

कराधान के उद्देश्य से। एक.

हानि या लाभ नहीं उठा सकते हैं

स्वयं के साथ लेनदेन।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

11

ढाकेश्वरी

लगभग पहली बार बाहर -

कॉटन मिल्स बनाम।

सी आई टी।

लोकस क्लासिकस।

(1954) 26 आईटीआर *775*

चेम्सफोर्ड क्लब

पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होता है

12

संपत्ति से आय।

वी. सी आई टी।

243 आईटीआर *89 (*एससी*)*

सी. आई. टी. वी. बांकीपुर

क्लब लिमिटेड *226* आईटीआर *97 (*एससी*)*

यह ऊपर निकाले गए संकलन से स्पष्ट है,

कि एन. टी. टी. के सदस्यों को निश्चित रूप से पारिवारिक कानून, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, कंपनी कानून, साझेदारी कानून, प्रादेशिकता से संबंधित कानून, न्यासों और समितियों से संबंधित कानून से उभरने वाले कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ेगा।

अनुबंध कानून, संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कानून, संबंधित कानून

बौद्धिक संपदा, क़ानूनों की व्याख्या और अन्य

समय-समय पर कानून के विविध प्रावधान। एनटीटी

उपरोक्त कानूनों के अलावा, न केवल तीन कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी, जिनमें से अपीलें

इसके द्वारा सुना जाएगा, लेकिन इसके लिए एक चुनौती की जांच भी करनी होगी

समय-समय पर उक्त प्रावधानों में किए गए वैधानिक संशोधनों के अधिकार। उन्हें कुछ मामलों में यह भी निर्धारित करना होगा,

चाहे जिन प्रावधानों पर भरोसा किया गया था, उनमें कोई संभावित या पूर्वव्यापी प्रयोज्यता थी।

78. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा *15* के संदर्भ में

एन. टी. टी. अधिनियम के तहत, एन. टी. टी. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा से अपीलों की सुनवाई करेगा।

कर अपीलीय न्यायाधिकरण *(*सी. ई. एस. टी. ए. टी.*)* केवल "सारगर्भित प्रश्नों पर *308* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

कानून के ", हमारे लिए औचित्य की सराहना करना मुश्किल है

अपील के लिए एक पक्ष की ओर से प्रतिनिधित्व, दोनों के माध्यम से

एन. टी. टी. से पहले चार्टर्ड एकाउंटेंट या कंपनी सचिव। एन. टी. टी. के हाथों में दृढ़ संकल्प की कमी है

तथ्यात्मक विवाद। इसे केवल "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों" का निर्णय लेना है। हमारी समझ में, चार्टर्ड एकाउंटेंट और

कंपनी सचिव सबसे अच्छा विशेषज्ञ होंगे

लेखाओं से संबंधित मुद्दों को समझना और समझाना।

ये मुद्दे विशुद्ध रूप से तथ्यों के दायरे में आते हैं। हम पाते हैं। कंपनी सचिवों द्वारा उन्हें अनुमति देने के लिए की गई प्रार्थना को स्वीकार करना मुश्किल है, एक अपील में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए

एनटीटी से पहले। यहाँ तक कि जहां तक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं

संबंधित, हम यह मानने के लिए विवश हैं कि उन्हें एन. टी. टी. के समक्ष एक पक्ष की ओर से उपस्थित होने की अनुमति देना होगा

कानून में अस्वीकार्य। हम तदनुसार दावे को अस्वीकार करते हैं

कंपनी सचिव, एन. टी. टी. के समक्ष एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तदनुसार कंपनी सचिवों द्वारा लिखित में की गई प्रार्थना

याचिका *(*सिविल*)* सं। *621 2007* को इसके द्वारा घटाया गया है। उपरोक्त निष्कर्ष को दर्ज करते समय, हम एक साथ अनुभाग का आयोजन करते हैं *13 (1)* , जहाँ तक यह सनदी लेखाकारों को एन. टी. टी. के समक्ष अपील करने के लिए किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है, असंवैधानिक और

कानून में अस्थिर।

VI. संविधान की धारा *5,6,7,8* और *13* की संवैधानिक वैधता एन. टी. टी. अधिनियमः

79. अब हम इसकी वैधता से निपटने का प्रयास करेंगे।

इस न्यायालय की संवैधानिक पीठों द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर एन. टी. टी. अधिनियम के कुछ अन्य व्यक्तिगत प्रावधान

और वेस्टमिंस्टर मॉडल पर बनाए गए संविधानों के लिए संदर्भित मान्यता प्राप्त संवैधानिक सम्मेलनों के आधार पर। रिट याचिका *(*सिविल*)* नं. में की गई प्रार्थनाओं से निपटने के दौरान।

621 2007 में, हम पहले ही एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *13* पर विचार कर चुके हैं और इसे आंशिक रूप से असंवैधानिक ठहरा चुके हैं। हम.

अब कालानुक्रमिक रूप से आगे बढ़ेंगे और एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5,6,7* और *8* की वैधता की जांच करेंगे।

80. हम सबसे पहले मद्रास बार एसोसिएशन *v* की धारा *5* की वैधता की जांच करेंगे।

भारत संघ *309*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

एनटीटी अधिनियम। उपरोक्त प्रावधान को चुनौती देने का आधार है -

प्रस्तुतियों से निपटने के दौरान हमारे द्वारा पहले से ही वर्णित किया गया है

चौथे के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की ओर से अग्रिम

विवाद। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5 (2)* में कहा गया है कि एन. टी. टी. इसकी बैठकें आम तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होती हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उपरोक्त आदेश

वादकारी निर्धारिती को सुविधा से वंचित कर देगा

राज्य में अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय का रुख करना, जिसके लिए

वह संबंधित है। एक निर्धारिती किसी दूरस्थ/दूरस्थ क्षेत्र से संबंधित हो सकता है।

बता दें कि किस स्थिति में उन्हें केवल पीड़ा नहीं उठानी पड़ेगी

लंबी दूरी की यात्रा करने में कठिनाई होती है, लेकिन इस तरह की यात्रा में अनावश्यक वित्तीय खर्च भी होता है। इसी तरह, एक वादी

उसे एन. टी. टी. के समक्ष, क्योंकि वही अनिवार्य है आम तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। यहां तक कि

यद्यपि हमने यह विचार व्यक्त किया है कि यह संसद के लिए खुला है कि वह अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों में निहित अपीलीय अधिकार क्षेत्र को प्रतिस्थापित करे और इसके लिए न्यायालयों/न्यायाधिकरणों का गठन करे -

उक्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, हमारा विचार है कि

उसी सुविधा और सुविधा के साथ, जैसा कि पहले था नवनिर्मित न्यायालय/न्यायाधिकरण की शुरूआत। इस प्रकार, एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5 (2)* में शामिल अधिदेश

प्रभाव कि एन. टी. टी. की बैठकें सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में,

उपचार अप्रभावी, और इस प्रकार कानून में अस्वीकार्य है। इस न्यायालय ने एस. पी. संपत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, *1985* के संदर्भ में मामले के तत्काल पहलू पर विचार किया था।

कुमार मामला *(ऊपर)* और एल. चंद्र कुमार मामला *(ऊपर),*

जिसमें यह आयोजित किया गया था कि स्थायी पीठों की आवश्यकता थी

प्रत्येक अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय की पीठ पर स्थापित। और

यदि यह संभव नहीं था, तो कम से कम हर उस स्थान पर एक सर्किट बेंच स्थापित करने की आवश्यकता थी जहां एक पीड़ित पक्ष लाभ उठा सके।

उसका इलाज। उपरोक्त मुद्दे पर स्थिति कोई अलग नहीं है *[2014] 10* एस. सी. आर.

310 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. टी. टी. अधिनियम इस द्वारा घोषित कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। अदालत।

81. उप-धारा *(2), (3), (4)* की भी जांच करने की आवश्यकता है।

और *(5)* एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5* की बैठक निर्धारित करने में केंद्र सरकार की भूमिका के स्पष्ट संदर्भ के साथ

एन. टी. टी. के बेंच। केंद्र सरकार को उस क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है जिसके संबंध में प्रत्येक पीठ

न्यायक्षेत्र का प्रयोग करेगा, पीठों के गठन का निर्धारण करेगा, और अंत में, के हस्तांतरण की शक्ति का प्रयोग करेगा

एक पीठ से दूसरी पीठ के सदस्य। कोई दृष्टि नहीं खो सकता है।

तथ्य यह है कि केंद्र सरकार प्रत्येक अपील/मामले में एक हितधारक होगी, जो इसके समक्ष दायर की जाएगी।

एनटीटी। इसलिए, केंद्र को अनुमति देना उचित नहीं हो सकता है।

सरकार उन स्थानों के संदर्भ में कोई भी भूमिका निभाएगी जहाँ

बेंचों की स्थापना की जाएगी, जिन क्षेत्रों पर बेंचें होंगी न्यायक्षेत्र, पीठों की संरचना और संविधान का प्रयोग करेगा, साथ ही, एक से सदस्यों का स्थानांतरण भी करेगा।

दूसरे के लिए बेंच। यह केंद्र के लिए अनुचित होगा

सरकार, एन. टी. टी. के साथ कोई भी प्रशासनिक लेनदेन करने के लिए या उसके सदस्य। अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों में, ऐसी शक्ति

न्याय प्रशासन के सर्वोत्तम हित में मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार को अनुमति देना

हमारे विचार में, एन. टी. टी. के वनाच्छादित प्रशासनिक कार्य में भाग लेने से स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा और

एनटीटी के सदस्यों की निष्पक्षता। एन. टी. टी. अधिनियम के वैध होने के लिए,

एन. टी. टी. के अध्यक्ष और सदस्यों के पास अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान स्वतंत्रता और सुरक्षा होनी चाहिए (जो एन. टी. टी. के लिए अनिवार्य है)।

प्रतिस्थापन)। अधिकारिता निर्धारित करने की शक्ति और विभिन्न सदस्यों की नियुक्ति का केंद्र के साथ निहित होना।

सरकार, हमारे सुविचारित विचार में, अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कमजोर करेगी और एन. टी. टी. के सदस्य, क्योंकि वे हमेशा अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए चिंतित रहेंगे।

काम के संदर्भ में झुकाव और मद्रास बार एसोसिएशन के संदर्भ में सुविधाएँ *v.*

भारत संघ *311*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।]

पोस्टिंग का स्थान। एक अनुपयुक्त/नुकसानदेह अध्यक्ष या सदस्य को आसानी से एक महत्वहीन पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

अधिकार क्षेत्र, या एक असुविधाजनक पोस्टिंग के लिए। ऐसा किया जा सकता है। उसे दंडित करने के लिए, एक पद स्वीकार करने के लिए जिसे वह स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हमारा विचार है कि

एन. टी. टी. अधिनियम की धारा 5 कानून में टिकाऊ नहीं है, जैसा कि यह करती है। यह सुनिश्चित नहीं करता है कि वैकल्पिक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पूरी तरह से

सभी प्रकार के हस्तक्षेप, दबाव या प्रभाव से अछूता

सरकार की समन्वित शाखाओं से। इसलिए वहाँ है

कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उस उप-धारा (2), (3), (4) और (5) को धारण करने के लिए

एन. टी. टी. अधिनियम की धारा 5 असंवैधानिक है।

82. अब हम धारा 6 की वैधता की जांच करेंगे।

एनटीटी अधिनियम। उपरोक्त प्रावधान इस निर्णय के पहले भाग में पहले ही निकाला जा चुका है, जब

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ,

चौथे विवाद का संदर्भ। धारा 6 का अवलोकन

यह बताता है कि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा, यदि वह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का सदस्य है या रहा है

कम से कम 5 वर्षों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से निपटने के दौरान, आयकर के संदर्भ में

कानून, सीमा शुल्क कानून, साथ ही, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून, हमने उन लोगों की पात्रता पर ध्यान दिया है जो हो सकते हैं

गठित अपीलीय न्यायाधिकरणों के सदस्यों के रूप में नियुक्त

उपरोक्त विधानों के अधीन। आयकर अधिनियम के तहत, ए

व्यक्ति जिसने चार्टर्ड के रूप में लेखांकन में अभ्यास किया हो

लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत) 10 साल की अवधि के लिए, या एक पंजीकृत लेखाकार (या

आंशिक रूप से एक पंजीकृत लेखाकार, और आंशिक रूप से एक चार्टर्ड लेखाकार) 10 साल की अवधि के लिए, लेखाकार सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है। सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम का सदस्य रहा हो।

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा (समूह ए), के अधीन

शर्त, कि ऐसे व्यक्ति ने कलेक्टर का पद संभाला है

सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क (स्तर 1), या समकक्ष या उच्चतर

पद, कम से कम 3 वर्षों के लिए, 312 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 10 एस. सी. आर. के रूप में नियुक्त होने के योग्य है।

तकनीकी सदस्य। यह अभिलिखित कथन से स्पष्ट है

इसके अलावा, उपरोक्त योग्यता वाले व्यक्ति, जिन्हें लेखाकार सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों में भी पात्र हैं

इस प्रकार निर्दिष्ट वर्षों की सेवा प्रदान की। निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त के साथ व्यक्ति योग्यताएँ, इस द्वारा घोषित कानून के मापदंडों को पूरा करती हैं

न्यायालय, जिसे एन. टी. टी. के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाएगा? और क्या वे मान्यता प्राप्त संवैधानिक सम्मेलनों को संतुष्ट करना?

83. इस न्यायालय ने इस संबंध में स्थिति घोषित की है

एल. चंद्र कुमार मामला (ऊपर) और भारत संघ बनाम। मद्रास

बार एसोसिएशन मामला (ऊपर), कि तकनीकी सदस्य कर सकते हैं

न्यायाधिकरणों में नियुक्त किया जाए, जहां तकनीकी विशेषज्ञता है

मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक है, और अन्यथा नहीं। यह भी है

अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी न्यायाधिकरण को हस्तांतरित न्यायिक प्रक्रिया में कोई विशेष कौशल, ज्ञान या विशेषज्ञता शामिल नहीं है, वहां गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

(न्यायिक सदस्यों के अतिरिक्त या उनके प्रतिस्थापन में) यह "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" और "कानून के शासन" पर भ्रम और अतिक्रमण का एक स्पष्ट मामला है। यह मुश्किल है।

लेखाकार सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की सराहना करने के लिए

सदस्य संबंधित कानून के जटिल प्रश्नों को संभालेंगे।

कर संबंधी मामलों के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर कानून के प्रश्न भी

(कर से असंबद्ध), के साथ निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में

एनटीटी। यह हमारे विचार में एक लंबा क्रम होगा। कठिन और

पूछने में डर लगता है। अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में

एन. टी. टी. को अपीलीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों" को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी, यह मुश्किल है

इस बात की सराहना करने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति, जो केवल खातों में पारंगत है, ऐसे कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम होगा। इसी प्रकार यह भी

हमारे लिए यह समझना मुश्किल है कि तकनीकी सदस्य, जिनके पास कानून की योग्यता भी नहीं हो सकती है, या जिनके पास कानून के अभ्यास में कोई अनुभव नहीं हो सकता है, वे कैसे काम कर सकेंगे।

"कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों" के साथ, जिसके लिए अकेले, एन. टी. टी. है

गठित किया गया।

84. हम पहले से ही डेटा से ऊपर देख चुके हैं।

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया, कि

एन. टी. टी. को परिवार से उत्पन्न विवादों का सामना करना पड़ेगा।

कानून, हिंदू कानून, मोहम्मदन कानून, कंपनी कानून,

साझेदारी, प्रादेशिकता से संबंधित कानून, न्यासों से संबंधित कानून

और समितियाँ, अनुबंध कानून, हस्तांतरण से संबंधित कानून

संपत्ति, बौद्धिक संपदा से संबंधित कानून, की व्याख्या

कानून/नियम और कानून के अन्य विविध प्रावधान।

उपरोक्त के अलावा, एन. टी. टी. के सदस्य नियमित रूप से

आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, सीमा शुल्क

अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम। हमारा मानना है कि

केवल कानून में पेशेवर योग्यता रखने वाला व्यक्ति,

कानून के अभ्यास में पर्याप्त अनुभव, एक स्थिति में होगा भारी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए जो एक अध्यक्ष और

एन. टी. टी. के सदस्यों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा।

85. इसमें कोई संदेह नहीं है कि

न्यायालय/न्यायाधिकरण के सदस्य जिनके लिए न्यायनिर्णायक कार्य हैं

स्थानांतरित, न्यायाधीशों/सदस्यों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जिनके

कद और योग्यताएँ न्यायालय के अनुरूप हैं

जिसे न्यायनिर्णायक प्रक्रिया स्थानांतरित कर दी गई है। यह

इस पद को दुनिया भर में पहचाना जाता है। संवैधानिक समझौते

जमैका, सीलोन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संबंध में,

यह

मामले के पहलू को ऊपर चित्रित किया गया है। राय. हिंद मामले में लॉर्ड डिप्लॉक द्वारा व्यक्त प्रिवी काउंसिल

(ऊपर*)*, को उन देशों में अनुसरण किए जाने के रूप में दिखाया गया है जो

वेस्टमिंस्टर मॉडल पर संविधान हैं। द इंडियन

संविधान ऐसा ही एक संविधान है। यह स्थिति रही है पर बनाए गए संविधानों की व्याख्या करते समय स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया

उपरोक्त मॉडल, अर्थात्, कि भले ही विधायिका कर सकती है

न्यायिक शक्ति को पारंपरिक न्यायालय से समान न्यायालय में स्थानांतरित करना।

एक अलग नाम के साथ न्यायालय/न्यायाधिकरण, जिस पर न्यायालय/न्यायाधिकरण ऐसी शक्ति हस्तांतरित की जाती है, उसी के पास होनी चाहिए

न्यायालय के रूप में मुख्य विशेषताएँ, मानक और मापदंड वह शक्ति जिसका हस्तांतरण किया जा रहा था। यह संभव नहीं है कि

हम स्वीकार करते हैं कि लेखाकार सदस्य और तकनीकी सदस्य

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास कद और योग्यता है अदालतें।

86. यह विवादित नहीं था कि एन. टी. टी. का निर्माण किया गया है

उन मामलों को संभालना जो पहले अपीलीय दायरे में थे

अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय। तदनुसार हम संतुष्ट हैं कि लेखाकार सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति

एन. टी. टी. के अपीलीय न्यायाधिकरणों के सदस्य होंगे

दुनिया भर में अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त संवैधानिक सम्मेलनों का स्पष्ट उल्लंघन। कानून के प्रश्नों पर संदर्भ (के तहत)

विचाराधीन तीन विधायी अधिनियम), एक द्वारा थे

विधायी जनादेश, जिसकी एक पीठ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीश। जब

संदर्भ के उपचार (उच्च न्यायालय के समक्ष) को एक अपीलीय उपचार में परिवर्तित कर दिया गया था (तीन विधायी अधिनियमों के तहत)

प्रश्न), फिर से एक विधायी जनादेश द्वारा, अपील की सुनवाई क्षेत्राधिकार के कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी थी।

उच्च न्यायालय। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अब तक इससे पहले, वे मुद्दे जो एनटीटी के अधिकार क्षेत्र में निहित होंगे,

उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया जा रहा था। कठिन और जटिल प्रकृति

न्यायनिर्णायक प्रक्रिया स्पष्ट है। हम एक साथ यह भी देख सकते हैं कि "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है।

एन. टी. टी. अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से हटा लिया गया। कोर्स के दौरान सुनवाई के दौरान, हमने उच्च न्यायालयों में निहित "न्यायिक समीक्षा" की शक्ति के संबंध में अपनी राय व्यक्त की थी

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227। हमारी नज़र में, शक्ति

इस तथ्य के कारण कि एन. टी. टी. अधिनियम की धारा 24 एक पीड़ित पक्ष के पास निहित है, अपील का एक उपाय है, खारिज कर दिया गया। एन. टी. टी. द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, सीधे सर्वोच्च न्यायालय को

अदालत। उपरोक्त धारा 24 निकाली जा रही है।

इसके नीचेः

"24. सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। - किसी भी व्यक्ति सहित

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित सरकार का विभाग इसके लिए अपील दायर कर सकता है -

राष्ट्रीय कर के निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय

उसे न्यायाधिकरणः

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ *315*

[जगदीश सिंह खेहर, जे। *]*

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को दाखिल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था,

उक्त अवधि के भीतर अपील, इसे भीतर दायर करने की अनुमति दें

ऐसा समय जो उचित लगे। ”

वनाच्छादित अपीलीय उपचार को देखते हुए, एक आदेश से

एन. टी. टी. द्वारा सीधे उच्चतम न्यायालय को पारित किया गया, वहाँ

आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले कर मामले पर चुनौती देने का शायद ही कोई अवसर हो।

अधिनियम और उत्पाद शुल्क अधिनियम, एक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के समक्ष। भले ही विद्वान महान्यायवादी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत *"*न्यायिक समीक्षा*"* की शक्ति

संविधान को नहीं हटाया गया था, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया,

कि निहित सीमाएँ होंगी जहाँ ऐसी शक्ति होगी

व्यायाम योग्य बनें। इसलिए, और भी अधिक, एन. टी. टी. की संरचना को न्यायाधीशों के समान मापदंडों पर होना होगा।

उच्च न्यायालय। चूँकि एन. टी. टी. के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्तियाँ यहाँ ऊपर व्यक्त किए गए मापदंडों पर नहीं हैं, इसलिए घोषित मानदंडों के तहत वे टिकाऊ नहीं हैं।

जहाँ तक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति का संबंध है एनटीटी का संबंध है। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में,

एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *6 (2) (*बी*)* घोषित करने के लिए उत्तरदायी है।

असंवैधानिक है। हम ऐसा होने की घोषणा करते हैं।

87. हम अब अग्रिम प्रस्तुतियों से निपटेंगे।

धारा के संबंध में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा

7 एन. टी. टी. अधिनियम। हमें ऐसा लगता है कि धारा *7* को शैलीबद्ध किया गया है।

एल. चंद्रा में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में

कुमार मामला *(*ऊपर*)*। उपरोक्त निर्णय के बाद

एन. टी. टी. के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के तरीके का निर्धारण, स्पष्ट रूप से एक स्पष्ट गलतफहमी है

इस न्यायालय द्वारा घोषित कानूनी स्थिति। यह नहीं भूलना चाहिए था कि प्रशासनिक प्रावधानों के तहत

न्यायाधिकरण अधिनियम, *1985*, जो एल.

316 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

चन्द्र कुमार मामला *(*उपरोक्त*)*, उक्त अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरणों को पहली बार अदालतों की तरह काम करना है। सभी निर्णय

न्यायाधिकरण के संविधान के अनुच्छेद *226/227* के तहत चुनौती देने के लिए उत्तरदायी हैं,

अधिकारिता वाला उच्च न्यायालय। ऐसी परिस्थितियों में यह स्पष्ट है,

कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, *1985* के तहत न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के अधीन थे। इसका तरीका

चयन, जैसा कि एल. चंद्र कुमार मामले में सुझाया गया है *(*ऊपर*)*

इसलिए प्रकृति के न्यायाधिकरण के लिए अपनाया नहीं जा सकता है

एनटीटी। इसमें मान्यता प्राप्त स्थिति यह है कि एन. टी. टी. उच्च न्यायालयों के प्रतिस्थापन के रूप में गठित किया गया। एनटीटी है,

इसलिए, वास्तविक अर्थ में उच्च न्यायालय के स्थान पर एक न्यायाधिकरण

अदालतें। एन. टी. टी. में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति का तरीका, उसी प्रक्रिया द्वारा *(*या एक प्रक्रिया द्वारा*)* होना चाहिए।

समान प्रक्रिया*)*, जो नियुक्ति के लिए प्रचलित है

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। जहाँ तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, उपरोक्त प्रस्ताव द्वारा घोषित किया गया था

भारत संघ बनाम में यह न्यायालय। मद्रास बार एसोसिएशन मामला *(*ऊपर*)*, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सदस्यों का कद न्यायाधिकरण का गठन कौन करेगा, यह उस अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करेगा जिसे न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया जा रहा था।

तदनुसार, यदि उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र हो रहा है न्यायाधिकरण के सदस्यों का दर्जा एन. टी. टी. को हस्तांतरित किया गया

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान होना चाहिए। तो यह भी इसके अध्यक्ष/सदस्यों की सेवा की शर्तें। और उनकी नियुक्ति और हटाने का तरीका, जिसमें स्थानांतरण भी शामिल है।

जिसमें उनकी नियुक्तियों का कार्यकाल भी शामिल है।

88. धारा *7* को अन्यथा भी संवैधानिक रूप से वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें एन. टी. टी. के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया शामिल है।

केंद्र सरकार के विभागों के सचिव। इसमें

इस ओर से यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि एक तरफ केंद्र सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

एन. टी. टी. के समक्ष प्रत्येक मुकदमे में। स्वीकार करना संभव नहीं है मुकदमे का पक्षकार, चयन प्रक्रिया में भाग ले सकता है,

जिसके द्वारा न्यायनिर्णायक मद्रास बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्य *v.*

भारत संघ *317*

[जगदीश सिंह खेहर, जे।*]*

शरीर का चयन किया जाता है। यह भी उल्लंघन होगा

संविधान का, यदि विधायिका अधिकार क्षेत्र का हस्तांतरण कर सकती है न्यायिक पदों के धारकों द्वारा पहले एक नए न्यायालय/न्यायाधिकरण के धारकों के लिए प्रयोग किया जा सकता था *(*जिसके लिए कुछ अलग नाम था

संलग्न*)* और यह प्रावधान करने के लिए कि नए न्यायिक अधिकारी कार्यालयों की नियुक्ति तरीके और शर्तों पर नहीं की जानी चाहिए

न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति के लिए विहित। के लिए

ऊपर दर्ज किए गए सभी कारणों की हम घोषणा करते हैं।

एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *7* असंवैधानिक है।

89. जहाँ तक एनटीटी अधिनियम की धारा *8* की वैधता है

इसके संबंध में, यह स्पष्ट रूप से इसके अवलोकन से सामने आता है कि पहले चरण में एनटीटी में एक अध्यक्ष/सदस्य की नियुक्ति की जाती है। उदाहरण के लिए, *5* साल की अवधि के लिए। ऐसे अध्यक्ष/सदस्य *5* साल की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं। हम.

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के हाथों अग्रिम प्रस्तुतियों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, कि एक प्रावधान

पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं एन. टी. टी. के अध्यक्ष/सदस्यों की स्वतंत्रता को कम करने का प्रभाव पड़ेगा। एन. टी. टी. में नियुक्त प्रत्येक अध्यक्ष/सदस्य होगा

मामलों को इस तरह से तय करने के लिए विवश किया गया जो एनटीटी अधिनियम की धारा *8* के संदर्भ में उनकी पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित करेगा। बिनि। निर्णय उसके स्वतंत्र होने पर आधारित हो भी सकते हैं और नहीं भी।

समझना। हम संतुष्ट हैं कि उपरोक्त प्रावधान अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कमजोर करना

और एन. टी. टी. के सदस्य। चूँकि एन. टी. टी. को अधिकारिता के साथ निहित किया गया है जो पहले उच्च न्यायालयों के पास थी, नियुक्ति और कार्यकाल के विस्तार के सभी मामलों में, इससे बचा जाना चाहिए।

एनटीटी अधिनियम की धारा *5* के साथ। इसलिए हम मानते हैं कि धारा *8* एन. टी. टी. अधिनियम असंवैधानिक है।

90. एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5,6,7,8* और *13* निर्धारित की गई हैं।

हमारे द्वारा *(*यहाँ ऊपर इंगित सीमा तक*)* अवैध होना और

318 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर असंवैधानिक।

इस न्यायालय की संवैधानिक पीठों के निर्णय और संविधानों के लिए संदर्भित मान्यता प्राप्त संवैधानिक सम्मेलनों के आधार पर

वेस्टमिंस्टर मॉडल पर बनाया गया। उपरोक्त प्रावधानों के अभाव में, जिन्हें असंवैधानिक माना गया है, शेष प्रावधानों को असंवैधानिक बना दिया गया है और

व्यर्थ, और इस प्रकार, एन. टी. टी. अधिनियम के प्रावधान, समग्र रूप से, इसके द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। निष्कर्ष -

91 ((i) संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है, और

न्यायिक कार्यों को निहित करने के लिए, जो पहले उच्च न्यायालय में निहित थे,

वैकल्पिक न्यायालय/न्यायाधिकरण के साथ। संसद द्वारा इस तरह की शक्ति का प्रयोग संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन नहीं करेगा।

((ii) वेस्टमिंस्टर मॉडल से संबंधित मान्यता प्राप्त संवैधानिक सम्मेलन, विधायी प्राधिकरण को इससे वंचित नहीं करते हैं।

न्यायिक कार्यों को निहित करने के लिए कानून बनाना, जो पहले निहित थे

एक उच्च न्यायालय में, एक वैकल्पिक न्यायालय/न्यायाधिकरण के साथ। व्यायाम संसद द्वारा दी गई ऐसी शक्ति स्वयं किसी का उल्लंघन नहीं करेगी।

संवैधानिक सम्मेलन।

(iii) संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन किया जाएगा, यदि हस्तांतरण से संबंधित कानून बनाते समय

न्यायिक शक्ति, संसद यह सुनिश्चित नहीं करती है कि नव निर्मित न्यायालय/न्यायाधिकरण, मुख्य विशेषताओं के अनुरूप है और

न्यायालय के मानकों को प्रतिस्थापित करने की मांग की गई।

(iv) वेस्टमिंस्टर मॉडल पर शैलीबद्ध संविधानों से संबंधित संवैधानिक सम्मेलनों का भी उल्लंघन होगा, यदि

न्यायिक शक्ति के हस्तांतरण से संबंधित कानून बनाते समय, न्यायालय की परंपराओं और मुख्य विशेषताओं की मांग की गई थी

प्रतिस्थापित किए गए, न्यायालय/न्यायाधिकरण में शामिल नहीं किए गए हैं जिन्हें बनाने की मांग की गई है।

(v) 2007 की रिट याचिका *(*सी*) No.621* में की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। कंपनी सचिवों को अयोग्य ठहराया जाता है, क्योंकि

एन. टी. टी. के समक्ष अपील के लिए एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करना।

(vi) निष्कर्षों की कसौटी पर जांच की गई *(iii)* और *(iv)*

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत का संघ

319

उपरोक्त, एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5,6,7,8* और *13 (*इस हद तक*)*

यहाँ ऊपर इंगित किया गया है*)*, असंवैधानिक माना जाता है। तब से

उपरोक्त प्रावधान, एन. टी. टी. अधिनियम की इमारत का गठन करते हैं, और इन प्रावधानों के बिना शेष प्रावधान हैंः

अप्रभावी और अप्रासंगिक होने पर, पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है।

*R.F.NARIMAN, J. (*परिणाम से सहमत*)*

1. इन मामलों में, अनिवार्य रूप से चार विवाद हुए हैं -

याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया। पहला तर्क यह है कि

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना का कारण मौजूद नहीं है कर कानूनों से संबंधित निर्णयों की एकरूपता शायद ही कोई कारण हो

एक अपीलीय न्यायाधिकरण के बीच एक अन्य न्यायाधिकरण को हस्तक्षेप करने के लिए और

उच्चतम न्यायालय, क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय कमोबेश समान हैं, क्योंकि वे एक दूसरे द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हैं। तब से

यही कारण है कि अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए। दूसरा तर्क यह है कि विधायिका के लिए वरिष्ठ को हटाने की अनुमति नहीं है

निर्णय लेने के मुख्य न्यायिक कार्य से अभिलेख की अदालतें

कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा विवाद अनुच्छेद *323*-बी की संवैधानिक वैधता के संबंध में है जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत, कानून के शासन सिद्धांत और न्यायिक का उल्लंघन करता है।

समीक्षा करें। चौथा विवाद खुद को बारीक किरकिरी से संबंधित करता है।

अधिनियम की विभिन्न धाराएँ न्यायनिर्णायक प्रक्रिया की स्वतंत्रता को कमजोर करती हैं और टिक नहीं सकती हैं।

उनके वर्तमान रूप में न्यायिक जांच। चूंकि मैं स्वीकार कर रहा हूँ

याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह किया गया दूसरा तर्क, यह निर्णय नहीं होगा किसी भी अन्य विवाद से निपटें।

2.

"यह दृढ़तापूर्वक न्यायपालिका का प्रांत और कर्तव्य है।

विभाग बताए कि कानून क्या है। जो लोग विशेष मामलों में नियम लागू करते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से इसका विस्तार करना चाहिए।

और उस नियम की व्याख्या करें। '

200 साल पहले मुख्य न्यायाधीश जॉन ने क्या कहा था

मार्बरी बनाम के प्रसिद्ध मामले में मार्शल। मैडिसन, धारण करता है

यह आज भी सरकार की हर महान गणराज्य प्रणाली में सच है।

ये शब्द अलेक्जेंडर हैमिल्टन के शब्द से अपना रंग लेते हैं।

प्रसिद्ध संघवादी पत्र *No.78* जो इस प्रकार चलाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

"जो भी ध्यान से अलग पर विचार करता है

बिजली विभागों को यह समझना चाहिए कि सरकार में

जिस मामले में वे एक-दूसरे से अलग हैं, न्यायपालिका अपने कार्यों की प्रकृति से हमेशा संविधान के राजनीतिक अधिकारों के लिए सबसे कम खतरनाक होगी; क्योंकि

यह उन्हें परेशान करने या घायल करने की क्षमता में कम से कम होगा। द.

कार्यपालक न केवल सम्मान प्रदान करता है, बल्कि तलवार भी धारण करता है

समुदाय से। विधायिका न केवल आदेश देती है पर्स, लेकिन उन नियमों को निर्धारित करता है जिनके द्वारा कर्तव्य और अधिकार निर्धारित किए जाते हैं

प्रत्येक नागरिक को विनियमित किया जाना है। न्यायपालिका, पर

इसके विपरीत, तलवार या पर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं है;

समाज की शक्ति या धन की कोई दिशा नहीं; और कोई भी सक्रिय संकल्प नहीं ले सकता है। यह वास्तव में कहा जा सकता है कि इसमें न तो बल है और न ही इच्छा, बल्कि केवल निर्णय है।

और अंततः कार्यपालिका की सहायता पर निर्भर होना चाहिए।

अपने निर्णयों की प्रभावकारिता के लिए भी हाथ।

इस मामले का यह सरल दृष्टिकोण कई महत्वपूर्ण परिणामों का संकेत देता है। यह निर्विवाद रूप से साबित करता है कि न्यायपालिका तुलना से परे तीनों में सबसे कमजोर है।

शक्ति विभाग, कि यह कभी भी अन्य दो में से किसी पर भी सफलता के साथ हमला नहीं कर सकता है; और यह कि अपने हमलों के खिलाफ खुद को बचाने में सक्षम बनाने के लिए हर संभव देखभाल की आवश्यकता है। यह समान रूप से

साबित करता है, कि हालांकि व्यक्तिगत उत्पीड़न अब और हो सकता है फिर न्याय की अदालतों से आगे बढ़ें, सामान्य स्वतंत्रता

विधायिका और कार्यपालिका दोनों। क्योंकि मैं सहमत हूँ कि "वहाँ" स्वतंत्रता नहीं है, अगर न्याय करने की शक्ति को अलग नहीं किया जाता है

विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ। और यह साबित करता है, अंतिम स्थान पर, कि स्वतंत्रता से डरने की कोई बात नहीं हो सकती है

अकेले न्यायपालिका, लेकिन इससे डरने के लिए सब कुछ होगा

अन्य विभागों में से किसी एक के साथ संघ; कि इस तरह के संघ के सभी प्रभावों की निर्भरता से उत्पन्न होना चाहिए

उत्तरार्द्ध पर पूर्व, एक नाममात्र और स्पष्ट अलगाव के बावजूद; कि, प्राकृतिक दुर्बलता से

न्यायपालिका, यह लगातार हावी होने के खतरे में है,

इसकी समन्वित शाखाओं से प्रभावित या प्रभावित; और यह कि मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *321*

*[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

चूंकि इसकी दृढ़ता और स्वतंत्रता में पद में स्थायित्व के रूप में कुछ भी योगदान नहीं दे सकता है, इसलिए इस गुण को इसके संविधान में एक अनिवार्य घटक के रूप में माना जा सकता है, और एक बड़े पैमाने पर, सार्वजनिक न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा के गढ़ के रूप में माना जा सकता है। *(* जोर दिया गया*)*

3. इन अपीलों में उत्पन्न होने वाला सटीक प्रश्न राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, *2005* की संवैधानिक वैधता से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया प्रश्न बहुत सार्वजनिक महत्व का है और इसलिए इसे इस संविधान पीठ के समक्ष रखा गया है। फैसले के बाद भारत संघ बनाम। *R.Gandhi, (2010) 11 SCC1,* इन मामलों को अलग कर दिया गया था और *(2010) 11 SCC 67* में रिपोर्ट किए गए *11* मई *2010* के निर्णय और आदेश के माध्यम से अलग से सुनवाई करने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से तैयार किया गया सटीक प्रश्न यह है कि क्या एक न्यायाधिकरण अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय का स्थान ले सकता है, जब कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने की बात आती है।

4. राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा *15* और *24* में कहा गया है:

"15. (1) राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण में एक अपील होगी।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश से, यदि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि

मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। *(2)* मुख्य आयुक्त या आय आयुक्त

कर या मुख्य आयुक्त या सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, या आयकर अपीलीय द्वारा पारित किसी भी आदेश से पीड़ित निर्धारिती न्यायाधिकरण या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण *(*इसके बाद पीड़ित व्यक्ति के रूप में संदर्भित*)* द्वारा पारित किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकता है और इस तरह की अपील के तहत

यह उप-धारा *(* क*)* उस तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर दायर किया जाए जिस दिन के खिलाफ अपील किया गया आदेश प्राप्त हुआ है

निर्धारिती या पीड़ित व्यक्ति या प्रमुख *[2014] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो*;*

(ख*)* सटीक रूप से अपील के ज्ञापन के रूप में हो

इसमें शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को बताते हुए*;* और

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े मामलों के लिए दाखिल किया जाएगा: बशर्ते कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर अपील पर विचार कर सकता है, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(3) जहां उप-धारा *(1)* के तहत अपील स्वीकार की जाती है,

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण। *(क)* अपील की सुनवाई के लिए कानून का प्रश्न तैयार करेगा*;* और

(ख) इस संबंध में किसी भी प्रासंगिक मुद्दे का निर्धारण भी कर सकता है।

इस तरह से तैयार किए गए प्रश्न के साथ *((i)* जो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार निर्धारित नहीं किया गया है या

((ii) जो आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गलत तरीके से निर्धारित किया गया है, और इस तरह से तैयार किए गए कानून के प्रश्न और इस तरह से निर्धारित अन्य प्रासंगिक मुद्दे पर निर्णय लेगा और उस पर आधार युक्त ऐसा निर्णय देगा।

जिस पर ऐसा निर्णय लिया जाता है और वह ऐसी लागत प्रदान कर सकता है जो वह उचित समझे।

(4) जहाँ इस धारा के तहत किसी भी अपील में, निर्णय

आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में भुगतान शामिल है।

किसी भी कर या शुल्क के लिए, निर्धारिती या पीड़ित व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपील तब तक की जाए जब तक कि वह आदेश के आधार पर देय ऐसे कर या शुल्क का कम से कम पच्चीस प्रतिशत जमा न कर दे।

भारत संघ *323*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

खिलाफः

बशर्ते कि जहां किसी विशेष मामले में राष्ट्रीय कर

न्यायाधिकरण की राय है कि इस उप-धारा के तहत कर या शुल्क जमा करने से ऐसे व्यक्ति को अनुचित कठिनाई होगी।

यह ऐसी शर्तों के अधीन ऐसी जमा राशि का भुगतान कर सकता है।

सरकार का विभाग किसी भी निर्णय से व्यथित है या राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण का आदेश एक अपील दायर कर सकता है

की तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय कर के निर्णय या आदेश का संचार

उसे न्यायाधिकरण*;*

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे इसके भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।

ऐसा समय जो उचित लगे। "

5. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेना, भले ही वे विशेष विषय मामलों से उत्पन्न हों, भारत के उच्च न्यायालयों का एक मुख्य कार्य होगा, और इसे किसी अन्य मंच द्वारा हड़पा नहीं जा सकता है। इस तर्क की वैधता का परीक्षण करने के लिए, हमें कुछ संवैधानिक मूल सिद्धांतों पर जाने की आवश्यकता है।

6. यह माना गया है कि अमेरिकी संविधान के विपरीत, भारत के संविधान में शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं है।

इसके बावजूद, संविधान में सरकार की तीन शाखाओं में से प्रत्येक के लिए समर्पित कई अलग-अलग अध्याय हैं। भाग *5* का अध्याय *4* विशेष रूप से केंद्रीय न्यायपालिका से संबंधित है और भाग *6* का अध्याय *5* राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है।

7. संविधान के अनुच्छेद *50* में कहा गया हैः

"*50.* न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करनाः राज्य

राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा।

8. Art.129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। कला. *131* सर्वोच्च *[2014] 10* एस. सी. आर.

324 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत सरकार और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों में मूल अधिकार क्षेत्र वाला न्यायालय। कला. *132 134* क उच्च न्यायालय से दीवानी और आपराधिक मामलों में एक अपीलीय क्षेत्राधिकार निहित करता है।

अदालतें। कला. *136* सर्वोच्च न्यायालय को अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए एक असाधारण विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है

भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी कारण या मामले में कोई निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश। कला के तहत। *137* , उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद *141* द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। और कला के आधार पर। *145 (3)* भारत के संविधान की व्याख्या के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं -

विशेष रूप से कम से कम *5* माननीय न्यायाधीशों की पीठ में निहित।

9. इसी तरह, कला के तहत। *214* प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए जाते हैं और कला के तहत होते हैं। *215* उच्चतम न्यायालय की तरह, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होंगे और उनके पास इस तरह की सभी शक्तियां होंगी।

अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित न्यायालय। कला के तहत। *225* , किसी भी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि संरक्षित है। कला. *226* उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को विभिन्न रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कला के तहत। *228* संविधान की व्याख्या से जुड़े प्रश्न होने चाहिए

केवल उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है जब उसके अधीनस्थ न्यायालय को इस तरह के प्रश्न का पता चलता है। इसके अलावा, इन प्रावधानों के महत्व को कला द्वारा और उजागर किया गया है। *368* परंतुक जो सभी उपरोक्त अनुच्छेदों के संशोधन की अनुमति केवल तभी देता है जब इस तरह के संशोधन को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी अनुमोदित किया जाता है। *10.* सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं जो उच्च न्यायालय को धारा *113* के तहत कानून के कुछ प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं और जब वे क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों से संबंधित होते हैं, तो धारा *115*।

11. कला. *227* यह प्राचीन काल का है। इसकी उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम *1915* की धारा *107* में हुई है जो इस प्रकार है:

" प्रत्येक उच्च न्यायालय का तत्समय सभी न्यायालयों पर पर्यवेक्षण उसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अधीन है, और मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *325*

[आर. एफ. नरीमन, जे. *]*

निम्नलिखित में से कोई भी काम कर सकते हैं, अर्थात।

(ए*)* वापसी के लिए कॉल करें*;*

(ख*)* ऐसे किसी भी न्यायालय से किसी भी वाद या अपील को समान या उच्चतर अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दें*;*

(ग*)* सामान्य नियम बनाएँ और जारी करें और इसके लिए प्रपत्र निर्धारित करें।

ऐसे न्यायालयों के व्यवहार और कार्यवाहियों को विनियमित करना*;*

(घ*)* प्रपत्र निर्धारित करें जिसमें ऐसे किसी भी न्यायालय के अधिकारियों द्वारा पुस्तकें, प्रविष्टियां और खाते रखे जाएँगे और शेरिफ, वकीलों और सभी को अनुमति दी जाने वाली शुल्क की तालिकाओं का निपटारा करें।

कुछ समय के लिए कानून के प्रावधानों के साथ असंगत कलकत्ता उच्च न्यायालय के मामले में गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी

परिषद, और स्थानीय सरकार के अन्य मामलों में। *12.* भारत सरकार अधिनियम *1935* की धारा *224* अधिक

एस. एस. ने कुछ परिवर्तनों के साथ *1915* के अधिनियम की धारा *107* को अपनाया।

" (1) प्रत्येक उच्च न्यायालय का तत्समय भारत के सभी न्यायालयों पर पर्यवेक्षण उसके अपीलीय कार्य के अधीन होगा।

अधिकारिता, और निम्नलिखित में से कोई भी काम कर सकता है, अर्थात

कहने के लिए, *(ए)* वापसी के लिए कॉल करें;

(ख) सामान्य नियम बनाएँ और जारी करें और इसके लिए प्रपत्र निर्धारित करें।

ऐसे न्यायालयों के व्यवहार और कार्यवाहियों को विनियमित करना;

(ग) प्रपत्र निर्धारित करें जिसमें पुस्तकें, प्रविष्टियाँ और खाते हों।

ऐसे किसी भी न्यायालय के अधिकारियों द्वारा रखा जाएगा; और

और अदालतों के सभी क्लर्क और अधिकारी: बशर्ते कि ऐसे नियम, प्रपत्र और तालिकाएँ

किसी भी कानून के प्रावधान के साथ असंगत

लागू है और इसके लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी राज्यपाल।

(2) इस धारा में कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. को देने के रूप में नहीं माना जाएगा।

उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय पर सवाल उठाने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र कोई निम्न न्यायालय जो अन्यथा अपील के अधीन नहीं है

या पुनरीक्षण।

संविधान के अनुच्छेद *227* में कहा गया है:

227. उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति

(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय का सभी पर अधीक्षण होगा। संबंध में सभी क्षेत्रों में न्यायालय और न्यायाधिकरण

जिसके लिए यह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है

(2) पूर्वगामी की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उपबंध, उच्च न्यायालय कर सकता है

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी की मांग करना;

(ख) सामान्य नियम बनाएँ और जारी करें और ऐसे न्यायालयों के व्यवहार और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित करें; और

(ग) प्रपत्र निर्धारित करें जिसमें पुस्तकें, प्रविष्टियाँ और खाते हों। ऐसे किसी भी न्यायालय के अधिकारियों द्वारा रखा जाएगा।

(3) उच्च न्यायालय भी अनुमति देने के लिए शुल्क की तालिकाओं का निपटारा कर सकता है

शेरिफ और ऐसे न्यायालयों के सभी क्लर्कों और अधिकारियों को और

इसमें वकालत करने वाले वकीलों, अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं के लिए:

खंड *(2)* या खंड *(3)* के तहत तय नहीं किया जाएगा कुछ समय के लिए किसी भी कानून के प्रावधान से असंगत

लागू है और इसके लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी

राज्यपाल *(4)* इस अनुच्छेद में कुछ भी प्रदान करने के लिए नहीं माना जाएगा

किसी भी न्यायालय पर अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ या

सशस्त्र निकायों से संबंधित किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित न्यायाधिकरण

बल "।

13. यह ध्यान दिया जाएगा कि कला। *227* "और न्यायाधिकरण" शब्दों को जोड़ता है *I* में कोई आवश्यकता नहीं है कि अधीक्षण समाप्त हो जाएअध्यादेश अदालतों और न्यायाधिकरणों को इसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अधीन होना चाहिए।

14. वरयाम सिंह बनाम। अमरनाथ, *1954* एससीआर *565,* दास, जे।

मद्रास बार एसोसिएशन वी. वी. भारत संघ *327*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

कला के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख किया। *227 :*

"अनुच्छेद *227* द्वारा प्रदत्त अधीक्षण की यह शक्ति, जैसा कि हैरिस सी. जे. ने डालमिया जैन एयरवेज लिमिटेड बनाम में बताया है। सुकुमार मुखर्जी का प्रयोग सबसे कम और केवल उपयुक्त मामलों में किया जाना चाहिए ताकि अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखा जा सके न कि सुधार के लिए। केवल त्रुटियाँ। जैसा कि न्यायपालिका ने ठीक ही कहा है

हमारे समक्ष मामले में आयुक्त निचली अदालतों ने निष्कासन के लिए आदेश देने से इनकार करते हुए मनमाने ढंग से काम किया।

निचली अदालतों ने कानूनी स्थिति को महसूस किया लेकिन वास्तव में वह करने से इनकार कर दिया जो धारा *13 (2) (i)* द्वारा उन्हें करने के लिए बाध्य किया गया था और इस तरह कानून द्वारा उनमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अतः यह एक ऐसा मामला था जिसमें न्यायिक आयुक्त की अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने का आह्वान किया गया था और

इसने ऐसा करने में काफी अच्छा काम किया। " *(571* पर*)*

15. यह स्वयंसिद्ध है कि उच्च की अधीक्षण शक्ति

कला के तहत न्यायालय। *227* न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को कानून की सीमा के भीतर रखना है। इसलिए, कानून की त्रुटियां जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट हैं, उन्हें ठीक किया जा सकता है। इस तरह की त्रुटियों को सुधारने में, उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से यह बताना होगा कि कानून के प्रश्नों का निर्णय करके कानून क्या है, जो अधीनस्थ अदालतों को बाध्य करते हैं और

भविष्य के मामलों में न्यायाधिकरण। इस तथ्य के बावजूद कि कला का कोई समकक्ष नहीं है। *141* जहाँ तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड बनाम कलकत्ता में। सीमा शुल्क कलेक्टर,

(1963) 3 एस. सी. आर. *338*, जे. सुब्बा राव ने कहाः

"इससे यह सवाल उठता है कि क्या एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून की अनदेखी कर सकता है और इस तरह घोषित कानून के सीधे उल्लंघन में कार्यवाही शुरू कर सकता है। कला के तहत। *215* , प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी। कला के तहत। *226* , इसके पास मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को आदेश या रिट जारी करने की पूर्ण शक्ति है, जिसमें उचित मामलों में कोई भी सरकार शामिल है।

अधिकार क्षेत्र। कला के तहत। *227* यह उन सभी क्षेत्रों में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधिकारिता रखता है जिनके संबंध में यह अधिकारिता का प्रयोग करता है। *[2014] 10* एस. सी. आर. का सुझाव देना विसंगत होगा।

कि एक न्यायाधिकरण जिस पर उच्च न्यायालय का अधीक्षक है

उस न्यायालय द्वारा घोषित कानून की उपेक्षा कर सकते हैं और इसका सीधा उल्लंघन करते हुए कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। यदि एक न्यायाधिकरण ऐसा कर सकता है, तो सभी अधीनस्थ अदालतें समान रूप से ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

उपबंध, उच्चतम न्यायालय के मामले की तरह, उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी बनाना। किसी उच्चतर न्यायाधिकरण को प्रदत्त पर्यवेक्षण की शक्ति में यह निहित है कि उसके पर्यवेक्षण के अधीन सभी न्यायाधिकरणों को उसके द्वारा निर्धारित कानून का पालन करना चाहिए। इस तरह की आज्ञाकारिता उनके सुचारू रूप से काम करने के लिए भी अनुकूल होगीः

अन्यथा कानून के प्रशासन में भ्रम पैदा हो जाएगा और कानून के प्रति सम्मान अपरिहार्य रूप से प्रभावित होगा। इसलिए हमारा मानना है कि राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून उसके पर्यवेक्षण के तहत अधिकारियों या न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी है और वे कार्यवाही शुरू करने या इसमें शामिल अधिकारों पर निर्णय लेने में इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

ऐसी कार्यवाही में "। *(366* पर) *16.* उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि उच्चतर द्वारा निर्णय

कानून के प्रश्नों के अभिलेख की अदालतें और ऐसे निर्णयों का बाध्यकारी प्रभाव चीजों की संवैधानिक योजना में निहित हैं। यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट रूप से उच्च न्यायपालिका का प्रांत है।

न केवल वर्तमान मामले के लिए बल्कि भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का मार्गदर्शन करने के लिए भी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना। कि यह ऊपर निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों द्वारा उल्लिखित न्यायिक कार्य का मूल है।

17. कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल क्या है, इसका फैसला बहुत पहले सर चुनीलाल वी. मेहता बनाम में किया गया है। द सेंचुरी स्पिन

और विनिर्माण कंपनी लिमिटेड, *(1962)* पूरक। *3* पृष्ठों पर एससीआर *549 557-558* इस प्रकारः

...... यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मामले में उठाया गया कानून का प्रश्न पर्याप्त है, हमारी राय में, यह होगा कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या क्या यह प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करता है और यदि ऐसा है तो क्या यह या तो इस अर्थ में एक खुला प्रश्न है।

कि यह अंततः इस न्यायालय या प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय द्वारा तय नहीं किया गया है या कठिनाई से मुक्त नहीं है या वैकल्पिक विचारों की चर्चा के लिए आह्वान नहीं है। यदि प्रश्न का समाधान किया जाता है तो मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *329*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

उच्चतम न्यायालय द्वारा या प्रश्न के निर्धारण में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का केवल एक सवाल है या यह कि उठाई गई याचिका स्पष्ट रूप से बेतुकी है कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न। *"*

18. इसलिए, यह स्पष्ट है कि कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय एक महान क्षण का विषय है। यह कानून का एक ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो सामान्य सार्वजनिक महत्व का हो या कठिनाई से मुक्त न हो और/या वैकल्पिक विचारों की चर्चा का आह्वान करता हो। इसलिए, यह स्पष्ट है कि कानून के प्रश्नों को तय करने के अनुभव के साथ एक न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग एक अनिवार्य शर्त है ताकि ऐसे प्रश्नों का सही निर्णय लिया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि हमारा ध्यान विभिन्न अधिनियमों की ओर आकर्षित किया गया है जहां प्रश्नों पर अपील की जाती है

कानून/कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न।

" ? i) विद्युत अधिनियम, *2003*

125. उच्चतम न्यायालय में अपील-अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *100* में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक आधार पर, उसे अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

1908 (5 1908 का*):*

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे इसके भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।

एक और अवधि जो साठ दिनों से अधिक न हो। *((ii)* राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010*

धारा *22*। उच्चतम न्यायालय में अपील-कोई भी व्यथित व्यक्ति

न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, निर्णय या आदेश द्वारा, नब्बे दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *100* में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक आधार पर न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश के बारे में उसे सूचित करने की तारीख,

1908 (5 1908)।

बशर्ते कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के बाद किसी भी अपील पर विचार करे।

.

नब्बे दिनों की समाप्ति, यदि यह संतुष्ट है कि अपीलार्थी को अपील करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(iii) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, *1997*

पक्षकारों की सहमति से अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा। *(3)* इस धारा के तहत प्रत्येक अपील को निर्णय या आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके खिलाफ अपील कीः

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय नब्बे दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारण से रोका गया था - समय पर अपील को प्राथमिकता देना।

((iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, *1992*

धारा *15Z.* सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। - कोई भी व्यक्ति

प्रतिभूति अपीलीय के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित

न्यायाधिकरण निर्णय की सूचना की तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। या ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न पर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेशः

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे साठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।

(v) कंपनी अधिनियम, *1956*

धारा *10* जी. एफ. सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। - कोई भी व्यक्ति

अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

भारत का संघ *331*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न पर उसे अपीलीय न्यायाधिकरण का

ऐसे निर्णय या आदेश से बाहरः

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे इसके भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।

एक और अवधि जो साठ दिनों से अधिक न हो।

19. चाहे कोई सिविल प्रक्रिया संहिता की पुरानी धारा *100* को देखे या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *100* को देखे।*1976* में प्रतिस्थापित किया गया, परिणाम यह है कि अकेले उच्च न्यायालय

कानून के प्रश्नों को तय करने की शक्ति निहित है।

धारा *100 (*संशोधन से पहले*)*

" 100 (1) . इसके अलावा जहां इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर, अर्थात्ः

(ए*)* निर्णय कानून के विपरीत या कुछ उपयोग के लिए

कानून का बल होना*;*

(ख*)* निर्णय कुछ सामग्री निर्धारित करने में विफल रहा है

कानून का मुद्दा या कानून का बल रखने वाला उपयोग*;*

(ग) इस संहिता या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण त्रुटि या दोष, जिसने संभवतः प्रक्रिया में त्रुटि या दोष उत्पन्न किया हो।

गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय।

(2) इस धारा के तहत एकतरफा पारित अपीलीय डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है।

धारा *100 (*संशोधन के बाद*)*

100. दूसरी अपील

(1) इस संहिता के मुख्य भाग में या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में एक महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है। कानून का सवाल।

(2) एक अपील इस धारा के तहत पारित एक अपीलीय डिक्री से हो सकती है।

(3) इस धारा के तहत एक अपील में,

अपील में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख होगा।

अपील में शामिल। *(4)* जहाँ उच्च न्यायालय का समाधान होता है कि एक सारवान

कानून का प्रश्न किसी भी मामले में शामिल है, यह उस प्रश्न को तैयार करेगा।

(5) इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात न्यायालय द्वारा प्रणीत नहीं किए गए कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति को, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छीनने या कम करने के लिए नहीं मानी जाएगी, यदि यह संतुष्ट है कि

इस मामले में ऐसा सवाल शामिल है।

20. यह स्पष्ट है कि अब तक संसद ने एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा है

कानून के प्रश्नों/कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णयों के साथ रिकॉर्ड की अदालत। इसके अलावा, जैसा कि पारंपरिक रूप से जे. खेहर के निर्णय में बताया गया है, ऐसे प्रश्नों का निर्णय हमेशा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता था।

देश में अदालतें। वर्तमान अधिनियम संसद द्वारा पहली बार बनाया गया एक प्रस्थान है।

21. इस संबंध में, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि चूंकि कराधान एक विशेष विषय है और एक पूर्ण संहिता निर्धारित की गई है

इस विषय को तय करने के लिए, वर्तमान विवादित अधिनियम उस संहिता का हिस्सा होने के कारण संवैधानिक रूप से मान्य है। इस उद्देश्य के लिए, उत्तरदाताओं

मफतलाल इंडस्ट्रीज बनाम में नौ न्यायाधीशों की पीठ के एक अंश पर भरोसा किया है। भारत संघ, *(1997) 5* एस. सी. सी. *536* पैरा *77* पर।

22. मफतलाल के मामले में इस अदालत का सामना इस बात से था कि क्या कन्हैया लाल मुकुंदलाल सराफ का मामला, *1959* एससीआर *1350* है।

जहां तक यह कहा गया है कि जहां करों का भुगतान कानून की गलती के तहत किया जाता है, वहां भुगतान करने वाला व्यक्ति गलती स्थापित करने पर राज्य से ऐसे करों की वसूली करने का हकदार है और

यह परिणाम अनुबंध अधिनियम की धारा *72* से आता है। में।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने एक टिप्पणी की कि इसलिए मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *333*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

जब तक सर्वोच्च न्यायालय को एक अपील प्रदान की जाती है

अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश, अधिनियम संवैधानिक रूप से मान्य होगा। इस न्यायालय ने यह निर्णय लेते हुए कि सराफ के मामले का निर्णय सही तरीके से किया गया था या नहीं, वर्तमान प्रश्न का बिल्कुल भी सामना नहीं किया। इसके अलावा, जिस समय मफतलाल के मामले का निर्णय लिया गया था, उस समय केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, *1944* में निहित योजना के लिए उच्च न्यायालय से अपील न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न कानून के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए उसे दिए गए मामले के एक बयान पर उच्च न्यायालय की आवश्यकता थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय को अपना निर्णय देना है और इसे उच्च न्यायालय को वापस भेजना है।

अपीलीय न्यायाधिकरण जो तब ऐसे आदेश देगा जो ऐसे निर्णय के अनुरूप मामले के निपटारे के लिए आवश्यक हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, *1944* की तत्कालीन वैधानिक योजना है -

धारा *35* जी से *35* एल में निहित है।

"35 जी. उच्च न्यायालय को मामले का विवरण।

(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर या अन्य पक्ष,

उस तारीख के साठ दिनों के भीतर जिस पर उसे धारा *35* सी के तहत एक आदेश की सूचना दी जाती है *(*अन्य बातों के अलावा, उत्पाद शुल्क की दर या निर्धारण के उद्देश्यों के लिए माल के मूल्य से संबंधित किसी भी प्रश्न के निर्धारण से संबंधित आदेश नहीं होने के कारण*)* निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, साथ में, जहां दूसरे पक्ष

द्वारा आवेदन किया जाता है, दो सौ रुपये के शुल्क से, अपीलीय न्यायाधिकरण से ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने की आवश्यकता होती है।

और, इस धारा में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, अपीलीय न्यायाधिकरण, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के एक सौ बीस दिनों के भीतर, एक बयान तैयार करेगा।

मामले के बारे में और इसे उच्च न्यायालय को भेजेंः

बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को पहले की अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था

निर्दिष्ट, इसे आगे की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दें

तीस दिनों से अधिक नहीं।

(2) इस सूचना की प्राप्ति पर कि उप-धारा *(1)* के तहत एक आवेदन किया गया है, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ ऐसा आवेदन किया गया है, वह अदालत की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. का समर्थन कर सकता है।

हो सकता है कि नोटिस प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर, आदेश के किसी भी हिस्से के खिलाफ निर्धारित तरीके से सत्यापित क्रॉस-आपत्तियों का ज्ञापन, जिसके संबंध में संदर्भ के लिए आवेदन किया गया हो, दायर नहीं किया गया हो और ऐसे ज्ञापन का निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह किया जाएगा जैसे कि यह उप-धारा में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया गया आवेदन हो।

(1) .

(3) यदि, उप-धारा *(1)* के तहत किए गए आवेदन पर,

अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले को आधार पर बताने से इनकार कर दिया

ताकि कानून का कोई सवाल न उठे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कलेक्टर, या, जैसा भी मामला हो, दूसरा पक्ष, उस तारीख से छह महीने के भीतर, जिस दिन उसे इस तरह के इनकार की सूचना दी जाती है, उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है और उच्च न्यायालय, यदि वह अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय की शुद्धता से संतुष्ट नहीं है, तो अपीलीय न्यायाधिकरण से मामले को बताने और इसे संदर्भित करने की अपेक्षा कर सकता है, और ऐसी कोई मांग प्राप्त होने पर,

अपीलीय न्यायाधिकरण मामले को बताएगा और उसी के अनुसार उसे भेजेगा। *(4)* जहां उप-धारा *(3)* के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण किसी ऐसे मामले को बताने से इनकार कर देता है जिसे किसी आवेदक द्वारा बताने की आवश्यकता होती है, तो आवेदक, उस तारीख से तीस दिनों के भीतर, जिस दिन उसे इस तरह के इनकार की सूचना मिलती है, अपना आवेदन वापस ले सकता है और, यदि वह

यदि ऐसा करता है, तो उसके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क, यदि कोई हो, वापस कर दिया जाएगा।

35 एच. कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय को मामले का विवरण।

यदि, धारा *35* जी के तहत किए गए किसी आवेदन पर, अपीलीय न्यायाधिकरण की राय है कि कानून के किसी विशेष प्रश्न के संबंध में उच्च न्यायालयों के निर्णयों में टकराव के कारण, यह समीचीन है कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया जाना चाहिए, तो अपीलीय न्यायाधिकरण आकर्षित कर सकता है।

मामले का एक बयान दें और इसे राष्ट्रपति के माध्यम से सीधे सर्वोच्च न्यायालय को भेजें।

351. बयान में संशोधन की आवश्यकता के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। यदि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं है कि किसी मामले में दिए गए बयान

यह मद्रास बार एसोसिएशन *v* के प्रश्नों को निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है।

भारत संघ *335*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इस प्रकार उठाए जाने पर, न्यायालय इस तरह के परिवर्धन करने के उद्देश्य से मामले को अपीलीय न्यायाधिकरण को वापस भेज सकता है

उसमें या उसमें परिवर्तन जो वह उस निमित्त निर्देशित करे। *35* जे. उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई कम से कम

दो न्यायाधीश।

(1) जब कोई मामला धारा *35* जी के तहत उच्च न्यायालय को भेजा जाता है, तो इसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी और इस पर निर्णय ऐसे न्यायाधीशों या न्यायाधीशों की राय के अनुसार किया जाएगा।

(2) जहाँ ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहाँ न्यायाधीश उस विधि के बिंदु को बताएँगे जिस पर उनका मतभेद है और मामले की सुनवाई उस बिंदु पर केवल उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी, और ऐसे बिंदु का निर्णय उन न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने पहले सुनवाई की है। यह।

35 के. मामले पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है।

(1) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी मामले की सुनवाई करते हुए उसमें उठाए गए कानून के प्रश्नों का निर्णय करेगा और उस पर अपना निर्णय देगा जिसमें वे आधार होंगे जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है और निर्णय की एक प्रति होगी।

न्यायालय की मुहर और पंजीयक के हस्ताक्षर के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा जो ऐसे आदेश पारित करेगा जो मामले के निपटारे के लिए आवश्यक हैं।

इस तरह के निर्णय के अनुरूपता। *(2)* उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को किसी भी संदर्भ की लागत जिसमें भुगतान करने के लिए शुल्क शामिल नहीं होगा।

निर्देश न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा।

35 एल. सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। उच्चतम न्यायालय में एक अपील होगी

(क) उच्च न्यायालय का कोई निर्णय जो किसी संदर्भ पर दिया गया हो।

किसी भी मामले में धारा 35 जी के तहत किया गया, जो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या पार्टी 336 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 10 एस. सी. आर. द्वारा या उसकी ओर से किए गए मौखिक आवेदन पर।

व्यथित, निर्णय पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय को अपील के लिए उपयुक्त होने के लिए प्रमाणित करता है

उच्चतम न्यायालय; या

(ख) अन्य बातों के अलावा, उत्पाद शुल्क की दर या मूल्य से संबंधित किसी भी प्रश्न के निर्धारण से संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश।

मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए माल का निर्धारण। "

23. यह स्पष्ट है कि नौ न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

केवल धारा 35 एल के उपखंड (बी) के तहत आने वाले अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णयों का उल्लेख कर रहा था जो द्वारा पारित आदेशों से संबंधित थे मूल्यांकन के उद्देश्य से उत्पाद शुल्क या माल के मूल्य की दर से संबंधित प्रश्नों पर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के बाद धारा 35 जी के तहत दिए गए उच्च न्यायालय के निर्णयों से अपील नहीं

कानून के बारे में। इसलिए यह स्पष्ट है कि मफतलाल के फैसले का संदर्भ पूरी तरह से अलग था और निर्णय का विज्ञापन नहीं किया गया था।

धारा 35 जी से 35 एल तक, जैसा कि वे तब थे।

24. कला. 323 बी संविधान 42 वें संशोधन अधिनियम का हिस्सा था जो, जैसा कि सर्वविदित है, एक संशोधन था जिसे 1975 के आपातकाल के दौरान जल्दबाजी में पारित किया गया था। इसकी कई विशेषताओं को संविधान के 44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्ववत कर दिया गया था।

वर्षों बाद। जिन दिलचस्प विशेषताओं को पूर्ववत किया गया था, उनमें से एक कला में संशोधन था। 227. 42 वें संशोधन ने अनुच्छेद के खंड (1) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया। 227 :

"(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय का अधीक्षण होगा।

अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी न्यायालयों पर।

25. प्रतिस्थापित खंड के सरसरी पठन से पता चलता है कि

भारत सरकार अधिनियम *1915* की पुरानी धारा *107* को वापस लाया गयाः न्यायाधिकरण अब उच्च न्यायालयों के अधीन नहीं थे

अधीक्षण और अधीनस्थ न्यायालय केवल उच्च न्यायालयों के अधीक्षण के अधीन थे, यदि वे भी इसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अधीन थे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, *44* वें संशोधन ने इसे रद्द कर दिया और उपखंड *(1)* को अपनी मूल स्थिति में बहाल कर दिया।

26. हालांकि, कला। *323* बी संविधान के हिस्से के रूप में जारी है। उक्त लेख को डालने का वास्तविक कारण वही था

कला में किए गए संशोधन के रूप में। *227-* उच्च मद्रास बार संगठन को हटाना *v.*

भारत संघ *337*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

न्यायाधिकरणों पर न्यायालयों का पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ *(1997) 3* एस. सी. सी. *261* ने उच्च न्यायालयों के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र को बहाल करके अनुच्छेद *323* बी के मूल कारण को समाप्त कर दिया ताकि अनुच्छेद *323* बी का संदर्भ अब संबंधित कानून बनाने के लिए विधायी क्षमता के रूप में आवश्यक न हो। न्यायाधिकरणों का किसी भी मामले में प्रविष्टि *77* से *79*, सूची *I* की *95*, सूची *II* की प्रविष्टि *65* और प्रविष्टि *11* ए और सूची *III* की *46* तक पता लगाया जा सकता है।

भारत के संविधान की *7* वीं अनुसूची।

27. कानून के एक महत्वपूर्ण बयान में, चंद्र कुमार का

निर्णय, उच्च न्यायालय के मूल निहित को बरकरार रखने में

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार कहा गया हैः

"संवैधानिक दायरे में न्यायालयों की शक्तियों की वैधता

विधायी कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए लोकतंत्रों पर पहली बार कल्पना किए जाने के समय से ही सवाल उठाए गए हैं। भारत के संविधान ने इस तरह की आलोचनाओं का सामना करते हुए उच्च न्यायपालिका को ऐसी शक्ति प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को शामिल किया है। जिस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया, उसके विश्लेषण से संकेत मिलता है कि वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए बहुत चिंतित थे। इन प्रयासों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि न्यायपालिका

न्यायिक समीक्षा की अपनी व्यापक शक्तियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम होना। जबकि संविधान उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, इसमें न्यायाधीशों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति की आयु के साथ-साथ न्यायाधीशों के कार्यकाल से संबंधित विस्तृत प्रावधान भी शामिल हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन के लिए तंत्र। इस तरह के विस्तृत प्रावधानों को शामिल करना प्रतीत होता है

इस विश्वास के कारण कि इस तरह के प्रावधानों से सशस्त्र, उच्च न्यायालय किसी भी कार्यपालिका से अछूते रहेंगे

क्या वे हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करना है कि संविधान द्वारा परिकल्पित शक्ति का संतुलन बनाए रखा जाए और विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों के निर्वहन में संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती है। यह समान रूप से उनका कर्तव्य *(2014) 10* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

:

यह निरीक्षण करना कि अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का संचालन करने वालों द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय कानूनी शुद्धता और न्यायिक स्वतंत्रता के सख्त मानकों के उल्लंघन में न पड़ें। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक सुरक्षा उपाय अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों या सामान्य न्यायपालिका द्वारा बनाए गए न्यायाधिकरणों का संचालन करने वालों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कानून। नतीजतन, बाद की श्रेणी के न्यायाधीशों को कभी भी उच्च न्यायपालिका के लिए पूर्ण और प्रभावी विकल्प नहीं माना जा सकता है।

संवैधानिक व्याख्या। इसलिए हम मानते हैं कि विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है -

उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद *226* के अधीन और इस न्यायालय में

अन्य पहलुओं पर आगे बढ़ने से पहले, हम इन न्यायाधिकरणों की अधिकारिता शक्तियों पर अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायाधिकरण उन मामलों की सुनवाई करने के लिए सक्षम हैं जहां वैधानिक प्रावधानों की शक्तियों पर सवाल उठाए जाते हैं। हालाँकि, इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, वे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के विकल्प के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत विशेष रूप से ऐसा दायित्व सौंपा गया है। इस संबंध में उनका कार्य केवल पूरक है और न्यायाधिकरणों के ऐसे सभी निर्णय संबंधित उच्च न्यायालयों की एक खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे। *(* पैरा *93* देखें*)*

मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *339*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

28. अब भारत संघ बनाम पर महान्यायवादी की निर्भरता के लिए मंच तैयार है। आर. गांधी *(2010) 11* एससीसी *1.* कंपनी अधिनियम, *1956* के विभिन्न प्रावधानों को संविधान पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। इनका प्रभाव

प्रावधान कंपनी विधि बोर्ड को मूल अधिकार क्षेत्र में निहित एक न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित करना और प्रथम अपील में उच्च न्यायालय को एक अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ प्रतिस्थापित करना था। फर्क देखने के बाद

पैरा *38* और *45* में न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के बीच, न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लेख किया, जैसा कि पैरा *46* से *57* में भारतीय संवैधानिक संदर्भ में समझा गया है। कानून के एक महत्वपूर्ण बयान में संविधान पीठ ने कहाः

"संविधान में न्यायिक शक्ति पर विचार किया गया है

न्यायालयों और न्यायाधिकरणों दोनों द्वारा प्रयोग किया जाता है। संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों में निहित शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को छोड़कर, न्यायालयों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को विधायी अधिनियमों द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। उच्च न्यायालयों में निहित हैं -

कई विशिष्ट विधायी अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसरण में अपीलों, संशोधनों और संदर्भों को स्वीकार करने और सुनने की अधिकारिता। यदि उच्च न्यायालयों द्वारा सुनवाई के लिए अपीलों, संशोधनों और संदर्भों का प्रावधान करके उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र बनाया जा सकता है, तो अपीलों, संशोधनों या संदर्भों के प्रावधानों को हटाकर भी अधिकार क्षेत्र को हटाया जा सकता है। इसका यह भी तात्पर्य है कि विधायिका के पास विशिष्ट अधिनियमों के संदर्भ में न्यायाधिकरण बनाने और उन्हें निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की शक्ति है

ऐसे विशेष अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में विवाद। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायिका के पास पारंपरिक रूप से न्यायिक कार्यों को स्थानांतरित करने की कोई शक्ति नहीं है

न्यायालयों द्वारा न्यायाधिकरणों को निष्पादित किया गया। *(* पैरा *87)*

एक अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद में, संविधान पीठ ने कहाः "लेकिन जब हम कहते हैं कि विधायिका के पास कानून बनाने की क्षमता है, यह प्रावधान करते हुए कि किन विवादों का फैसला अदालतों द्वारा किया जाएगा, और किन विवादों का फैसला न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाएगा, तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किए बिना और कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक सीमाओं के अधीन है।

[2014] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

}

यदि न्यायाधिकरणों को अब तक अदालतों में निहित या उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक शक्ति के साथ निहित किया जाना है, तो ऐसे न्यायाधिकरणों के पास होना चाहिए

इससे जुड़ी स्वतंत्रता, सुरक्षा और क्षमता

अदालतें। यदि न्यायाधिकरणों का उद्देश्य किसी ऐसे क्षेत्र की सेवा करना है जिसके लिए विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है

न्यायिक सदस्यों के अलावा तकनीकी सदस्य भी हो सकते हैं। जहां हालांकि कुछ श्रेणी के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र केवल अदालतों से न्यायाधिकरणों को स्थानांतरित किया जाता है ताकि मामले में तेजी लाई जा सके।

सुनवाई और निपटान या साक्ष्य की कठोरता से राहत

अधिनियम और प्रक्रियात्मक कानूनों में, स्पष्ट रूप से किसी गैर-न्यायिक तकनीकी सदस्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसे न्यायाधिकरणों के संबंध में, केवल न्यायपालिका के सदस्य ही होने चाहिए

पीठासीन अधिकारी/सदस्य। इस तरह के विशेष न्यायाधिकरणों के विशिष्ट उदाहरण किराए के न्यायाधिकरण, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कई अधिनियमों के तहत विशेष अदालतें हैं। इसलिए, जब न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता को न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित किया जाता है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता शामिल नहीं होती है और निपटान में तेजी लाना और प्रक्रिया में ढील देना एकमात्र उद्देश्य है, तो न्यायिक सदस्यों के अलावा या प्रतिस्थापन में तकनीकी सदस्यों के लिए एक प्रावधान स्पष्ट रूप से न्यायपालिका और कानून के शासन की स्वतंत्रता को कमजोर करने और अतिक्रमण करने का मामला होगा और यह असंवैधानिक होगा। *(पैरा में 90)*

इसके बाद पीठ ने यह निर्णय दिया कि केवल कुछ क्षेत्रों को अदालतों से न्यायाधिकरणों में स्थानांतरित किया जा सकता है। *(पैरा देखें*

पैराग्राफ *101* और *102* में कानून इस प्रकार कहा गया हैः

"के निर्धारण के लिए स्वतंत्र न्यायिक न्यायाधिकरण

नागरिकों के अधिकार, और नागरिकों के विवादों और शिकायतों के निर्णय के लिए, एक आवश्यक सहवर्ती है।

कानून के शासन से। कानून के शासन के कई पहलू हैं, जिनमें से एक यह है कि नागरिकों के विवादों का फैसला उन न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा जो स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं; और वे विवाद इस प्रकार हैं - सरकार के कार्यों की वैधता का निर्णय उन न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा जो कार्यपालिका से स्वतंत्र हैं। इसका एक और पहलू

कानून का शासन कानून के समक्ष समानता है। समानता का सार मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *341*

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह है कि इसे एक स्वतंत्र न्यायिक मंच द्वारा लागू करने और निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता

और कार्यपालिका से न्यायिक शक्ति को अलग करना हमारे जैसे संविधान में निहित सामान्य कानून परंपराओं का हिस्सा है जो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है।

कानून के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार और कला द्वारा गारंटीकृत कानूनों का समान संरक्षण। *14* संविधान का,

स्पष्ट रूप से व्यक्ति के अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, जो एक मंच द्वारा निर्णय लिया जाता है जो निष्पक्ष रूप से न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है। और स्वतंत्र तरीके से, मान्यता प्राप्त के अनुरूप

न्यायनिर्णयन के सिद्धांत। इसलिए जहाँ भी पहुँच हो

ऐसे अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों को संक्षिप्त, परिवर्तित, संशोधित या प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि उन्हें किसी अधिकार का उपयोग करने का निर्देश दिया जा सके। वैकल्पिक मंच, इस तरह का विधायी अधिनियम चुनौती देने के लिए खुला है

यदि यह एक स्वतंत्र मंच द्वारा निर्णय लेने के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए, हालांकि एम. बी. ए. द्वारा चुनौती मूल संरचना का हिस्सा बनने वाले सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर है, वे संविधान के अधिक स्पष्ट प्रावधानों में से एक से संबंधित हैं जिसने ऐसे सिद्धांतों को जन्म दिया। हालांकि विधायी अधिनियम के प्रावधानों की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह मूल संरचना को विक्षेपित करता है

संविधान, इसे उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जा सकती है

संवैधानिक प्रावधान जो सिद्धांतों को स्थापित करते हैं -

कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और स्वतंत्रता

न्यायपालिका "।

29. गाँधी के मामले में एक विशेष न्यायाधिकरण ने एक अन्य विशेष न्यायाधिकरण *(*कंपनी लॉ बोर्ड*)* की जगह ली।

मूल चरण। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलीय न्यायाधिकरण को दी गई पहली अपील केवल कानून के प्रश्नों तक ही सीमित नहीं है। यह एक पूर्ण पहली अपील है जैसा कि सी. पी. सी. की धारा *96* के अर्थ में समझा गया है।

- *(* कंपनी अधिनियम की धारा *10* एफक्यू देखें*)*। एक और अपील

केवल कानून के प्रश्नों पर धारा *10* जी. एफ. के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। जब गांधी के मामले में पैराग्राफ *87* में कहा गया है कि अपील, संशोधन या संदर्भों के प्रावधानों को हटाकर उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटाया जा सकता है, और ये

अदालतों द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाले कार्यों को स्थानांतरित किया जा सकता है न्यायाधिकरण, अदालत केवल उच्च *342* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. की स्थिति से निपट रही थी।

जहां तक कंपनी के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, मूल और पहले अपीलीय चरण में प्रतिस्थापित किया जाने वाला न्यायालय ऐसी स्थिति में है जहां तथ्य के प्रश्नों को पहले अपीलीय चरण में भी नए सिरे से निर्धारित किया जाना है। ये अवलोकन स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते हैं।

तार्किक रूप से वर्तमान जैसी स्थिति को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाए जहां उच्च न्यायालय को एक न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जो होगा

केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय लेना।

30. वर्तमान मामला गांधी के मामले से बहुत ही मौलिक तरीके से अलग है। राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण जो प्रतिस्थापित करता है

देश में उच्च न्यायालय केवल कराधान से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए उनकी जगह लेते हैं। वास्तव में, एक प्रत्यक्ष कर कानून समिति ने *1978* में एक रिपोर्ट दी जिसे चोकसी कहा जाता है।

अपने अध्यक्ष के बाद समिति। इस रिपोर्ट ने वास्तव में सिफारिश की थी

कि एक केंद्रीय कर न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है:

"? II-6.10। अपनी अंतरिम रिपोर्ट के पैराग्राफ *11.30* में हमने यह विचार व्यक्त किया था कि सरकार को विचार करना चाहिए।

आय-कर अधिनियम और अन्य केंद्रीय कर कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मामलों से निपटने के लिए एक केंद्रीय कर न्यायालय की स्थापना, और इस मामले को हमारी अंतिम रिपोर्ट में अधिक विस्तार से विचार के लिए छोड़ दिया था। हम तब से जांच कर रहे हैं

यह सभी पहलुओं से महत्वपूर्ण है। *II-6.11*। हाल के वर्षों में भारत में कर मुकदमेबाजी की समस्या ने चौंका देने वाला अनुपात ले लिया है। आंकड़ों से

यह देखा गया है कि *30* जून, *1977* तक प्रत्यक्ष कर के तहत *10,500* संदर्भ थे। विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कानून, सबसे अधिक लंबित बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हैं। सभी कर कानूनों के तहत भारत में उच्च न्यायालयों को दिए गए संदर्भों की संख्या एक वर्ष में लगभग *3,300* है, जबकि सभी उच्च न्यायालयों द्वारा इस तरह के संदर्भों का वार्षिक निपटान कुल मिलाकर राशि है।

एक वर्ष में लगभग *600* तक। इन संदर्भों के अलावा, कर मामलों पर लगभग *750* रिट याचिकाएं भी हर साल उच्च न्यायालयों में दायर की जाती हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय की मौजूदा प्रथा के तहत कर मामलों से निपटने के लिए केवल एक ही पीठ है और वह भी पूरे वर्ष नहीं,

स्पष्ट रूप से समस्या को मद्रास बार एसोसिएशन *v* से नीचे लाए जाने की कोई संभावना नहीं है।

भारत संघ *343*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

भविष्य में किसी भी समय प्रबंधनीय अनुपात के लिए, लेकिन, दूसरी ओर, यह बदतर होने की संभावना है। यहाँ तक कि लेखन भी।

कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ तत्काल उपाय की मांग करने वाली याचिकाएं

निपटान में कई साल लगते हैं। वांचू समिति,

जिसने इस समस्या पर विचार किया था, सिफारिश की थी उच्च न्यायालयों में स्थायी कर पीठों का निर्माण और

बैकलॉग को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद *224* ए के तहत ऐसी पीठों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। हालांकि अधिक

उस सिफारिश को किए हुए *6* साल से अधिक समय बीत चुका है, कर मामलों में बकाया की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी ओर, यह बिगड़ गया है। में।

इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य होगा कि वांचू

समिति ने व्यवहार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग पर विचार किया

एक कर न्यायालय की स्थापना के माध्यम से इस समस्या के साथ लेकिन उन्होंने उस पर कोई सिफारिश करने से इनकार कर दिया

आईएल-*6.12*। कर मामलों में अदालतों के समक्ष लंबित मामलों का भी अपीलीय पदानुक्रम की रेखा के साथ एक बर्फबारी प्रभाव पड़ता है क्योंकि सैकड़ों मामलों में कार्यवाही शुरू की जाती है और लंबित रखी जाती है, अंततः कानून के आने का इंतजार किया जाता है। लंबे मुकदमे के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझा लिया गया

विभाग और अव्यवस्थाओं में निष्फल शब्दों का बोझ सभी स्तरों पर अपीलीय प्राधिकरणों की फाइलों को उनकी दक्षता पर प्रतिकूल परिणामों के साथ प्रस्तुत करना। आंकड़ों के अनुसार

हमें दी गई, कर बकाया राशि में से रु। *31* दिसंबर, *1977* को *986.53* करोड़ रु. *293.26* करोड़ *(30)*

प्रतिशत*)* विभिन्न मामलों से पहले की कार्यवाही में विवादित थे

II-6.13। मौजूदा प्रणाली में अंतर्निहित देरी के अलावा, उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र भी टालने योग्य कार्य के सृजन में योगदान देता प्रतीत होता है। वर्तमान में, उच्च न्यायालय आने वाले मामलों पर निर्देश सुनने के लिए बाध्य हैं। उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर इसके बावजूद कि संदर्भों पर

अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा समान बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है।

एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे उच्च न्यायालय पर समान मुद्दों पर भी बाध्यकारी नहीं है। अंतिम रूप तभी दिया जाता है जब सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर फैसला करता है जिसमें *10* से *15* साल लग सकते हैं। आईएल-*6.14*। कर मुकदमेबाजी को वर्तमान में तदर्थ आधार पर गठित उच्च न्यायालयों की विभिन्न पीठों द्वारा संभाला जाता है। द.

स्थायी पीठों की अनुपस्थिति भी उच्च न्यायालयों द्वारा कर मामलों के निपटारे में देरी का कारण बनती है।

II-6.15। इन समस्याओं का उत्तर, हमारे विचार में, उच्च न्यायालयों को छोड़कर इस तरह के मुकदमे से निपटने के लिए अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र के साथ एक केंद्रीय कर न्यायालय की स्थापना है। इस तरह के कदम के

कई फायदे होंगे। सबसे पहले, यह निर्णयों में एकरूपता लाएगा और एक उपाय लाएगा कर संबंधी मामलों में निश्चितता। सामान्य मुद्दों से जुड़े संदर्भों को आसानी से समेकित किया जा सकता है और एक साथ निपटाया जा सकता है, जिससे निपटान की गति में तेजी आती है। पीठों के बीच बेहतर समन्वय से मामलों का तेजी से निपटारा होगा और निचले अपीलीय अधिकारियों के समक्ष उन्हीं मुद्दों पर अपीलों के प्रसार की गुंजाइश कम होगी, जिससे बदले में कर न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी की मात्रा भी कम हो जाएगी। एक बार केंद्रीय कर

न्यायालय की स्थापना हो जाती है, इसकी पीठों में नियुक्त न्यायाधीश इस क्षेत्र में निरंतर काम करके आवश्यक विशेषज्ञता विकसित करेंगे। इससे कर मामलों के त्वरित निपटान में सुविधा होगी और निर्णयों में एकरूपता सुनिश्चित करके मुकदमेबाजी को कम करने में भी मदद मिलेगी। *II-6.16*। पूर्वगामी चर्चाओं के आलोक में, हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए

भविष्य में। हम सुझाव देते हैं कि ऐसी अदालत का गठन एक अलग क़ानून के तहत किया जाना चाहिए। चूंकि इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए संशोधन की आवश्यकता हो सकती है संविधान, जिसमें समय लगने की संभावना है, हम आगे अनुशंसा करते हैं कि सरकार इस बीच,

विशेष कर पीठों के गठन की वांछनीयता पर विचार करें

1 मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *345*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

बड़ी संख्या में कर मामलों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों में

साल भर लगातार बैठे रहना। न्यायाधीशों इन विशेष पीठों में नियुक्त होने के लिए चुना जा सकता है

उन लोगों में से, जिन्हें विशेष ज्ञान है और

प्रत्यक्ष कर कानूनों से संबंधित मामलों से निपटने का अनुभव ताकि, जब बाद में केंद्रीय कर न्यायालय की स्थापना की जाए, तो इन न्यायाधीशों को उस न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सके। आईएल-*6.17*। केंद्रीय कर न्यायालय में महत्वपूर्ण केंद्रों पर पीठें होनी चाहिए। इसके साथ शुरू करने के लिए निम्नलिखित सात स्थानों पर पीठ हो सकती हैं। , अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, मद्रास और नागपुर। प्रत्येक पीठ में दो न्यायाधीश होने चाहिए। उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को

केंद्रीय कर न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं। परिस्थितियों के मामले में

सेवा, तराजू या वेतन और अन्य विशेषाधिकारों, के न्यायाधीश

केंद्रीय कर न्यायालय को उच्च न्यायालय के बराबर होना चाहिए

न्यायाधीशों।

अधिनियम के जीव संवैधानिक पर उच्चारण नहीं कर सकते हैं अधिनियम के किसी भी प्रावधान की वैधता या अधिकार; कि; इसलिए, ऐसा प्रश्न न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न नहीं हो सकता है और इसे उच्च न्यायालय के संदर्भ और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में अपील का विषय नहीं बनाया जा सकता है; और यह कि वैधता या अधिकार का ऐसा प्रश्न निम्नानुसार हो सकता हैः

केवल एक वाद या एक रिट याचिका में उठाया गया। जबकि एक आय-कर प्राधिकरण या न्यायाधिकरण वैधता पर निर्णय नहीं ले सकता है।

या कानून के अन्य प्रावधानों के अधिकार। हम अनुशंसा करते हैं कि इस संबंध में केंद्रीय कर न्यायालय की शक्तियों को विशेष रूप से अधिकार देकर कानून में ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। कर के प्रावधानों की वैधता के प्रश्नों पर जाने के लिए

कानून या उसके तहत बनाए गए नियम।

II-6.19। एक अन्य महत्वपूर्ण मामला, जिसमें हम मानते हैं कि वर्तमान स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, की प्रकृति है कर मामलों में न्यायालय की अधिकारिता। वर्तमान कानून के तहत, ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. है।

अल।

कानून के प्रश्नों पर परामर्श। इस उद्देश्य के लिए, अपीलीय न्यायाधिकरण को मामले का एक बयान तैयार करना होगा और उसे अपनी राय के लिए उच्च न्यायालय को भेजना होगा। उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ पर अपना निर्णय देने के बाद, मामला न्यायाधिकरण के पास वापस चला जाता है, जिसे तब ऐसे आदेश पारित करने होते हैं जो मामले के अनुरूप निपटारे के लिए आवश्यक होते हैं -

इस तरह का निर्णय। इस प्रक्रिया के तहत, पीड़ित पक्ष को न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर करना होता है जिसमें

कानून के निर्दिष्ट प्रश्नों पर उच्च न्यायालय को निर्देश

न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न। न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह के आवेदन की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय में मामले का बयान तैयार करने से उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर विचार करने में काफी समय तक देरी होती है। जहां न्यायाधिकरण आवेदक द्वारा मांगे गए मामले को बताने से इनकार करता है, तो फिर से, कानून उच्च न्यायालय को निर्देश जारी करने के लिए सीधे संपर्क का प्रावधान करता है अपीलीय न्यायाधिकरण कानून के प्रासंगिक प्रश्न पर मामले को उच्च न्यायालय को बताएगा। इस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय द्वारा मामले पर विचार करने में भी काफी देरी होती है।

समय। इस प्रकार की देरी के अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा मामले का फैसला करने के बाद और देरी होगी, क्योंकि न्यायाधिकरण को मामले का निपटारा करने के लिए परिणामी आदेश पारित करने होंगे।

इससे पहले कि राहत, यदि कोई देय हो, निर्धारिती को दी जा सकती है। आईएल-*6.20*। हमारे विचार में, प्रस्तावित केंद्र में अधिकार क्षेत्र निहित करके कर मुकदमेबाजी के निपटान में काफी तेजी लाई जा सकती है।

कर न्यायालय ऐसे आदेशों से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्नों पर न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा। हम,

तदनुसार, सिफारिश करें कि केंद्रीय कर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अपीलीय होना चाहिए न कि सलाहकार। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि केंद्रीय कर न्यायालय के समक्ष अपीलों की सुनवाई दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए। डिवीजन बेंच का निर्णय अन्य डिवीजन बेंच पर बाध्यकारी होना चाहिए।

कर न्यायालय जब तक कि यह उच्चतम न्यायालय या कर न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के विपरीत न हो।

आईएल-*6.21*। केंद्रीय कर न्यायालय के समक्ष अपील के मामले में, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित होने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट को सक्षम बनाने के लिए एक विशेष प्रावधान करना आवश्यक होगा।

या उत्तरदाताओं को उसके सामने एन्नियल्स पर बहस करने के लिए।

कानूनी मद्रास बार एसोसिएशन *v.* भारत संघ *347*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

न्यायालय द्वारा उसके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, कर मामलों में अपीलार्थी या प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। आईएल-*6.22*। केंद्रीय कर न्यायालय की स्थापना के लिए हमारी सिफारिश को केवल एक संशोधित संस्करण के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

संविधान के *42* वें संशोधन द्वारा किए गए संशोधनों के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थापित किए जाने के लिए प्राधिकृत प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों की अवधारणा। केंद्रीय कर न्यायालय, जिसे हम देखते हैं, एक विशेष न्यायालय होगा। कर मामलों पर कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय

और उसी तरीके से न्यायिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए

उच्च न्यायालयों की तरह। इसलिए संविधान के *42* वें संशोधन से उत्पन्न विवाद को उच्च न्यायालय के कार्यों का प्रयोग करने के लिए केंद्रीय कर न्यायालय की स्थापना के प्रस्ताव के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए।

कर मामलों में न्यायालय "।

संसद ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था।

31. यह स्पष्ट है कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कराधान से संबंधित हैं, उनमें नागरिक और आपराधिक के कई क्षेत्र भी शामिल होंगे।

कानून, उदाहरण के लिए हिंदू संयुक्त परिवार कानून, साझेदारी, वस्तुओं की बिक्री, अनुबंध, मुस्लिम कानून, कंपनी कानून, संबंधित कानून न्यास और समितियाँ, संपत्ति का हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा से संबंधित कानून, कानूनों और उनसे संबंधित धाराओं की व्याख्या

अपराधों के लिए अभियोजन। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कराधान, एक विशेष विषय होने के कारण, एक न्यायाधिकरण द्वारा निपटा जा सकता है। सभी

हमारी संवैधानिक योजना के तहत कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय केवल उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। वास्तव में, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों में से एक, जैसा कि मंत्री ने सदन में कहा है, यह है कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण पूरे भारत के लिए कानून निर्धारित कर सकता है जो तब अन्य सभी प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों को बाध्य करेगा। यह अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति पर सीधा अतिक्रमण है। *227* ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी मामला, उपरोक्त के अनुसार कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय करना जो सभी न्यायाधिकरणों को बाध्य करेगा।

2. वास्तव में, यह थोड़ा आश्चर्यजनक है कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण

अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. के बीच हस्तक्षेप किया जाता है।

न्यायालय बहुत अच्छे कारण के लिए कि अंततः यह केवल सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भविष्य में कानून का पालन करने की घोषणा करेगा। चूँकि अपीलीय न्यायाधिकरण पहले से ही एक दूसरा अपीलीय न्यायालय है, इसलिए यह पूरी तरह से अनावश्यक होगा कि एक राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण परस्पर विरोधी निर्णयों के मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय ले।

उच्च न्यायालयों और अपीलीय न्यायाधिकरणों को अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही तय किया जाएगा, जो निर्णय अनुच्छेद *141* के तहत सभी कर प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी होगा। दूसरा, सभी कर मामलों में, राज्य हमेशा एक पक्ष है और

उच्च न्यायालय आदर्श रूप से राज्य और निजी व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय करने के लिए स्थित है।

33. वास्तव में, अन्य संविधान जो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित हैं, जैसे ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम जो कनाडा ने भी ऐसा ही किया है। क्यूबेक के लिए महान्यायवादी बनाम। फराह *(1978), Vol.86 DLR [3d] 161* एक परिवहन न्यायाधिकरण को क्यूबेक परिवहन आयोग पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र दिया गया था। न्यायाधिकरण ने कानून के प्रश्नों को तय करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। चूँकि यह कार्य अंततः केवल उच्च न्यायालयों द्वारा किया गया था, इसलिए विवादित धारा को असंवैधानिक माना गया था। यह

फैसले का पालन रे में किया गया था। आवासीय किरायेदारी अधिनियम, *123* डी. एल. आर. *(3* डी*) 554*। यह निर्णय आगे बढ़ा और आवासीय किरायेदारी अधिनियम को निरस्त कर दिया, जिसने एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जिसमें मकान मालिकों और किरायेदारों को इसके तहत लगाए गए दायित्वों का पालन करने की आवश्यकता थी।

अधिनियम। अदालत ने कहाः

"अपील न्यायालय ने एक सावधानीपूर्वक और विद्वतापूर्ण सर्वसम्मत निर्णय दिया जिसमें इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आवासीय किरायेदारी अधिनियम, *1979* में प्रदान किए गए निष्कासन आदेश और अनुपालन आदेश देने के लिए आवासीय किरायेदारी आयोग को सशक्त बनाना ओंटारियो के विधायी प्राधिकरण के भीतर नहीं था। इस मुद्दे का महत्व इस तथ्य में

परिलक्षित होता है कि मुख्य न्यायाधीश और सहायक मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायालय के पांच न्यायाधीश अपील पर बैठे थे। मद्रास बार एसोसिएशन *v.*

भारत संघ *349*

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इसके बाद इसने तीन चरणों वाले परीक्षण का प्रतिपादन किया जिसके साथ हम

सीधे तौर पर चिंतित नहीं। अंततः न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

"की ओर से दिए गए पूरे तर्क में निहित

ओंटारियो के अटॉर्नी-जनरल की धारणा है कि

न्यायालय प्रणाली बहुत बोझिल, बहुत महंगी और

इसलिए सामाजिक जरूरतों को ठीक से पूरा करने में असमर्थ जो आवासीय किरायेदारी अधिनियम, *1979* का उद्देश्य है

मिलते हैं। सभी कानून सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। न्यायालय समानता और निष्पक्षता, न्याय, सुविधा, तर्कसंगतता की अवधारणा से अपरिचित हैं। *1976* में अधिनियमन के बाद से देश को "कार्यकाल की सुरक्षा" का आश्वासन देने वाले कानून का

ओंटारियो के न्यायालय के न्यायाधीश मामलों को निपटाते रहे हैं। उस कानून से उत्पन्न, जाहिरा तौर पर उचित के साथ

वर्तमान में मकान मालिक और किरायेदार दोनों के रूप में भेजें

कार्यवाही ने हस्तांतरण के खिलाफ स्पष्ट रूप से बात की है

बेदखली और अनुपालन आदेशों के संबंध में अधिकार क्षेत्र

न्यायालयों से विशेष आयोग तक। शायद यह भी दिलचस्प है कि हमारे पास दायर सामग्री में ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि विधि सुधार आयोग ने अदालतों से ऐतिहासिक कार्यों को हटाने का समर्थन किया है।

100 न्यायालयों द्वारा वर्षों तक।

इस दृष्टिकोण के समर्थन में दिए गए तर्कों से मैं न तो अनजान हूं और न ही असम्मानित हूं। *96* होना चाहिए प्रांतीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के भविष्य के विकास को विफल करने या अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी। फिर भी, नीतिगत उद्देश्य कितने भी योग्य क्यों न हों, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हमें, एक न्यायालय के रूप में, यह चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि क्या

समस्या ऐसी है कि संघीय के बजाय प्रांतीय प्राधिकरण को इससे निपटना चाहिए। हमें संविधान को प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए जैसा कि हम इसे समझते हैं और उचित सम्मान के साथ करते हैं

जिस तरीके से इसकी न्यायिक रूप से व्याख्या की गई है अतीत में। यदि आक्षेपित शक्ति एस का उल्लंघन करती है। *96* होना ही चाहिए।

गिराए जाएँ "।

34. हिन्स वी. लोक अभियोजन की रानी निदेशक जैक्सन जमैका के महान्यायवादी *(मध्यस्थ) 1976*

सभी ई. आर. *353,* प्रिवी काउंसिल को जमैका के संविधान के तहत एक मामले का फैसला करना था।

एक बंदूक अदालत अधिनियम, *1974 350* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर. पारित किया गया था।

जमैका की संसद द्वारा जिसमें इसने विभिन्न न्यायालयों की स्थापना की। ए.

तत्काल मामले में पूछे गए प्रश्न के समान प्रश्न का निर्णय इस प्रकार किया गया था:

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ अलग-अलग अध्याय। न्यायपालिका से संबंधित अध्याय में निश्चित रूप से विधि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं - सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की सुरक्षा

न्यायपालिका जो उन्हें कुछ हद तक आश्वस्त करने के लिए बनाई गई है

सरकार की अन्य दो शाखाओं से स्वतंत्रता।

जैसा कि सीलोन के संविधान के मामले में है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। जिस हद तक संविधान स्वयं न्यायिक शक्ति के पूर्ण वितरण के बारे में चुप है

विभिन्न न्यायालयों में यह निहित है कि इसका वितरण जारी रहेगा।

उन न्यायालयों के बीच और उनके द्वारा प्रयोग किया गया जो पहले से ही

अस्तित्व में जब नया संविधान लागू हुआ; लेकिन विधायिका, राज्य की शांति, व्यवस्था और अच्छी सरकार के लिए कानून बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए,

नए न्यायालयों की स्थापना और पहले से प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता के पूरे या हिस्से के हस्तांतरण के लिए एक मौजूदा अदालत द्वारा। हालाँकि, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर संविधान की संरचना में जो निहित है वह यह है कि

न्यायिक शक्ति, हालांकि इसे समय-समय पर वितरित किया जाता है

विभिन्न न्यायालयों के बीच, व्यक्तियों में निहित रहना है

तरीके से और न्यायिक पद धारण करने के लिए नियुक्त

न्यायपालिका से संबंधित अध्याय में निर्धारित शर्तें,

भले ही यह संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो *(* लियानगे वी। आर *[1966] 658 [1976]* एसी *259* पर सभी ईआर *650*

287 , 288]

वेस्टमिंस्टर मॉडल पर हाल के संविधानों में, उनके पहले के प्रोटोटाइप के विपरीत, एक अध्याय शामिल है जिसमें

मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएँ। इस अध्याय के प्रावधान राज्य के मूल कानून का हिस्सा हैं और जब तक संशोधित नहीं किया जाता है।

संविधान में जो भी विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है

इस उद्देश्य के लिए, व्यायाम पर एक बंधन लागू करें

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका

अपनी-अपनी शक्तियों से। के शेष अध्याय संविधान मुख्य रूप से विधायिका मद्रास बार एसोसिएशन से संबंधित नहीं हैं।

भारत संघ *351*

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं को अमूर्त के रूप में, लेकिन वे व्यक्ति जो सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से हकदार होंगे

विधायी, कार्यपालिका या न्यायपालिका की पूर्णता का प्रयोग करना।

शक्तियाँ-विधायी, कार्यकारी या न्यायिक पद के लिए उनकी योग्यताएँ, उन्हें चुनने की विधि, उनका कार्यकाल,

जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना है जहाँ शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं

सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के एक वर्ग और बहुमत पर

इन शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक। अतः जहाँ ए

वेस्टमिंस्टर मॉडल पर संविधान एक विशेष *'अदालत'* की बात करता है जो पहले से ही अस्तित्व में है जब संविधान आता है।

बल, यह इस अभिव्यक्ति का उपयोग सामूहिक विवरण के रूप में करता है

वे सभी व्यक्तिगत न्यायाधीश जो, चाहे अकेले बैठे हों या उनके साथ

अन्य न्यायाधीश या जूरी के साथ, संविधान लागू होने से पहले उस न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के हकदार हैं। उस न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की नियुक्ति या सुरक्षा के लिए संविधान में कोई भी स्पष्ट प्रावधान उन सभी व्यक्तिगत न्यायाधीशों पर लागू होगा जिन्हें बाद में एक नियम का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया था। समान अधिकारिता, जो भी अन्य नाम दिया जा सकता है

उस *'अदालत'* में जहाँ वे बैठते हैं *(ओंटारियो के लिए महान्यायवादी)*

वी. कनाडा के लिए अटॉर्नी जनरल।)

जहाँ, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर एक संविधान के तहत,

संसद द्वारा एक कानून बनाया जाता है जिसका उद्देश्य प्रदान करना है

एक नए नाम से वर्णित अदालत पर अधिकार क्षेत्र, यह सवाल कि क्या कानून न्यायिक शक्ति के प्रयोग से संबंधित संविधान के प्रावधानों के साथ संघर्ष करता है, लेबल पर निर्भर नहीं करता है (तत्काल मामले में 'द गन कोर्ट') जो

प्रयोग करते समय संसद न्यायाधीशों से जुड़ती है

कानून द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारिता जिसकी संवैधानिकता विवादित है। यह कानून का सार है जिसे माना जाना चाहिए, न कि रूप। उन न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति क्या है जिन्हें उस न्यायालय की रचना करनी है जिससे नया लेबल जुड़ा हुआ है? उनकी नियुक्ति का तरीका क्या है और

उनके कार्यकाल की प्रतिभूति की आवश्यकताओं के अनुरूप है

संविधान उन न्यायाधीशों पर लागू होता है जो उस समय

संविधान लागू हुआ, जिसके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया गया

प्रकृति? (ऑस्ट्रेलिया के लिए महान्यायवादी बनाम। आर एंड बॉयलरमेकर्स '

सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया) "।

35. अंततः, अदालत के बहुमत ने पाया कि प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 10 एस. सी. आर.

352

1974 के अधिनियम के अनुसार, जहाँ तक वे तीन निवासी मजिस्ट्रेटों से युक्त बंदूक न्यायालय के एक पूर्ण अदालत प्रभाग की स्थापना के लिए प्रावधान करते हैं, वे असंवैधानिक थे।

36. विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आय की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

कर अधिनियम और इसी तरह के अन्य कर कानूनों को आम लोगों द्वारा हटाया जा सकता था।

कानून और ऐसी धाराओं को हटाया जा सकता है। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से उक्त धारा द्वारा उच्च न्यायालय में निहित अधिकारिता को किसी अन्य निकाय को हस्तांतरित किया जा सकता है।

37. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक अपील क़ानून का एक प्राणी है और इसे क़ानून द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यहाँ सवाल यह है कि

पूरी तरह से अलग और उस प्रश्न का उत्तर हमारे न्यायशास्त्र के लिए मौलिक हैः कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र हमारे संविधान के तहत केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के पास निहित है, और इसे किसी अन्य निकाय में निहित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक मुख्य संवैधानिक मूल्य है।

38. वास्तव में, महान्यायवादी ने पैरा *16* और *21 (ए)* में अपने लिखित तर्क में हमारे सामने कहा हैः

"16. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अधिनियम उच्च न्यायालय के न्यायिक अधीक्षण की शक्ति को नहीं छीनता है।

अनुच्छेद *227*। प्रथम दृष्टया न्यायाधिकरण के फैसलों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील न्यायिक जांच का एक स्वीकार्य रूप है। न्यायाधिकरण के निर्णय से उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का प्रावधान विशुद्ध रूप से कानून के प्रश्नों पर भी हो सकता है। चूंकि उच्च न्यायालय एक नियम के रूप में

जब उच्चतम न्यायालय को अपील प्रदान की जाती है तो न्यायिक अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, ऐसे मामलों में भी न्यायाधिकरण पर उच्च न्यायालय की न्यायिक अधीक्षण की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन यह कटौती

lawi.e की अदालत के रूप में कानून के शासन का उल्लंघन नहीं करता है. सर्वोच्च न्यायालय कानून का अंतिम दुभाषिया बना हुआ है। के द्वारा

उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अप्रतिबंधित अधिकार *227* के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को कम नहीं करेगा क्योंकि अनुच्छेद *226/227* के तहत उच्च न्यायालय का सहारा अभी भी उपलब्ध होगा। यदि न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता को पार करता है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या ऐसे अन्य उल्लंघन करता है।

21. (क*)* वर्तमान अधिनियम की धारा *24* के तहत अपील के रूप में न्यायिक जांच के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है। अधिनियम और अनुच्छेद *226/227*, अनुच्छेद *32* और अनुच्छेद के तहत भी

136 संविधान से।

39. उपरोक्त तर्क को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि इस तर्क के अनुसार भी, उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति

लेख *226/227* के तहत समीक्षा वास्तव में द्वारा प्रतिस्थापित की गई है

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण, कुछ ऐसा जो एल. चंद्रकुमार ने कहा था, किया नहीं जा सकता। ऊपर उद्धृत एल. चंद्र कुमार के मामले का पैरा *93* देखें। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, *2010 (3)* एस. सी. सी. *571*, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय दियाः

"39. यह सामान्य बात है कि भारत में अपनाई गई संवैधानिक योजना में, संविधान की सर्वोच्चता के अलावा, विधायिका, कार्यपालिका और सरकार के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया है।

न्यायपालिका संविधान की बुनियादी विशेषताओं का गठन करती है। वास्तव में, हमारी व्यवस्था में शक्तियों के पृथक्करण का महत्व

शासन को विशेष संदर्भ संख्या में मान्यता दी गई थी।

1 1964 का *[*ए. आई. आर. *1965* एस. सी. *745: (1965) 1* एससीआर *413]*। , केशवानंद भारती बनाम के प्रसिद्ध मामले में मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन होने से पहले ही। केरल राज्य *[(1973) 4* एस. सी. सी. *225],* जिसमें संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं का पता लगाते हुए यह राय दी गई थी कि शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। बाद में, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम में भी इसी तरह का विचार प्रतिध्वनित किया गया था। राज नारायण *[1975* पूरक एस. सी. सी. *1]* और इस मुद्दे पर अन्य मामलों की एक श्रृंखला में। फिर भी, इस तथ्य के अलावा कि हमारा संविधान एक कठोर और सख्त अलगाव की परिकल्पना नहीं करता है

राज्य के उक्त तीन अंगों के बीच की शक्तियों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति पूरी तरह से एक अलग आधार पर है। स्वयं संविधान की मूल संरचना का हिस्सा होने के कारण, इसे संविधान द्वारा भी हटाया या संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है।

संशोधन। *(* एल. चंद्र कुमार बनाम देखें। भारत संघ *[(1997) 3* एस. सी. सी. *261: 1997* एस. सी. सी. *(*एल एंड एस*) 577]*।*)* इसके अलावा, न्यायिक समीक्षा अन्यथा संबंधित विवादों को हल करने के लिए आवश्यक है। संवैधानिक शक्ति की सीमाएँ और संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में संवैधानिक सीमाओं में प्रवेश करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2014] 10* एस. सी. आर.

354

" 68. इस प्रकार, संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी विवादों की जांच करने के बाद

संवैधानिक योजना के बारे में हम इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हैं: *((*ग*)* संवैधानिक योजना और अधिकारिता को ध्यान में रखते हुए

इस न्यायालय को अनुच्छेद *32* के तहत और उच्च न्यायालयों को प्रदत्त संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत न्यायिक शक्ति

मूल संरचना का एक अभिन्न अंग होने के नाते समीक्षा

संविधान, संसद का कोई भी अधिनियम इसे बाहर या कम नहीं कर सकता है संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियाँ

मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। वास्तव में, इस तरह

उद्देश्यों को व्यावहारिक सामग्री देने के लिए एक शक्ति आवश्यक है।

भाग *III* और अन्य भागों में सन्निहित संविधान का

संविधान। इसके अलावा, संघीय संविधान में,

संसद और संसद के बीच विधायी शक्तियों का वितरण

राज्य विधानमंडल में विधायी शक्तियों पर सीमाएं शामिल हैं।

और इसलिए इसके लिए संसद के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

यह पता लगाने के लिए कि क्या ऐसी सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। न्यायिक

समीक्षा अंतिम मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है न केवल प्रभाव देने के लिए

संसद और संसद के बीच विधायी शक्तियों का वितरण

राज्य विधानमंडलों को यह भी दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक इकाई द्वारा उल्लंघन। इसलिए शब्दों को उधार लेने के लिए

लॉर्ड स्टेन की न्यायिक समीक्षा के संयोजन द्वारा उचित ठहराया जाता है

"शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, कानून का शासन, सिद्धांत

संवैधानिकता और न्यायिक समीक्षा की पहुंच "।

40. प्रोपराइटरी आर्टिकल्स ट्रेड्स एसोसिएशन *v.* वकील

कनाडा के लिए जनरल, *1931* एसी *311*, लॉर्ड एटकिन ने कहाः

"उनके प्रभुत्व में कोई संदेह नहीं है कि केवल समय ही ऐसा नहीं कर पाएगा।

एक अधिनियम को मान्य करें जिसे चुनौती दिए जाने पर अमान्य पाया जाता है।

अधिकार; और न ही प्रगति की एक क्रमिक श्रृंखला का इतिहास होगा

इस सीमा को अंततः पार किया जाता है ताकि अंतिम सीमा की रक्षा की जा सके।

अतिक्रमण "। पेज *317* पर।

41. चंद्र कुमार और आर. गांधी ने न्यायाधिकरण की अनुमति दी है।

मूल अवस्था में कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन। इस मामले में आखिरकार सीमा पार कर दी गई है। इसलिए, मेरा मानना है कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम असंवैधानिक है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालयों के अनन्य अधिकार क्षेत्र पर अंतिम अतिक्रमण है

भारत में रिकॉर्ड। देविका गुजराल

मामलों का निपटारा किया गया।